बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 146

# राज्यों की वित्तीय सेहत

क्रिसिल की एक हालिया रिपोर्ट दिखाती है कि भारत के 18 सबसे बड़े राज्य जो मिलकर देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी में 90 फीसदी से अधिक का योगदान करते हैं, उनका राजस्व 2025-26 में 7 से 9 फीसदी तक बढ़ने की उम्मीद है। 2024-25 में यह महज बढ़त 6.6 फीसदी थी। कुल समेकित राजस्व के 40 लाख करोड़ रुपये हो जाने का अनुमान है। इसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रह, शराब पर यानी आबकारी शुल्क में इजाफे और बेहतर केंद्रीय हस्तांतरण की अहम भूमिका है। पेट्रोलियम कर संग्रह जरूर 2 फीसदी की वृद्धि के साथ कमजोर बना हुआ है।

यह स्पष्ट रूप से राज्यों की वित्तीय हालत में स्थिरता का संकेत है। यह स्थिरता ऐसे समय में नजर आ रही है जबकि वैश्विक हालात चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं और घरेलू आर्थिक हालात भी वैसे ही हैं। यह पूंजीगत आवंटन में तेज वृद्धि की स्थितियां निर्मित करता है। हालांकि यह गहन ढांचागत मुद्दों की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। राजस्व वृद्धि दशक के 10 फीसदी के औसत से कम बनी हुई है और अधिकांश राज्य बहुत हद तक केंद्र से होने वाले हस्तांतरण पर निर्भर हैं। 2015-16 से 2024-25 तक राज्यों के राजस्व का 23 से 30 फीसदी तक हिस्सा केंद्र के हस्तांतरण से आया। 2000 और 2010 के दशक में यह 20 से 24 फीसदी के बीच हुआ करता था। इसके साथ ही गत दशक में राज्यों के गैर कर राजस्व में केंद्र सरकार के अनुदान 65 से 70 फीसदी के हिस्सेदार रहे जबकि पहले इनका योगदान 55 से 65 फीसदी तक होता था। यह दीर्घकालिक रुझान इस बात को रेखांकित करता है कि कैसे केंद्र की भूमिका बढ़ रही है और राज्यों के पास अपनी वित्तीय हालत सुधारने के स्वतंत्र उपाय सीमित हो रहे हैं। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की रिपोर्ट भी दिखाती है कि 2024-25 में राज्यों द्वारा अपनी राजस्व प्राप्तियों का 58 फीसदी हिस्सा अपने कर और गैर कर स्रोतों से हासिल किया गया जबकि 42 फीसदी राजस्व केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्र के अनुदान से हासिल होने का अनुमान है।

भारकीय रिजर्व बैंक ने 2023-24 में राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें कहा गया था कि राज्य सरकारों का समेकित ऋण-जीडीपी अनुपात 28.5 फीसदी है जो वित्तीय जवाबदेही और बजट प्रबंधन समीक्षा समिति द्वारा तय 20 फीसदी की सीमा से अधिक था। आंकड़े बताते हैं कि 12 राज्यों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2023-24 में 35 फीसदी का स्तर पार कर गया जबकि करीब 24 राज्यों का अनुपात 20 फीसदी से अधिक था। बहरहाल कुछ को छोड़कर अधिकांश राज्यों का प्रदर्शन केंद्र से बेहतर रहा है। कई राज्यों ने बजट पारदर्शिता में सुधार किया है, सामाजिक क्षेत्र में अपन क्षमताएं बेहतर की हैं और पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी है। वास्तव में अधिकांश राज्यों ने काफी हद तक राजकोषीय समझदारी दिखाई है। उन्होंने मोटे तौर पर एफआरबीएम के मानकों का पालन किया और अपने राजकोषीय घाटे को जीएसडीपी के 3 फीसदी तक सीमित रखा। राज्यों का समेकित सकल राजकोषीय घाटा 1998-99 के जीडीपी के औसतन 4.3 फीसदी से कम होकर 2004-05 से 2023-24 के बीच जीडीपी का 2.7 फीसदी रह गया।

बहरहाल, राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जीएसटी अनुपालन में सुधार को तत्काल प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। राज्यों को डिजिटल राजस्व निगरानी का विस्तार करना चाहिए और संपत्ति कर तथा उपयोगकर्ता शुल्क आदि में आने वाली खामियों को दूर करना चाहिए। इसके साथ ही केंद्र सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि हस्तांतरण समय पर और अनुमानित ढंग से हो, खासतौर पर वित आयोग द्वारा अनुशंसित अनुदान जो राजस्व वृद्धि और व्यय में असमानता की समस्या दूर करने में मदद करते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के बीच केंद्र द्वारा उपकर और अधिभार के इस्तेमाल को लेकर भी काफी मतभेद हैं। उपकर और अधिभार पर अधिक निर्भरता राज्यों और केंद्र के बीच राजकोषीय संतुलन को खराब करता है। इससे बचने की आवश्यकता है।

विनय सिन्हा

# विकसित भारत और शून्य उत्सर्जन का लंबा रास्ता

**जब तक यह स्पष्ट नहीं होगा कि असल में कौन-सा लक्ष्य हासिल करना है और कैसे करना है तब तक विकसित भारत और शुद्ध शून्य उत्सर्जन के लक्ष्यों से भटक जाना आसान है। बता रहे हैं अजय त्यागी**

आकांक्षाएं जब पक्के इरादों से जुड़ी होती हैं तब किसी भी व्यक्ति, कंपनी या देश को आगे बढ़ने और तरक्की करने के लिए प्रेरित करती हैं। कोई भी बड़ी कंपनी अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों से जुड़े दस्तावेजों में अपनी आकांक्षाएं दिखाती है। अगर देशों की बात करें तो उनकी कई आकांक्षाएं अलग-अलग सरकारी दस्तावेजों में अंतर्निहित होती हैं जिनमें से कुछ मुख्य बातें उनके संविधान में ही शामिल होती हैं। इसके अलावा समय-समय पर देश का राजनीतिक नेतृत्व अपनी विचारधारा, तात्कालिक जरूरत और अन्य प्रतिबद्धताओं के हिसाब से कुछ बड़े लक्ष्य तय करता है।

यह लेख भारत के मौजूदा राजनीतिक नेतृत्व द्वारा घोषित किए गए दो सबसे महत्त्वाकांक्षी दीर्घकालिक लक्ष्यों के बारे में है। ये दो लक्ष्य हैं, वर्ष2047 तक 'विकसित भारत' बनाना और वर्ष2070 तक ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन शुद्ध शून्य करना। इन दोनों लक्ष्यों को हासिल करने के रास्ते कई मायने में एक-दूसरे से जुड़े हैं और इसके लिए एक सामंजस्यपूर्ण दृष्टिकोण आवश्यक है ताकि हम मंजिल तक पहुंच सकें। सवाल यह है कि क्या हमें इसको लेकर पर्याप्त स्पष्टता है कि वास्तव में क्या हासिल करने का लक्ष्य है और इसे कैसे हासिल किया जाएगा?

आइए सबसे पहले 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को समझते हैं। 'विकास' शब्द थोड़ा अस्पष्ट है और अलग-अलग लोगों के लिए इसके अलग मायने हो सकते हैं। सवाल यह है कि असल में हम क्या हासिल करना चाहते हैं? सामान्य तौर पर जो जानकारी उपलब्ध है, उसके मुताबिक इस लक्ष्य के तहत भारत, निम्न मध्यम आय वाले देशों की सूची से निकलकर विश्व बैंक के अनुसार अपनी प्रति व्यक्ति आय को निम्न मध्यम से उच्च मध्यम स्तर तक ले जा सकता है।

निश्चित रूप से इसका लक्ष्य तय होना चाहिए लेकिन क्या यह पर्याप्त है? अन्य मापदंडों का क्या होगा जिनमें सामाजिक और पर्यावरणीय स्थितियों को बेहतर बनाने वाले मापदंड भी शामिल हैं, मसलन मानव विकास सूचकांक रैंकिंग, आय की असमानता कम करना, शहरों सहित बुनियादी ढांचे में सुधार और पर्यावरणीय क्षति को रोकना आदि? क्या इन सभी बातों पर विचार करके किसी सही निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक चर्चा की गई है?

सरकार को स्पष्ट तौर पर 'विकसित भारत' के लक्ष्य के तहत आने वाले सभी वांछित मापदंडों की एक सूची बनाने की जरूरत है जिसमें हर पहलू को पर्याप्त महत्त्व दिया जाए और जहां संभव हो वहां संख्यात्मक लक्ष्य भी तय हों। जब इन बातों पर स्पष्टता होगी तभी अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी सही नीतियां और रोडमैप बन पाएंगे। शुद्ध शून्य उत्सर्जन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र इसे कुछ इस तरह परिभाषित करता है, 'कार्बन उत्सर्जन में इतनी कटौती करना कि बचे हुए उत्सर्जन को प्राकृतिक तरीके और कार्बन डाइऑक्साइड हटाने के अन्य उपायों द्वारा अवशोषित किया जाए और प्रकृति को सतत तरीके से संभाल सकने लायक रखा जा सके ताकि वायुमंडल में शून्य उत्सर्जन रह जाए।'

सबसे अधिक आशावादी लोग भी इस बात पर सहमत होंगे कि भारत के लिए 2070 तक 'शून्य उत्सर्जन' दर हासिल करना एक बड़ी और मुश्किल चुनौती है। फिलहाल, भारत दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जक है। अधिकतर विकसित देशों में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कुछ समय पहले ही चरम पर पहुंच गया था। खबरों के अनुसार, चीन में भी यह हाल ही में चरम पर पहुंचा है या इस साल पहुंच जाएगा। भारत की कहानी बिल्कुल अलग है। हमारी विकास की बड़ी जरूरतों को देखते हुए, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता और मानवीय गतिविधियों के चलते होने वाले पर्यावरणीय बदलाव के स्तर को देखते हुए, यहां निकट भविष्य में उत्सर्जन चरम पर पहुंचने की संभावना नहीं है। वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के रोडमैप और इसके मॉडल को वास्तव में पर्यावरणीय बाधाओं को ध्यान में रखना ही होगा, जिससे यह लक्ष्य और भी चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।

वर्ष 2047 और 2070 काफी दूर हैं और इन लक्ष्यों से ध्यान भटकना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसा कि कीन्स की यह उक्ति बेहद चर्चित है, '...लंबे समय में हम सब मर जाएंगे।' इससे भी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि अब से 2047 और 2070 के बीच कई अलग-अलग सरकारें होंगी। मौजूदा सरकार को चाहिए कि वह इन लक्ष्यों में शामिल किए जाने वाले सभी मापदंडों पर सभी राजनीतिक दलों के बीच एक राष्ट्रीय स्तर की सहमति बनाए और आगे बढ़ने की राह क्या हो उसकी रूपरेखा ठीक से दस्तावेज के रूप में तैयार की जाए। अपनी महत्त्वाकांक्षाओं को पूरा करने में गंभीरता दिखाने के लिए, सरकार को व्यावहारिक और भरोसेमंद योजनाएं बनानी होंगी, जो जनता के सामने उपलब्ध होना चाहिए। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें।

'विकास' शब्द भले ही थोड़ा अस्पष्ट हो, लेकिन अच्छी बात यह है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को शायद स्कोप 3 उत्सर्जन और कार्बन सोखने की क्षमता को छोड़कर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किए गए मानदंडों और सही अनुमानों का उपयोग कर मापा जा सकता है। उत्सर्जन के स्तर की जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफ-सीसीसी) पार्टियों के सम्मेलन (कॉप) की बैठकों में भी निगरानी की जाती है जहां विभिन्न देश समय-समय पर राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के रूप में कमी लाने की प्रतिबद्धताएं जताते हैं।

उदाहरण के तौर पर, फिलहाल भारत ने 2030 तक अपनी सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45 फीसदी तक कम करने की प्रतिबद्धता जताई है। कई विशेषज्ञों का मानना है कि यह लक्ष्य समयसीमा से पहले ही आसानी से हासिल किया जा सकता है। अगर ऐसा है, तो 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन के अपने अंतिम लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, एनडीसी प्रतिबद्धता से आगे बढ़कर, अपने लिए ऊंचे लक्ष्य क्यों न निर्धारित किए जाएं?

सवाल यह भी है कि ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को मध्यम से लंबी अवधि में कम करने के लिए सरकार की वास्तविक कार्य योजना क्या है? इसमें से कितना कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र के माध्यम से हासिल किया जाएगा जैसे कि कार्बन कर और विभिन्न बाध्यकारी संस्थाओं के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन लक्ष्य तय करना, खासतौर पर एक मजबूत कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग तंत्र के साथ उन क्षेत्रों के लिए जहां इसमें कटौती करना मुश्किल है?

अनिवार्य आदेश के माध्यम से कितना लक्ष्य हासिल होने का अनुमान है, जो कार्बन मूल्य निर्धारण सिद्धांत द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित हो भी सकते हैं और नहीं भी जैसे कि जीवाश्म ईंधन की जगह अक्षय ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा दक्षता में सुधार, इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहन देना, कृषि पद्धतियों में सुधार, वनरोपण को बढ़ाना, कार्बन पृथक्करण और इसी तरह के अन्य उपाय? इन मामलों पर एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाने के लिए व्यापक स्तर पर सभी हितधारकों के साथ परामर्श करना, गहन डेटा विश्लेषण करना, तकनीकी उपकरणों का उपयोग करना और विशेषज्ञों की सलाह की आवश्यकता है।

आप वर्ष 2047 और 2070 की अवधि को पांच साल (अल्पकालिक) और 10 साल (मध्यम अवधि) के खंडों में विभाजित करें और दोनों लक्ष्यों के लिए सहमत मापदंडों के तहत, वास्तविक उपलब्धियों की तुलना लक्ष्यों से किसी तीसरे पक्ष (निगरानी, रिपोर्टिंग और सत्यापन) के विशेषज्ञों द्वारा समय-समय पर की जानी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।

वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' और 2070 तक 'शून्य उत्सर्जन' की महत्त्वाकांक्षाएं वास्तव में वांछनीय लक्ष्य हैं और ये इस वक्त की जरूरत भी है। वास्तव में सबसे मुश्किल हिस्सा रोडमैप के बारे में स्पष्टता कायम करना है।

*(लेखक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में विशिष्ट फेलो हैं और सेबी चेयरमैन रह चुके हैं।)*

# मध्य वर्ग की बदलती प्रकृति को समझना जरूरी

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

**अर्थशास्त्री** सुबीर गोकर्ण (अब दिवंगत) ने 2007 के आसपास इस अखबार में 'मिडल क्लास ओरिजिन्स' (मध्य वर्ग की उत्पत्ति) शीर्षक से एक ऐतिहासिक लेख लिखा था। उसमें कही गईं बातें आज लगभग 20 साल बाद और भी ज्यादा प्रासंगिक हैं। मध्य वर्ग की उत्पत्ति अथवा वह प्रक्रिया जिससे यह वर्ग उभरा, बहुत मायने रखती है। इस वर्ग के बारे में हम जैसा सोचते हैं और उसके व्यवहार एवं दृष्टिकोण के प्रति हमारी जो धारणा है, उसमें इसकी संघर्ष यात्रा को भी ध्यान में रखना चाहिए।

यह मानना बिल्कुल गलत होगा कि आने वाले समय में मध्य वर्ग का व्यवहार खर्च और बचत (इससे आगे उसकी तार्किकता की बात करें तो, राष्ट्र, राजनीति एवं सामाजिक कर्तव्यों पर वैश्विक दृष्टिकोण) के मामले में मौजूदा मध्य वर्ग जैसा ही होगा। समकालीन मध्य वर्ग सार्वजनिक क्षेत्र के रोजगार से बना था। सरकारी नौकरियों ने उस वक्त उच्च और निम्न दोनों स्तरों पर स्थायी रोजगार पैदा किया था। इसमें स्वास्थ्य सेवा और पेंशन, कम ब्याज वाले ऋण (इसमें नियमित वेतन वृद्धि भी जोड़ी जा सकती है) आदि कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जो सुरक्षा एवं भविष्य में आय के प्रति निश्चिंतता का आभास देती थीं। इन्हीं चीजों ने मध्य वर्ग के व्यवहार और दृष्टिकोण को आकार दिया था। फिर, 1990 के दशक से यह स्थायी सरकारी रोजगार के स्रोत कम होते गए। औपचारिक निजी क्षेत्र भी पर्याप्त रोजगार नहीं दे पा रहा है। गोकर्ण ने महसूस किया कि इस बदलते परिदृश्य में सबसे अधिक प्रभावित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में निचले स्तर के कर्मचारी हैं।

उन्होंने यह भी माना कि भविष्य का मध्य वर्ग पहले की तरह एक समान नहीं होगा, क्योंकि अब इसके लिए रोजगार का कोई एकल स्रोत, कोई एक मजबूत पोषक या निर्माता नहीं है। आज इस वर्ग का दायरा फैल रहा है, लेकिन अधिकांश के पास पहले जैसी आय की स्थिरता और निश्चिंतता, नौकरी की सुरक्षा या जीवन के बुनियादी स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं का ध्यान रखने जैसी ऐतिहासिक विशेषताएं नहीं हैं। आय के आधार पर आकार लेने वाला मध्यम वर्ग स्वतः निरंतर आर्थिक प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने वाले कारक अलग-अलग हैं।

रमा बीजापुरकर

जैसा कि इस कॉलम में अक्सर बताया गया है, हमें सिर्फ आय पर आधारित मध्य वर्ग की गणना की वास्तविकता की जांच करनी होगी। इसमें आय की स्थिरता और पूर्वानुमान के उन आयामों को शामिल करना होगा जो कौशल, कार्य-पद्धति और ऐसे व्यवसाय से आते हैं जो अस्थिर समय में लचीलापन प्रदान करते हैं। इसके अलावा, यह भी देखना होगा कि मौजूदा समय में देखभाल और भविष्य की सुरक्षा एवं अगली पीढ़ी की सामाजिक गतिशीलता बनाए रखने के उद्देश्य से तमाम खर्चों के बाद भी उसके पास निवेश करने के लिए कम से कम 30 फीसदी बचत हो। यदि फिलहाल हम इस संख्या को बनाए रखना चाहते हैं और मौजूदा क्रय शक्ति के आइने से मध्यम वर्ग की परिभाषा देखते हैं तो हमें उन क्षेत्रों के बारे में सोचना होगा जिनसे ये अलग-अलग तरह के आय स्रोत बने हैं, ताकि यह समझा जा सके कि उपभोक्ता, मतदाता, करदाता या नागरिक के रूप में यह मध्य वर्ग कैसे व्यवहार करेगा।

सरकारी कर्मचारियों और बड़ी निजी कंपनियों में औपचारिक नौकरी करने वाले लोगों का एक सेगमेंट ऐसा है जिसमें अभी भी पहले वाले मध्य वर्ग की निशानियां बाकी हैं। लेकिन व्यवसाय के आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि पहले से ही छोटे इस वर्ग की भविष्य के बढ़ते मध्य वर्ग में हिस्सेदारी घटती जा रही है। इस मध्य वर्ग का अधिकांश हिस्सा अर्ध-औपचारिक या अर्ध-अनौपचारिक छोटी निजी कंपनियों में रोजगार, सीमित व्यावसायिक क्षमता और पर्यावरणीय चक्रों का सामना करने की क्षमता वाले छोटे उद्यमी, और अलग-अलग कौशल स्तर और कम स्थिरता वाले स्व-नियोजित गिग कर्मचारी के रूप में होगा।

निम्न मध्य आय वर्ग जिसमें बहुत से कॉलेज जाने वाले वाले पहली पीढ़ी के युवा हैं, पर किया गया हमारा अध्ययन संकेत देता है कि भविष्य का मध्य वर्ग कैसा होगा (मेरे पिछले स्तंभों में इस अध्ययन का विस्तार से उल्लेख किया गया था)।

वे सार्थक काम खोजने और सामाजिक-आर्थिक सीढ़ी पर आगे बढ़ने के लिए जरूरी ऊर्जा जुटाने में थक चुके हैं, क्योंकि उनके पास कोई सुविधाजनक ढांचा नहीं है। वे दफ्तर वाली नौकरियों जैसा सम्मान, स्थिरता, सुरक्षा, पूर्वानुमान, सामाजिक गतिशीलता, मान्यता (जो पुराने मध्य वर्ग के पास थी) की तलाश में हैं। विडंबना यह है कि उनकी चाहत सरकारी नौकरी ही है। उनकी तीव्र इच्छा यही है कि वे ऐसा जीवन जिएं (कम आकांक्षा स्तर, छोटे सपने), जिसमें संघर्ष और अनिश्चितता कम से कम हो। क्या भारत का प्रसिद्ध आकांक्षी मध्य वर्ग भविष्य में एक थके हुए मध्य वर्ग के लिए रास्ता तैयार कर रहा है?

मध्य वर्ग में हम जिस स्थिरता और समरूपता की कल्पना करते हैं, वह वास्तव में विविधता का एक समूह है और इसमें अंतर्निहित आय और व्यवसाय की परिवर्तनशीलता जैसे गुण हैं। साहित्य में कहा जाता है कि कम सामाजिक विविधता (अधिक समरूपता) मध्य वर्ग की सक्रियता को दर्शाती है, क्योंकि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करने के लिए एक समूह के रूप में कार्य करते हैं। भविष्य का मध्य वर्ग न केवल कम समरूप होगा बल्कि अधिक संकीर्ण भी होगा, जो अपने पूर्ववर्ती को उपलब्ध सार्वजनिक क्षेत्र स्थानांतरणीय नौकरियों के अखिल भारतीय जीवन के अनुभवों से वंचित होगा।

हमें शायद एकल मध्य वर्ग की अपनी वैचारिक संरचना को दो-स्तरीय संरचना में बदलना होगा- एक आर्थिक विकास-संचालित वास्तविक मध्य वर्ग, जिसमें पूर्व में बताई गईं कई विशेषताएं हों; और दूसरा वर्तमान में क्रय शक्ति रखने वाला खपत करने में सक्षम वर्ग। मध्य वर्ग के विकास और आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देने में उसके योगदान के बीच का संबंध अलग-अलग समूहों के लिए अलग-अलग होगा, जैसे कि उनके खर्च और बचत के विकल्प, नीतिगत आधार और चुनावी मूल्य प्रस्ताव भी अलग-अलग होंगे। शायद गोकर्ण का यही मतलब रहा हो जब उन्होंने कहा था कि एक उपयोगी चक्र सुनिश्चित करने के लिए हमें इस वर्ग की बदलती प्रकृति को पहचानने और उसी हिसाब से काम करने की जरूरत है।

*(लेखिका ग्राहक-आधारित कारोबारी रणनीति क्षेत्र में व्यवसाय सलाहकार हैं।)*

## आपका पक्ष

### अमेरिकी व्यापार घाटे की सच्चाई

संपादकीय 'जारी रहे बातचीत' और लेख 'राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति से बचने में आड़े आते विरोधाभास' (4 अगस्त) के संदर्भ में भारत-अमेरिकी व्यापार को आंकड़ों से इतर समझने की आवश्यकता है और अमेरिका को भी समझाने की आवश्यकता है कि भारत के साथ व्यापार और व्यापार घाटे को लेकर उसकी सूचनाएं भ्रामक हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका के लिए वैश्विक व्यापार से घाटा या सरप्लस बहुत महत्त्व नहीं रखता। अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति विशुद्ध रूप से राजनीतिक स्वरूप की है जहां वह संपूर्ण विश्व को अमेरिका फर्स्ट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने समक्ष झुकाना चाहते हैं। अमेरिका की अर्थव्यवस्था में उसकी पेटेंट, बौद्धिक संपदा और लाइसेंसिंग से आय 7.8 लाख करोड़ डॉलर है, जो अभी हमारे अर्थशास्त्री और नीति निर्माता नहीं ध्यान दे रहे।

**भारत का अमेरिका के साथ व्यापार केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं है, बल्कि यह शिक्षा, तकनीक, ई-कॉमर्स तक फैला है**

केवल सीमा पार क्रॉस बार्डर बौद्धिक संपदा से ही अमेरिका की आय 128 अरब डॉलर है। अभी यह भी संज्ञान में लेने की आवश्यकता है कि भारत का अमेरिका के साथ व्यापार केवल आयात और निर्यात तक सीमित नहीं है। हमारे विद्यार्थी, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंसल्टिंग, डिफेंस, एमेजॉन जैसी विशालकाय ई-कॉमर्स कंपनियां, फिनटेक, वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनियां डेलॉयट, मैकेंजी, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स भारत से कुल 100 करोड़ डॉलर से अधिक की आय अमेरिका के लिए कर रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति दुनिया भर को भ्रमित कर रहे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत कहकर उन्होंने देश का घोर अपमान किया है और यह भारत के आत्म सम्मान को गहरी चोट पहुंचाता है। हम अमेरिका के लिए अपने सबसे विश्वसनीय मित्र रूस को नहीं छोड़ सकते।

*विनोद जौहरी, दिल्ली*

### बाल तस्करी : विचलित करने वाली वास्तविकता

देश में बद से बदतर होती जा रही अंतरराज्यीय बाल तस्करी की समस्या के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रविधानों के अनुसार, तस्करी के शिकार मुक्त कराए गए बच्चों को विद्यालयों में दाखिला दिलाया जाए। इसके पूर्व भी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने बाल तस्करी और बच्चा चोरी में शामिल गिरोहों के खिलाफ स्वतः संज्ञान लेकर,गंभीर चेतावनी देते हुए कहा था कि देश भर के माता-पिता को अपने बच्चों के प्रति बेहद सतर्क और सावधान रहना चाहिए। अगर किसी भी अस्पताल से किसी नवजात शिशु की तस्करी की जाती है, तो अस्पताल के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करते हुए अस्पताल का लाइसेंस निलंबित किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर, बाल तस्करी के खतरे का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए इस क्षेत्र में कार्य करने वाली कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठनों की क्षमता का विस्तार करना काफी जरूरी हो गया है।

*सुधीर कुमार सोमानी, देवास*

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

## देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

**सामान्य केंद्रीय सचिवालय (सीसीएस) के पहले भवन 'कर्तव्य भवन' का बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि कर्तव्य भवन-03 सेंट्रल विस्टा परियोजना का हिस्सा है और सीसीएस के तहत सभी 10 इमारतों का निर्माण अगले 22 महीनों में किया जाएगा।**

# प्यार, परिवार और संपत्ति का बखेड़ा

भारत में लिव-इन रिलेशनशिप एक जटिल सामाजिक वास्तविकता बन गई है। लेकिन इसके कानूनी दायरे, खासकर संपत्ति के अधिकारों को लेकर, अक्सर भ्रम की स्थिति है। पारंपरिक विवाह के इतर इस रिश्ते में रहने वाले भागीदारों के लिए संपत्ति का अधिकार अक्सर एक अंधकारमय गलियारे जैसा होता है, जहां न्याय की राह आसान नहीं, क्योंकि सामाजिक मानदंडों में बदलाव और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बढ़ते जोर के साथ, यह व्यवस्था अब महानगरों तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों में भी इसका प्रचलन बढ़ रहा है। हालांकि, इस बढ़ती प्रवृत्ति के साथ कई कानूनी और सामाजिक चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के संपत्ति के अधिकार का मुद्दा, जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां स्पष्ट कानूनी ढांचे की कमी के कारण अक्सर जटिल समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लिव-इन रिलेशनशिप में रिश्तों के टूटने पर संपत्ति के बंटवारे से जुड़ी कई चुनौतियां सामने आती हैं, जैसे कि संयुक्त संपत्ति का अभाव और वित्तीय योगदान साबित करने में मुश्किल। अक्सर पार्टनर संपत्ति अलग-अलग खरीदते हैं या एक कमाता है और दूसरा घर चलाता है, जिससे यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सी संपत्ति किसकी है। भावनात्मक और सामाजिक दबाव भी महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए लड़ने से रोकता है। उत्तराधिकार का मुद्दा भी एक बड़ी समस्या है, क्योंकि वसीयत न होने पर लिव-इन पार्टनर का संपत्ति में अधिकार जताना असंभव हो जाता है। हमारे देश में लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर कोई स्पष्ट और व्यापक कानून मौजूद नहीं है, जिसके कारण ऐसे रिश्तों में संपत्ति के अधिकारों पर अक्सर अस्पष्टता बनी रहती है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न फैसलों में इसे ह्वविवाह जैसी प्रकृति का रिश्ताह्व माना है, खासकर घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के तहत गुजारा भत्ता के मामलों में। फिर भी संपत्ति के बंटवारे या विरासत को लेकर कोई ठोस कानूनी दिशानिर्देश स्थापित नहीं किए गए हैं। यदि एक लिव-इन पार्टनर की मृत्यु हो जाती है, या रिश्ता टूट जाता है, तो संयुक्त रूप से अर्जित संपत्ति के बंटवारे या विरासत को लेकर विवाद उठना तय है। इसका दुष्परिणाम अक्सर महिला साथी को भुगतना पड़ता है। वे अपनी कमाई या रिश्ते में किए गए योगदान का कानूनी प्रमाण पेश करने में कमजोर होती हैं। यह कानूनी लड़ाई लंबी और महंगी साबित होती है, जिसमें न्याय मिलना मुश्किल हो जाता है। हालांकि न्यायपालिका ने विभिन्न फैसलों के माध्यम से लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर के अधिकारों, खासकर संपत्ति के संदर्भ में, को परिभाषित किया है लेकिन वे पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए यह जरूरी है कि जब लिव इन रिलेशन को मान्यता दी जा चुकी है तो उसके कानून भी बनायें जाएं ताकि रिश्तों में स्पष्टता हो।

# पश्चिम के आगे झुकने का युग समाप्त

नीरज कुमार दुबे
(वरिष्ठ स्तंभकार)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक जटिल कूटनीतिक और राजनीतिक परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। एक ओर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए शुल्क बढ़ाने और दंडात्मक कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भारत-रूस ऊर्जा साझेदारी को मजबूती से बनाए रखना चाहते हैं। इसके पीछे सिर्फ आर्थिक कारण नहीं, बल्कि एक व्यापक भू-राजनीतिक संदेश भी है कि पश्चिम के सामने झुकने का युग अब समाप्त हो चुका है।

देखा जाये तो मोदी सरकार वैश्विक मंचों पर ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं की प्रतिनिधि बनकर उभरी है। यूक्रेन युद्ध के बाद पश्चिमी प्रतिबंधों और नैतिक उपदेशों के बावजूद भारत ने रूस के साथ अपने हितों को स्वतंत्र रूप से साधने की नीति अपनाई। यह वही 'रणनीतिक स्वायत्तता' है, जिसकी बात भारत दशकों से करता आया है, पर जिसे आज व्यवहार में लाने का साहस शायद पहली बार किसी सरकार ने इस हद तक दिखाया है।

प्रधानमंत्री मोदी के लिए यह चुनौती केवल बाहरी नहीं है। देश के भीतर कांग्रेस जैसे विपक्षी दल उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से निकटता पर तंज कस रहे हैं। 'माई फ्रेंड डोनाल्ड' जैसे वाक्य अब राजनीतिक व्यंग्य बन चुके हैं। कांग्रेस यह सवाल उठा रही है कि अगर अमेरिका से घनिष्ठता इतनी ही प्रभावशाली थी, तो भारत को टैरिफ धमकी क्यों झेलनी पड़ रही है? देखा जाये तो यह आलोचना राजनीतिक रूप से स्वाभाविक है, पर इसमें कूटनीतिक यथार्थ की गहराई को नजरअंदाज किया जा रहा है। भारत आज आर्थिक, सामरिक और राजनीतिक दृष्टि से एक उभरती शक्ति है और ऐसे में विश्व के साथ उसकी मोल-भाव करने की शैली भी बदली है। मोदी जिस भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वह न केवल अपने हितों की रक्षा करना जानता है, बल्कि विकल्पों का निर्माण भी कर रहा है– जैसे ब्रिक्स + का मंच, ऊर्जा विविधता की दिशा में कदम और नए व्यापारिक सहयोग।

इसके अलावा, 'मोदी है तो मुमकिन है' सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि इस समय एक परीक्षण की कसौटी बन चुका है। प्रधानमंत्री को अब यह साबित करना है कि वह पश्चिम के दबाव को संतुलित करते हुए, रूस से रिश्ते बनाए रखते हुए और विपक्ष की आलोचनाओं को दरकिनार करते हुए भारत को एक स्वाभिमानी, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेता के रूप में उभार सकते हैं। देखा जाये तो इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मोदी को तीन स्तरों पर निर्णायक पहल करनी होगी- 1. अमेरिका के साथ संवाद बनाए रखते हुए, ट्रेड वार को टालना होगा और भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की स्पष्ट पैरवी करनी होगी। 2. घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना होगा ताकि आयात और शुल्क जैसे हथियारों का असर सीमित हो और ऊर्जा आपूर्ति में विविधता भी लानी होगी। 3. आंतरिक एकता और विपक्ष के प्रहारों का उत्तर तथ्यों और नीतिगत पारदर्शिता से देना होगा, ताकि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि दिखाई दे।

देखा जाये तो यह वह घड़ी है जब प्रधानमंत्री मोदी को नेतृत्व के अपने सबसे कठिन अध्याय में प्रवेश करना पड़ा है। लेकिन यदि वे इस दौर को सफलता से पार कर जाते हैं, तो यह केवल उनकी नहीं, बल्कि एक नए भारत की विजय होग२शी– जो दबाव में नहीं झुकता, हितों की रक्षा करता है और दुनिया को सम्मान के साथ संवाद करना सिखाता है। और तब शायद 'मोदी है तो मुमकिन है' सिर्फ चुनावी नारा नहीं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति का यथार्थ भी बन जाएगा।

जहां तक ताजा घटनाक्रमों की बात है तो आपको बता दें कि भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद पर अमेरिका और यूरोपीय संघ की आलोचना को सख्ती से खारिज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किये गए वक्तव्य में साफ तौर पर कहा गया है कि रूस से आयात ऊर्जा की कीमतों में स्थिरता को बनाये रखने के लिए उठाया गया कदम है। विदेश मंत्रालय ने यह भी उजागर किया है कि अमेरिका और यूरोप स्वयं अभी भी रूस से उर्वरक, खनिज, रसायन, यूरेनियम और एलएनजी जैसी सामग्रियों का भारी व्यापार कर रहे हैं। भारत का यह तर्क एकदम सही है कि जब तक अमेरिका और यूरोपीय संघ स्वयं रूस के साथ व्यापार संबंध समाप्त नहीं करते, तब तक भारत को नैतिकता के कटघरे में खड़ा करना न केवल दोहरा मापदंड है, बल्कि 'अनुचित और अविवेकपूर्ण' भी।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

दूसरी ओर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर शुल्क बढ़ाने और रूसी तेल की खरीद पर दंडात्मक कार्रवाई की धमकी को विशेषज्ञ अमेरिका की घरेलू राजनीति और आगामी चुनावों से जोड़कर देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ट्रंप ने भारत पर आरोप लगाया है कि वह रूस से सस्ता तेल खरीदकर उसे ऊँचे दामों में बेचकर लाभ कमा रहा है, साथ ही यूक्रेन युद्ध में नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपना रहा। किंतु यह आरोप राजनीतिक बयानबाजी अधिक लगता है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में पुनः बिक्री और रिफाइनिंग एक सामान्य प्रक्रिया है, जिसे कई देश अपनाते हैं। देखा जाये तो ट्रंप द्वारा शुल्क बढ़ाने की घोषणा एक तरफ भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता को प्रभावित करने का प्रयास है, तो दूसरी ओर इसे अमेरिका के कृषि और डेयरी उद्योग के समर्थन में लॉबिंग के रूप में भी देखा जा सकता है।

वहीं, रूस ने इस पूरे घटनाक्रम को अमेरिका की 'नव-उपनिवेशवादी' नीति का उदाहरण बताया है। क्रेमलिन का यह दावा कि अमेरिका अपने प्रभुत्व को बनाए रखने के लिए ग्लोबल साउथ पर आर्थिक दबाव बना रहा है, इस बात की पुष्टि करता है कि रूस अमेरिका की एकध्रुवीय विश्व व्यवस्था को चुनौती देना चाहता है। भारत जिस रणनीतिक स्वायत्तता की बात करता आया है, उसका असली परीक्षण ऐसे ही समय में होता है जब उसे पश्चिमी दबावों, वैश्विक व्यापारिक हितों और घरेलू राजनीतिक आलोचनाओं के बीच संतुलन साधना हो। अमेरिका और यूरोपीय देशों को समझना होगा कि रूस से तेल खरीद केवल व्यापारिक सौदा नहीं, बल्कि भारत की एक आत्मनिर्भर और व्यावहारिक विदेश नीति का प्रतीक भी है।

# मीडिया में यह तीसरा आदमी कौन है

दयानंद पांडेय
(वरिष्ठ पत्रकार)

इंडियन एक्सप्रेस के रामनाथ गोयनका जब प्रभाष जोशी को संपादक बनाने के लिए दिल्ली के गांधी स्मारक निधि में उन से मिलने के लिए अचानक पहुंचे तो प्रभाष जी के पास गोयनका जी को बैठाने के लिए सही सलामत कुर्सी भी नहीं थी। एक ही कुर्सी थी जिस का एक पैर टूटा हुआ था। और उसे किसी तरह ईटा जोड़ कर टिका रखा था। जोशी जी ने सकुचाते हुए गोयनका जी को उसी पर बैठाया था। बाद के दिनों में जब जनसत्ता अपने उरुज पर था तब गोयनका जी जोशी जी का वेतन कुछ ज्यादा ही बढ़ाना चाहते थे लेकिन जोशी जी ने एक शर्त रख दी कि अगर जनसत्ता के सभी सहयोगियों का वेतन बढ़ा दिया जाए उन के साथ तभी उन का वेतन बढ़ाया जाए। गोयनका जी चुप हो गए।

बी जी वर्गीज को जब रामनाथ गोयनका ने इंडियन एक्सप्रेस का चीफ एडीटर बनाने का प्रस्ताव रखा साथ ही तब के समय में बीस हजार रुपए महीने वेतन का प्रस्ताव रखा। वर्गीज साहब ने गोयनका से कहा, यह तो बहुत ज्यादा है। ज्यादा से ज्यादा दस हजार रुपए दे दीजिए। लेकिन गोयनका जी ने कहा कि हमारे यहां संपादकों का वेतन तो बीस हजार रुपए महीना ही है। उस समय तक वर्गीज साहब हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक रह चुके थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सूचना सलाहकार भी रह चुके थे।

थोड़ा और पीछे चलते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय को राजा साहब कालाकांकर ने हिन्दुस्थान का संपादक बनाया। वेतन दिया दो सौ रुपया महीना। जो बहुत नहीं तो आज के दस लाख रुपए के बराबर समझ लीजिए। यह ब्रिटिश पीरियड की बात है। मालवीय जी ने राजा साहब से सिर्फ एक शर्त रखी और कहा कि आप जब कभी शराब पिए हुए हों तो मुझे भूल कर भी अपने पास नहीं बुलाएं, न मुझ से बात करें। जिस दिन आप ने यह शर्त तोड़ी, मैं अखबार छोड़ दूंगा। राजा साहब ने सहर्ष यह शर्त स्वीकार ली। अखबार चल निकला। राजा साहब बहुत समय तक इस शर्त को निभाते रहे। एक रात उन्होंने मालवीय जी को बुलाया। राजा साहब शराब पिए हुए थे। मालवीय जी उलटे पांव लौटे। और इस्तीफा भेज दिया। समय बीतता रहा। बहुत समय बाद एक सार्वजनिक कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई तो मालवीय जी ने राजा साहब से कहा कि मैं ने आप के अखबार से संपादक का दायित्व तो कब का त्याग दिया लेकिन आप मुझे वेतन नियमित क्यों भेजते जा रहे हैं। राजा साहब ने हाथ जोड़ कर मालवीय जी से कहा, मैं तब भी आप को वेतन नहीं भेजता था, न अब भेज रहा हूं। आप को संपादक का दायित्व दिया था, कर्मचारी नहीं बनाया था। बाकी मेरी खुशी है, इसे बने रहने दें। और मालवीय जी को दो सौ रुपए महीना पूर्ववत भेजते रहे।

अरविंद कुमार सरिता, मुक्ता, कैरवां वाले दिल्ली प्रेस में सहायक संपादक थे। सभी पत्रिकाओं के प्रभारी संपादक। दिल्ली प्रेस के स्वामी, प्रकाशक विश्वनाथ जी अरविंद जी के रिश्तेदार भी थे। अरविंद जी विश्वनाथ जी को अपना गुरु भी मानते हैं। इस दिल्ली प्रेस में अरविंद कुमार ने बाल श्रमिक के तौर पर कम्पोजीटर से भी नीचे बतौर डिस्ट्रीब्यूटर काम शुरू किया था। और इस मुकाम तक पहुंचे थे। लेकिन एक बार किसी बात पर विश्वनाथ जी उन से नाराज हो गए। उनके कमरे से कुर्सी निकलवा कर स्टूल रखवा दिया। सहयोगियों को उन से मिलने पर पाबंदी लगा दी। तरह-तरह से उन्हें तंग किया गया। इसी बीच टाइम्स आफ इंडिया ग्रुप की मालकिन रमा जैन ने उन्हें बुलाया और हिंदी फिल्मी पत्रिका माधुरी का संपादक बनने का प्रस्ताव दे दिया। अरविंद कुमार ने ज्वाइन करने के लिए थोड़ा समय मांग लिया। और इस विपरीत हालात में भी दिल्ली प्रेस नियमित जाते रहे। अंततः विश्वनाथ जी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्हों ने अरविंद जी से इस बात को स्वीकार करते हुए उन्हें उन का रुतबा वापस दे दिया। तब जा कर अरविंद जी ने अपना इस्तीफा देते हुए उन से माधुरी जाने के लिए विदा मांगी। विश्वनाथ जी हतप्रभ रह गए यह जान कर कि टाइम्स आफ इंडिया के प्रस्ताव के बावजूद अरविंद जी विपरीत स्थितियों में भी दिल्ली प्रेस में बने रहे। खैर अरविंद जी मुम्बई गए और एक शानदार पत्रिका माधुरी निकाली। चौदह बरस बाद थिसारस पर काम करने के लिए माधुरी छोड़ दिया। पर यह प्रत्यक्ष कारण था। यह बात सब लोग जानते हैं। अरविंद जी खुद भी यही बताते हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि अरविंद कुमार के माधुरी छोड़ने के पीछे एक अप्रत्यक्ष कारण भी था। यह कारण था कि तब के दिनों नवभारत टाइम्स से अक्षय कुमार जैन रिटायर होने वाले थे और प्रबंधन ने अरविंद कुमार को नवभारत टाइम्स का संपादक बनने का प्रस्ताव रखा था जिस पर अरविंद कुमार ने सहमति दे दी थी। लेकिन अक्षय जी रिटायर हुए तो अज्ञेय जी नवभारत टाइम्स के संपादक हो गए। अरविंद जी ने बिना कुछ इधर-उधर कहे-सुने माधुरी से चुपचाप इस्तीफा दे कर थिसारस का काम शुरू कर दिया। यह एक पत्रकार, एक संपादक के स्वाभिमान का प्रश्न था। जिसे अरविंद कुमार ने खामोशी से निभाया।

आप ने देखा ही होगा कि आज लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के नेता खड़गे ने ए बी पी न्यूज चैनल में मालिकाना हक बदलने के चलते चैनल से बाहर हुए दो एंकर सहित तीन लोगों का मामला बड़े जोर-शोर से उठाया। एन डी टी वी समेत तमाम चैनलों से, अखबारों से हजारों लोग इधर निकाले गए हैं। कांग्रेस सहित किसी भी पार्टी ने यह मामला कभी संसद में क्यों नहीं उठाया। लाखो, करोड़ो के पैकेज पर काम कर रहे इन चैनलों के लोगों की आवाज संसद से सोशल मीडिया तक चौतरफा सुनाई दे गई। पर इन्हीं चैनलों और अखबारों में बेचारे अल्प वेतन भोगी पत्रकारों की बात लोकसभा में कभी किसी ने उठाई क्या? इन्हीं मीडिया संस्थानों में दिल्ली, मुम्बई, लखनऊ, पटना, भोपाल, चेन्नई, बेंगलूर आदि जगहों पर दिहाड़ी मजदूरों से भी कम पैसे तीन हजार, पांच हजार, दस हजार रुपए में हजारों लोग काम कर रहे हैं, किसी ने कोई सुधि क्यों नहीं ली।

मजीठिया आयोग की सिफारिशें किसी मीडिया हाऊस ने क्यों नहीं अभी तक लागू किया। सुप्रीम कोर्ट में सैकड़ो लोग इस बाबत लड़ रहे हैं, लेबर कोर्टों में लड़ रहे है। क्या संसद के लोग नहीं जानते। नहीं जानते कि मीडिया हाऊसों ने सारे लेबर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक खरीद लिए हैं। लेकिन इस गूंगी, बहरी संसद को तब पता जरूर चलता है जब करोड़ो रुपए के पैकेज पर उन की कुत्तागिरी करने वालों के हितों को चोट पहुंचती है। धूमिल ने ठीक ही लिखा है :

एक आदमी
रोटी बेलता है
एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है
जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है
वह सिर्फ.रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूँ--
'यह तीसरा आदमी कौन है?'
मेरे देश की संसद मौन है।

# संपादकीय

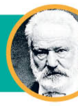

"अच्छा बनना आसान है, लेकिन न्यायपूर्ण होना बेहद कठिन। -विक्टर ह्यूगो

**उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से हुई तबाही ने एक बार फिर इस राज्य में प्राकृतिक दुर्योग से अचानक आने वाली आपदा की ओर ध्यान खींचा है। राहत व बचाव कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं नीति नियंताओं के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए।**

## फिर तबाही

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में बादल फटने के कारण खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आने से हुई तबाही भीषण तो है ही, इस त्रासदी ने एक बार फिर इस राज्य में प्राकृतिक दुर्योग से अचानक आने वाली आपदा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। दरअसल, राज्य का भूगोल चरम मौसमी घटनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, जो इसे ऐसी आपदाओं का केंद्र बनाता है। धराली में आई बाढ़ के जो दृश्य दिख रहे हैं, वे वाकई भयावह हैं। यह अपने साथ कितने घर, दुकानें और होटल बहा ले गई, उसका आकलन होना बाकी है, लेकिन पीछे छूटे डर व अनिश्चितता के चिह्नों को साफ देखा जा सकता है। उत्तरकाशी के लोग ऐसी विपत्तियों से अपरिचित नहीं हैं, फिर भी इस त्रासदी की गंभीरता आत्ममंथन की मांग तो करती ही है, कि प्रतिक्रिया के बजाय पूर्व तैयारी की जरूरत को समझने से पहले हमें और कितनी जानें गंवानी पड़ेंगी। लगातार बारिश और बाढ़ के साथ काफी मलबा आने से बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच धराली के पास सुखी टॉप में भी बादल फटने की खबरें मिली हैं। दरअसल, पूरा हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रहा है, जहां अनियमित मौसमी पैटर्न, ग्लेशियरों का टूटना और बादल फटने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। अनियोजित शहरीकरण और वनों की कटाई ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है, जिससे ढलान अस्थिर और बाढ़ की विनाशकारी शक्ति और बढ़ गई है। फिलहाल, पूरा ध्यान त्वरित बचाव और राहत कार्यों पर होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता तो तुरंत मिले ही, बचे हुए लोगों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक राहत के उपाय भी होने चाहिए। दरअसल, भविष्य को देखते हुए, उत्तराखंड को अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप एक व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीति की जरूरत है। अन्य आपदा-प्रवण क्षेत्रों में

प्रभावी साबित हुई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को अपनाने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आपदा तैयारियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी उन्हें ज्यादा जागरूक बनाएगी। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण व भूमि उपयोग के कुछ सख्त नियम बनाने भी जरूरी हैं। धराली में जो नुकसान हुआ, वह फिर यह स्मरण कराता है कि प्रकृति भेदभाव नहीं करती, पर हमारी तैयारियां फर्क ला सकती हैं। बेशक सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ आदि की तत्काल सक्रियता से नुकसान को यथासंभव कम किया जा सका है, इसके बावजूद उत्तराखंड में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं नीति नियंताओं के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए।

## आखिर कमी कहां रह जाती है

**मुंबई की लोकल ट्रेनों व मालेगांव बम धमाकों में अभियोजन पक्ष अंततः अभियुक्तों के अपराध को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में विफल रहा। कहा जा सकता है कि न्यायपालिका उच्च कानूनी मानकों को बनाए रखना चाहती थी। उसने संदेह या त्रुटिपूर्ण जांच के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराने से इन्कार कर दिया।**

हाल ही में दो हाई-प्रोफाइल आतंकी हमलों के मामलों में आए फैसलों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच, साक्ष्य संकलन और कानूनी ढांचे से जुड़ी गंभीर खामियों को उजागर किया है। दोनों ही फैसलों में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और उसके निहितार्थों की गहन जांच की मांग उठी है।

वर्ष 2006 में मुंबई में पश्चिमी लाइन पर लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार सात बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोग मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए थे। बीती 22 जुलाई को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इसने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें पहले दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई जांच की भी कड़ी आलोचना की तथा गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं और विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव की ओर इशारा किया। अदालत ने टिप्पणी की कि एटीएस ने 'मामले को सुलझाने का झूठा दिखावा' किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाई-प्रोफाइल आतंकी मामलों में जांच-प्रक्रिया की निष्पक्षता और पुलिस की जवाबदेही के प्रति चिंता जताई। अदालत की टिप्पणियों ने उचित प्रक्रिया को बनाए रखने और निष्पक्ष सुनवाई के मानकों को सुनिश्चित करने में व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा किया।

शेखर अय्यर
*वरिष्ठ पत्रकार*

बम बनाने में प्रयुक्त सामग्री, जिहादी साहित्य आदि सहित साक्ष्यों की मौजूदगी के बावजूद, जांच एजेंसी ने मकोका के तहत दर्ज इकबालिया बयानों पर ही काफी हद तक भरोसा किया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त पाया, क्योंकि उनके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अलावा, प्रक्रियागत त्रुटि का हवाला देते हुए जांच एजेंसी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर दिए।

देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मिसाल के तौर पर हाईकोर्ट के फैसले के

अमल पर रोक लगा दी। हालांकि, उसने कहा कि रिहा किए गए दोषियों को आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है।

महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर, 2008 को विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 31 जुलाई को मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने घटना के लगभग 17 साल बाद, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष 'विश्वसनीय और ठोस' सुबूत पेश करने में विफल रहा।

रमजान के आखिरी दिन और नवरात्र शुरू होने से पहले हुए हमले के इरादे पर अदालत ने साफ कहा कि 'यह स्पष्ट था कि षड्यंत्रकारियों ने लोगों को आतंकित करने, जान-माल की हानि पहुंचाने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने, सांप्रदायिक दरार पैदा करने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से बम विस्फोट किया।' हालांकि, विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अध्यक्षता वाली एनआईए अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई गंभीर कमियों को उजागर किया। अदालत ने जोर देकर कहा कि 'मात्र संदेह वास्तविक सुबूत की जगह नहीं ले सकता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अदालत केवल धारणा के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती।' अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि के लिए काल्पनिक आरोपों के बजाय ठोस सुबूतों की आवश्यकता होती है।

मालेगांव मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा शुरू की गई थी। उस समय एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, जो जांच का नेतृत्व कर रहे थे, इस मामले में पहली गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद 26 नवंबर, 2008 को मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 'हिंदू आतंकवाद' का ढिंढोरा पीटा था। साध्वी प्रज्ञा ने अदालत में शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व अन्य का नाम लेने के लिए उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। इसी प्रकार, सैन्य खुफिया विभाग में कार्यरत कर्नल पुरोहित को भी अपराध स्वीकार करने के लिए मानसिक यातना दी गई। वर्ष 2011 में, एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और एटीएस की जांच की आलोचना की, जबकि वह उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हालात बदलने लगे। वर्ष 2016 में, उसने यह तर्क देते हुए कि एटीएस ने कड़े आतंकवाद-रोधी कानून को लागू करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, मकोका के आरोप हटा दिए।

इसके अलावा भी कई खामियां और चूकें थीं, जैसे अदालती रिकॉर्ड से 13 गवाहों के बयान गायब हो गए। तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक, रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि एनआईए ने उन्हें आरोपियों के प्रति 'नरम रुख अपनाने' के लिए कहा था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगभग दो दशकों की कानूनी लड़ाई नाकाम हो गई है। पीड़ितों के परिवार अब भी न्याय की तलाश में हैं। दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष अंततः अभियुक्तों के अपराध को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में विफल रहा। फैसलों ने जांच प्रक्रियाओं में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। इसके अलावा, दोनों ही मामलों में अभियुक्तों को बरी होने से पहले वर्षों जेल में बिताने पड़े।

कहा जा सकता है कि न्यायपालिका उच्च कानूनी मानकों को बनाए रखना चाहती थी। उसने संदेह या त्रुटिपूर्ण जांच के आधार पर दोषी ठहराने से इन्कार कर दिया। इन मामलों ने दिखाया कि न्याय के लिए मजबूत जांच पद्धतियों और उच्च-गुणवत्ता वाले साक्ष्यों की जरूरत क्यों है।

चूंकि, एनआईए ने यह नहीं कहा है कि वह बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील करेगी, इसलिए 2006 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित मामलों का अभी तक कोई समापन नहीं हुआ है। इसी प्रकार, 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों, जिनमें 68 लोग मारे गए थे, 2007 के हैदराबाद मक्का मस्जिद विस्फोटों, जिनमें नौ लोग मारे गए थे, तथा 2007 के अजमेर दरगाह शरीफ विस्फोटों, जिनमें तीन लोगों की जान गई थी, के बारे में भी कोई अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है।

लोग अपने छतों को बिजलीघरों में तब्दील कर सकते हैं, वह भी कम से कम लागत पर। साथ में उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान भी मिलेगा।

## हाफ बिजली से मुफ्त बिजली की ओर अग्रसर छत्तीसगढ़

### उपभोक्ताओं को बिजली निर्माता बनाने की पहल

विष्णुदेव साय सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की बिजली बिल हाफ योजना के मुकाबले मुफ्त बिजली की अवधारणा लांच की है। राज्य सरकार सस्ती की जगह मुफ्त बिजली की राह पर चलकर अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को बिजली निर्माता बनाना चाहती है। लोग अपने छतों को बिजलीघरों में तब्दील कर सकते हैं, वह भी कम से कम लागत पर। साथ में उन्हें केंद्र और राज्य सरकार से अनुदान भी मिलेगा। सरकार के इस कदम से राज्य में बिजली की उपलब्धता बढ़ने के साथ उपभोक्ताओं को आमदनी भी होगी। वे सरप्लस बिजली बेच भी सकते हैं। पर्यावरण भी ठीक रहेगा। घरों की छत पर बिजली पैदा करने से न धुआं उठेगा, न ही आसमान काला होगा।

400 यूनिट मासिक बिजली खपत पर छूट में बदलाव को लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम भी माना जा रहा है। अब लोग प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना से अपने को जोड़ेंगे तो उन्हें भी फायदा मिलेगा और राज्य को भी। प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना में उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित करने पर केंद्र और राज्य सरकारों से अधिकतम 1.08 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है। इस योजना के तहत एक किलोवॉट क्षमता के सोलर प्लांट से प्रतिमाह औसतन 120 यूनिट बिजली का उत्पादन होता है, जिस पर 30,000 रूपए केंद्र से और 15,000 रुपए राज्य से यानी कुल 45,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाती है। इसमें उपभोक्ता को लगभग 15,000 रुपए स्वयं वहन करने होते हैं। 2 किलोवॉट और 3 किलोवॉट प्लांट से औसतन बिजली उत्पादन, सब्सिडी और उपभोक्ता का खर्च इसी अनुपात में है। पीएम सूर्यघर योजना के तहत सोलर प्लांट लगाने के लिए उपभोक्ताओं को 6 फीसदी की दर से 10 साल के लिए लोन भी दिया जा रहा है।

हाफ बिजली बिल योजना में बदलाव को भले ही कुछ राजनीतिक दल मुद्दा बनाने की कोशिश में लगे हों, पर बदलाव उजले पक्ष को भी देखा जाना चाहिए। प्रदेश सरकार ने एक ओर बिजली उपभोक्ताओं के सुनहरे अवसर का द्वार खोला है, तो गरीबों और कम बिजली खर्च करने वालों का हक बरकरार रखा है। बीपीएल परिवारों को 30 यूनिट बिजली फ्री में मिलती रहेगी। सौ यूनिट बिजली जलाने वाले 'हाफ योजना' के दायरे में बने रहेंगे। वर्तमान में राज्य में 45 लाख घरेलू उपभोक्ता हैं, जिनमें से 31 लाख की मासिक खपत 100 यूनिट से कम है। यानी वे योजना के दायरे में ही रहेंगे। माना जा रहा है कि शेष 14 लाख उपभोक्ता बिजली उत्पादन के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे, तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ बिजली का बड़ा सप्लायर राज्य बन जाएगा।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

### 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही

अभी राज्य के सरकारी बिजली संयंत्रों से करीब 3000 मेगावाट बिजली पैदा हो रही है। एनटीपीसी और निजी उत्पादकों की हिस्सेदारी मिलाकर छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली स्टेट है और लोगों को बिजली कटौती से रूबरू नहीं होना पड़ता। पर आंधी -तूफान या अन्य कारणों से लोग बिजली कटौती से परेशान हो जाते हैं। जब अपने घर पर ही बिजली पैदा होगी तो लोगों को आंधी-तूफान से बिजली गुल की चिंता नहीं रहेगी। उम्मीद है कि प्रदेशवासी इस बदलाव को स्वीकार करेंगे और मुफ्त बिजली की तरफ कदम बढ़ाएंगे।

- रवि भोई

**दूसरा पहलू**

एक चिड़ियाघर ने हिंसक पशुओं के आहार के लिए लोगों से उनके मरणासन्न पालतू जानवरों को दान देने की अपील की है।

## क्यों विवादों में घिरे हैं डेनमार्क के चिड़ियाघर

**डेनमार्क** का एक चिड़ियाघर मरणासन्न पालतू जानवरों-गिनी पिग, खरगोश, मुर्गियों और यहां तक कि छोटे घोड़ों-के मालिकों से अनुरोध कर रहा है कि वे इन्हें शिकारी जानवरों के आहार के लिए दान कर दें। बीते दिनों फेसबुक पर आल्बोर्ग चिड़ियाघर ने ऐसी अपील की। इन जानवरों को प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा 'धीरे-धीरे मार दिया जाएगा' और फिर चिड़ियाघर के शिकारी जानवरों, जैसे यूरोपीय वनबिलाव, शेर व बाघ आदि के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। घोड़ों के लिए शर्त रखी गई है कि उनका हाल में किसी बीमारी के लिए इलाज न हुआ हो। मुर्गियों, खरगोशों और गिनी पिग्स को कार्यदिवसों में सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच स्वीकार किया जाएगा, लेकिन एक बार में चार से ज्यादा जानवर नहीं होने चाहिए।

अलेक्सा रॉबलेस गिल

आलोचक इसे अस्वीकार्य और गलत चलन बता रहे हैं। हालांकि, ऑलबोर्ग चिड़ियाघर प्रबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आलोचक इसे अस्वीकार्य व गलत चलन बता रहे हैं। आल्बोर्ग चिड़ियाघर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक प्रवक्ता ने *पॉपुलर साइंस* को बताया कि 'कई वर्षों से' कर्मचारी 'मांसाहारी जानवरों को छोटे जानवर खिलाते आ रहे हैं।' हालांकि, कुछ लोग इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। एक यूजर ने टिप्पणी की कि उसका खरगोश को दान करने का अनुभव शानदार रहा। बीते चालीस वर्षों से आल्बोर्ग चिड़ियाघर में नियमित आने वाली सिग्ने फ्लाइवहोम ने कहा कि वह अपने प्रिय घोड़े को दान करना चाहती हैं, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया है। यह पहली बार नहीं है कि डेनमार्क के चिड़ियाघरों को उनके बेपरवाह दृष्टिकोण के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2014 में कोपेनहेगन चिड़ियाघर ने शेर व अन्य हिंसक जानवरों को खिलाने के लिए मारियस नाम के एक स्वस्थ युवा जिराफ को मार दिया था और शव का परीक्षण देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था। कुछ हफ्तों बाद चिड़ियाघर में चार शेरों-दो शावक और उनके माता-पिता को मार डाला। इसके पीछे चिड़ियाघर प्रबंधन ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि नर शेर अपनी बेटियों के साथ प्रजनन न कर सकें और युवा नर शेर शावकों पर हमले न कर सकें। इन मौतों ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ाई, लेकिन चिड़ियाघर प्रबंधन के प्रति एक ट्रांस-अटलांटिक दार्शनिक विभाजन को भी दर्शाया। अमेरिकी चिड़ियाघर अक्सर जानवरों की आबादी में तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए गर्भनिरोधक उपायों पर निर्भर रहते हैं, जबकि यूरोपीय चिड़ियाघर जानवरों को प्रजनन करने की अनुमति देते हैं, और बाद में 'अतिरिक्त' जानवरों को मार देते हैं।

2014 में कोपेनहेगन चिड़ियाघर ने हिंसक जानवरों को खिलाने के लिए मारियस नाम के एक स्वस्थ युवा जिराफ को मार दिया था और शव का परीक्षण देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था।

**आंकड़े**

### जीएसटी की चोरी

बीते पांच वित्त वर्षों में देश में सात लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। यह एजेंसियों की सक्रियता की वजह से संभव हुआ है।

| | |
|---|---|
| 2021 | 49,384 |
| 2022 | 73,238 |
| 2023 | 1,31,613 |
| 2024 | 2,30,332 |
| 2025 | 2,23,375 |

आंकड़े संबंधित वित्त वर्षों में पकड़ी गई जीएसटी चोरी के, करोड़ रुपये में | स्रोत : FoM

एक धनवान ने महाराज गोसाईं जी से कहा कि वह उनकी कुटिया को मजबूत और टिकाऊ बनवा देगा। उन्होंने कहा, अपने मन की कुटिया को मजबूत करो।

## ईंटों की कोठी कितने दिन टिकेगी

**बाबा** चैनराम जी के शिष्य महाराज गोसाईं पूर्वी बलिया के मिल्की गांव के निवासी थे। वह गृहस्थ जीवनयापन करते थे। किसी से अधिक मतलब नहीं रखते थे और कहीं किसी के यहां शीघ्र नहीं जाते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। फिर भी महाराज गोसाईं जी अपने गांव के बाहर पेड़ों के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान के भजन में लीन रहते थे। वह पूर्णतः विरक्त जीवन जीते थे।

उनके शिष्यों ने भगवान का नाम जपते हुए अपने हाथों से मिट्टी खोदकर सुंदर और विशाल कुटिया तैयार की थी। एक धनवान व्यक्ति ने महाराज गोसाईं जी से कहा कि वह कुटिया को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसे पक्की करने की आज्ञा दे दें। गोसाईं जी ने कहा, 'बेटा! तुम्हारी ईंटों की कोठी कितने दिन टकेगी? हमारी मिट्टी की कुटिया ही अच्छी है।' उन्होंने कहा, 'करना ही है, तो अपने मन की कोठी को मजबूत करो।' यह बात सुनते हुए धनवान को समझ आ गया कि असली संपत्ति तो राम नाम की कमाई है। कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, तो गोसाईं जी महाराज कहते, 'मन लगाकर इस कुटिया को साफ कर दो।' ईश्वर कृपा से उसकी समस्या ठीक हो जाती। बताते हैं कि गोसाईं जी कुटिया की सफाई के लिए इसलिए कहते थे कि ताकि व्यक्ति को अपने अंदर की सफाई की प्रेरणा भी मिले।

**अंतर्यात्रा**
संकलित

**आज का इतिहास**

### भारत में जन्मा पहला टेस्ट ट्यूब शिशु

**सृष्टि का सृजन अपने आप में एक अजूबा है और बच्चे के जन्म लेने की प्रक्रिया कुदरत के किसी करिश्मे से कम नहीं, लेकिन इंसान ने टेस्ट ट्यूब के जरिए बच्चे के जन्म की प्रणाली का विकास कर इस करिश्मे में एक और कड़ी जोड़ दी। भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बच्चे का जन्म 1986 में छह अगस्त के दिन ही हुआ था। 1825 : बोलीविया ने पेरू से स्वतंत्रता हासिल की। 1862 : मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना। 1906 : प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी चितरंजन दास और अन्य कांग्रेस नेताओं ने मिलकर वंदेमातरम समाचार पत्र का प्रकाशन शुरु किया। 1914 : ऑ(ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1960 : क्यूबा ने देश की तमाम संपत्ति का राष्ट्रीयकरण किया। 1962 : जमैका को स्वतंत्रता मिली। 1996 : नासा ने मंगल पर जीवन होने की संभावना जताई। 2007 : मध्य त्रिनिदाद में एक पुराने हिन्दू मंदिर को क्षतिग्रस्त किया गया। 2007 : हंगरी के वैज्ञानिकों ने लगभग 80 लाख साल पुराने देवदार के वृक्ष का जीवाश्म प्राप्त करने का दावा किया। 2010 : जम्मू कश्मीर में अचानक आई बाढ़ से कम से कम 255 लोग मारे गए।**

## पुलिस भी तो स्मार्ट बने

**साइबर धोखाधड़ी और हाईटेक अपराधों के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं, पुलिस व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित होने की जरूरत है।**

सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व आईपीएस, विधिक एवं प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ | **तकनीक**

साइबर धोखाधड़ी, तस्करी, शहरी अपराध और सीमा पार आतंक जैसी जटिल समस्याएं बढ़ रही हैं, पुलिस व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित होने की जरूरत है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनिवार्य तत्व बन गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए एआई को सक्रिय रूप से अपना रही हैं।

हवाई अड्डों पर 'डिजीयात्रा' परियोजना के तहत चेहरा पहचानने के सिस्टम से न सिर्फ बोर्डिंग की प्रक्रिया तीव्र हो रही है, बल्कि वांछित व्यक्ति भी पहचाने जा रहे हैं। हाईवे पर एआई आधारित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली का पायलट परीक्षण हो रहा है, ताकि संदिग्ध या चोरी हुए वाहनों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोका जा सके। ये प्रणाली केंद्रीय अपराध डाटाबेस से जुड़ी होती हैं और

निकटतम गश्ती दल को त्वरित सूचना भेजती हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से अंतरराज्यीय तस्करी, अपहरण या वाहन चोरी जैसे मामलों में प्रभावी सिद्ध हो रही है। टोल प्लाजा, सीसीटीवी नेटवर्क और सीमा चौकियां अब एक जुड़े हुए निगरानी तंत्र का हिस्सा बनती जा रही हैं।

पारंपरिक तरीकों की सीमाएं हैं-जैसे धुंधले सीसीटीवी फुटेज या अधूरी गवाही-एआई आधारित समाधान सहायक सिद्ध हो रहे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एआई-सक्षम स्केचिंग सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया गया है, जो गवाहों द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर डीप लर्निंग तकनीक से चेहरे की डिजिटल छवियां तैयार करता है। तैयार की गई छवियों की तुलना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा बनाए गए चेहरे पहचान डाटाबेस से की जाती है। यह प्रणाली विशेष रूप से गुमशुदा व्यक्तियों, झपटमारी और नए अपराधियों की पहचान में प्रभावी रही है। एनसीआरबी के अनुसार, भारत में साइबर अपराधों में 20 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तेलंगाना व कर्नाटक जैसे राज्यों में एआई-सक्षम साइबर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

एनसीआरबी द्वारा विकसित 'ई-साक्ष्य' एप पुलिस अधिकारियों को वीडियो या ऑडियो जैसे डिजिटल साक्ष्यों को मेटाडाटा और एन्क्रिप्शन सहित प्रस्तुत करने की सुविधा देता है, जिससे वे अदालत में स्वीकार्य और छेड़छाड़ से मुक्त रहते हैं। इसी तरह, 'ई-प्रोसीक्यूशन' पोर्टल जो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जुड़ा हुआ है, पुलिस थानों से अभियोजन कार्यालयों तक प्रकरण विवरण को स्वचालित रूप से भेजता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने इस प्लेटफॉर्म का सबसे प्रभावी उपयोग किया है और मामलों का त्वरित निपटारा किया है।

एआई आधारित पुलिसिंग केवल दिल्ली, मुंबई या बंगलूरू जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों में भी इसे 'डिजिटल इंडिया' के तहत परीक्षण के लिए अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक रीयल-टाइम एआई डैशबोर्ड लागू किया गया है, जो एफआईआर की प्रगति पर नजर रखता है, समय पर चार्जशीट दाखिल करने को सुनिश्चित करता है और प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पहचान करता है। आगरा और भोपाल जैसे जिलों में पुलिस अधिकारियों को एआई आधारित चैट असिस्टेंट के माध्यम से एफआईआर का मसौदा तैयार करने, केस लॉ का सारांश बनाने और शिकायतों का भाषाई अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। 2024 में प्रकाशित एक अध्ययन ने एआई को लेकर प्रमुख चिंता उजागर की है-'ब्लैक बॉक्स समस्या', यानी पारदर्शिता की कमी। उदाहरण के लिए, चेहरे की पहचान प्रणालियों में विश्व स्तर पर महिलाओं, वृद्धों और गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्तियों में त्रुटि दर अधिक पाई गई है। भारत में जिम्मेदार और प्रभावी एआई पुलिसिंग को साकार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं। पहले, राज्यों को एक समान राष्ट्रीय ढांचा अपनाना चाहिए, जो एआई उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण, जवाबदेही और सार्वजनिक शिकायत निवारण की प्रक्रियाओं को निर्धारित करे।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 73 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। -वाल्तेयर

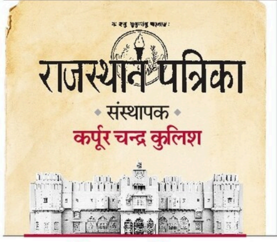


# एआइ इस्तेमाल को लेकर कानून बनाने का वक्त

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआइ) के अगुवा माने जाने वाले जैफ्री हिंटन की चेतावनी सचमुच गौर करने योग्य है, जिसमें उन्होंने कहा है कि यदि एआइ ने खुद के लिए कोई नई भाषा का निर्माण कर लिया तो ये इंसानों की पकड़ से बाहर होगा। इतना ही नहीं, हम यह भी पता नहीं कर पाएंगे कि वह क्या सोच रहा है। अभी एआइ अंग्रेजी में सोचता है। हिंटन एक ऐसे वैज्ञानिक हैं, जो लगातार दुनियाभर की सरकारों से एआइ पर सख्त नियमन की मांग कर रहे हैं। हिंटन के इस बयान से पहले चैटजीपीटी निर्माता ओपनएआइ की एक रिपोर्ट भी लोगों को चौंका चुकी है, जिसमें कहा गया था कि एआइ मॉडल बार बार अपनी मर्जी से तथ्य गढ़ रहे हैं। खास बात यह है कि दोनों तथ्य आम लोगों की ओर से नहीं, बल्कि एआइ की गहरी समझ रखने वालों की ओर से सामने आए हैं।

भारत जैसे देश में इस मुद्दे पर बहस का यह सही वक्त है। विशाल आबादी वाले इस देश में तकनीक इस्तेमाल की छूट के खतरे कम नहीं है। जिस तरह के खतरे सामने आने की बात कही जा रही है, उसे देखते हुए जल्द से जल्द एआइ के इस्तेमाल को लेकर भी अब कानून बनाने की जरूरत वक्त का तकाजा है। यह इसलिए भी क्योंकि, बेरोजगारी, डिजिटल असमानता जैसे सामाजिक संकट पहले से ही यहां चुनौती बनकर खड़े हैं। ऐसे समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अनियंत्रित और बिना नीति के होता रहा तो समाज के लिए एक गंभीर संकट भी बन सकता है। एआइ यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता अब केवल रोबोट या विज्ञान का विषय नहीं रहा। यह तकनीक अब हमारे रोजमर्रा के जीवन में प्रवेश कर चुकी है। इसलिए यह कहा जा रहा है कि भारत में बेरोजगारी की स्थिति को देखते हुए एआइ आधारित ऑटोमेशन को बगैर योजना के अपनाया गया तो लाखों नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। वैसे भी इसकी उपयोगिता उन्हीं क्षेत्रों में संभव है, जहां इंटरनेट, तकनीकी शिक्षा और संसाधन उपलब्ध हैं। भारत के ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में यह सुविधा नहीं होने पर समाज दो वर्गों में बंट जाएगा- एक जो तकनीक का उपयोग कर आगे बढ़ेगा और दूसरा, जो बहुत पीछे छूट जाएगा। देश में डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर संकट की भी आशंका रहेगी। डेटा प्राइवेसी के मामले में हम वैसे ही काफी पीछे हैं। आम नागरिक की निजता के खतरे के साथ-साथ डीपफेक वीडियो और भ्रामक खबरों के दुष्परिणाम हम पहले ही देख चुके हैं।

समय आ गया है कि भारत को भी एआइ पर स्पष्ट नीति और कानूनी ढांचा तैयार करना चाहिए। वहीं डेटा प्रोटेक्शन कानून को सख्ती से लागू करना चाहिए। एआइ शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण में शामिल करने के साथ-साथ एआइ के अनियंत्रित प्रयोग से होने वाली समस्याओं पर खुले मंच पर चर्चा जरूरी है। एआइ जैसी तकनीक के लिए नियमन और विवेकपूर्ण उपयोग अनिवार्य है।

**तेल का खेल:** भारत को आंतरिक सुधार, विविध साझेदारी और परिपक्व कूटनीति का रास्ता अपनाना होगा

# ट्रंप की बौखलाहट बनाम भारत की रणनीतिक दृढ़ता

विनय कौड़ा
अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार
@patrika.com


आने वाले वर्षों में भारत को एक धैर्यवान, संतुलित और अपेक्षाकृत 'गैर-प्रतिबद्ध विदेश नीति' की आवश्यकता होगी। उसे स्पष्ट करना होगा कि वह वैश्विक राजनीति के किसी एक ध्रुव का मोहताज नहीं, बल्कि सार्थक सहयोग का पक्षधर है।

डॉनल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमरीका की पाकिस्तान नीति में आया ताजा बदलाव एक भूचाल से कम नहीं है। भले ही भारत-अमरीका संबंधों की दशकों पुरानी साझेदारी रही हो, लेकिन तेजी से बदलते हालात में वाशिंगटन द्वारा पाकिस्तान के ऊर्जा क्षेत्र में निवेश और वहां के विशाल तेल भंडार के विकास संबंधी दावे ने न केवल नई भू-राजनीतिक आशंकाएं पैदा की हैं, बल्कि भारतीय हितों के समक्ष तगड़ी चुनौतियां भी खड़ी कर दी हैं। यह घटनाक्रम स्पष्ट रूप से एक व्यापक शक्ति-खेल का हिस्सा है, जहां अमरीका का पाकिस्तान के प्रति झुकाव और भारत के खिलाफ दबाव का माहौल दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों के लिए चुनौती पेश कर रहा है। ट्रंप ने जब सोशल मीडिया पर पाकिस्तान और अमरीका के बीच ऊर्जा सहयोग के सपनों को उजागर किया तो पूरी दुनिया के सामने इसे बड़े ही आकर्षक व्यापारिक अवसर के रूप में प्रस्तुत किया गया। दावा यह है कि अमरीकी कंपनियां पाकिस्तान के कथित विशाल तेल भंडार में निवेश करेंगी और शायद भविष्य में भारत भी पाकिस्तान से कच्चा तेल खरीद पाएगा। लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है।

पाकिस्तान के पास सिद्ध कच्चे तेल का स्टॉक केवल 353 मिलियन बैरल है, जो वैश्विक भंडार का नाममात्र अंश है। वह आज भी अपनी 85 प्रतिशत से अधिक तेल जरूरतें मध्य-पूर्व पर ही निर्भर होकर पूरी करता है और उसकी आंतरिक तेल उत्पादन क्षमता उसकी रोजमर्रा की आवश्यकता का सिर्फ 15 प्रतिशत ही पूरी करती है। हाल के वर्षों में कराची और बलूचिस्तान तटवर्ती क्षेत्रों में कुछ संभावित हाइड्रोकार्बन संरचनाओं के चिह्न जरूर मिले हैं पर सच तो यही है कि यहां का भंडारण एवं उसका व्यावसायिक शोधन और उत्पादन अभी एक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं। जाहिर है कि अमरीकी निवेश दरअसल पाकिस्तान को तात्कालिक आर्थिक राहत देने के लिए नहीं, बल्कि भारत और चीन दोनों को संतुलित करने तथा दबाव में लेने के लिए किया जा रहा है।

इस नीति का सीधा असर भारत के लिए कई स्तरों पर परेशानियां लेकर आया है। सबसे पहले देखें तो ऊर्जा के क्षेत्र में भारत, निरंतर विविध स्रोतों पर निर्भरता कायम करने का प्रयास करता रहा है और हालिया वर्षों में उसने रूस से भी सस्ते कच्चे तेल की आपूर्ति को प्रोत्साहित किया है। यही नहीं, इस साल के आरंभ से तो भारत ने अमरीका से भी अपने तेल आयात में इजाफा किया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन का पाकिस्तान को संभावित ऊर्जा केंद्र के रूप में बढ़ावा देना भारत पर अप्रत्यक्ष दबाव बनाने जैसा है, जिससे भारत को भविष्य में अपनी ऊर्जा नीति में बदलाव का दबाव महसूस हो। इसके अलावा पाकिस्तान की तरफ अमरीका का झुकाव और साथ ही भारत के निर्यात पर 25 प्रतिशत टैरिफ की घोषणा, भारतीय उद्योग और व्यापार पर सीधा प्रहार है। इस कदम ने दोनों देशों की व्यापार वार्ता को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। कृषि, फार्मा, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स सभी क्षेत्रों में भारत को नुकसान की आशंका बनी हुई है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्त्वपूर्ण संदेश कूटनीतिक स्तर पर निहित है। पाकिस्तान से ऊर्जा संबंधी गठजोड़ की घोषणा और भारत पर आर्थिक दबाव का एक साथ आना यह स्पष्ट करता है कि अमरीका अब भारत को प्राथमिक मित्र की बजाय नियंत्रित करने योग्य भागीदार के रूप में देख रहा है- विशेषकर तब, जब अमरीकी दबाव के बावजूद भारत एक स्वतंत्र कूटनीतिक रुख पर अडिग है। पाकिस्तान के लिए एक नई भूमिका गढ़ी जा रही है, जहां अमरीका निवेश की आड़ में उसकी राजनीतिक-सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने, अफगानिस्तान के पेचीदा समाधान में उसे फिर से सहभागी बनाने और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को संतुलित करने की दिशा में सक्रिय हो गया है। हालांकि, पाकिस्तान की वर्तमान आर्थिक बदहाली, विदेशी कर्ज का भार, ऊर्जा संकट और बलूचिस्तान में गहराती अशांति यह दर्शाती है कि यह निवेश जनहित से अधिक भू-राजनीतिक सौदेबाजी और क्षेत्रीय नियंत्रण की रणनीति का हिस्सा है। इसी रणनीतिक पृष्ठभूमि में पाकिस्तान भी अमरीका को यह भरोसा दिलाने में जुटा है कि वह क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक भू-रणनीतिक संतुलन में एक अपरिहार्य एजेंट है।

वैसे भारत ने ट्रंप की अनर्गल बयानबाजी पर कड़ा रुख अख्तियार करते हुए उनकी बेतुकी नीतियों के खिलाफ जवाबी कदम की तैयारी आरंभ कर दी है। अमरीकी कंपनियों पर डिजिटल टैक्स लगाने और डेयरी-खेती क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती पर विचार मंथन हो चुका है।

वाणिज्य मंत्री सार्वजनिक तौर पर यह कह चुके हैं कि भारत अपने औद्योगिक, कारोबारी और रणनीतिक हितों की रक्षा करने के लिए सक्रिय रहेगा। इन सबके बीच भारत की दीर्घकालिक विदेश नीति की परीक्षा भी हो रही है। ऊर्जा संवाद में रूस, ईरान, वियतनाम जैसे देशों के साथ साझेदारी गहराने और बहुध्रुवीय स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की उसकी प्रतिबद्धता एक बार फिर प्रासंगिक हो उठी है। आने वाले वर्षों में भारत को एक धैर्यवान, संतुलित और अपेक्षाकृत 'गैर-प्रतिबद्ध विदेश नीति' की आवश्यकता होगी। उसे स्पष्ट करना होगा कि वह वैश्विक राजनीति के किसी एक ध्रुव का मोहताज नहीं, बल्कि सार्थक सहयोग का पक्षधर है। भारत को अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता, ऊर्जा सुरक्षा और अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए आंतरिक सुधार, विविध साझेदारी और परिपक्व कूटनीति का रास्ता अख्तियार करना ही होगा। केवल तभी वह अमरीका-पाकिस्तान के हालिया समीकरण से उत्पन्न चुनौतियों का सामना कर सकेगा और अपने दीर्घकालिक वैश्विक हितों की रक्षा कर सकेगा।

**प्रसंगवश**

## रोजगार की संभावनाओं पर पानी फेरने वाली बन रही खनन कार्य में देरी

### सरकारी खजाने में 5 लाख करोड़ रुपए तक के राजस्व की उम्मीद हो सकती है

राजस्थान के भूगर्भ में अकूत खजाना दबा है। सोना, पोटाश, बेस मेटल, मैगनीज व अन्य कई बहुमूल्य खनिजों से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सकती है। सरकार पिछले दस वर्षों में 103 मेजर मिनरल खानों की नीलामी कर चुकी है। इसके बावजूद तस्वीर बेहद निराशाजनक है। आज भी खनन केवल 5 लाइम स्टोन खदानों में शुरू हो पाया है। बाकी खदानें कागजों और फाइलों में धूल फांक रही हैं। यह सुस्ती न सिर्फ प्रदेश के विकास के रास्ते में बाधा है, बल्कि लाखों युवाओं की रोजगार संभावनाओं पर भी कुंडली मारकर बैठी है। माना जा रहा है कि अगर सभी खदानें चालू हो जाएं तो दो से ढाई लाख लोगों को प्रत्यक्ष और 6 से 7 लाख युवाओं को अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। इतना ही नहीं, आने वाले वर्षों में प्रदेश के खजाने में पांच लाख करोड़ रुपए तक का राजस्व आ सकता है। इस विलंब का एक बड़ा कारण उन कंपनियों का रवैया है, जिन्होंने नीलामी में ये खदानें हासिल की।

इस बीच, चरागाह भूमि से जुड़े विवाद और पर्यावरण स्वीकृतियों के मुद्दे भी अटके पड़े हैं। कंपनियों की ओर से राजस्व विभाग या कलक्टर स्तर पर आवेदन ही नहीं किए गए। क्या इतनी बड़ी संभावनाओं को सुस्त रवैये और कागजी कार्रवाई की धीमी रफ्तार पर छोड़ा जा सकता है? नीलामी की प्रक्रिया भी सवाल खड़े करती है। वर्ष 2016 से शुरू हुई यह प्रक्रिया पहले सात साल में मात्र 23 खदानों तक सीमित रही। पिछले तीन साल में 80 खदानों की नीलामी हुई, पर नतीजा वही, खनन शुरू न होना। क्या नीलामी सिर्फ आंकड़े बढ़ाने के लिए की जा रही है या सचमुच प्रदेश की खनिज संपदा का दोहन विकास के लिए होगा? जरूरत इस बात की है कि राज्य सरकार इस सुस्ती पर कठोर रुख अपनाए। खदानें लेने वाली कंपनियों को समयबद्ध लक्ष्य दिए जाएं और अनुपालन नहीं करने पर दंडात्मक कार्रवाई हो। चरागाह और पर्यावरण मामलों में विभागीय समन्वय बढ़ाया जाए और लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निपटाया जाए। खान विभाग को केवल नीलामी कराने से आगे बढ़कर खनन शुरू कराने की जवाबदेही लेनी होगी।


- आशीष जोशी
ashish.joshi@epatrika.com


https://t.me/AllNewsPapersPaid1

**बुक इनसाइट**

## मेलमैन: डाक वितरण का रोमांच

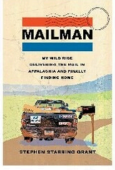


स्टीफन स्टारिंग ग्रांट की किताब 'मेलमैन' एक आत्मकथा है, जो पोस्टमैन के जीवन और अप्पलाचिया क्षेत्र की खूबसूरती को बयान करती है। यह किताब न केवल डाक वितरण के रोमांच को दर्शाती है बल्कि एक व्यक्ति के घर की तलाश और आत्म-खोज की कहानी भी है। कवर पर एक डाक वाहन और मेलबॉक्स की तस्वीर ग्रामीण जीवन और मेहनत का प्रतीक है, जो पाठक का ध्यान आकर्षित करती है। कहानी की शुरुआत लेखक के डाकिया के रूप में अपने सफर से होती है जहां वह अप्पलाचिया के पहाड़ी इलाकों में मेल डिलीवर करता है। यह सफर आसान नहीं है, क्योंकि वह मुश्किल रास्तों, बदलते मौसम और अकेलेपन से जूझता है। लेकिन इन चुनौतियों के बीच स्थानीय लोगों से जुड़ता है और उनके जीवन को समझता है। ग्रांट ने अपनी लेखनी से इन अनुभवों को इतने जीवंत ढंग से पेश किया है कि पाठक खुद को उस गाड़ी में बैठा महसूस करता है। किताब में हास्य और भावनात्मक गहराई का मिश्रण है। ग्रांट ने बताया है कि कैसे डाक वितरण ने उन्हें एक नई जिंदगी और आत्मविश्वास दिया।

**फैक्ट फ्रंट**

## योडा बैट : एक अनोखा चमगादड़

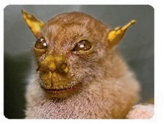

योडा बैट जिसे हैमामास ट्यूब-नोज्ड फ्रूट बैट भी कहा जाता है। पापुआ न्यू गिनी के घने वर्षावनों में पाया जाने वाला एक अनूठा फ्रूट बैट है। इसका नाम 'योडा' प्रसिद्ध फिल्म 'स्टार वॉर्स' के पात्र योडा से मिलता-जुलता होने के कारण पड़ा, लेकिन स्थानीय भाषा में इसे 'हैमामास' कहा जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम संरक्षणवादी डॉ. डेब राइट के सम्मान में रखा गया, जिन्होंने पापुआ न्यू गिनी में 20 वर्षों तक संरक्षण कार्य किया। यह चमगादड़ नाइक्टिमीन जीनस का हिस्सा है, जिसमें 18 प्रजातियां शामिल हैं जो उत्तरी ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, सोलोमन द्वीप समूह और पूर्वी इंडोनेशिया में पाई जाती हैं। योडा चमगादड़ की खासियत इसकी ट्यूब जैसी नाक, चमकीले रंग, पीठ पर मोटी धारी और पंखों पर धब्बे हैं। इसका जबड़ा अन्य प्रजातियों से चौड़ा और गोल होता है जिससे यह हमेशा मुस्कुराता प्रतीत होता है। इसके बड़े कान और छोटा चेहरा इसे और भी आकर्षक बनाते हैं। यह चमगादड़ वर्षावनों के संरक्षण की आवश्यकता को दर्शाता है।

**दृष्टिकोण** नई नौकरियों का सृजन भी होगा

## एआइ से डरने की नहीं, स्किल्स अपडेट करने की है जरूरत

डॉ. प्रभात दीक्षित
मीडिया शिक्षिका एवं युवा मामलों की जानकार
@patrika.com


एआइ के बढ़ते प्रभाव ने जहां एक ओर दुनियाभर में कामकाज के तरीके को बदला है, वहीं दूसरी ओर नौकरी खोने का डर भी गहराया है। भारत में भी यह आशंका जताई जा रही है। लेकिन विशेषज्ञों और ताजा सर्वे बताते हैं कि इसका असली कारण एआइ नहीं, बल्कि स्किल गैप यानी कौशल की कमी है। मैकेंजी ग्लोबल इंस्टीट्यट की रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक भारत में 6 करोड़ से अधिक नौकरियों में एआइ और ऑटोमेशन का प्रभाव दिखेगा। लेकिन यह प्रभाव पूरी तरह नकारात्मक नहीं होगा। वहीं रिपोर्ट यह भी बताती है कि नई तकनीकों के चलते नौ करोड़ नई नौकरियों का सृजन भी होगा। प्रश्न यह है कि यदि नई नौकरियां भी बन रही हैं, तो फिर डर क्यों है? इसका उत्तर है स्किल गैप।

नास्कॉम की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में वर्तमान में 40% से अधिक कामगारों को आवश्यक डिजिटल या तकनीकी कौशल प्राप्त नहीं हैं जो आने वाली नौकरियों के लिए जरूरी होंगे। यही वजह है कि तकनीक अवसर तो पैदा कर रही है, लेकिन लोग उन अवसरों के लिए तैयार नहीं हो पा रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम की 2023 की 'फ्यूचर ऑफ जॉब्स' रिपोर्ट बताती है कि 2027 तक दुनिया की लगभग 44% स्किल्स अप्रचलित हो जाएंगी और हर व्यक्ति को अपने कार्यक्षेत्र में बने रहने के लिए औसतन हर 5 साल में नए कौशल सीखने की जरूरत होगी। भारत सरकार ने कई पहल शुरू की हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया मिशन जैसे कार्यक्रमों के तहत लाखों लोगों को एआइ डेटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे विषयों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। लेकिन समस्या की जड़ गहरी है। एनएसडीसी के आंकड़ों के अनुसार, अब भी भारत में 60% युवा रोजगार योग्य कौशल से वंचित हैं। इसका सबसे बड़ा प्रभाव उन सेक्टर्स में दिख रहा है जहां ऑटोमेशन तेजी से हो रहा है जैसे कि ग्राहक सेवा, बीपीओ, बेसिक डेटा एंट्री और रूटीन मैन्युफैक्चरिंग कार्य। पहले ये क्षेत्र बड़ी संख्या में कम-कौशल युवाओं को रोजगार देते थे। लेकिन अब एआइ बॉट्स, चैटबॉट्स और ऑटोमेटेड सिस्टम्स की वजह से इन क्षेत्रों में मानव संसाधन की मांग घट रही है। दूसरी ओर, एआइ मशीन लर्निंग, बिग डेटा, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी और डिजाइन थिंकिंग जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञों की भारी मांग है। लेकिन ये स्किल्स भारत के पारंपरिक शिक्षा ढांचे में अब भी सीमित रूप से पढ़ाई जाती हैं। यह स्किल गैप ही असली खतरा बन चुका है। एआइ को नौकरी का दुश्मन मानने से बेहतर है कि इसे कौशल सुधार व नवाचार का प्रेरक माना जाए।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

**अनूठी जगह:** जहां पैदल चलना भी साहसिक

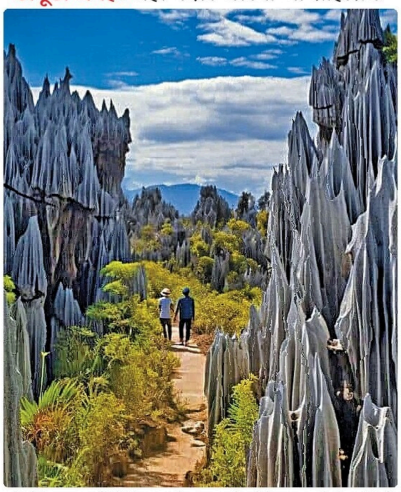

**पश्चिमी** *मेडागास्कर का त्सिंगी डे बेमराहा राष्ट्रीय उद्यान अपनी नुकीली चूना पत्थर की संरचनाओं के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें स्थानीय भाषा में त्सिंगी कहा जाता है, जिसका अर्थ है अंगुलियों के बल चलना। यह नाम इस क्षेत्र की दुर्गमता और रोमांचकारी भू-दृश्य को दर्शाता है, जहां चलना किसी साहसिक अभियान से कम नहीं।*

**जोमो** सच्चे जुड़ाव को महसूस करना सीखें

## कुछ 'छूट जाने का आनंद' भी जीवन में आत्मसंतुष्टि देता है

डॉ. नितिन राजवंशी
डिजिटल अवेयरनेस एक्सपर्ट
@patrika.com


लाइक्स, शेयर्स और लगातार अपडेट्स से भरी दुनिया में, 'छूट जाने का डर' (फोमो) एक आम चिंता बन गया है। लेकिन एक नया उपाय ट्रेंड बनकर उभर रहा है 'छूट जाने का आनंद' यानी जॉय ऑफ मिसिंग आउट (जोमो)। जोमो का मतलब खुद को पूरी तरह से अलग-थलग कर लेना नहीं है, बल्कि सचेत रूप से खुद से अलग होने, खुद की देखभाल को प्राथमिकता देने और वर्तमान क्षण में संतुष्टि पाने का चुनाव करना है।

सोशल मीडिया की हाइलाइट रील्स से प्रेरित फोमो, लगातार कुछ न कुछ करते रहने, हर कार्यक्रम में शामिल होने और एक बेहतरीन ऑनलाइन व्यक्तित्व बनाने का दबाव पैदा करता है। इससे तनाव, चिंता और अपर्याप्तता की भावना पैदा हो सकती है। दूसरी ओर, जोमो सोच में बदलाव को प्रोत्साहित करता है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि कुछ चीजों के लिए 'ना' कहने से आप दूसरों के लिए 'हां' कह सकते हैं। जैसे प्रियजनों के साथ क्वालिटी टाइम बिताना, घर पर सुकून भरी शाम बिताना या काम पर ध्यान केंद्रित करना। जोमो को अपनाने का मतलब एकांतप्रिय बन जाना नहीं है। यह आपके विकल्पों के प्रति सचेत रहने और उन चीजों को प्राथमिकता देने के बारे में है, जो आपके लिए सचमुच मायने रखती हैं। यह समझने के बारे में है कि आप हर जगह मौजूद नहीं रह सकते और सब कुछ नहीं कर सकते और यह बिल्कुल ठीक है। यह एकांत में अपने शौक पूरे करने में और बस अपने जीवन में मौजूद रहने में आनंद खोजने के बारे में है। सूचनाओं और तुलनाओं की लगातार बौछार से खुद को अलग करके व्यक्ति तनाव कम कर सकते हैं, नींद में सुधार कर सकते हैं और अपनी समग्र भलाई की भावना को बढ़ा सकते हैं। जोमो गहरे जुड़ाव की अनुमति देता है, क्योंकि यह सतही जुड़ाव के बजाय वास्तविक बातचीत और उपस्थिति को प्रोत्साहित करता है।

कुछ छूट जाने के आनंद को अपनाकर व्यक्ति आत्म-जागरूकता, भावनात्मक नियंत्रण और संतुष्टि की गहरी भावना विकसित कर सकते हैं। वे साधारण चीजों में आनंद पा सकते हैं और मजबूत, ज्यादा सार्थक रिश्ते बना सकते हैं। जोमो का उदय आधुनिक जीवन के दबावों के विरुद्ध एक स्वस्थ और आवश्यक सोच को प्रस्तुत करता है। यह हमें याद दिलाता है कि खुशी बाहरी मान्यता या अंतहीन गतिविधियों में नहीं, बल्कि उपस्थिति, आत्म-चिंतन और सच्चे जुड़ाव के शांत क्षणों में मिलती है। जैसे-जैसे हम निरंतर उत्तेजना से भरी दुनिया में आगे बढ़ते हैं, जोमो को अपनाना-सीखना आनंदमय और संपूर्ण जीवन जीने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है।

विस्तार से पढ़ने के लिए **क्यूआर कोड स्कैन करें**

**आपकी बात**

### उपयुक्त भूमि चिह्नित हो

**ग्रीन** बैल्ट जिसे हरित पट्टी भी कहते हैं, यह प्रकृति को करीब लाने का एक माध्यम है। इसके लिए उपयुक्त भूमि को चिह्नित किया जाना चाहिए। यहां लगाए जाने वाले पौधों की देखरेख का जिम्मा आमजन, एनजीओ आदि को देना चाहिए। **- निर्मला वशिष्ठ,** अलवर

**patrika.com** पर पढ़ें

### पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

**पत्रिकायन** का सवाल था, 'शहरों में ग्रीन बैल्ट को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें। https://shorturl.at/b69FH

इसे स्कैन करें

**आज का सवाल**

**त्योहारों पर सार्वजनिक परिवहन की परेशानी कैसे दूर की जा सकती है?**

ईमेल करें: edit@epatrika.com

**ग्रामीण विकास** जल की हर बूंद सहेजने का संकल्प लेकर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचाएं

# *मिशन अमृत सरोवर से जल संरक्षण की नई गाथा लिखते गांव*

शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार
@patrika.com


ग्रामीण विकास को मजबूती देने वाली योजनाओं में 'मिशन अमृत सरोवर' एक महत्त्वपूर्ण पहल बन चुका है। यह केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, खेती को संजीवनी देने और जल संरक्षण की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब गांवों में अमृत सरोवर बनते हैं तो वह केवल पानी का केंद्र नहीं रहते। वे खेत-खलिहानों को सींचते हैं, पशु-पक्षियों को जीवन देते हैं और हरियाली को बढ़ावा देते हैं।

मैं जब गांव-गांव जाता हूं तो देखता हूं कि जिन खेतों में पहले पानी की कमी थी और बंजर भूमि नजर आती थी, अब वही खेत अमृत सरोवर के कारण हरे-भरे हो उठे हैं। बरसात का पानी अब व्यर्थ नहीं जाता, बल्कि सरोवरों में संचय होकर पूरे वर्षभर उपयोगी होता है। इस मिशन की सफलता का एक बड़ा कारण है- जनसहभागिता। शुरुआत में जहां प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य रखा गया था, वहीं अक्टूबर 2024 तक पूरे देश में 68 हजार से अधिक सरोवरों का निर्माण हो चुका है।

इस मिशन का परिणाम न केवल लोगों की आंखों में, बल्कि वैज्ञानिक आंकड़ों में भी दिखता है। अमृत सरोवरों के कारण भूजल स्तर में 16.3% तक की बढ़ोतरी हुई है, जो खुद प्रमाण है कि यह योजना कितनी प्रभावी है। ये सरोवर आज खेती को नई शक्ति दे रहे हैं, पशुपालन को स्थायित्व मिल रहा है और मछली पालन के जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ग्रामीण महिलाएं समूह बनाकर मछली पालन, मोती उत्पादन और जल पर्यटन जैसे कार्यों में हाथ बंटा रही हैं और अपने परिवार की आय को बेहतर बना रही हैं। अमृत सरोवर सिर्फ जल संरक्षण तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बाढ़ के समय अतिरिक्त पानी को समेटकर आपदाओं से भी सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। गर्मियों में जब नदी-नाले सूख जाते हैं, तब यही सरोवर जीवनदायिनी बनकर गांवों को राहत देते हैं। इनके चारों ओर उगने वाली वनस्पति और वन्य जीवों को भी आश्रय मिलता है, जिससे पर्यावरण को संतुलन मिलता है। इस अभियान से ग्रामीणों को रोजगार भी मिला है। केवल महात्मा गांधी नरेगा के तहत ही 46 हजार अमृत सरोवरों का निर्माण हुआ हैं, जिससे हजारों ग्रामीणों को काम मिला और उनकी जीवनशैली को मजबूती मिली। इसमें हमारी संवेदनशील संस्कृति और पारंपरिक जल-पूजा की भावना भी जुड़ी हुई है। जैसे गंगा को मां माना जाता है, वैसे ही इन सरोवरों की ओर भी श्रद्धा से देखा जाने लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान ग्रामवासियों को और अधिक प्रकृति से जोड़ने का कार्य कर रहा है।

इन सरोवरों के आसपास पौधरोपण हुआ है, जिससे पशु-पक्षियों को सहज आश्रय मिलता है। साथ ही, वहां खुले जिम, योग स्थल और चौपाल बनाए गए हैं, जो आज सामाजिक एकता और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुके हैं। योग दिवस जैसे कार्यक्रमों ने इन स्थलों को और भी जीवंत बना दिया है। इतना सब कुछ तभी संभव हो पाया है जब परंपरा और तकनीक को एक साथ जोड़ा गया है।

जलवायु परिवर्तन की समस्या को देखते हुए इस मिशन में मोबाइल ऐप, पोर्टल, ड्रोन, जीआइएस मैपिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आधुनिक साधनों का उपयोग किया जा रहा है। इससे काम की निगरानी और पारदर्शिता बनी रहती है और लोगों का भरोसा भी बढ़ता है। इससे यह भी प्रमाणित हुआ है कि जब विज्ञान और जनसंख्या की सहभागिता साथ आती है, तो बदलाव अवश्य आता है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस कार्य को आगे भी निरंतर श्रम से सींचते रहें। आइए, हम सब मिलकर इन सरोवरों की स्वच्छता, रखरखाव, पौधरोपण और जल की हर बूंद को सहेजने का सामूहिक संकल्प लें।

## प्रेरणा

सुनो अधिक से अधिक, लेकिन बोलो कम से कम। और जब भी बोलो, सोचकर बोलो। - **शेक्सपीयर**

## संपादकीय

# क्या स्थानीय निकाय ठीक से काम कर पा रहे हैं?

**जनता** की सरकार शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं। प्रजातंत्र के अस्तित्व का यह ध्येय-वाक्य भी है। इसका एक और स्वरूप है स्थानीय स्व-शासन। संविधान के संशोधन 73 और 74 के जरिये 1992 में ग्रामीण क्षेत्र के लिए त्रि-स्तरीय पंचायत राज सिस्टम बना और शहरों, कस्बों के लिए स्व-शासित निकाय। नीति-निर्देशक तत्व के इस भाव को कानूनी जामा पहनाकर समझा गया कि अब व्यावहारिक प्रजातंत्र अपने अंतिम सोपान तक पहुंच गया। लेकिन समय पर चुनाव होने की व्यवस्था, निकायों और पंचायतों को धन और चुने प्रतिनिधियों को कतिपय अधिकार देकर हम भूल गए कि सामूहिक चेतना का दबाव तब पड़ता है, जब समूह जाति-उपजाति में न बंटा हो और अधिकारों को लेने की समझ व ललक सभी में समान हो। 33 साल से चल रहे इस सिस्टम में जन-चेतना के अभाव या विखंडित चेतना के कलुषित होने से वही विद्रूपता आने लगी, जो देश राष्ट्रीय स्तर पर झेल रहा था। मुखिया, सरपंच या ब्लॉक-प्रमुख द्वारा विकास के पैसों में बंदरबांट की खबरें सामने आने लगीं। महिलाओं को आरक्षण दिया गया ताकि इनमें सशक्तीकरण का भाव आए, लेकिन इसके बजाय 'मुखिया-पति' नामक अनौपचारिक संस्था सिस्टम को भ्रष्ट करने लगी, क्योंकि गांवों में महिलाएं अशिक्षित थीं और दस्तावेजों को पढ़ना-समझना उनके वश से बाहर था। सामाजिक ढांचा भी सपोर्ट नहीं करता था। यानी जनता का शासन फिर विफल रहा। उपाय एक ही है- जनचेतना की गुणवत्ता बढ़ाना और उसे संकीर्ण सोच से ऊपर रखना।

## जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

# दिशा, अवधि और अक्ल को अपनी मेहनत से जोड़ लें

**केवल** परिश्रम से सफलता नहीं मिलती। लेकिन ये भी सच है कि परिश्रम तो करना ही पड़ेगा। तो जब आप परिश्रम कर रहे हों तो दिशा, समय-अवधि और अक्ल को अपनी मेहनत से जोड़ लीजिए। कहते हैं कि परिश्रम करते समय मूर्ख दिखें पर बुद्धिमान होना चाहिए। क्योंकि परिश्रम करते समय इन तीन बातों का तालमेल बहुत जरूरी है। जैसे जिंदगी और संगीत के इन्स्ट्रूमेंट एक जैसे होते हैं। संगीत का जो इन्स्ट्रूमेंट होता है, वह तो एक ही होता है, पर उस पर हर बार राग, बोल, धुन बदल जाते हैं। कलाकार जब उसका इस्तेमाल करता है, वो इन्स्ट्रूमेंट वैसा होने लगता है। वो इन्स्ट्रूमेंट कलाकार से शिकायत तो नहीं करता। बस, जिंदगी ऐसी ही होती है। हम इसमें से जो चाहे वो स्वर, बोल निकाल सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के जीवन में सबकुछ संयुक्त है, अखंड है। तालमेल बैठाना पड़ता है। राग, स्वर, धुन बदलते रहेंगे, इन्स्ट्रूमेंट वही रहेगा। जीवन वही रहेगा, स्थितियां बदलती रहेंगी। इसलिए जब भी परिश्रम का अवसर आए, यह मानकर चलना कि केवल मेहनत से सफलता नहीं मिलेगी। जीवन में बहुत कुछ और भी ऐसा होगा, जो आपने सोचा न होगा।

• Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

## पाठकों के पत्र

### हमेशा याद रहेगी ओवल की जीत

**भारतीय** क्रिकेट टीम ने इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन से दिखा दिया कि यह टीम आगे बहुत कुछ करने वाली है। ओवल की जीत हमेशा याद की जाएगी। सीरीज में हमारे बल्लेबाजों ने 12 शतक जमाए। चाहे दोनों टीमों में से कोई सीरीज नहीं जीत पाया मगर टेस्ट क्रिकेट जरूर जीत गया। सीरीज का हर टेस्ट रोमांचक रहा। क्योंकि ऐसे ही करीबी मैचों से टेस्ट क्रिकेट का मजा बना रहेगा।
**- साजिद अली, इंदौर,** मध्यप्रदेश

### बेटियां चुका रहीं प्रथा की कीमत

**हरियाणा** में घटते लिंगानुपात का गहरा असर दिखने लगा है। लड़कों के लिए दुल्हनें नहीं मिल रहीं। 'अट्टा-सट्टा' प्रथा चल रही है, जिसमें शर्त रखी जाती है कि लड़के की शादी तभी होगी जब दुल्हन के भाई के लिए भी दुल्हन ढूंढ कर लाओगे। इसी वजह से कई बार लड़की के लिए मिला अच्छा रिश्ता भी ठुकराया जा रहा है। यहां भी बेटियों को ही कीमत चुकानी पड़ रही है।
**- बबलू सिंह,** ईमेल पर प्राप्त

### मर्यादा बनाए रखें सांसद

**नेताओं** का आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप होना चाहिए। प्रदर्शन और हंगामे से दूर रहना चाहिए। सदन की कार्यवाही स्थगित करके जनता की करोड़ों रुपए की गाढ़ी कमाई खर्च की जा रही है। देशवासियों की अपेक्षा है कि सांसदगण सदन की मर्यादा बनाए रखकर अपने दायित्वों का निर्वहन करें। विधेयक प्रस्तुत करने से पहले हंगामा लोकतांत्रिक मूल्यों की क्षति है।
**- कांतिलाल मांडोत,** सूरत, गुजरात

### हिरोशिमा से सबक ले दुनिया

**6 अगस्त,** 1945 को ही अमेरिका ने हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराकर हजारों लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। युद्ध के भयंकर परिणामों को देखते हुए अब वैज्ञानिकों को ऐसे हथियारों को बनाने से गुरेज करना चाहिए। विज्ञान को अब जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और अन्य उन सभी बातों को ध्यान में रखकर काम करना होगा, जो प्राणी जाति के लिए हानिकारक नहीं हों।
**- राजेश कुमार चौहान,** जालंधर, पंजाब

आप अपने पत्र editpage@dbcorp.in पर भेज सकते हैं

## क्या आप जानते हैं

# लॉन्गयरब्येन में शवों को दफनाना है गैरकानूनी

**नॉर्वे** के स्वालबार्ड द्वीप समूह के लॉन्गयरब्येन में शवों को दफनाना गैरकानूनी है। बहुत कम तापमान के कारण यहां मिट्टी पर्माफ्रॉस्ट, यानी हमेशा जमी हुई स्थिति में रहती है। ऐसे में दफनाए गए शव लंबे समय तक विघटित नहीं हो पाते और शवों के साथ वायरस भी वर्षों तक मौजूद रहते हैं। एक शोध में शवों में 1918 के एक इंफ्लुएंजा वायरस के नमूने मिले थे। ऐसे में वहां शवों को नहीं दफनाने का नियम बना दिया गया।

**1950 में लॉन्गयरब्येन में शवों के दफनाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इलाके में करीब 2700 लोग रहते हैं।**

---

## बामुलाहिज़ा • सबसे पहले हम अपने सत्तातंत्र के विमर्श में मौजूद विरोधाभासों का विश्लेषण करें...

# अमेरिका के साथ ऐसी नौबत क्यों आई?

## कूटनीति

शेखर गुप्ता
एडिटर-इन-चीफ, 'द प्रिन्ट'
X @ShekharGupta

**इन** दिनों दुनियाभर में ट्रम्प का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया जा रहा है। हम भी इसमें अपनी तरफ से योगदान दे रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया वाली ट्रम्पियन कूटनीति से रक्षा करने के लिए सबसे पहले हमें अपने सत्तातंत्र के अंदर के विमर्श में जो विरोधाभास हैं, उनका विश्लेषण करना होगा। आप 2014 से शुरू कर सकते हैं। यह वो समय था, जब हमारा सत्तातंत्र एक ताकतवर नेता के लिए 30 वर्षों से इंतजार के खत्म होने का जश्न मना रहा था। चेतावनी की पहली घंटी तब बजी जब शी जिनपिंग की फौज दक्षिणी लद्दाख के चुमार इलाके में टहलने के लिए आ पहुंची। यह लगभग उसी समय हुआ जब हम अहमदाबाद में शी की खातिरदारी कर रहे थे।

एक नई दुनिया में भारत ने ऐसी ताकत के रूप में कदम रखा था, जिसकी अनदेखी नहीं की जा सकती और जो बहुध्रुवीकरण और बहु-गुटबंदी का पाठ पढ़ा रहा था। चरम स्थिति 2023 में आई, जिस साल जी-20 का आयोजन हुआ। इस समय तक दुनिया में भारत के ही चर्चे होने लगे थे। जल्द ही वह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा था, 'क्वाड' की धुरी बन गया था, इस सबसे भी उल्लेखनीय बात यह थी कि हम किसी संधि से बंधे नहीं थे। हम उन महज चार देशों में शुमार थे, जो चीन की आंखों में आंखें डालकर देख सकते थे और जिसने अपनी 3,488 किमी लंबी सीमाओं पर एक लाख सैनिकों को तैनात कर रखा था।

भारत अंततः अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा था, जो अपने चरम पर तब दिखा, जब भारत मंडपम में मोदी से हाथ मिलाने और गले लगने के लिए जी-20 देशों के शासनाध्यक्ष कतार में खड़े नजर आए। भारत दुनिया को और खास तौर से पश्चिम को उपदेश पिला रहा था। यह सब मिलकर सत्तातंत्र के विरोधाभास के दो ध्रुवों का पहला ध्रुव बनाता है।

दूसरा ध्रुव तब उभरता है जब जी-20 शिखर सम्मेलन में अमेरिका, कनाडा और दबे रूप से ब्रिटेन के साथ रिश्ते में खटास उभरती है। निज्जर-पन्नू मसले की छाया उभरी, लेकिन ट्रूडो के कनाडा को छोड़ किसी ने कोई हंगामा नहीं खड़ा किया। पहला झटका तब लगा, जब तत्कालीन अमेरिकी राजदूत एरिक गार्सेटी ने घोषणा की कि बाइडन को नई दिल्ली में जनवरी में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है और गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि बनने का भी न्योता दिया गया है। उन्होंने इसे रद्द कर दिया, तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने हमें शर्मिंदगी से बचा लिया।

इस समय तक हमारा विरोधाभास उभर आया था और उसमें वृद्धि हो रही थी। एक दशक तक यही धारणा बनी रही कि पश्चिमी खेमा भारत को एक महत्वपूर्ण रणनीतिक सहयोगी मानता है। चीन के साथ उत्तर-पश्चिमी और पूर्वी सेक्टरों में तनाव के दौरान अमेरिकी मदद की खामोश स्वीकृति भी उभरी। अपनी ताकत को फिर से याद किया जाने लगा। यह कि पश्चिम हमारे प्रति उग्र रवैया रखता है, वह 'आत्मनिर्भर भारत' के उत्कर्ष को मंजूर नहीं कर सकता, आदि-इत्यादि। एक दशक तक तो हम खुद को पश्चिम का अपरिहार्य, अनिवार्य, स्वाभाविक सहयोगी मानकर खुश होते रहे लेकिन अब उसके प्रति इंदिरा युग वाली चिढ़ उभरने लगी थी।

रूस से तेल की खरीद को चुपचाप एक स्वाभाविक प्रक्रिया, प्रतिबंध के तहत निर्धारित कीमत पर व्यावहारिक खरीद मान लेने की जगह इसे अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के प्रमाण के रूप में उछाला गया। पिछले साल लगभग इसी समय पीड़ित होने का भाव इससे पहले के जोश पर हावी होने लगा था। शेख हसीना के पतन के लिए अमेरिका, उदारवादी प्रतिष्ठानों और क्लिंटन-ओबामा के 'डीप स्टेट' (गुप्त मंडली) को जिम्मेदार बताया जाने लगा। लेकिन उन सबने निश्चित ही अपने हिसाब से लोकतांत्रिक शक्तियों की उसी तरह मदद की, जिस तरह 'अरब स्प्रिंग' की की थी।

**क्या हम नई हकीकत का आकलन कर पा रहे हैं?...**

**हमें लगता है हर कोई हमारे खिलाफ है। लेकिन हम कहते हैं कि हम अकेले ही लड़ेंगे। यह हमारे विरोधाभास का दूसरा पहलू है। अफसोस की बात यह है कि हम नई हकीकत का आकलन किए बिना और उसका माकूल जवाब दिए बिना पीछे लौटने को तैयार हैं।**

इसने दो तरह से हमें नुकसान पहुंचाया। एक तो यह कि 1998 के बाद 25 वर्षों में हमने अमेरिका से नए रिश्ते जोड़ने के लिए जो निवेश किए, वे बेकार गए। दूसरे, हम खुद को इतना प्रताड़ित मानने लगे कि यह समझने की भी कोशिश नहीं की कि हमारी कूटनीति इतनी आसानी से कैसे हार गई। भारत ने बांग्लादेश में भारी निवेश किया था और यह केवल व्यापार के क्षेत्र में नहीं था। दोनों देशों ने सीमा समझौता भी खुले दिल से किया था। भारत हर साल 20 लाख से ज्यादा बांग्लादेशियों को वीजा जारी कर रहा था। किसी को भनक नहीं लगी कि हसीना कितनी अलोकप्रिय हो गई थीं।

कड़वी हकीकत यह है कि बांग्लादेश का हसीना विरोधी नेटवर्क और पाकिस्तान- दोनों अमेरिका से बेहतर तरीके से निबटे। यह तब था जब हम अमेरिका में प्रवासी भारतीयों के उत्कर्ष का जश्न मनाते रहे हैं, टॉप सीईओ के पदों पर और अमेरिकी राजनीति के कुछ सितारों में भारतीय मूल के व्यक्तियों की गिनती करते रहते हैं। ये हस्तियां हमारी बड़ी पैरोकार बनें, इसके लिए हमारी कूटनीति को उन्हें जोड़ने की कोशिश करनी पड़ेगी।

हमें लगता है हर कोई हमारे खिलाफ है। लेकिन हम कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम अकेले ही लड़ेंगे। यह हमारे विरोधाभास का दूसरा पहलू है। अफसोस की बात यह है कि हम नई हकीकत का आकलन किए बिना और उसका माकूल जवाब दिए बिना पीछे लौटने को तैयार हैं। संसद में हुई बहस ने साफ कर दिया कि हम अभी भी शीतयुद्ध वाले नारों में उलझे हैं। पाकिस्तान को सद्बुद्धि देने और उसे खुद को विनाश से बचाने की सलाह देने के लिए ट्रम्प को धन्यवाद दिया जाता तो इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ट्रम्प को झूठा बताने के संकेत देने की जगह संसद में यह बयान दिया जा सकता था।

ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि राहुल गांधी ने संघर्ष विराम होने के चंद घंटे के भीतर ही पहला वार कर दिया कि सरकार ने मध्यस्थता स्वीकार की। राहुल सरकार को अपना एजेंडा बदलने के लिए अक्सर उकसाते रहते हैं। यह सब पीड़ित होने के गहरे भाव में और इजाफा ही करता है। **(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

---

## स्पीक-अप • बीसीसीआई निर्णय पर पुनर्विचार करे

# हमें अब पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए

## आस-पड़ोस

मिन्हाज मर्चेंट
लेखक, प्रकाशक और सम्पादक
mmleditorial@gmail.com

**सितंबर** में यूएई में एशिया कप होने जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद बीसीसीआई ने घोषणा की थी कि यह प्रतियोगिता रद्द की जाएगी। कहा गया था कि पाकिस्तान के साथ खेलने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तीन माह में ही रुख बदल गया। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ढाका में हुई एशियाई क्रिकेट परिषद (एसीसी) की वार्षिक आमसभा की बैठक में परिषद के अन्य सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल रूप से शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता एसीसी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) के अध्यक्ष और पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं। नकवी ने कहा कि यूएई में एशिया कप की मेजबानी से एशिया भर के प्रशंसकों को एक ऐसे माहौल में एक साथ आने का मौका मिलेगा, जो हमारे क्षेत्र की विविधता को प्रदर्शित करता है। टूर्नामेंट के मुकाबलों को देखने के लिए जब भीड़ एकत्र होगी, तो यह इस बात की शानदार निशानी होगी कि कैसे क्रिकेट लोगों को आपस में जोड़ने की ताकत रखता है।

टूर्नामेंट में भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा गया है, ताकि दोनों देशों की टीमें फाइनल मुकाबले समेत टूर्नामेंट में तीन बार आमने-सामने हो सकें। इससे दिवालिया होने की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का खजाना भर जाएगा। बीसीसीआई दुनिया का सबसे धनी क्रिकेट बोर्ड है, इसलिए उसे तो पैसों की दरकार नहीं। फिर भी बीसीसीआई ने कहा है कि वह अब टूर्नामेंट या किसी मैच से नहीं हट सकता। एसीसी की बैठक के बाद यह फैसला किया जा चुका है। आधिकारिक स्तर की बातचीत के बाद सबकुछ तय किया गया था। मैच निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होंगे।

बीसीसीआई के बदले रुख ने क्रिकेट प्रशंसकों को हैरानी में डाल दिया है। यहां तक कि राजनेताओं ने भी इस पर टिप्पणी की है। संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हुई बहस में एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 'जब पाकिस्तान के विमान हमारे एयरस्पेस में नहीं आ सकते, उनकी नावें हमारे जल क्षेत्र में नहीं आ सकतीं, आपसी व्यापार बंद हो चुका है, तो आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच कैसे खेलेंगे? जब हम पाकिस्तान का 80 प्रतिशत पानी यह कहते हुए रोक रहे हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा तो क्या ऐसे में भी आप उनसे क्रिकेट खेलेंगे?'

विरोध करने वाले नेताओं में कई अन्य भी शामिल थे। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और अब पश्चिम बंगाल में राज्यमंत्री मनोज तिवारी ने कहा कि 'मैं इसके विरोध में हूं। भारत-पाक मैच नहीं होना चाहिए। खासतौर पर पहलगाम हमले के बाद, जिसमें भारतीय नागरिक मारे गए थे। मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करना चाहिए। ऐसे माहौल में मैच नहीं होना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। ऐसे में हम कैसे पाकिस्तान से मैच खेल सकते हैं?'

बर्मिंघम में खेली गई वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स (डब्ल्यूसीएल) एक लिटमस टेस्ट जैसी थी, जिसमें हरभजन सिंह, युवराज सिंह, शिखर धवन,

**दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरोध में भारत ने 1974 के डेविस कप फाइनल से हटकर एक उदाहरण स्थापित किया था। वही नजीर अब वैश्विक रूप ले चुकी है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर रूस को भी बहिष्कृत किया गया।**

इरफान पठान और यूसुफ पठान के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने ग्रुप स्टेज और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया था। दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरोध में भारत ने 1974 के डेविस कप टेनिस फाइनल से हटकर एक उदाहरण स्थापित किया था। वही नजीर अब वैश्विक रूप ले चुकी है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ने पर रूस को यूरोपियन फुटबॉल कप समेत कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से बाहर किया जा चुका है।

जो कहते हैं कि राजनीति और खेल को मिलाना नहीं चाहिए, वही अब जता रहे हैं कि खून और खेल को मिलाया जा सकता है। बीसीसीआई ने बार-बार खुद को एक धन-लोलुप निकाय की भांति दर्शाया है। लेकिन उसे अब भारतीय टीम को निर्देश देने चाहिए कि वह एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ ना खेले।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

---

## नजरिया • फिल्में सामाजिक रूप से उपयोगी हों

# समाज की स्याह सच्चाइयों को परदे पर लाने वाला सिनेमा

## चित्रपट

कावेरी बामजेई
पत्रकार और लेखिका
kavereeb@gmail.com

**जब** सेंसर बोर्ड ने 'धड़क-2' के निर्माताओं से आग्रह किया कि वे प्रखर राजनीतिक आशयों वाली कविता 'ठाकुर का कुआं' को अपनी फिल्म से निकाल दें, तो वो इससे हताश नहीं हुए। उन्होंने एक और सशक्त कविता खोज निकाली, जिसे शैलेंद्र ने लिखा था और 1959 की फिल्म 'कल हमारा है' में प्रयुक्त किया गया था। कविता के शब्द थे : 'सच है डूबा-सा है दिल जब तक अन्धेरा है \ इस रात के उस पार लेकिन फिर सवेरा है \ हर समन्दर का कहीं पर तो किनारा है \ आज अपना हो न हो पर कल हमारा है!' ये ना केवल सशक्त शब्द थे, बल्कि उस महान गीतकार के प्रति आदरांजलि भी थी, जिन्हें राज कपूर के निकटतम सहयोगी होने के बावजूद अपनी दलित पहचान को छिपाने पर मजबूर होना पड़ा था!

'धड़क-2' ऐसे ही अप्रत्याशित क्षणों से भरी है और स्पष्टता और साहस के साथ समाज में अंदरूनी तौर पर बदलाव लाने की एक बेहतरीन मिसाल है। शाजिया इकबाल द्वारा निर्देशित यह फिल्म दिल से निकली पुकार है, जो आज के भारत में पहचान की राजनीति की कुछ सबसे कठोर सच्चाइयों को दर्शाती है- रोहित वेमुला की आत्महत्या से लेकर युवाओं के आदर्श के रूप में बीआर आम्बेडकर के पुनरुत्थान तक। यह आत्महत्या करार दी जाने वाली ऑनर किलिंग की घटनाओं पर भी रोशनी डालती है।

मुख्यधारा की अधिकतर बॉलीवुड फिल्मों के विपरीत समाज में जाति और जेंडर की कशमकश कोई ऐसी कृत्रिम चीज नहीं है, जिसका इस्तेमाल प्रेम-संबंधों की कहानियों में महज कुछ टकराव पैदा करने के लिए किया जाता हो। बल्कि 2025 में भी समाज में आपकी स्थिति इससे तय होती है कि आपका जन्म किस वर्ग में हुआ है। और जहां शिक्षा सामाजिक गतिशीलता में हमारी मदद जरूर करती है, लेकिन आजादी के 78 साल बाद भी यह पूरी तरह से स्वीकार्य नहीं हुई है। फिल्म में एक ऊंची जाति का व्यक्ति कहता है- 'ये लोग रोटी-बेटी का रिश्ता रखना चाहते हैं।' यहां पर 'ये लोग' कहकर जिन्हें अपने से भिन्न और पृथक बताया जा रहा है, वे निचली जाति के लोग हैं, जिन्हें आज भी समाज में अपनी जगह नहीं पता है। और उनके लिए शादियां किसी युद्ध से कम नहीं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

'ये लोग' अपने गांवों को स्वेच्छा से छोड़कर शरणार्थी बन जाते हैं, क्योंकि उनका कुछ भी अपना नहीं है- न गलियां, न खेत, न पानी। 'आपकी इमारतें ऊंची हैं पर आपकी सोच बहुत छोटी,' नायक उस लड़की के परिवार से कहता है, जिससे वह प्यार करता है। वो सही है। मानसिकताएं भूगोल से बंधी नहीं होतीं। सबसे संकीर्ण मानसिकताएं सबसे अमीर जिप-कोड में पाई जा सकती हैं और सबसे गरीब परिवारों में अक्सर सबसे प्रगतिशील विचार होते हैं- उस युवक के पिता की तरह, जो गांव के मेलों में महिला नर्तकी के रूप में नृत्य करते हैं क्योंकि वे ऐसा करना चाहते हैं, और क्योंकि उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया है।

तमिल फिल्म 'पेरियाराम पेरुमल' पर आधारित

**'धड़क-2' में लैंगिक समानता को महत्व दिया गया है, लेकिन फिल्म के असली नायक बाबासाहेब आम्बेडकर हैं, और उनका 'शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित होओ' का संदेश आज समाज के हर वंचित वर्ग में गूंजता है।**

'धड़क-2' हमारे रिश्तों में प्यार की वापसी, द्वेष के त्याग और सामाजिक रूप से उस उपयोगी सिनेमा के पुनरागमन की अपील है, जो अपने दर्शकों से कुछ कहना चाहता है। वो उन्हें केवल खूबसूरत लोकेशंस ही नहीं परोसना चाहता। यह गुरुदत्त का जन्म-शताब्दी वर्ष है, जो अपनी प्रेम कहानियों में भी देश के हालात पर टिप्पणी किया करते थे। 'मिस्टर एंड मिसेज 55' को ही ले लीजिए, जिसमें गुरुदत्त ने एक कार्टूनिस्ट की भूमिका निभाई थी। अपने समझौतावादी अंत के बावजूद यह फिल्म हिंदू कोड बिल और समाज में महिलाओं की स्थिति पर बात करती थी। 'धड़क-2' में लैंगिक समानता को महत्व दिया गया है, लेकिन फिल्म के असली नायक बाबासाहेब आम्बेडकर हैं, और उनका 'शिक्षित बनो, आंदोलन करो और संगठित होओ' का संदेश आज समाज के हर वंचित वर्ग में गूंजता है।

**(ये लेखिका के अपने विचार हैं)**

---

## डिफ्रेंट एंगल • कम बोलें या फिर उसी विषय के बारे में बोलें, जिसे हम अच्छी तरह से जानते और समझते हैं

# उनका क्या करें जो यह भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते हैं?

## एआई

डॉ. चन्द्रकांत लहारिया
जाने माने चिकित्सक
c.lahariya@gmail.com

**साल** 1995 में अमेरिका के पिट्सबर्ग शहर में बन्दूक की नोक पर दिन-दहाड़े दो बैंक लूटे गए। खास बात यह थी कि दोनों ही घटनाओं में लुटेरों ने अपने चेहरे को ढका नहीं था, बल्कि वे कैमरे में अपना चेहरा दिखाकर मुस्करा रहे थे। बाद में जब दोनों पकड़े गए तो उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने चेहरों पर नींबू के रस का लेप लगा रखा था। दोनों लुटेरों में से एक ने बचपन में नींबू के रस से कागज पर लिखने का खेल- जिसमें लिखे गए शब्द अदृश्य रहते हैं- खेला था। बचपन के उस अनुभव के आधार पर उसे लगा था कि जिस तरह नींबू का रस कागज पर शब्दों को अदृश्य कर देता हैं, उस दिन नींबू के लेप से उनके चेहरे भी सर्विलांस कैमरों में अदृश्य होने चाहिए थे!

दिन-दहाड़े इस तरह की बैंक लूट अमेरिका और कई देशों में एक बड़ी खबर थी। जब मिशिगन विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान विभाग के प्रोफेसर डेविड डनिंग ने यह पूरी घटना सुनी तो इस पर शोध करने का निर्णय लिया और अपने स्नातक छात्र जस्टिन क्रुगर को उस शोध में जोड़ा। 1999 में वे अपने शोधपत्र 'अनस्किल्ड एंड अनअवेयर ऑफ इट' में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब किसी विषय या विशेष क्षेत्र में लोगों का ज्ञान या क्षमता सीमित या कम होती है तो वे अपनी क्षमताओं को अधिक आंकने या उसे अच्छे से समझने की भूल में रहते हैं। यह कॉग्निटिव बायस या एक प्रकार का संज्ञानात्मक पूर्वग्रह है, जिसे अब 'डनिंग-क्रुगर प्रभाव' के नाम से जाना जाता है।

अपने दैनिक जीवन में हम अक्सर ऐसे लोगों से मिलते हैं, जिनके पास कुछ विशेष क्षेत्रों के बारे में सीमित ज्ञान होता है या बिलकुल भी ज्ञान नहीं होता, फिर भी वे उस बारे में आत्मविश्वास से भरे होते हैं और उन पर विस्तार से बात कर सकते हैं। जर्मन-अमेरिकी लेखक चार्ल्स बुकोवस्की ने इसे बहुत अच्छे से वर्णित किया है कि दुनिया की समस्या यह है कि बुद्धिमान लोग हमेशा संदेह से भरे रहते हैं, जबकि मूर्ख आत्मविश्वास से।

महात्मा गांधी जब जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो वे करीब 22 साल देश से बाहर रहकर आ रहे थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने उन्हें सलाह दी कि किसी भी राजनीतिक गतिविधि में शामिल होने से पहले देशभर में एक साल यात्रा करके देश और उसके लोगों को समझें। गांधी ने यही किया भी। इसमें कोई संदेहनहीं है कि किसी भी चीज की अच्छी समझ विकसित करने से पहले समय, प्रयास, समर्पण और संसाधनों की आवश्यकता होती है। जब रामायण में राम और लक्ष्मण को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजा गया था, तब भी यही विचार रहा होगा। भारतीय दर्शन में इस बात का काफी उल्लेख है कि बिना प्रयास के प्राप्त की गई वस्तु अच्छी नहीं होती।

लेकिन अब समय बदलता नजर आ रहा है। इंस्टेंट कॉफी या नूडल्स का तो पहले भी समय था, लेकिन हम एआई और चैटजीपीटी के युग में प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में हर कोई बिना मेहनत और कोशिशों के हर विषय का ज्ञानी बनता नजर आ रहा है। आपने भी अकसर देखा होगा कि लोग जिस विषय को गहराई से नहीं समझते हैं, चर्चाओं में उसी पर सबसे ज्यादा बोलते हैं। इस चुनौती का एक चिंताजनक प्रभाव अकादमिक और विश्वविद्यालयीन शिक्षा और शोध पर भी पड़ रहा है। साइंटिफिक जर्नल में छपे शोधपत्रों को करियर ग्रोथ के लिए जरूरी कर दिया गया है। गुणवत्ता के बजाय संख्या पर बहुत ध्यान दिया जाता है, जिसका परिणाम प्रकाशन के लिए होड़ में होता है। नतीजा है जर्नलों में चैटजीपीटी-जनरेटेड या चुराए हुए कंटेंट वाले लेख छपने लगे हैं। भारत के एक निजी विश्वविद्यालय ने वैज्ञानिक शोधपत्रों को वापस लेने के लिए दुनिया में नंबर 1 होने का श्रेय पाया है।

एआई उपयोगी जरूर साबित होगा, लेकिन हर क्षेत्र में नहीं। जब बात ज्ञान की आती है तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जो सच में ही सीखना चाहते हैं, वो तो ज्ञान अर्जित करने के रास्ते निकाल लेते हैं, लेकिन उनका क्या किया जाए जो यह भी नहीं जानते कि वो नहीं जानते हैं? इसके लिए सामाजिक स्तर पर चिंतन, मनन और मीमांसा करनी होगी। लेकिन सबसे पहले हमें- व्यक्तिगत स्तर पर- सीखने, कम बोलने या उसी के बारे में बोलने, जिसे हम अच्छे-से जानते-समझते हैं, की आदत डालनी होगी।

**(ये लेखक के अपने विचार हैं)**

# शहरों में जलभराव

## स्थायी समाधान की जरूरत

दिल्ली या यूं कहें कि किसी भी बड़े शहर की सड़कों पर जलभराव अब आम बात हो गई है। हम इसके इतने आदी हो गए हैं कि इसे मानसून में होने वाली एक आम बात मान लेते हैं। लेकिन क्या यह वाकई प्राकृतिक है या योजना और तैयारी की कमी इसकी वजह है? सड़कों पर पानी भर जाना, फंसे हुए वाहन, उफनते नाले और अंतहीन ट्रैफिक जाम आम बात हो गई है। दुर्भाग्य से, हम अधिकारियों से पूछना भी नहीं चाहते और इसे एक प्राकृतिक घटना मानकर स्वीकार कर लेते हैं। इस बीच, दुनिया भर के शहरों ने इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने में सफलता प्राप्त की है। यह विरोधाभास और भी गहरा हो सकता है।

तो फिर, भारत साल-दर-साल इन्हीं समस्याओं से क्यों जूझ रहा है? हर मानसून भारत के शहरों में एक पूवार्नुमानित आपदा की तरह सामने आता है। सड़कें नदियों में तब्दील हो जाती हैं, सार्वजनिक परिवहन ठप हो जाता है, व्यवसाय ठप हो जाते हैं और आपातकालीन कर्मचारी सीमित साधनों के साथ बढ़ते पानी से जूझते हैं। साल-दर-साल, अधिकारी दावा करते हैं कि वे तैयार हैं और साल-दर-साल, बारिश उन्हें गलत साबित कर देती है।

आर्थिक प्रभाव चौंका देने वाला है। कथित तौर पर भारत को शहरी बाढ़ के कारण सालाना अरबों डॉलर का नुकसान होता है। इस बार-बार आने वाले संकट का एक प्रमुख कारण पुराना बुनियादी ढांचा है। भारतीय शहरों में कई जल निकासी प्रणालियाँ औपनिवेशिक काल के दौरान बनाई गई थीं। उदाहरण के लिए, मुंबई को ही लीजिए, इसकी वर्षा जल प्रणाली 1860 के दशक की है और इसे यहाँ होने

वाली मूसलाधार बारिश के एक अंश को संभालने के लिए डिजाइन किया गया था।

उदाहरण के लिए, बेंगलुरु में, पिछले कुछ दशकों में शहर के लगभग 80 प्रतिशत जल निकाय लुप्त हो गए हैं। चेन्नई में भी, इसकी आर्द्रभूमि को आवासीय कॉलोनियों और आईटी पार्कों में बदल दिया गया है। फिर प्रशासनिक अराजकता का मुद्दा है। भारत में शहरी शासन खंडित है। समन्वय बहुत कम है और जब बाढ़ आती है, तो दोषारोपण का खेल शुरू हो जाता है। शहरी बाढ़ प्रबंधन के लिए एक एकीकृत कमांड सेंटर के अभाव के परिणामस्वरूप टुकड़ों में प्रतिक्रियाएँ होती हैं।

भारत की विफलता को और अधिक स्पष्ट करने वाली बात यह है कि अन्य देश समान चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफल रहे हैं। उदाहरण के लिए, टोक्यो में, अधिकारियों ने दुनिया की सबसे बड़ी भूमिगत बाढ़ मोड़ प्रणालियों में से एक का निर्माण किया है, सुरंगों और भंडारण टैंकों का एक विशाल नेटवर्क जो पूरे जिलों की जल निकासी करने में सक्षम है। चीन के गुंजू ने भी एक जटिल भूमिगत नहर प्रणाली विकसित की है। ये रातोंरात हासिल की गई उपलब्धियां नहीं हैं, बल्कि वर्षों के निवेश, सावधानीपूर्वक योजना और अटूट राजनीतिक इच्छाशक्ति को दशार्ती हैं।

दुर्भाग्य से, भारत में दीर्घकालिक दृष्टिकोण अक्सर अल्पकालिक राजनीतिक लाभों के आगे पीछे छूट जाता है। एक दशक में परिणाम देने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाएं तात्कालिक चुनावी चक्रों पर केंद्रित राजनेताओं को कम आकर्षक लगती हैं। परिणामस्वरूप, संरचनात्मक समाधानों के बजाय, पैसा अक्सर सतही सफाई और संकट प्रबंधन पर खर्च किया जाता है।

जवाबदेही का भी गहरा अभाव है। नौकरशाहों और नगर निकायों को बार-बार होने वाली विफलताओं के परिणामों का सामना शायद ही करना पड़ता है, और बारिश के कम होने के बाद जनता की स्मृति भी धुंधली पड़ जाती है। आगे का रास्ता स्पष्ट है, लेकिन कठिन भी। भारतीय शहरों को बड़े पैमाने पर आधुनिक बुनियादी ढांचे में निवेश शुरू करना होगा। तब तक, बाढ़ग्रस्त सड़कें, खोई हुई जानें और दम तोड़ती उम्मीदें जारी रहेंगी।

# प्रबंधन की कला और विज्ञान

**आज नेतृत्व के लिए असली चुनौती उच्च या निम्न मानदंडों के बीच चयन करने में नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक, निर्णय-संचालित दृष्टिकोण तैयार करने में है जो परिचालन उपकरणों को मानवीय अंतर्दृष्टि के साथ एकीकृत करता है।**

**विनयशील गौतम**
लेखक, प्रबंध परामर्शदाता हैं।

दक्षता की खोज की वकालत हर जगह की जाती है। इसमें मानकों का निर्धारण, पर्याप्त संसाधन, प्रावधान की निकटता और प्रभावी ढंग से अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है, जिससे स्थायी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। ये विशेषताएं सरल लग सकती हैं, लेकिन इन्हें लागू करना जटिल है। यह कोई साधारण जटिलता नहीं है, बल्कि गहरे मनोवैज्ञानिक निहितार्थों वाली है।

कई लोग दूसरे व्यक्ति से कार्यकुशलता की अपेक्षा करते हैं। हालांकि, जब बात खुद की आती है, तो वे अधिक उदार दृष्टिकोण पसंद करते हैं, जिसे यथार्थवादी कहकर प्रस्तुत किया जाता है।

कार्यात्मक दृष्टि से, कई अधीनस्थ अपने वरिष्ठ से मानकों का पालन करने में समझदारी और अक्सर लचीलेपन की अपेक्षा करते हैं। यह अपेक्षा व्यवस्था में एक समायोज्य लचीलापन बनाने की होती है। यह प्रशंसनीय दृष्टिकोण, यदि प्रत्येक स्तर पर अपनाया जाए, तो व्यवस्था को शिथिल बनाने और मानकों के निर्धारण और उनके संचालन को व्यक्तिगत पसंद और समायोजन के मामलों में बदलने में एक शक्तिशाली कारक हो सकता है।

इस स्थिति के परिणामों में से एक समग्र उत्पादकता पर प्रभाव पड़ता है और अक्सर, समग्र स्तर पर उत्पादन में गिरावट आती है। इसका अपने आप में एक व्यापक प्रभाव हो सकता है: संगठन की समग्र विश्वसनीयता कम हो सकती है और जल्द ही यह जीवन का एक हिस्सा बन सकती है।

इसे देखते हुए, मानकों से विचलित न होना ही बेहतर है, बल्कि मानकों के निर्धारण को अधिक यथार्थवादी बनाना ही बेहतर है। इससे एक दुविधा पैदा होती है।

यह दुविधा इस मौन स्वीकृति में निहित है कि संगठन अपनी सर्वोत्तम क्षमता से कार्य नहीं कर सकता। परिचालन की दृष्टि से, इसका अर्थ यह नहीं हो सकता कि निम्न-स्तरीय मानक निर्धारित किए जाएं। जैसा कि ऊपर बताया गया है, वे निम्न-स्तरीय मानक भी लचीले हो जाते हैं, और समय के साथ, उनमें गिरावट का रुझान शुरू हो सकता है। यह दो तरह से खतरनाक है: प्रत्येक संगठन समान संस्थानों के समूह का हिस्सा होता है, और यदि कोई अपने प्रतिस्पर्धियों से निचले स्तर पर काम करता है, तो वह बाजार खो सकता है—अर्थात उत्पादकता और लाभप्रदता। यह प्रतिस्पर्धा से अंततः बाहर निकलने के द्वार खोल सकता है।

प्रस्ताव सरल है: मानकों को कम करने की अपनी कीमत होती है, और कभी-कभी वह कीमत संगठन को इतना निष्क्रिय बना सकती है कि वह बाजार से पूरी तरह बाहर हो जाता है, आत्म-विनाश के कगार पर।

इसलिए, पारंपरिक दुविधा बनी हुई है: ऐसा दृष्टिकोण कैसे खोजा जाए जो यथार्थवादी हो, लेकिन बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंकने जैसा न हो। यहीं पर रणनीति की भूमिका आती है। रणनीति, नीति और कार्रवाई के बीच का वह प्रयास है जो रोजमर्रा के कामकाज के लिए एक परिचालन दृष्टिकोण की रूपरेखा तैयार करता है। इसके लिए निर्णय और अपने सहयोगियों की क्षमता की समझ की आवश्यकता होती है। दुर्भाग्य से, केवल कुछ ही सांख्यिकीय उपकरण हैं जो समग्र तस्वीर के लिए सीमित, अस्थायी जानकारी प्रदान करते हैं। पूरी तस्वीर के लिए अभी भी निर्णय की आवश्यकता है, वास्तव में, गहन निर्णय की।

यह हमें प्रबंधन में एक प्रमुख चिंता की ओर ले जाता है: परिचालन उपकरण कहाँ काम करते हैं, और निर्णय कहां काम करता है? एक पेशे के रूप में प्रबंधन लंबे समय से इन दो खेमों में बँटा हुआ है। संचालन

**प्रबंधन, एक कला और विज्ञान, दोनों रूपों में, एक शिल्प के अधिक निकट है। यह एक ऐसा मार्ग अपनाने में सहायता करता है जो न केवल अस्तित्व बल्कि प्रयासों की सफलता भी सुनिश्चित करता है। उत्तरोत्तर और विशिष्ट रूप से, प्रबंधन की प्रकृति विकसित होती रहती है।**

अनुसंधान और सांख्यिकीय पृष्ठभूमि वाले लोग मात्रात्मक विधियों को प्राथमिकता देते हैं, जबकि राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और इतिहास जैसे विषयों के लोग निर्णयात्मक दृष्टिकोण को प्राथमिकता देते हैं।

उपरोक्त विवरण एक सरल प्रस्ताव का पर्याप्त उदाहरण है, जो कारकों और विकल्पों के एक जटिल ढांचे में अंतर्निहित है। यहीं पर नेतृत्व और निर्णय आवश्यक हो जाते हैं, और शीर्ष प्रबंधन को सांख्यिकीय नोट्स से परे निर्णय लेने के कौशल की आवश्यकता होती है। प्रबंधन की प्रकृति, विशेष रूप से जहां दक्षता मापदंडों का संबंध है, केवल उच्च या निम्न मानकों का मामला नहीं है। यह इस बारे में है कि बाजार में क्या कारगर है और क्या संगठन के अस्तित्व, उत्पादकता और लाभप्रदता को सुनिश्चित करेगा।

कुल मिलाकर, इसके लिए अनुभव और निर्णय दोनों के विलय की आवश्यकता होगी। इसके लिए सांख्यिकीय उपकरणों और निर्णयात्मक विधियों के एकीकरण की भी आवश्यकता होगी। इसके लिए पायलट परीक्षण और प्रयोग की आवश्यकता होगी, जिसमें संगठन की क्षमता और उसके भीतर के लोगों का ठोस आकलन हो। इसके लिए समय, सरकारी नीतियों और व्यापक संदर्भ की समझ की भी आवश्यकता होगी, ताकि संगठन के शीर्ष प्रबंधन द्वारा अपनाई गई कार्य-प्रणाली समय के तनावों से उबर सके। और यह कार्य-स्थितियों को न केवल आकर्षक बनाता है, बल्कि व्यवहार्य भी बनाता है।

शासन का विज्ञान, शासन की कला भी है। ये दोनों मिलकर विकास और अस्तित्व का मार्ग प्रशस्त करते हैं। कोई आसान उत्तर नहीं हैं, लेकिन यह समाधान की खोज को छोड़ने का कारण नहीं है। उपरोक्त विवरण निर्णय लेने और समस्या-समाधान के लिए एक एकीकृत सोच और समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता को दशार्ता है। केवल यही संसाधन अनुकूलन को प्रोत्साहित करेगा और संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करेगा।

प्रबंधन, एक कला और विज्ञान, दोनों रूपों में, एक शिल्प के अधिक निकट है। यह एक ऐसा मार्ग अपनाने में सहायता करता है जो न केवल अस्तित्व बल्कि प्रयासों की सफलता भी सुनिश्चित करता है। उत्तरोत्तर और विशिष्ट रूप से, प्रबंधन की प्रकृति विकसित होती रहती है। एक समय था जब संगठन को प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त देने के लिए संसाधनों को बड़े पैमाने पर 'भौतिक संस्थाओं' के रूप में देखा जाता था। (उन्नीसवीं सदी के अधिकांश समय तक यही स्थिति रही।)

बीसवीं सदी के उत्तरार्ध में, 'भौतिक' संसाधनों के स्थान पर 'विचारों' ने अपना विशेषाधिकार साझा करना शुरू कर दिया। संगठनात्मक प्रतिस्पर्धात्मकता उत्तरोत्तर गैर-भौतिक संपत्तियों से प्रभावित होने लगी।

यह यहीं नहीं रुकी। विचार महत्वपूर्ण हो गए और संस्थाओं के विकास और समृद्धि को आकार देने लगे। अब ऐसा लगता है कि एक ऐसा चरण निकट आ रहा है जहाँ विचारों को 'बुद्धिमत्ता' जैसी अवधारणाओं के साथ अपना स्थान साझा करना होगा। संगठनों की अवधारणा विकसित हुई है और तीव्र गति से विकसित हो रही है।

आज संगठनों का वर्गीकरण पहले की तुलना में कहीं अधिक समृद्ध है। ऐसा लगता है कि यह पैटर्न जारी रहेगा।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

# उभरती अर्थव्यवस्था में श्रमजीवी

**भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति का श्रेय गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों ड्राइवरों, डिलीवरी कर्मियों और सेवा प्रदाताओं, के मौन लेकिन अपरिहार्य प्रयासों को जाता है।**

**मीनू द्विवेदी**
लेखिका, स्तम्भकार हैं।

भारत की तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की गति का श्रेय गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों, ड्राइवरों, डिलीवरी कर्मियों और सेवा प्रदाताओं, के मौन लेकिन अपरिहार्य प्रयासों को जाता है, जो त्वरित वाणिज्य और ऐप-आधारित सेवा पारिस्थितिकी तंत्र की रीढ़ हैं। उपभोक्ता सुविधा और सेवा दक्षता को आकार देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बावजूद, ये कर्मचारी अभी भी एक अस्पष्ट क्षेत्र में काम कर रहे हैं क्योंकि वर्तमान में उन पर लागू श्रम और रोजगार कानूनों में एक कानूनी शून्यता है।

केंद्र और कुछ राज्यों के विधानमंडलों ने इस श्रेणी के श्रमिकों को औपचारिक रूप से मान्यता देने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा कवरेज और बीमा लाभों के लिए पात्र बनाने के लिए कानून बनाए हैं। हालांकि, केंद्र द्वारा बनाए गए कानून प्रवर्तन के लिए लंबित हैं और कुछ राज्यों द्वारा बनाए गए कानून अभी तक पूरी तरह से लागू नहीं हुए हैं। न्यायपालिका को गिग कर्मचारियों के नियोक्ताओं के अधिकारों और दायित्वों से जुड़े मामले प्राप्त हो रहे हैं। 2017 में, दिल्ली कमर्शियल ड्राइवर्स यूनियन ने भारतीय कानून के तहत 'कामगार' का दर्जा और संबंधित वैधानिक लाभों का दावा करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ कैब एग्रीगेटर्स के खिलाफ मुकदमा दायर किया था।

याचिका वापस लेने के कारण इस मुद्दे पर फैसला नहीं हो सका। ऐप-आधारित परिवहन श्रमिकों के भारतीय महासंघ (आईएफएटी) ने 2021 में सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर कर असंगठित श्रमिक समाज कल्याण सुरक्षा अधिनियम, 2008 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को असंगठित श्रमिक के रूप में मान्यता देने का दावा किया था, जो वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

गर्मी के चरम महीनों के दौरान, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को एक सलाह जारी की थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि काम के घंटों के पुनर्निर्धारण और चरम गर्मी के घंटों के

दौरान शारीरिक कार्य की तात्कालिकता का आकलन करने सहित सक्रिय उपाय पूरे भारत में मजदूरों और आकस्मिक श्रमिकों पर लू के प्रभाव को कम करने के लिए किए जाएं। उल्लेखनीय है कि यह सलाह गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को शामिल करने के लिए पर्याप्त व्यापक थी।

हालाँकि, फ्लिपकार्ट, इटरनल और अमेजन जैसी कई कंपनियों ने इस तरह की सलाह जारी करने से पहले स्वेच्छा से इस दिशा में उपयुक्त उपाय किए थे।

कोविड-19 के दौरान सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों ने स्पष्ट किया था कि किसी सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा जारी आदेश की प्रकृति वाली कोई भी सलाह दंडात्मक प्रावधानों को आकर्षित करेगी और सभी राज्य सरकारों, सार्वजनिक प्राधिकरणों और नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि वे जन सुरक्षा के हित में केंद्र द्वारा जारी निदेशों, सलाहों और आदेशों का अक्षरशः पालन करें। तदनुसार, यह तर्क दिया जा सकता है कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सलाह बाध्यकारी प्रकृति की नहीं थी क्योंकि यह आदेश के रूप में संरचित नहीं थी और इसमें चूक करने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं था।

इस पृष्ठभूमि में, यह निष्कर्ष निकालना गलत नहीं होगा कि गिग वर्कर्स/एग्रीगेटर्स के नियोक्ताओं के पास अपनी विशिष्ट व्यावसायिक आवश्यकताओं के आधार पर गिग वर्कर्स के नियम और शर्तें निर्धारित करने की छूट है।

हालांकि आईएफएटी के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स की स्थिति पर बहुप्रतीक्षित स्पष्टता आने की संभावना है, यह उल्लेखनीय है कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को कर्मचारी का दर्जा देने वाला कानून न होने के बावजूद, कुछ राज्यों में ट्रेड यूनियनों के रजिस्ट्रार ऐसे श्रमिकों द्वारा गठित ट्रेड यूनियनों का पंजीकरण कर रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अंतर्गत मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 तैयार किए थे, जिनका उद्देश्य अन्य बातों के अलावा, कार्य घंटों को विनियमित करना और एग्रीगेटर्स द्वारा शामिल किए गए ड्राइवरों को बीमा लाभ प्रदान करना था। गौरतलब है कि ये दिशानिर्देश न केवल कुछ समय से अस्तित्व में हैं, बल्कि आने वाले महीनों में मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 द्वारा इनका स्थान लेने का भी प्रस्ताव है, जिसका उद्देश्य ऐसे ड्राइवरों को व्यापक कवरेज और बेहतर लाभ प्रदान करना है।

मौजूदा गतिशील आर्थिक परिस्थितियों में, रोजगार कानूनों के तहत गिग कार्यबल की कानूनी स्थिति पर स्पष्टता की तत्काल आवश्यकता है। गिग-श्रमिकों पर केंद्र और राज्य-विशिष्ट रोजगार कानूनों को लागू करने और/या लागू करने से पहले, संबंधित अधिकारी मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2025 से प्रेरणा ले सकते हैं।

इससे पारंपरिक रोजगार संबंधों और नए युग के बातचीत से तय कार्य संबंधों/आर्थिक व्यवस्थाओं के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी ताकि आधुनिक न्यायसंगत कार्य संबंध बनाए जा सकें और सफल व्यावसायिक परिणामों पर ध्यान केंद्रित किया जा सके जो एक राष्ट्र के रूप में भारत के हितों को आगे बढ़ाते हैं।

## आप की बात

### भारत की शानदार जीत

**भारत** और इंग्लैंड के बीच एंडरसन -तेंदुलकर ट्रॉफी भारतीय खिलाड़ियों के जोश ,उत्साह ,टीम एकता,अनुशासन , दृढ़ संकल्प ,मेहनत और जीतने की इच्छा शक्ति के लिए हमेशा यादगार रहेगी। इस टीम के चुनाव करते समय बहुत से सवाल टीम चयन को लेकर किए गए थे लेकिन उन सभी सवालों को शुभमन गिल की कप्तानी में युवा टीम ने खारिज कर दिये। प्रथम टेस्ट से लेकर अंतिम टेस्ट तक हर मैच रोमांचक हुआ ,भारत ने हारे हुए टेस्ट को या तो ड्रॉ करवा दिया या फिर जीत लिया वहीं दो टेस्ट मैच जीतते जीतते रह गए अन्यथा ये सीरीज भारत की ऐतिहासिक जीत के साथ खत्म होती। भारत की तरफ से मुख्य तेज गेंदबाज बुमराह की अनुपस्थिति में भी भारत ने जो दो टेस्ट जीते उससे ये पता लगता है कि भारत का पेस अटैक कितना ताकतवर है। बैटिंग लाइनअप भी सुदृढ़ है। पांचवें टेस्ट की जीत ने बता दिया कि टेस्ट मैच कितना रोमांचक हो सकता है और टेस्ट मैच से ही क्रिकेट में खिलाड़ियों का असली टेस्ट होता है। साथ ही इंग्लैंड के खिलाड़ियों का भी खेल के प्रति जज्बा काबिले तारीफ था। उनके तेज गेंदबाज वोक्स तो फ्रैक्चर के बाद भी अंतिम खिलाड़ी के रूप में एक हाथ से बैटिंग करने आया। सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा के सामने अंग्रेज बल्लेबाज असहाय नजर आये।

– **भगवानदास छारिया**, 15 सोमानी नगर इंदौर

### आस्था की भीड़ में हादसे

**मध्यप्रदेश** के सीहोर में प्रसिद्ध पंडित प्रदीप मिश्राजी के कुबरेश्वर धाम में मंदिर में दर्शन के दौरान भगदड़ मचने से 2 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई व कुछ घायल हो गए. इससे पहले भी हरिद्वार के मनसा माता मंदिर में भी भगदड़ से दर्दनाक हादसा हो चुका है। देश में धार्मिक स्थलों पर प्रवचन-दर्शन के दौरान अनेक घटनाएं भगदड़ या यूं कहिये स्थानीय प्रशासक और आयोजकों की लापरवाही से भीड़ पर नियंत्रण नहीं रख पाने अथवा माकूल इंतजान न होने से गड़बड़ियां हुई हैं जिससे निर्दोष श्रद्धालुओं जिनमें महिलायें व बच्चे भी होते हैं मारे गए हैं और घायल भी हुए हैं। कभी-कभी अंदाज से अधिक भीड़ आ जाने से भी आयोजक और प्रशासक नियंत्रण खो बैठे हैं और कभी उनकी लापरवाही से भी हादसे हुए हैं. जिसका खामियाजा श्रद्धालुओं को भुगतना पड़ा है.। अतः आयोजक और प्रशासक आयोजनों में होने वाले संभावित "भीड़तंत्र" हेतु अधिक माकूल इंतजान रखें ताकि दुर्घटना न हो, क्योंकि इससे "धरम करे करम फूटे" वाली कहावत बेवजह चरितार्थ हो जाती है। और आयोजक, प्रशासक व धर्मस्थल भी बदनाम हो जाते हैं व भय का आदेश भी श्रद्धालुओं में बना रहता है। इसलिए श्रद्धालुओं को भी संयम बरतना चाहिए ताकि प्रवचन व देवदर्शन पाने से वे प्रफुल्लि्त भी हो सकें और अपार आनंद की अनुभूति भी वे पा सकें।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

### राहुल को फटकार

**यह** अत्यंत खेदजनक है कि देश के नेता विपक्ष को बार-बार सुप्रीम कोर्ट की सख्त फटकार झेलनी पड़ रही है। लोकतंत्र में आलोचना और सवाल उठाना विपक्ष का अधिकार ही नहीं, कर्तव्य भी है पर यह अधिकार तथ्यों और गरिमा की कसौटी पर परखा जाता है। राहुल गांधी का यह कहना कि ह्लचीन ने भारत की 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया हैह्व, एक संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसे हवा में उछालना न केवल सेना के मनोबल को ठेस पहुंचाता है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश की स्थिति को भी कमजोर करता है। सुप्रीम कोर्ट ने सही सवाल उठाया – उन्हें यह जानकारी कैसे मिली? और यदि मिली, तो क्या यह संसद में उठाए जाने योग्य मुद्दा नहीं था? यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने बिना पुख्ता आधार के गंभीर आरोप लगाए हैं। राफेल सौदे को लेकर की गई गलतबयानी पर भी उन्हें कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। विदेशों में भारतीय लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने वाले उनके बयानों पर पहले ही बहस हो चुकी है। अब जब वे देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्थाओं – चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक – पर निशाना साध रहे हैं, तो यह केवल राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मयार्दाओं का अतिक्रमण है।

– **विभुक्ति बुपक्या**, खाचरोद, उज्जैन

### अवैध धर्मांतरण

**भारत** का संविधान समानता और धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है, परंतु इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग कर प्रलोभन, धोखे और दबाव के माध्यम से अवैध धर्मांतरण जैसी घटनाएं दशकों से सामने आती रही हैं। विशेषकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्गों को निशाना बनाकर किया जाने वाला यह मतांतरण, सामाजिक न्याय और आरक्षण व्यवस्था की मूल भावना पर आघात करता है। आदिवासी नेता बाबा कार्तिक उरांव ने 1967 में संसद में प्रस्तुत एससी-एसटी आदेश संशोधन विधेयक के माध्यम से यह स्पष्ट किया था कि जो आदिवासी जन इस्लाम या ईसाई धर्म ग्रहण कर लेते हैं, उन्हें अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 1969 में संसद की संयुक्त समिति ने भी इस सिफारिश की पुष्टि की थी, परंतु दुर्भाग्यवश तत्कालीन सरकार ने राजनीतिक दबाव के चलते इस विधेयक को लागू नहीं किया। संविधान के अनुच्छेद-341 के अनुसार अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण और अन्य विशेषाधिकार केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म में रहने वाले व्यक्तियों को ही प्राप्त हैं। धर्म परिवर्तन करने पर ये लाभ समाप्त हो जाते हैं। किंतु अनुच्छेद-342, जो अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, उसमें ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण आदिवासी समुदाय में मतांतरित लोग भी आरक्षण और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाते रहे हैं।

– **सुभाष बुड़ावनवाला**, रतलाम

## ट्रंप को करारा जवाब

भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नयी धमकी पर तीखी प्रतिक्रिया जताते हुए अमेरिका को जिस तरह आईना दिखाया है, उससे यह स्पष्ट है कि अपना देश अमेरिका के दबाव में नहीं आने वाला है. दरअसल व्यापार समझौते पर भारत के अडिग रवैये को देखते हुए ट्रंप ने भारतीय आयात पर शुल्क दरों में और वृद्धि करने की धमकी दी है. हालांकि टैरिफ में और वृद्धि करने के बारे में ट्रंप ने स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा है, लेकिन यह साफ है कि उनकी ताजा धमकी व्यापार समझौते से पहले भारत पर दबाव बनाने की एक और सुनियोजित कोशिश है. भारत के विदेश मंत्रालय ने अपनी प्रतिक्रिया में ट्रंप की इस धमकी को अकारण और अन्यायपूर्ण तो बताया ही है, उसने यह भी कहा है कि भारत सरकार अपनी जनता को किफायती दरों पर ईंधन देने के लिए रूस से तेल खरीदती है, जबकि कई यूरोपीय देश तो रूस के साथ व्यापार कर रहे हैं. भारत सरकार ने ट्रंप को याद दिलाया कि यूक्रेन युद्ध के समय से भारत को कच्चे तेल के लिए रूस पर निर्भर होना पड़ा है, क्योंकि तेल आपूर्ति करने वाले पारंपरिक देशों से कच्चा तेल तब यूरोप जा रहा था. और अमेरिका ने ही तब वैश्विक स्तर पर तेल की कीमत को निचले स्तर पर बनाये रखने के लिए रूस से तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया था. भारत ने ट्रंप को यह भी याद दिलाया है कि अमेरिका अब भी रूस से यूरेनियम तथा इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम खरीद रहा है. जहां तक यूरोपीय संघ की बात है, तो 2024 में रूस के साथ उसके दोतरफा व्यापार का जो आंकड़ा रहा, वह उस साल भारत और रूस के बीच हुए व्यापार के आंकड़ों से अधिक है. इतना ही नहीं, रूस और यूरोपीय संघ के बीच कच्चे तेल के अतिरिक्त उर्वरक, रसायन, लोहा, इस्पात आदि का भी कारोबार होता है. ऐसे में सिर्फ भारत को निशाना बनाने का कोई औचित्य नहीं है. अन्य देशों की तरह भारत भी अपने हितों और राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से कदम उठायेगा. तथ्य यह है कि भारत की तुलना में चीन रूस से कच्चे तेल की ज्यादा खरीद करता है, लेकिन ट्रंप चीन को निशाना नहीं बना रहे, इससे भी स्पष्ट है कि ट्रंप भारत पर दबाव बनाने की कोशिश में लगे हैं. लेकिन सरकार की तीखी प्रतिक्रिया से यह साफ है कि अब वह कूटनीतिक लिहाज नहीं करने जा रही और न ही अमेरिका-यूरोप के दबाव बनाने की कोशिशों पर खामोश रहने वाली है.

**टैरिफ में वृद्धि की ट्रंप की ताजा धमकी पर सरकार की तीखी प्रतिक्रिया से यह साफ है कि अब वह कूटनीतिक लिहाज नहीं करने जा रही और न ही अमेरिका-यूरोप के दबाव बनाने की कोशिशों पर खामोश रहने वाली है.**

# पाकिस्तान के साथ अमेरिका की गलबहियां

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
prabhuchawla@newindianexpress.com

**नये अमेरिकी टैरिफ मोदी और ट्रंप के बीच बने भरोसे की दोस्ती के विरुद्ध हैं. ट्रंप झूठे ही यह श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाक संघर्ष रुकवाया. पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव आतंक के ढांचों को नयी ताकत दे रहा है. इससे 1970 की अमेरिकी नीति की पुनरावृत्ति हो रही है: भारत को अलग-थलग करो, पाकिस्तान से दोस्ती गांठो और शांति बहाली का बहाना करो. मगर आज का भारत दब्बू नहीं है. यह करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ की आधारशिला है.**

कुछ घटनाएं इतिहास में दो बार घटित होती हैं: पहली बार कॉमेडी के रूप में और दूसरी बार प्रहसन के रूप में. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दोनों रूपों में देखा गया है. रियलिटी टीवी के मेजबान से टैरिफ तानाशाह बने ट्रंप ने विगत 30 जुलाई को भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी टैरिफ का आर्थिक बम फोड़ा, दूसरी ओर लगातार वह झूठ बोलते रहे कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्षविराम करवाया है. नयी दिल्ली की पीठ में छुरा भोंकने के एवज में उन्होंने इस्लामाबाद से दोस्ती की. उन्होंने जो आर्थिक कदम उठाये हैं, वे अमेरिका के नहीं, खुद उनके हित में हैं. पाकिस्तानी जनरल सैयद आसिम मुनीर अहमद शाह के साथ ट्रंप की सुनियोजित साजिश कायरता में लिपटी है, जो भारत को दुःस्वप्नों के पुराने दौर में ले गयी है. वर्ष 1971 के बांग्लादेश युद्ध को याद कीजिए, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने भारत को धमकाने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस इंटरप्राइज भेज दिया था. मगर इंदिरा गांधी टस से मस नहीं हुई थीं. इतिहास उन्हें याद रखता है, जो मुश्किल दौर में भी अपनी रीढ़ तनी हुई रखते हैं. इस बार इतिहास खुद को प्रहसन के रूप में नहीं, चेतावनी के रूप में दोहरा रहा है. लाल टाई वाले ट्रंप निक्सन ही हैं और अमेरिका फिर पाकिस्तान के साथ खड़ा है. फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अमेरिका टैरिफ और ट्वीट्स के साथ पाकिस्तान के साथ खड़ा है, जबकि भारत पहले की तरह अपने रुख पर अडिग है.

पिछले सप्ताह ट्रंप ने अमेरिका में 87 अरब डॉलर के भारतीय निर्यात पर टैरिफ मिसाइल दागी, जिससे उसके महत्वपूर्ण कारोबारी साझेदार भारत को सात अरब डॉलर के घाटे की आशंका है. विगत फरवरी से अब तक ट्रंप ने आठ बार कहा है कि भारत अमेरिकी उत्पादों पर बहुत ज्यादा शुल्क लगाता है. और अब तो रूस और भारत की अर्थव्यवस्थाओं को मृत बताकर उन्होंने अति ही कर डाली है. ट्रंप ने एक कहानी यह भी बनायी कि भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है. उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अमेरिका के साथ बगैर टैरिफ के व्यापार करने पर सहमत हो गया है, जिसका विरोध जयशंकर ने यह कहते हुए किया कि किसी सौदे पर सहमति तभी बन सकती है, जब वह दोनों पक्षों के लिए लाभकारी हो. नये अमेरिकी टैरिफ मोदी और ट्रंप के बीच बने भरोसे की दोस्ती के विरुद्ध हैं, जो 2017 में व्हाइट हाउस में ट्रंप-मोदी की गलबहियों, 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप के आयोजन और फिर मोदी के अमेरिकी दौरे के जरिये विकसित हुई थी. वर्ष 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर तक पहुंच गया था. विगत फरवरी में ट्रंप के जवाबी टैरिफ से बचने के लिए मोदी ने टैरिफ में कटौती की पेशकश की थी और 2030 तक आपसी व्यापार को बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक ले जाने की बात कही थी. लेकिन पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान ट्रंप का रवैया बदल गया. अमेरिकी राष्ट्रपति झूठे ही यह श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने भारत-पाक संघर्ष रुकवाया. उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया. जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में हुई बहस का जवाब देते हुए कहा कि किसी विदेशी नेता ने भारत को निर्देश नहीं दिया.

ट्रंप की देहभाषा, मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति और बीमार मानसिकता का झूठ उन्हें लोकतंत्र के संरक्षक के बजाय वैश्विक दादा ही ज्यादा साबित करता है. और उनकी नीति अमेरिका फर्स्ट की नहीं, ट्रंप फर्स्ट की है. पाकिस्तान की तरफ उनका झुकाव आतंक के ढांचों को नयी ताकत दे रहा है. इससे 1970 के दौर की अमेरिकी नीति की पुनरावृत्ति हो रही है: भारत को अलग-थलग करो, पाकिस्तान से दोस्ती गांठो और शांति बहाली का बहाना करो. लेकिन आज का भारत दब्बू देश नहीं है. यह करीब 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र और ग्लोबल साउथ की आधारशिला है. भारत के 1.4 ट्रिलियन डॉलर का बाजार और ग्लोबल साउथ का नेतृत्व अमेरिकी राष्ट्रपति के टैरिफ वार के निशाने पर है. मोदी के '2047 में विकसित भारत' का लक्ष्य स्वायत्तता मांगता है, किसी की अधीनता नहीं. अंकटाड के मुताबिक, ट्रंप के टैरिफ विकासशील देशों को अंततः क्षेत्रीय गठबंधनों की ओर ले जायेंगे. भारतीय फार्मास्युटिकल्स और कपड़े एशिया व यूरोप का रुख कर सकते हैं. ट्रंप के तेवर की ग्लोबल साउथ में तीखी प्रतिक्रिया हो सकती है तथा भारत के नेतृत्व में ब्रिक्स देश अमेरिकी वर्चस्ववाद के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. अकेला भारत नहीं, ब्रिक्स भी उभर रहा है, आसियान पूरे घटनाक्रम पर नजर रखे हुए है और यूरोप नये सिरे से चीजों को समायोजित कर रहा है. अगर ट्रंप का यह रवैया जारी रहा, तो भारत ब्रिक्स के साथ रिश्ते मजबूत करेगा और अमेरिका को एक महत्वपूर्ण दोस्त के खोने का अफसोस करना पड़ेगा.

ट्रंप की टैरिफ धोखाधड़ी कूटनीति के वेश में उन पर भरोसा करने वालों को धोखा देने की दुष्प्रवृत्ति है. ट्रंप का तर्क है कि भारत उनके हर्ले डेविडसन और हैम पर भारी शुल्क लगाता है. ट्रंप के दुस्साहसी रवैये से भले उनकी मजबूत छवि बनी हो, लेकिन उन्होंने भारत, जापान, कनाडा, यहां तक कि नाटो से भी अपने रिश्ते खराब कर लिये हैं. ट्रंप के झूठ और टैरिफ से उनका साम्राज्य भले मजबूत हो रहा हो, लेकिन यह दोस्तों के साथ धोखा है. उनके आर्थिक प्रसारवाद ने चौदह देशों पर 25 से 40 फीसदी तक टैरिफ लगाया है. ट्रंप के निरंकुश तौर-तरीकों के कारण अमेरिकी मदद से संचालित शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, कॉरपोरेट दिग्गजों और संभ्रांत सामाजिक कार्यकर्ताओं के वे अंतरराष्ट्रीय समूह कमजोर पड़ सकते हैं, जो दुनियाभर के प्रमुख आर्थिक और कूटनीतिक फैसलों को प्रभावित करते हैं. वाशिंगटन को नयी दिल्ली का संदेश यह होना चाहिए कि भारत को दबाया, खरीदा या धमकाया नहीं जा सकता. अपने 1.4 अरब उपभोक्ताओं और 120 अरब डॉलर के व्यापारिक दांव वाला भारत सम्मान का अधिकारी है. मोदी की संसदीय विजय भारत की दृढ़ इच्छाशक्ति के बारे में बताती है. मोदी की यह जीत उस विजेता को आखिरकार मात देगी, जिसकी दगाबाजी वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल रही है. इसलिए श्रीमान ट्रंप, निक्सन की भूमिका निभाते रहिए. लेकिन कृपया मत भूलिए कि भारत की स्मृति क्षणिक नहीं है. भारत प्रतिरोध करता है. वह उठ खड़ा होगा और जब वैश्विक अस्थिरता की यह धूल जम जायेगी, तब दुनिया को दिखाई पड़ेगा कि कौन दोस्त था और कौन धोखेबाज.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

# भगदड़ पर रोक के लिए राष्ट्रीय नीति की जरूरत

उमेश चतुर्वेदी
वरिष्ठ पत्रकार
uchaturvedi@gmail.com

**दुनिया की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अधिकारियों का कल्पनाशील और अनुमानशील होना जरूरी माना जाता है. लेकिन भारतीय प्रशासनिक ढांचे में इस कल्पनाशीलता की अक्सर कमी नजर आती है. उसमें भावी संकटों और समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए जरूरी सोच की कमी है.**

हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की सुर्खियों की स्याही अभी सूखी नहीं कि उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से भी भगदड़ की खबर आ गयी है. दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर देश तेजी से कदम बढ़ा रहा है. तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का मतलब है कि देश तकनीक और सहूलियतों से लैस होता जा रहा है. इस संदर्भ में जब भगदड़ की घटनाएं सामने आती हैं, तो आधुनिकता से कदमताल करने वाली ये छवियां दरकने लगती हैं. ऐसा नहीं कि देश का ध्यान इस विरोधाभास की ओर नहीं है. फिर भी ऐसी घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रहीं. ऐसी घटनाएं जब भी होती हैं तो एहतियाती कदम उठाये जाने की प्रशासनिक तंत्र की ओर से घोषणाएं होती हैं. कुछ दिनों में देश ऐसी घटनाओं को भुला देता है.

भगदड़ की घटनाओं को लेकर अपनी व्यवस्था कितनी संजीदा है, इसी वर्ष हुई घटनाओं से इसका अनुमान लगाया जा सकता है. वर्ष 2025 में ही सात घटनाएं हो चुकी हैं, जिनमें आधिकारिक तौर पर 81 लोगों की जान जा चुकी है. ये घटनाएं कुंभ जैसे भीड़भाड़ वाले सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन में तो हुईं ही, राष्ट्रीय राजधानी के रेलवे स्टेशन से लेकर गोवा जैसे कम जनसंख्या वाले राज्य में भी घटीं. भगदड़ की घटनाओं के लिए नागरिक बोध की कमी को पहला कारण माना जाता है. लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि भगदड़ की ज्यादातर घटनाएं प्रशासनिक तंत्र की खामी की वजह से होती हैं. मसलन, 15 फरवरी को नयी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर घटी घटना की वजह रेलवे अधिकारियों की सोच रही, जिन्होंने आनन-फानन में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदल दिया और उसमें जगह पाने के लिए लोग दौड़ पड़े. दुनिया की बेहतर प्रशासनिक व्यवस्थाओं में अधिकारियों का कल्पनाशील और अनुमानशील होना जरूरी माना जाता है. लेकिन भारतीय प्रशासनिक ढांचे में इस कल्पनाशीलता की अक्सर कमी नजर आती है. उसमें भावी संकटों और समस्याओं का अनुमान लगाने के लिए जरूरी सोच की कमी है. वह किसी समस्या का अंदाजा लगाकर उसे शुरू में रोकने और व्यवस्थित करने की बजाय आखिरी छोर पर निपटने की सोच से लगातार लैस रहता है. मेले-ठेले में जाने वाले लोगों की भीड़ को मेले में घुसने से पहले व्यवस्थित करने और उसे रोकने में भारतीय प्रशासनिक तंत्र की दिलचस्पी कम होती है, लेकिन जब मेले में भीड़ बढ़ जाती है, तब मेले वाली जगह के दरवाजे पर वह अचानक से रोक लगा देता है. दरवाजे पर भीड़ को रोकने से मेले में भीड़ भले ही न घुसे, लेकिन पीछे से आ रहे रेले पर रोक नहीं लग पाती. फिर रेला लोगों को धकियाते आगे बढ़ने लगता है.

भगदड़ के बारे में एक अवधारणा रही है कि गरीब-गुरबा और अशिक्षित लोग ही इसके शिकार बनते हैं. यह अधूरा सच है. यह सच है कि उत्तर भारत के मंदिरों में दर्शनार्थियों की भीड़ में ज्यादातर निम्न मध्यम वर्ग के लोग होते हैं. उत्तर भारत में मंदिरों तक में वीआइपी संस्कृति का बोलबाला है. इसकी तुलना में दक्षिण भारतीय मंदिरों में वीआइपी संस्कृति कुछ कम है. इसलिए उत्तर के मंदिरों और धार्मिक मेले-ठेले में अनुशासनहीन भीड़ की बहुलता होती है. चूंकि प्रशासनिक तंत्र कल्पनाशीलता से उन्हें व्यवस्थित नहीं कर पाता, लिहाजा भगदड़ की दुर्भाग्यजनक घटनाएं हो जाती हैं. इसमें दो राय नहीं कि भारत की एक बड़ी समस्या उसकी बड़ी जनसंख्या भी है. देश की एक और बड़ी समस्या यह है कि भीड़ को अनुशासित करने का संस्कार और शिक्षण पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर नहीं है. इसकी वजह से मौका पाते ही हर व्यक्ति रसूख के साथ भीड़ से निकलना चाहता है या फिर अपना वर्चस्ववादी स्वभाव दिखाना चाहता है. कई बार पिछड़ती हुई भीड़ अपना आपा भी खो देती है. भारत का एक बड़ा हिस्सा अरसे तक चूंकि गरीबी की मार झेलता रहा है, इसलिए उसके अवचेतन में कुछ पाने की चाह में दूसरों को पीछे छोड़ने की सोच हावी रहती है. इसमें यदि अफवाह मिल जाती है, तो हालात भयावह हो जाते हैं.

सवाल है कि क्या ऐसी व्यवस्था नहीं बनायी जा सकती कि देश के भीड़भाड़ वाले आयोजन बिना किसी भगदड़ या अव्यवस्था के संपन्न हो सकें. इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक मुकम्मल नीति बनाने और उसे कड़ाई से लागू करने की जरूरत है. आज के दौर की हर कठिन राह को तकनीक ने आसान किया है. ऐसे में नीतिगत स्तर पर प्रशासनिक तंत्र को प्रशिक्षित करना होगा कि तकनीक के इस्तेमाल से वे ठीक से पता लगा पायें कि किस बिंदु पर भीड़ को रोका जाना चाहिए, कहां बैरिकेडिंग कर भीड़ को नियंत्रित किया जाना चाहिए. इसके साथ ही, प्रशासनिक तंत्र की सोच में कल्पनाशीलता को बढ़ावा देने के लिए भी उसे तैयार करना होगा. प्रशासनिक तंत्र समस्याओं का अनुमान लगाने वाला मानस विकसित कर सके, इसके लिए भी जरूरी इंतजाम करना होगा. वहीं भीड़ को अनुशासित करने के लिए दो स्तरों पर काम करना होगा. स्कूली स्तर से ही इस दिशा में शिक्षा और संस्कार देना होगा. साथ ही, आम लोगों को पीछे छोड़ने या किनारे रखने वाली वीआइपी संस्कृति पर पूरी तरह रोक लगाना भी इस दिशा में जरूरी कदम होना चाहिए. इसके साथ ही अफवाहों पर लगाम लगाने के मुकम्मल इंतजाम भी होने चाहिए.

(ये लेखक के निजी विचार हैं.)

### देश दुनिया

## टैरिफ के कारण अमेरिकी उत्पादों से दूर हो सकते हैं उपभोक्ता

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

ऐसा लगता है कि अमेरिकी सरकार द्वारा 90 से अधिक अर्थव्यवस्थाओं के उत्पादों पर उच्च टैरिफ लगाने का ताजा निर्णय आयात कम करने, अमेरिकी उद्योगों को पुनर्जीवित करने और टैरिफ राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है. फिर भी इसके आर्थिक परिणाम के अनुमान से कहीं अधिक पेचीदा होने की आशंका है. इस संरक्षणवादी नीति की प्रभावशीलता अंततः प्रभावित देशों द्वारा किये जाने वाले जवाबी उपायों और अमेरिकी उत्पादों के प्रति बाजार की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी. जो अर्थव्यवस्थाएं अमेरिका के उच्च टैरिफ का सामना करेंगी, वे चुपचाप तो नहीं ही बैठेंगी. वे दूसरे देशों के साथ व्यापार करने और आपूर्ति शृंखला के विकल्प तलाशने के जरिये इसका जवाब देंगी. इस कवायद में उपभोक्ताओं के भी अमेरिकी उत्पादों से दूर होने की आशंका है. टैरिफ की मार झेल रहे विकासशील देशों को निर्यात में व्यवधान, बढ़ती बेरोजगारी और घटी हुई आय का सामना करना पड़ेगा, जिससे वे अमेरिकी सामान कम खरीद पायेंगे. इस स्थिति में अमेरिका के साथ उनका व्यापार बढ़ेगा नहीं, बल्कि घटेगा. मूलभूत आवश्यकताओं और महत्वपूर्ण तकनीकों के अतिरिक्त, कई अर्थव्यवस्थाएं कुछ मध्यम से उच्च स्तरीय अमेरिकी उत्पादों और उपकरणों पर, जिनके विकल्प उपलब्ध हैं, प्रतिशोधात्मक टैरिफ लगाने का विकल्प भी चुन सकती हैं. इससे एक ऐसा बाजार अवसर पैदा होगा जहां गैर-अमेरिकी उत्पाद अमेरिकी निर्यात को आसानी से विस्थापित कर देंगे. दुनियाभर के औसत उपभोक्ता अमेरिकी उत्पादों, खासकर महंगे उत्पादों, को खरीदने पर रोक लगा सकते हैं. ऐसे में स्वाभाविक रूप से वे अन्य देशों के गुणवत्ता युक्त अधिक किफायती विकल्पों की ओर आकर्षित होंगे. यह बाजार की शक्तियों की वास्तविक कार्यप्रणाली का प्रतिनिधित्व करेगा. ऐसे में चीनी विनिर्माण को इन बाजार क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा का पूरा लाभ मिलेगा. हालांकि इसके लिए चीनी विनिर्माण को वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बनाये रखने और अंतरराष्ट्रीय ब्रांड विकसित करने होंगे.

GLOBAL TIMES

### बोधि वृक्ष

## पंचतत्वों का महत्व

भारत में पंचतत्वों यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को सम्मान देने तथा उनका आभार जताने की परंपरा रही है. क्योंकि यह शरीर, धरती, सौर मंडल और ब्रह्मांड- सब कुछ पंचतत्वों का खेल है. इस संस्कृति में हम जिन लोगों की पूजा करते हैं, चाहे वह शिव हों, राम हों या कृष्ण- वे उन सभी मुश्किलों से गुजरे, जिनसे ज्यादातर मनुष्य गुजरते हैं. हम उनकी पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके हालात चाहे जो भी रहे हों, चाहे उन्हें जीवन में कैसी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ा हो, वे अपनी भीतरी प्रकृति से कभी नहीं भटके. नदी कई तरह से ऐसी ही होती है. चाहे कैसे भी लोग उसे छुएं, बहने की प्रकृति के कारण वह हमेशा शुद्ध रहती है. इस संस्कृति में हमने नदियों को सिर्फ जल भंडार की तरह नहीं देखा. हमने उन्हें जीवनदायी देवी-देवताओं के रूप में देखा. तर्क की सीमाओं में बंधे विचारशील मन को यह बात मूर्खतापूर्ण या आदिम लग सकती है. नदी तो केवल नदी है, वह देवी कैसे हो सकती है? यदि ऐसे व्यक्ति को आप किसी कमरे में तीन दिन तक बिना पानी के कैद कर दें और फिर उसे एक गिलास पानी दिखायें, तो वह उसके आगे सिर झुकायेगा. हमने कभी नदियों को भौगोलिक इकाई की तरह नहीं देखा. हमने उन्हें जीवन को बनाने वाले सामान की तरह देखा, क्योंकि हमारे शरीर का 70 प्रतिशत हिस्सा भी जल है. जब भी हम जीवन की खोज करते हैं, तो सबसे पहले एक बूंद पानी ढूंढते हैं. जब हम जीना भूल जाते हैं, जब हम अपने जीवन को बनाने वाली चीजों का सम्मान नहीं करते- जिस धरती पर हम चलते हैं, जिस हवा में सांस लेते हैं, जिस जल को पीते हैं और जो आकाश हमें थामे रखता है- जब हमारे मन में उनके लिए कोई सम्मान और श्रद्धा नहीं होती, तो वे हमारे अंदर बहुत अलग तरह से बर्ताव करते हैं. यदि आप स्वस्थ, प्रसन्न और सफल होना चाहते हैं, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके भीतर के तत्व इसमें मदद करें. यदि वे मदद नहीं करते, तो कुछ भी कारगर नहीं होगा. अब समय है कि हम तत्वों के साथ सम्मान से पेश आने की संस्कृति को वापस लायें.

**-सद्गुरु जग्गी वासुदेव**

### कुछ अलग

## खिलौनों को लेकर सजगता आवश्यक

डॉ मोनिका शर्मा
टिप्पणीकार
monikasharmawriting@gmail.com

बीते दिनों एम्स द्वारा किये गये एक रिसर्च में सामने आया कि ऑटिज्म पीड़ित बच्चों के शरीर में लेड, क्रोमियम, मरकरी, मैंगनीज, कॉपर, आर्सेनिक, कैडमियम जैसे भारी धातु पाये गये हैं. स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने वाली ये धातुएं प्रदूषित भोजन, सिगरेट के धुएं, प्रदूषित हवा, औद्योगिक कचरे और खिलौनों के जरिये बच्चों के शरीर में पहुंच रही हैं. ध्यातव्य है कि अध्ययन में ऑटिज्म से पीड़ित तीन से बारह वर्ष के 180 बच्चों और 180 स्वस्थ बच्चों को शामिल किया गया था. इनमें ऑटिज्म से पीड़ित 32 प्रतिशत बच्चों में सात तरह के हेवी मेटल पाये गये. जबकि स्वस्थ बच्चों में इस तरह की समस्या देखने को नहीं मिली. ऐसे में अभिभावकों का, बच्चों के शरीर में पहुंचते हानिकारक रसायनों और धातुओं को लेकर, जागरूक होना आवश्यक है.

हमारे यहां खिलौनों के जरिये बढ़ते स्वास्थ्य जोखिमों को लेकर आज भी सजगता कम ही बरती जाती है. बच्चों को खिलौनों से दूर नहीं किया जा सकता. बाल मन के मनोरंजन और खेलने के लिए खिलौने तो जरूरी है हीं. ऐसे में हमारा परंपरागत खिलौनों की ओर लौटना आवश्यक है. लकड़ी, मिट्टी, कपड़े और धागे आदि से बने देसी खिलौने न केवल परंपरा के वाहक हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवनशैली को समझने का जरिया भी हैं. इनसे बच्चों के स्वास्थ्य को कोई खतरा नहीं होता. वहीं प्लास्टिक और अन्य सामान से बने विदेशी खिलौनों में मौजूद रसायन बच्चों की सेहत के लिए बेहद खतरनाक होते हैं. अधिकतर देसी खिलौने ग्रामीण जन-जीवन की झलक और प्रकृति से जुड़ाव का सबक लिये होते हैं. ये खेल-खेल में जीवन से जुड़ी शिक्षा देने के लिए भी एक सुंदर माध्यम हैं. भारत के कारीगरों और कलाओं को देश ही नहीं, दुनियाभर में पहचान दिलाने के लिए भी बाल मन को बहलाने वाले इन कलात्मक उत्पादों की बहुत अहमियत है.

बाल स्वास्थ्य से जुड़े अनगिनत जोखिमों के बावजूद प्लास्टिक या धातु के खिलौने बच्चों के हाथ में थमा दिये जाते हैं. अब तो बाजार इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों से भी अटे पड़े हैं. यह भी सच है कि हानिकारक रसायन ही नहीं, कई तरह की तकनीकों से लैस स्वचालित खिलौने भी बच्चों की मनःस्थिति पर दुष्प्रभाव डालते हैं. सो, सेहत सहेजने और बच्चों को सहज और संवेदनशील जीवनशैली का पाठ पढ़ाने के लिए परंपरागत खिलौने जरूरी हैं. अधिकतर देसी खिलौने ग्रामीण जीवन की झलक और प्रकृति से जुड़ाव का सबक लिये होते हैं. बड़े होते बच्चों के लिए ये मनोरंजन के साथ ही जमीनी जुड़ाव और समझ को पोषित करने वाले प्यारे साथी बन सकते हैं.

### आपके पत्र

**चरमरायी जल निकासी की व्यवस्था**

बरसात के मौसम में देश के प्रायः सभी शहरों में जलजमाव हो जाता है. सभी शहरों में जल निकासी की व्यवस्था चरमरा गयी है. सरकार व संबंधित विभाग हर साल इससे निजात दिलाने का वादा करते हैं, लेकिन समस्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जाती है. बरसात में मुसीबतों के लिए हम खुद जिम्मेदार हैं. शहरों में नदी, नालों का अतिक्रमण कर घर बना लिया गया है. प्लास्टिक के बढ़ते इस्तेमाल की वजह से सभी नदी और नालों के मुहानों पर प्लास्टिक कचरों का अंबार लगा रहता है. इन कचरों की वजह से जल निकासी रुक जाती है.

**हिमांशु शेखर**, केसपा (गयाजी)

**बारिश ने खोली सिस्टम की पोल**

सावन की आखिरी सप्ताह में बारिश होने से मोतिहारी शहर के लोगों को घर से निकलना मुश्किल हो गया है. नगर निगम की तैयारी 10 से 15 घंटे की बारिश में बहर गयी. बारिश से जन निकासी के सिस्टम को तहस-नहस कर दिया. नगर निगम के कमिश्नर के आवास से महज डेढ़ सौ मीटर की दूरी पर तालाब बन गया है. इससे साफ होता है कि नगर निगम ने बारिश के पानी की निकासी के लिए ठोस काम काम नहीं किया है. हर साल नालों की उड़ाही के नाम पर लाखों रुपये खर्च होते हैं, लेकिन इस बार भी इसका असर नहीं दिखा.

**प्रभाकर कुमार**, मोतिहारी

पोस्ट करें : प्रभात खबर, प्लॉट संख्या डी-9-10, पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, पटना (बिहार) - 800013, ■ मेल करें : patna @prabhatkhabar.in पर ■ ई-मेल संक्षिप्त व हिंदी में हो. लिपि रोमन भी हो सकती है.

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 06-08-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP6 User: kamlesh.mestry Time: 08-05-2025 22:32 Color:

विचार

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । बुधवार, 6 अगस्त 2025

# कुदरत की चेतावनी

**उत्तराखंड के** उत्तरकाशी में आई आपदा प्रकृति की एक और गंभीर चेतावनी है। यह बताती है कि पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन साधने की कितनी जरूरत है। देश के पहाड़ी राज्यों, खासकर उत्तराखंड को लेकर ऐसी नीति चाहिए, जिससे पहाड़ और इंसानों के बीच संतुलन बना रहे।

**बड़ी हानि ।** उत्तरकाशी के धराली गांव में खीरगंगा नदी के ऊपरी क्षेत्र में बादल फटा और फ्लैश फ्लड ने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। प्रभावित इलाके से आ रहे विडियो दिल दहलाने वाले हैं। अभी चारधाम यात्रा सीजन चल रहा है और यह गांव गंगोत्री वाले रास्ते पर पड़ता है। श्रद्धालुओं के रुकने का यह एक अहम पड़ाव है। ऐसे में जानमाल की बड़े पैमाने पर हानि की आशंका है।

उत्तरकाशी में आपदा

**लगातार आफत ।** हाल के बरसों में उत्तराखंड इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं के केंद्र में रहा है। 2021 में चमोली जनपद में, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान के पास एक ग्लेशियर टूटकर गिर गया था। इसकी वजह से धौलीगंगा नदी में अचानक बाढ़ आ गई और तपोवन विष्णुगाड पनबिजली परियोजना में काम करने वाले कई श्रमिकों को जान गंवानी पड़ी। इसी तरह, 2023 की शुरुआत में एक और धार्मिक पर्यटन स्थल जोशीमठ में भूस्खलन ने एक बड़ी आबादी को विस्थापित कर दिया।

**खतरनाक स्थिति ।** साल 2013 में केदार घाटी में मची भयानक तबाही से लेकर अभी तक, छोटी-बड़ी ऐसी कई प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी हैं। सवाल यहां आकर रुकती है कि पहाड़ से छेड़छाड़ कब रुकेगी? आरोप है कि उत्तराखंड में चल रहे बेशुमार पावर प्रॉजेक्ट्स ने पहाड़ों को खोखला कर दिया है। इसमें बढ़ती आबादी, लाखों पर्यटकों के बोझ, अनियंत्रित निर्माण और घटती हरियाली को मिला दीजिए तो स्थिति विस्फोटक बन जाती है।

**अनियंत्रित निर्माण ।** बादल फटना प्राकृतिक घटना है, जिस पर इंसानों का जोर नहीं। लेकिन, यह भी तथ्य है कि पानी निकलने के रास्तों, नालों-गदेरों के मुहानों पर कंक्रीट के बड़े-बड़े स्ट्रक्चर खड़े हो चुके हैं। तमाम जगहों पर, जिन रास्तों से पानी को बहना था, वहां इंसान बस चुका है। यह जानबूझकर आफत बुलाने जैसा है।

**संभलने की जरूरत ।** उत्तराखंड को लेकर यह बहस करीब 5 दशक पुरानी है कि विकास किस कीमत पर होना चाहिए। साल 1976 में, गढ़वाल के तत्कालीन कमिश्नर एमसी मिश्रा की अध्यक्षता में गठित कमिटी ने जोशीमठ को बचाने के लिए फौरन कुछ कदम उठाने की सिफारिश की थी- इनमें संवेदनशील जोन में नए निर्माण पर रोक और हरियाली बढ़ाना प्रमुख था। 49 साल बाद आज वह रिपोर्ट पूरे पहाड़ के लिए प्रासंगिक हो चुकी है।

## कभी-कभी

# पढ़े-देखे का असर

ललित वर्मा

**नॉवेल का** ज्यादा शौक नहीं था। कहानियां, ग़ज़लें, कविताएं पढ़ लेता था। पर, जब सिलेबस में हो तो नॉवेल भी पढ़ने पड़ते हैं। ऐसे ही पड़ते हैं के कारण ग्राहम ग्रीन का 'The heart of the matter' पढ़ रहा था कि लगा इसमें खो सा रहा हूं। नॉवेल खत्म होते-होते अजीब सी उदासी महसूस होने लगी। कई दिन नहीं गई। स्कॉबी मेरे लिए कभी न भूलने वाला किरदार बन चुका था। उसकी विडंबनाएं, उसकी बेचारगी परेशान करने लगी। इतनी कि इसके कई साल बाद मैंने स्कॉबी पर एक कविता भी लिखी। अब इस नॉवेल के बारे में बहुत कुछ भूल चुका हूं। स्कॉबी याद है।

कई फिल्में देखीं कि बहुत दिन उनका असर मन पर रहा। वजूद, शिद्दत, आंखों देखी। शायद इनके अंत रूटीन से अलग थे। एक बार पापा से सुना था कि वे हमारे एक बुजुर्ग को जबरदस्ती 'गाइड' दिखाने ले गए। उस फिल्म ने उनकी सोच बदल दी। ऐसे किस्से वक्त-बे-वक्त खूब सुने कि फलां फिल्म, फलां नाटक देखकर किसी की जिंदगी बदल गई। इसमें कोई नई बात नहीं। दुनियाभर में ऐसा होता आया है। 1774 में 24 साल के Johann Wolfgang Goethe ने जर्मन उपन्यास लिखा 'Die Leiden des jungen Werthers' ( युवा वर्थर के दुख)। इसका लोगों पर ऐसा असर पड़ा कि वर्थर की नकल कर लोग आत्महत्या करने लगे। इसे बाकायदा 'वर्थर इफेक्ट' का नाम दिया गया। नाटक 'मैकबेथ', फिल्म 'द ब्रिज', नेटफ्लिक्स की सीरीज '13 reasons why' ऐसे प्रभाव वाले कई उदाहरण हैं।

धर्मवीर भारती के नाटक 'अंधा युग' को देखते हुए लोग रोने लगते थे। कई जगह इसके मंचन की अनुमति टाली गई। भारती जी के ही बेहद उदास नॉवेल 'गुनाहों का देवता' का युवाओं पर हैरान करने वाला असर था। अब तक इसके 83 संस्करण आ चुके हैं। नया दौर, आंधी, रंग दे बसंती जैसी फिल्मों ने ऐसे ही जादुई प्रभाव दर्शकों पर छोड़े। हर जनरेशन के पास अपने-अपने उदाहरण हैं।

जब भी देखने-पढ़ने वाले ने कुछ खुद से रिलेट किया, ऐसा ही मनोवैज्ञानिक प्रभाव जगा, जैसा हाल ही में 'सैयारा' को लेकर दिखा। यह 'Gen Z' का जमाना है। वे थियेटरों में रो रहे हैं, तो इसमें हैरानी की क्या बात है।

## एकदा

# कहानियों से क्रांति

**Lu Xun** (झोउ झांगशौ) 20वीं सदी के प्रारंभ में चीन के सबसे प्रभावशाली लेखक माने जाते हैं। वह डॉक्टर बनना चाहते थे। उन्होंने जापान जाकर मेडिसिन की पढ़ाई शुरू की, ताकि चीन के बीमार और गरीब लोगों की सेवा कर सकें। एक दिन उन्होंने क्लास में एक विडियो देखा, जिसमें एक चीनी नागरिक को जापानी नागरिक अपमानित कर रहे थे। वहां खड़े चीनी लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। यह देखकर लू शुन को महसूस हुआ कि चीन की सबसे बड़ी बीमारी मन और आत्मा की गुलामी है। उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दिया और कहा, 'अगर मैं दवा से लोगों की जान बचा भी लूं, लेकिन यदि उनकी आत्मा मरी हुई है, तो इसका क्या लाभ?' उन्होंने ठान लिया कि कलम से ही वह लोगों की अंतरात्मा को जगाएंगे। इसके बाद लू शुन ने लेखन शुरू किया। उनकी सबसे पहली पुस्तक 'Call to Arms (Nahan)' 1923 में प्रकाशित हुई। इस कहानी संग्रह से उन्होंने साहित्य की दुनिया में प्रवेश किया। उनकी कहानियां क्रांतिकारी थीं, जिनमें समाज की गहराइयों तक झांकने की शक्ति थी। उनकी कहानियां आम लोगों की पीड़ा और शोषण को उजागर करती थीं। इस पुस्तक का पहला संस्करण पेइचिंग के 'नई संस्कृति आंदोलन' के दौर में आया था, जब चीन एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था।

Subrata Dhar

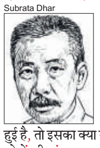

संकलन : **रिंकल शर्मा**

### रूस के साथ भारत के संबंध अगर चीन संग भी बेहतर होते हैं तो मुश्किल में पड़ जाएगा अमेरिका

# अमर, अकबर, एंथनी जैसी होगी ये तिकड़ी

आशीष शुक्ला

AI Image

**धमकी में कितना दम?**
- ट्रंप टैरिफ से भारत को ज्यादा नुकसान नहीं
- संभावित नुकसान की भरपाई के कई उपाय हैं
- दूसरी धुरी उभरी तो बढ़ जाएगा अमेरिका का सिरदर्द

**अमेरिका भारत** पर गुरुवार से व्यापार में 25% और टैरिफ लगाने वाला है। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत अगर रूस से तेल और हथियार खरीदना जारी रखता है तो टैरिफ और अधिक हो सकता है। मंगलवार को अपनी धमकी दोहराते हुए उन्होंने 24 घंटे के अंदर टैरिफ बढ़ाने की बात कह दी। भारत में स्वाभाविक ही इससे चिंता है। सवाल है कि ट्रंप अपने कहे पर अड़े रहे तो क्या होगा?

**सच्चा दोस्त ।** पहले रूस की बात कर लें। भारत अपना 85% तेल आयात करता है। इसका 35% फिलहाल वह रूस से ले रहा है। सोचिए, आज का भारत किस पर आश्रित है? यह उस मुल्क पर आश्रित है, जो आपकी शर्तों पर तेल मुहैया करवाता है। पैसे भी आपकी ही करंसी में लेता है। जहां तक हथियारों का सवाल है, हमने हमेशा रूस की उंगली थामी है। क्यों? क्योंकि वह उसकी तकनीक भी साझा करता है। अमेरिका की तरह इससे इनकार नहीं करता। ऑपरेशन सिंदूर में हम S400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तारीफ कर रहे थे ना, यह रूस से ही भारत को मिला है। फिर मिसाइल हों, टैंक हों, Made in India में भारत के साथ कंधे से कंधा मिला कर रूस खड़ा है।

**सैंक्शंस की धमकी ।** अमेरिका कहता है ऐसे दोस्त को छोड़ दो। भला क्यों? क्योंकि व्यापार में भारत को अमेरिका 44 बिलियन डॉलर (सरप्लस ट्रेड) का फायदा देता है। भारत के साथ अमेरिका का फिलहाल व्यापार करीब 132 बिलियन डॉलर का है। वह कहता है 2030 तक इसे 500 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देंगे। आशय यह है कि अगर बात मान ली, तो शायद टैरिफ की मार हलकी हो जाए। नहीं तो लगेंगे सैंक्शंस।

**पर्दे के पीछे का खेल ।** जहां तक रूस से तेल खरीदने का सवाल है, भारत इससे समझौता नहीं करेगा। रूस से तेल भी आएगा और हथियार भी। भारत पर सैंक्शंस तब लगेंगे जब पहले रूस पर नए सैंक्शंस लगें। अभी ट्रंप डांवाडोल हैं। एक-आध दिन में उनके विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मॉस्को में होंगे। पर्दे के पीछे दोनों महाशक्तियां एक दूसरे से उलझना नहीं चाहतीं।

**नौकरियों पर संकट ।** जहां तक 25% टैरिफ का सवाल है, इससे सबसे अधिक नुकसान गुजरात के हीरे-जवाहरात के व्यापारी, झींगा के आयात में लगे आंध्र प्रदेश और ओडिशा के सौदागरों को होगा। हजारों की तादाद में नौकरियां जा सकती हैं।

**मुमकिन है भरपाई ।** इस नुकसान की भरपाई करने के कई तरीके हैं। एक तरीका छोटे उद्योगों को पांच साल तक ब्याज से मुक्त राशि निर्यात के लिए देकर हो सकता है। जो हमारा सर्विस सेक्टर है, उसकी निर्यात की राशि फिलहाल विश्व में 336 बिलियन डॉलर की है। इसमें अमेरिका का योगदान सिर्फ 14% है। यहां गुंजाइश है क्योंकि ये टैरिफ के बाहर है।

**ना तुम जीते, न हम हारे ।** दूसरा उपाय यह हो सकता है कि भारत अमेरिका से ज्यादा सामान खरीदे। वह उस पर कम टैरिफ लगाकर ट्रंप को छाती ठोंकने का मौका भी दे सकता है। ये सेक्टर व्हिस्की, ऑटो आदि हो सकते हैं। जिन खाद्य पदार्थों पर हम 64% तक का टैरिफ लगाते हैं, जैसे बादाम, पिस्ता, दालें, कपास, सेब वगैरह-वगैरह, उन्हें कम कर सकते हैं। बदले में अगर वह भारत पर टैरिफ 25% से घटा देते हैं तो इससे 'ना तुम जीते, ना हम हारे' वाला समीकरण बन सकता है।

**टैरिफ का असर ।** वैसे इस 25% टैरिफ को लेकर कुछ ज्यादा ही हाय-तौबा मची है। इससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टैरिफ इतना लगा तो देश की विकास दर 6.5 से घटकर 6.2% रह जाएगी। भारत और अमेरिका के संबंधों की उम्र भी ट्रंप की अवधि से आगे जानी है। और जिस तरह का ट्रंप का व्यक्तित्व है, यह 25% कोई पत्थर की लकीर नहीं है।

**भारत के लिए मौका ।** भारत के लिए अपना घर ठीक करने का यह उपयुक्त मौका है। भारत को उन सेक्टरों पर ध्यान देना होगा, जिनके लिए विश्व को हमेशा उसकी जरूरत रहे। चीन ने ऐसा ही किया था। उसने 1990 से ही लिथियम और कोबाल्ट का खनन अफ्रीका और दक्षिणी अमेरीकी मुल्कों में शुरू किया। उसने उन टेक्नॉलजी पर ध्यान देना शुरू किया, जिसकी जरूरत तेजी से बदल रहे विश्व को पड़ने वाली थी। आज चाहे सौर विद्युत वाहन हों या दुर्लभ पृथ्वी खनिज (रेयर अर्थ मटीरियल) इसमें चीन की जरूरत पड़ती है। विश्व की 80% सामान्य दवाएं चीन के निर्यात किए गए कंपाउंड से बनती हैं। अमेरिका के F-35 जेट भी चीनी अलॉय से मिल के बनते हैं।

**संभावनाएं कम नहीं ।** भारत को भी अपनी सोच आगे की रखनी होगी। टेक्नॉलजी में कुछ ऐसा खेल करना पड़ेगा जिससे भारत का दबदबा विश्व व्यापार में रहे। कई ऐसे सेक्टर हैं जिनमें काफी संभावनाएं हैं। समुद्री उत्पाद, कपड़े और पर्यटन में ग्रोथ की की काफी गुंजाइश है।

**वैकल्पिक तिकड़ी ।** पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने एक बार कहा था- अमेरिका से दुश्मनी भारी होती है और दोस्ती जानलेवा। भारत के लिए चीन से संबंधों में सुधार अच्छा कदम है। विश्व के मानचित्र पर एक नजर डालें तो पता चल जाएगा कि रूस, चीन और भारत कितने बड़े देश हैं। ये अगर एक साथ हों, तो एक नए विश्व की संरचना संभव है।

*(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं)*

# न नौ मन तेल होगा...

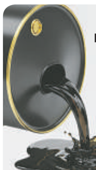

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप पाक के ऑयल रिजर्व को डिवेलप करने जा रहे हैं। उनकी उम्मीदों का आलम देखिए, उन्हें भरोसा है कि एक दिन भारत भी पाकिस्तान से तेल खरीदेगा! क्या उनकी इस उम्मीद के पीछे कोई ठोस वजह है, किन देशों के पास है कच्चे तेल का भंडार और उनके बीच कहां खड़ा होता है पाकिस्तान, एक नजर डालते हैं :

### तेल भंडार में दुनिया के सबसे अमीर देश

| | |
|---|---|
| 303 | वेनेजुएला |
| 267 | सऊदी अरब |
| 209 | ईरान |
| 168 | कनाडा |
| 145 | इराक |
| 113 | UAE |
| 101.5 | कुवैत |
| 80 | रूस |
| 48.4 | लीबिया |

*बिलियन बैरल

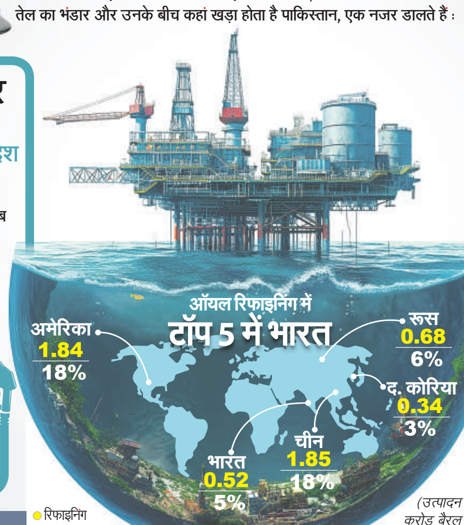



### ग्लोबल प्रॉडक्शन में US सबसे आगे

| | *रिफाइनिंग | वैश्विक हिस्सेदारी |
|---|---|---|
| अमेरिका | 2.01 | 21% |
| सऊदी अरब | 1.09 | 11% |
| रूस | 1.08 | 11% |
| कनाडा | 0.59 | 6% |
| ईरान | 0.59 | 5% |

(उत्पादन करोड़ बैरल प्रतिदिन में)

### अरब सागर में बड़ा भंडार, असम सबसे पुराना

**1889** में असम के डिगबोई में खोजा गया था पहला तेल भंडार

**1974** में बॉम्बे हाई में तेल मिला, सबसे बड़ा offshore तेल क्षेत्र

### इमरान नाकाम हो चुके, अब ट्रंप की बारी!

**2019** में अरब सागर में Kekra-1 नाम के तेल और गैस कुंए में ड्रिलिंग की गई

**5643** मीटर तक खुदाई के बाद भी कोई तेल भंडार नहीं मिला, बस पानी हाथ लगा

बलूचिस्तान में अशांति के चलते पाकिस्तान में ऑयल रिजर्व डिवेलप करना अमेरिका के लिए भी आसान नहीं। वैसे भी बड़ा तेल भंडार मिलने भर से इकॉनमी को बूस्ट मिल जाए, जरूरी नहीं। वेनेजुएला का उदाहरण सामने है। यह दूर की कौड़ी है कि पाकिस्तान में तेल भंडार मिले और अमेरिकी मदद से वहां बड़ी रिफाइनरी भी बन जाए। - **समीर रस्तोगी, डायरेक्टर, सक्षम वेल्थ**

### भारत के पास कितना तेल

**651.8** मिलियन मीट्रिक टन क्रूड ऑयल का भंडार

**1,138.6** बिलियन घन मीटर प्राकृतिक गैस का भंडार

**7.3** लाख बैरल क्रूड ऑयल उत्पादन होता है प्रतिदिन

**20** से 30 साल की जरूरत पूरी हो सकती है देश की

**7** सबसे बड़ा निर्यातक रिफाइंड पेट्रो प्रॉडक्ट्स का

**1%** जरूरत दुनिया की भारत से पूरी होती है

**85%** तेल अपनी जरूरत का, भारत बाहर से मंगाता है। इसके बावजूद यह ऑयल रिफाइनिंग का बड़ा हब है

### अब नजर पाकिस्तान पर

**35.3** करोड़ बैरल तेल भंडार प्रमाणित तौर पर मौजूद है

**0.021%** हिस्सा दुनिया के तेल भंडार में पाकिस्तान का

**52** नंबर है ऑयल रिजर्व के मामले में वैश्विक स्तर पर

**5.56** लाख बैरल तेल की खपत हर दिन है पाकिस्तान में

**2** साल से भी कम समय चलेगा पाकिस्तान का तेल भंडार

**0.07%** ऑयल प्रॉडक्शन में योगदान पाक का

**यह तेल निकालना भी है मुश्किल...**
- सुरक्षा के खराब हालात और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी
- अभी केवल 5 लाख बैरल तेल रिफाइन कर पा रहा

कंटेंट : **शैलेंद्र पांडेय**, ग्राफिक : **उमेश कुमार**

# मोहब्बत में नहीं है फ़र्क़ जीने और मरने का

पारोमिता वोहरा

AI Image

## कॉमन रूम

**ऑफिस से** देर रात काम खत्म करने के बाद हम कैब का इंतजार कर रहे थे। तभी मैंने अपनी दो सहयोगियों से पूछा, 'क्या प्यार अब फैशन में नहीं रहा?' उनमें से एक 50 साल की शादीशुदा थी और दूसरी 25 साल की युवा, जो रिलेशनशिप में थी। युवा सहयोगी ने तपाक से जवाब दिया, 'हां, मैं जिन लोगों को जानती हूं, उनमें तो प्यार का फैशन चला गया है। अब कोई भी प्यार की बात नहीं करता। लोगों का कहना है कि प्यार बड़ी अजीब शै है।'

हमने उस युवा साथी से कहा, 'प्यार अजीब ही होता है, यह बात तो एकदम सही कही तुमने!' लेकिन आज हमारे लिए प्यार की नई कल्पना करना मुश्किल क्यों हो गया है? शायद इसकी वजह यह है कि जिस प्यार को अजीब कहा जा रहा है, उसमें अजीब का अर्थ बदल चुका है। अजीब का अर्थ है- जब कोई खुलकर किसी से चाहत का इजहार करता है और इस तरह खुद को ठुकराए जाने का खतरा मोल लेता है। लेकिन आज की ऑनलाइन दुनिया में अब इसका कोई मतलब नहीं है।

मेरे पास एक उदाहरण है, 26 साल के फोटोग्राफर का जिसका नाम है जे। उसने एक स्प्रेडशीट बनाई है, जिस पर उन लोगों की जानकारी दर्ज है, जिनके साथ उसके रिलेशनशिप में जाने की आशा है। वह Gay है। खैर, उस स्प्रेडशीट में अलग-अलग कॉलम हैं- लोगों के नाम, उनमें जे की कितनी दिलचस्पी है और सामने वाला इंसान किस तरह के रिश्ते के लिए ठीक हो सकता है - कैजुअल, थोड़ा स्थायी या फिर बस देखने लायक। इस स्प्रेडशीट की बात सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन इससे कम से कम यह बात तो जाहिर होती है कि विकल्पों की कमी नहीं होती और अघगर एक ही रिश्ते में सब कुछ झोंक न दें तो दिल टूटने से भी बचा रह सकता है।

पुराने दिनों में लोग प्यार में नहीं पड़ते थे, क्योंकि तब अरेंज मैरिज का चलन था। आज लोग इसलिए प्यार नहीं कर रहे ताकि डेटिंग के खेल में बने रह सकें।।

इन्हीं के बीच नए शो और फिल्मों की एक सीरीज पुरानी यादें ताजा कर रही है। 'Sex and the City : And Just Like That' को ही लीजिए। जो लोग इस शो की लोकप्रियता के दौर में अपनी 20s में थे, उन्हें इसके नए संस्करण से निराशा हुई है। लेकिन इस शो की सबसे खास बात यही है कि यह हर तरह के प्यार को खुलकर स्वीकार करता है। इसी सिलसिले में Lena Dunham के नए शो 'Too Much' का भी जिक्र लाजिमी है। यह शो बताता है कि इंसान के लिए प्यार ही आखिरी तलाश है।

दूसरी ओर, सैयारा जैसी फिल्मों की चौंकाने वाली सफलता समर्पण और पीड़ा के अतीत की वापसी लगती है। ज्यादातर प्रशंसक इस बात पर सहमत हैं कि, 'यह अजीब है, लेकिन हमें अभी अजीब चाहिए।' हम 'सैयारा' और 'एनिमल' के संवाद की कल्पना भी कर सकते हैं। शायद इन फिल्मों की कहानियों की कमियां रिश्तों में बढ़ती कड़वाहट की ओर इशारा कर रही हों। शायद हम इनका संदेश भी पढ़ सकें कि जिस दौर में हर रिश्ते को तौला जा रहा है, उसमें फिर से गहरी तड़प वाले प्यार की दरकार है।

*(लेखिका 'एजेंट्स ऑफ इश्क' की संस्थापिका हैं)*

THE SPEAKING TREE

और पढ़ने के लिए देखें www.speakingtree.nbt.in

# असफलता अंत नहीं, सफल होने की शुरुआत है

मुकुंदानंद स्वामी

**असफलता अंत** नहीं, नई शुरुआत का अवसर है। यह हमें भीतर से संवारती है, हमारी सोच बदलती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जब हम आशा और विश्वास के साथ हर चुनौती का सामना करते हैं, तो जीवन में चमत्कार अवश्य होते हैं।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

विकास और प्रगति की राह में असफलता का सामना करना स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह जीवन का ऐसा चरण है, जिससे हर कोई गुजरता है। हालांकि असफलता निराशाजनक लग सकती है, लेकिन इसका उज्ज्वल पक्ष भी है। यह हमें सीखने, समझने और आत्ममंथन करने का अमूल्य अवसर देती है।

जीवन की हर सफलता, असफलताओं की मजबूत नींव पर खड़ी होती है। जब हम किसी कार्य में सफल नहीं हो पाते, तो यह हमारे लिए आत्म-विश्लेषण का समय होता है। यही आत्ममंथन हमें बताता है कि कहां चूक हुई, क्या सुधार किया जा सकता है, और अगली बार कैसे बेहतर परिणाम पाया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर, महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब के आविष्कार के लिए 4000 से अधिक प्रयोग किए। उन्होंने असफलता को निराशा के रूप में नहीं, बल्कि सीखने के एक चरण के रूप में लिया।

समस्याएं और कठिनाइयां हमारी दुश्मन नहीं होतीं, ये हमें हमारी सीमाओं का आभास कराती हैं और उनसे बाहर निकलने की प्रेरणा देती हैं। जब हम जूझते हैं, तो न केवल बेहतर परिणाम पाते हैं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध होते हैं। इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा है, जहां महान हस्तियों ने असफलता के बाद नई ऊंचाइयां प्राप्त कीं। आइंस्टाइन के बारे में बचपन में कहा गया था कि 'यह जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा', और वह आधुनिक विज्ञान की नींव बन गए। मीरा बाई को तमाम कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, पर उन्होंने अपने दुखों को ईश्वर भक्ति में बदल दिया और आध्यात्मिक महानता प्राप्त की।

असफलता हमें यह भी सिखाती है कि स्थायी सुख केवल भौतिक उपलब्धियों से नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन से मिलता है। जब हम केवल बाहरी सफलता को लक्ष्य बनाते हैं, तो समस्याएं हमें तोड़ सकती हैं। लेकिन यदि हम आत्मिक विकास को प्राथमिकता दें, तो हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने का साधन बन जाती है।

देवर्षि नारद कहते हैं कि हर प्रतिकूलता में कोई न कोई दैवीय वरदान छिपा होता है। जब हम कठिनाइयों को प्रभु का संदेश समझ कर स्वीकार करते हैं, तो न केवल हम उनमें छुपे अवसरों को पहचानते हैं, अपने जीवन को भी एक उच्चतर उद्देश्य की ओर ले जाते हैं।

असफलता से घबराना नहीं चाहिए। यह जीवन का एक अध्याय है, अंत नहीं। यदि हम इससे मिली सीखों को अपनाते हुए आगे बढ़ें, तो असफलता ही हमें सफलता के शिखर तक पहुंचाने वाली सीढ़ी बन सकती है।

**आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957** स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वारा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबई: (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। **स्थानीय संपादक (मुंबई) : सुंदर चंद ठाकुर** (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व **रायगढ़** जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

Machine Translated by Google


## धमकाने की रणनीति

### भारत अमेरिका या यूरोपीय संघ को अपने व्यापार साझेदारों के चयन का निर्णय लेने की अनुमति नहीं दे सकता

ए महीनों की काफी सहनशीलता के बाद, सोमवार को विदेश मंत्रालय (MEA) का बयान, भारत को "लक्षित" करने के लिए अमेरिका और यूरोपीय संघ (EU) के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में महत्वपूर्ण है। यह बयान श्री ट्रम्प द्वारा भारत के खिलाफ दंडात्मक शुल्क की घोषणा के दो घंटे बाद आया, जो रूसी तेल के आयात, प्रसंस्करण और बिक्री के लिए इस सप्ताह लागू होने वाली मौजूदा 25% दर से "काफी" अधिक है। एक दिन पहले, ट्रम्प के एक वरिष्ठ सहयोगी ने भारत पर यूक्रेन में रूस के युद्ध को "वित्तपोषित" करने का आरोप लगाया था। और 18 जुलाई को, यूरोपीय संघ ने भारत के वाडिनार संयंत्र (आंशिक रूप से रूसी स्वामित्व वाले) पर प्रतिबंधों की घोषणा की थी, और माध्यमिक प्रतिबंध जो भारतीय संयंत्रों को प्रभावित करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये उपाय "अनुचित और अनुचित" थे क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय संघ एलएनजी, महत्वपूर्ण खनिजों और परमाणु ईंधन आवश्यकताओं सहित वस्तुओं के लिए रूस के साथ व्यापार करना जारी रखते हैं बयान में यह भी कहा गया है कि वैश्विक बाजारों को स्थिर करने के लिए भारत को रूसी तेल खरीदते रहने के लिए अमेरिका ने ही प्रोत्साहित किया था, जिसकी पुष्टि बाइडेन प्रशासन ने भी की थी। सरकार ने कहा कि पश्चिमी देशों की तुलना में, यूक्रेन में संघर्ष के परिणामस्वरूप भारत की रूसी तेल खरीद एक "महत्वपूर्ण राष्ट्रीय मजबूरी" है, और कहा कि भारत "... अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करेगा"। विदेश मंत्रालय का बयान यूक्रेन संघर्ष के बाद इस मुद्दे पर पहली स्पष्ट प्रतिक्रिया है।

7 अगस्त से भारत पर 25% पारस्परिक कर लगाने की अमेरिकी घोषणा पर पिछले हफ्ते केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बयान को ध्यान में रखते हुए, सोमवार का बयान आव्रजन, व्यापार वार्ता, ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान, और भारत की ब्रिक्स सदस्यता सहित भारत के खिलाफ अमेरिका के बढ़ते आक्रामक रुख से नई दिल्ली की बढ़ती हताशा को दर्शाता है। यह स्पष्ट नहीं है कि सरकार श्री ट्रम्प की धमकाने वाली रणनीति का कैसे और किस हद तक सामना करने के लिए तैयार है। श्री गोयल ने कहा कि अमेरिका ने 7 अगस्त से भारत पर 25% पारस्परिक कर लगाने की घोषणा की है, और यह भी कि सोमवार का बयान भारत के खिलाफ अमेरिका के बढ़ते आक्रामक रुख से नई दिल्ली की बढ़ती हताशा को दर्शाता है।

ट्रम्प ने मंगलवार को कहा कि भारत एक "अच्छा व्यापारिक साझेदार" नहीं रहा है - यह संभवतः व्यापार वार्ता और एक छोटे समझौते की विफलता का संदर्भ था, जो कृषि बाजार पहुंच, डेयरी उत्पादों और जीएम खाद्य पदार्थों पर भारत के प्रतिरोध के कारण हुआ था।

हालाँकि यह आशा की जाती है कि नई दिल्ली वाशिंगटन और ब्रुसेल्स के साथ अपनी-अपनी व्यापार वार्ता को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत जारी रखेगी, विदेश मंत्रालय का बयान एक व्यापक मुद्दे पर ज़ोर देता है। न तो अमेरिका और न ही यूरोपीय संघ यह तय कर सकता है कि भारत किस देश के साथ साझेदारी करेगा या व्यापार करेगा। इस साल के अंत में रूसी राष्ट्रपति की भारत यात्रा की तैयारी के लिए सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री एस. जयशंकर की मास्को यात्राओं से यह संदेश स्पष्ट हो रहा है। भारत की संप्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता और उसकी विदेश नीति के विकल्पों में दूसरे देश हेरफेर नहीं कर सकते, चाहे उनके भारत के साथ कितने भी महत्वपूर्ण संबंध क्यों न हों।

## खतरनाक मोड़

### ट्रम्प को यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए कूटनीति पर कायम रहना होगा

पी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की घोषणा कि उन्होंने "दो परमाणु पनडुब्बियों" का आदेश दिया है पूर्व रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव के "भड़काऊ बयानों" के जवाब में, "उचित क्षेत्रों में तैनात की जाने वाली नावें" अमेरिका-रूस संबंधों में एक खतरनाक मोड़ का संकेत देती हैं, जिसे रिपब्लिकन नेता ने पिछले साल के अंत में अपने चुनाव से पहले सुधारने का वादा किया था। श्री मेदवेदेव, जो अब रूसी सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष हैं, ने कहा था कि रूस पर टैरिफ लगाने की श्री ट्रम्प की धमकियाँ "युद्ध की ओर एक कदम" थीं। श्री ट्रम्प ने यह स्पष्ट नहीं किया कि उन्होंने परमाणु हथियारों से लैस अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें दागने में सक्षम पनडुब्बियाँ भेजी हैं या पारंपरिक हथियारों से लैस परमाणु-शक्तिशाली नावें। हाल के हफ़्तों में, श्री ट्रम्प ने यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के प्रति बढ़ती निराशा व्यक्त की है। शुरुआत में, उन्होंने श्री पुतिन को युद्ध समाप्त करने या अमेरिकी टैरिफ का सामना करने के लिए 50 दिनों की समय सीमा दी थी। 29 जुलाई को, इसे घटाकर 10 से 12 दिन कर दिया गया। श्री ट्रम्प ने द्वितीयक "दंड" की भी धमकी दी है। इसमें भारत और चीन जैसे रूस के साथ व्यापार करने वाले देशों पर भी ध्यान दिया गया है।

श्री ट्रम्प की हताशा समझ में आती है। उन्होंने यूक्रेन पर युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार करने का दबाव डाला। उनके रक्षा सचिव ने सार्वजनिक रूप से कहा कि यूक्रेन को नाटो में शामिल नहीं किया जाएगा। फिर भी, वे श्री पुतिन से ज़्यादा से ज़्यादा काला सागर में एक सीमित युद्धविराम और यूक्रेनी बुनियादी ढाँचे पर हमलों पर अस्थायी रोक लगवाने में कामयाब रहे।

इस गतिरोध के मूल में पश्चिमी राजधानियों और मास्को में युद्ध को समाप्त करने के तरीकों पर अलग-अलग विचार हैं। जहाँ पश्चिमी नेता तत्काल युद्धविराम पर ज़ोर दे रहे हैं, वहीं मास्को का मानना है कि यह एक व्यापक शांति समझौते का हिस्सा होना चाहिए जो उसकी मुख्य सुरक्षा चिंताओं, जिनमें नाटो का पूर्व की ओर विस्तार भी शामिल है, को संबोधित करे। रूस को भी ऐसे समय में तनाव कम करने का कोई ख़ास प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है जब उसके सैनिकों के पास रणनीतिक गति है। यूक्रेन ने कई रूसी शहरों पर घातक ड्रोन हमले किए हैं, लेकिन युद्धक्षेत्र में, उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके अलावा, श्री ट्रम्प द्वारा इज़राइल की ओर से ईरान पर बमबारी करने के फ़ैसले ने, ऐसे समय में जब ईरान तकनीकी रूप से अमेरिका के साथ बातचीत कर रहा था, रूस के रुख को और कड़ा कर दिया है। फिर भी, कूटनीतिक असफलताएँ परमाणु हथियार लहराने का बहाना नहीं हैं। आज दुनिया अमेरिका और रूस के बीच सीधा टकराव बिल्कुल नहीं चाहती। संकट को बढ़ाने के बजाय, श्री ट्रम्प को इस बात पर विचार करना चाहिए कि अमेरिका का वर्तमान दृष्टिकोण - रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को यूक्रेन के लिए सैन्य समर्थन के साथ जोड़ना - श्री ट्रम्प को रोकने में विफल क्यों रहा है।

पुतिन। कूटनीति की ओर उनका शुरुआती रुख़ सही दिशा में उठाया गया एक कदम था। उन्हें अपने रास्ते पर बने रहना होगा और युद्ध समाप्त करने के मामले में पश्चिमी और रूसी रुख़ के बीच की खाई को कम करना होगा।

# भू-राजनीति के टूटे हुए ढांचे के बीच भारत की उपस्थिति

टीएस तिरुमूर्ति
पूर्व है
राजदूत/
स्थायी
इसका प्रतिनिधि
भारत से संयुक्त राष्ट्र
नेशंस, न्यूयॉर्क और पूर्व सचिव,
विदेश मंत्रालय
एयर्स, नई दिल्ली

मैं ऐसे समय में जब वैश्विक भू-राजनीति नए सिरे से गढ़ी जा रही है, भारत के लिए अपनी ताकत दिखाने और अपनी वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने का समय आ गया है। लेकिन, अभी तक, यह भारत के रास्ते पर नहीं बढ़ रहा है।

ऑपरेशन सिंदूर एक वास्तविकता की जाँच थी जब भारत के कई रणनीतिक साझेदार संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों और आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाने को तैयार नहीं थे। अब यह ज्ञात है कि पहलगाम हमले (22 अप्रैल, 2025) के तीन अपराधी, जिन्हें हाल ही में मार गिराया गया, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी थे।

हालांकि पाकिस्तान में आतंकी शिविरों के खिलाफ भारत की जवाबी कार्रवाई निर्णायक थी, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा बार-बार यह दावा किए जाने के कारण कि उन्होंने ही व्यापार को हथियार के रूप में इस्तेमाल करके युद्धविराम करवाया था, भारत को यह बात कहने में कठिनाई हुई - हाल ही में संसदीय बहस में सरकार ने इस दावे का खंडन किया।

एक अप्रिय मोड़ तब आया जब पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर को ऑपरेशन सिंदूर के बाद श्री ट्रम्प के साथ लंच पर आमंत्रित किया गया। हालाँकि, अमेरिका ने पहलगाम हमले की ज़िम्मेदारी लेने वाले द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) और विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (SDGT) घोषित कर दिया। और एक स्वागत योग्य मान्यता के रूप में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की निगरानी टीम की रिपोर्ट में भी पहलगाम हमले के लिए TRF का नाम लिया गया।

ट्रम्प द्वारा निर्मित बाधाओं वाला मार्ग लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। जिस ऐतिहासिक दिन NISAR उपग्रह (भारत-अमेरिका सहयोग) का प्रक्षेपण हुआ, उसी दिन श्री ट्रम्प ने भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया।

हालांकि, उन्होंने एक विशुद्ध व्यापारिक मुद्दे को, जिसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, भू-राजनीतिक मुद्दा बना दिया और भारत को धमकी दी कि जब यूक्रेन के लोग "रूसी युद्ध मशीन" द्वारा मारे जा रहे हैं, तब वह रूसी तेल आयात करने पर शुल्क में "काफी" वृद्धि करेगा। भारत को विशेष रूप से तब परेशान किया जा रहा था जब श्री ट्रम्प स्वयं अमेरिका-रूस संबंधों में सुधार के प्रबल समर्थक हैं।

हालांकि इसे ट्रम्प-शैली का अंतिम क्षण का दबाव कहकर खारिज किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने पहले ही अमेरिकी कंपनियों से भारत में निवेश न करने, बल्कि केवल अमेरिका में निवेश करने तथा केवल अमेरिकियों को ही नौकरी पर रखने का आह्वान किया है।

यह घटना अमेरिका द्वारा अपने हिंद-प्रशांत सहयोगियों और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ किए गए सुरक्षा और व्यापार समझौतों के बाद हुई है। अमेरिकी तकनीकी दिग्गज एनवीडिया को अमेरिका ने चीन को अपने एच20 एआई चिप्स की बिक्री फिर से शुरू करने की अनुमति दे दी है, जिसे पहले राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं के कारण रोक दिया गया था। चीन को यह सौदा पूरा करने के लिए और समय दिया गया है।

यूक्रेन और पश्चिम एशिया में उलझने के बाद अमेरिका का ध्यान पूर्वी एशिया पर कम हो गया है।

नतीजतन, अगर पूर्वी एशिया पर अमेरिका और चीन के बीच व्यापक भू-राजनीतिक समझ बनती है, तो इससे भारत के लिए जगह कम हो जाएगी। पूर्वी एशियाई देश पहले से ही अपनी बाजी लगाने की तैयारी में हैं।

दक्षिण एशिया पर अमेरिका के रुख़ से भी कोई मदद नहीं मिली है। अमेरिका-पाकिस्तान के बढ़ते रिश्ते फिर से एक परेशानी बन गए हैं। भले ही यह द्विपक्षीय संबंधों में एक नया मोड़ हो, लेकिन अमेरिका ने यह ज़रूर दिखाया है कि

**अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति को सही दिशा में ले जाने के लिए, भारत को अपनी भू-राजनीति को सही करने की आवश्यकता है**

आतंकवाद निरोधक प्रयासों और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए पाकिस्तान की प्रशंसा करके भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति आश्चर्यजनक असंवेदनशीलता।

बांग्लादेश में, शेख हसीना को सत्ता से बेदखल करने में अमेरिका ने भारतीय हितों के विरुद्ध जाकर मदद की थी। म्यांमार में, सैन्य सरकार का विरोध करने वाली ताकतों को अमेरिका और यूरोपीय देशों का समर्थन भारत के पूर्वोत्तर में अस्थिरता पैदा कर रहा है। गलवान और पहलगाम के बाद, क्षेत्रीय सुरक्षा हितों पर अमेरिका के साथ बेहतर समझ और समन्वय की भारत की उम्मीदें धूमिल हो गई हैं। आपसी विश्वास तेज़ी से कम हो रहा है।

अमेरिका के साथ मिलकर काम करते हुए यूरोपीय संघ भारत की आयात-आधारित ऊर्जा सुरक्षा को ऐसे समय में लक्ष्य बना रहा है, जब भारत, भारत-यूरोपीय संघ व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौते पर बातचीत कर रहा है।

यूरोपीय संघ ने भारत की वाडिनार रेनरी पर प्रतिबंध लगा दिया है, जहाँ रूसी रोज़नेफ्ट की बड़ी हिस्सेदारी है, यह अच्छी तरह जानते हुए कि भारत में रूसी तेल की आपूर्ति बंद होने से तेल की कीमतों पर भारी दबाव पड़ेगा। दूसरी ओर, हंगरी, स्लोवाकिया, बेल्जियम, स्पेन और अन्य कंपनियाँ पाइपलाइनों और एलएनजी के माध्यम से, छूट प्राप्त करके या मौजूदा अनुबंधों के तहत रूसी तेल का आयात कर रही हैं। यूरोप को रूसी एलएनजी निर्यात का 51% प्राप्त होता है। भारत पर यूरोपीय संघ का कार्बन सीमा कर और डिजिटल तथा अन्य व्यापार बाधाएँ अभी भी बनी हुई हैं। भारत को उम्मीद है कि हाल ही में संपन्न भारत-ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता (सीईटीए) यूरोपीय संघ को अपनी व्यापार वार्ताओं में अपनी माँगों को कम करने के लिए मजबूर करेगा।

चीन की चालें इन सबने चीन को एक बार फिर भारत के पड़ोस में सक्रिय होने का अवसर दे दिया है।

चीन ने भारत को बाहर रखने के लिए नए समूहों और नए समझौतों का प्रस्ताव रखा है। उदाहरण के लिए, 19 जून, 2025 को कुनमिंग में पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ चीन की बैठक में एक त्रिपक्षीय पहल को औपचारिक रूप देने का प्रस्ताव रखा गया था, लेकिन बांग्लादेश इस पर सहमत नहीं हुआ। चीन बांग्लादेश को सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास लालमोनिरहाट में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बने एक एयरबेस को पुनर्जीवित करने में भी मदद कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को व्यापक समर्थन दिया था।

चीन ने अरुणाचल प्रदेश के भीतर स्थानों के लिए मंदारिन नामों का भी मानकीकरण कर दिया है। और वह भारत से दलाई लामा की संस्था का भविष्य छीनना चाहता है। भारत के साथ भारी व्यापार अधिशेष का लाभ उठाकर, चीन भारत की महत्वपूर्ण आपूर्ति श्रृंखलाओं, जैसे दुर्लभ मृदा, उर्वरक, सक्रिय औषधि अवयव, सुरंग खोदने वाली मशीनें और तकनीकी कर्मियों को निचोड़ रहा है। इससे भी अधिक चिंताजनक तिब्बत में यारलुंग ज़ंग्बो (ब्रह्मपुत्र का तिब्बती नाम) पर चीन के सबसे बड़े बांध के निर्माण की योजना है, जो भारतीय सीमा के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया मालदीव यात्रा चीन के प्रभाव को देखते हुए समय पर हुई है।

एक अप्रत्याशित और यहां तक कि संतुलन के लिए अविश्वसनीय अमेरिका, अनुत्तरदायी यूरोपीय संघ और आक्रामक चीन के बीच, भारत एक कड़ा रुख अपना रहा है। गलवान संघर्ष के बाद समीकरणों को फिर से स्थापित करने के लिए उसने चीन के साथ संबंधों में मौजूदा सुधार को तेज़ करने को प्राथमिकता दी है - जबकि उसके बाद सीमा पर तनाव कम करने की कोई पहल नहीं हुई है।

अक्टूबर 2024 में प्रारंभिक विघटन।

इसके अलावा, भारत को अपने संविधान पर गंभीरता से पुनर्विचार करना चाहिए। वैश्विक संघर्षों के हाशिये पर बने रहने के लिए तैयार हैं। भारत, यदि खुले तौर पर इज़राइल का समर्थन नहीं करता है, तो भी, चल रहे इज़राइल-गाज़ा युद्ध पर काफ़ी हद तक चुप रहा है - जो एक बहुआयामी मानवीय त्रासदी है।

भारत हाल ही में हुए इज़राइल-ईरान संघर्ष और अमेरिकी बमबारी पर भी काफ़ी हद तक चुप रहा, जबकि दोनों युद्धरत पक्षों के साथ उसके गहरे संबंध हैं और खाड़ी में उसकी बड़ी हिस्सेदारी है। हालाँकि यूक्रेन संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र के मतदान में भारत ने सही ही भाग नहीं लिया, लेकिन विश्व संघर्षों पर सक्रिय रुख न अपनाने का उसका समग्र दृष्टिकोण उसके व्यापक हितों को नुकसान पहुँचा सकता है और जब तक वह किनारे पर रहेगा, तब तक उसके भू-राजनीतिक प्रभाव को कम कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत को दिखा दिया है कि अगर वह अपने संघर्षों और मुद्दों में अपने सहयोगियों की अधिक भागीदारी चाहता है, तो उसे उनके संघर्षों और मुद्दों में और अधिक शामिल होना होगा।

कुछ लोगों का तर्क है कि भारत को अपना सिर झुकाकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और एक बड़ी भू-राजनीतिक भूमिका उसके आर्थिक विकास को नुकसान पहुँचा सकती है। सच इसके विपरीत है। एक खंडित विश्व व्यवस्था में, भू-राजनीति, दबाव, धमकियाँ और संरक्षणवाद आर्थिक और तकनीकी परिणामों का निर्धारण कर रहे हैं - न कि सर्वाधिक पसंदीदा राष्ट्र या मुक्त व्यापार या विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित बहुपक्षीय व्यापार मानदंड।

इसलिए, अपनी आर्थिक और तकनीकी प्रगति को सही करने के लिए भारत को अपनी भू-राजनीति को सही करने की आवश्यकता है।

आगे की राह: यह समझते हुए कि भू-राजनीतिक दायरा सिकुड़ रहा है, भारत अंततः इससे मुक्त हो रहा है और उसने "लक्ष्यीकरण" पर आपत्ति जताई है। इसने अपने आर्थिक हितों की रक्षा की आड़ में अमेरिका और यूरोपीय संघ के दोहरे चरित्र की निंदा की है—यूरोपीय संघ 2024 में भारत की तुलना में रूस के साथ वस्तुओं और सेवाओं के बड़े व्यापार के लिए, और अमेरिका रूसी यूरेनियम, पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों के आयात के लिए। गाजा में युद्धविराम का भारत का आह्वान (दो महीने पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा के एक समान प्रस्ताव पर उसने मतदान में भाग नहीं लिया था), इस बात का एहसास है कि अपनी रणनीतिक स्वायत्तता को बनाए रखने के लिए उसे वैश्विक संघर्षों में मुखर होने की आवश्यकता है। अमेरिका के साथ विश्वास में कमी और अमेरिका-चीन समझौते का सामना करते हुए, भारत को संबंधों में और गिरावट को रोकने और श्री ट्रम्प को क्वाड शिखर सम्मेलन (भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया) के लिए भारत आने के लिए राजी करने के लिए जल्द ही एक भारत-अमेरिका व्यापार समझौता करने की आवश्यकता है।

श्री ट्रम्प के गुस्से के बाद, यह एक विवादास्पद मुद्दा है कि क्या भारत आरआईसी (रूस-भारत-चीन) को पुनर्जीवित करेगा। हालाँकि, ब्रिक्स (भारत में 2026 शिखर सम्मेलन), शंघाई सहयोग संगठन और पूर्वी एशिया (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी से चूकने के बाद) के साथ अधिक जुड़ाव भारत की बहु-संरेखण नीति को और मज़बूत करेगा और उन लोगों को पीछे धकेलेगा जो इसे बाधित करते हैं। अब भारत बस यूँ ही सिर झुकाकर, अपने आर्थिक मामलों पर ध्यान देकर विकास की उम्मीद नहीं कर सकता। वह ढाँचा अब टूट चुका है।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

# भारत के कल्याणकारी राज्य का तकनीकी गणित

अनमोल रतन सिंह
पंजाब स्थित नीति अनुसंधान थिंक टैंक, PANJ फाउंडेशन के सह-संस्थापक हैं

अगस्त्य शुक्ल
एक कार्यक्रम है
PANJ में सहयोगी
फाउंडेशन, एक
पंजाब स्थित नीति अनुसंधान थिंक टैंक

1,206 योजनाओं को एकीकृत किया गया एक अरब आधार नामांकन के साथ, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण प्रणाली और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 36 शिकायत पोर्टलों के साथ, भारत का कल्याणकारी दृष्टिकोण एक तकनीकी गणित में परिवर्तित हो रहा है। लीक पाइपलाइनों को दरकिनार करते हुए और छद्म लाभार्थियों को हटाकर, बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण प्रदान करने के वादे ने एक ऐसे 'पुनर्निर्माण' को जन्म दिया है जो 'लोकतांत्रिक मानदंडों' और 'राजनीतिक जवाबदेही' की कीमत पर 'गुणवत्ता' और 'कवरेज' प्रदान करता है।

क्या हम अधिकारों पर आधारित कल्याणकारी व्यवस्था के उदय को देख रहे हैं? क्या भारतीय डिजिटल कल्याणकारी राज्य एक व्यवस्थागत गतिरोध की ओर बढ़ रहा है? इस सब के पीछे तकनीकी गणित क्या है? हाल के खेल-सिद्धांत संबंधी शोध से पता चलता है कि तकनीकी शासन वहीं फलता-फूलता है जहाँ दल ध्रुवीकृत होते हैं। ज़ाहिर है, हमारे सवाल बदल गए हैं। हम "समर्थन का हकदार कौन है और क्यों?" से हटकर "हम लीकेज को कैसे कम करें और कवरेज को कैसे अधिकतम करें?" पर आ गए हैं। हमारे राजनेता, चाहे वे किसी भी दल के हों, संवैधानिक मूल्यों की जटिलताओं पर सवाल उठाए बिना, तर्कपूर्ण ढंग से कठिन विकल्पों को डेटा-संचालित एल्गोरिदम पर थोप रहे हैं।

हैबरमास की 'तकनीकी चेतना' और फूको की 'सरकारीता' को संदर्भ में रखते हुए, भारत का कल्याणकारी ढाँचा मापनीय, लेखापरीक्षित और अराजनीतिकरण युक्तिसंगतता द्वारा तेजी से आकार ले रहा है। ई-श्रम और पीएम किसान जैसी योजनाएँ एक-दिशात्मक, नवाचार-प्रधान तर्क को मूर्त रूप देती हैं जो सुव्यवस्थित, मापनीय और अस्पष्टता या त्रुटि के प्रति असहिष्णु है। इसके विपरीत, हमारे पास सहभागी नियोजन और स्थानीय प्रतिक्रिया के लिए सुविचारित आह्वान हैं जो लोकतांत्रिक सोच के लंबे समय से भुला दिए गए मूल को मूर्त रूप देते हैं, जो जियोर्जियो अगम्बेन की 'होमो सेकर' की अवधारणा - राजनीतिक एजेंसी से रहित जीवन - को प्रतिध्वनित करता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि समकालीन संदर्भ में, कल्याण, लोकतांत्रिक विचार-विमर्श का केंद्र नहीं रहा। सूक्ष्म स्तर पर, अधिकार-संपन्न नागरिक की जगह लेखापरीक्षा योग्य लाभार्थी ने ले ली है। इसलिए, राज्य को (एक रैंसीरियन अर्थ में) इस बात पर पुनर्विचार करने की तत्काल आवश्यकता है कि क्या वह यह तय कर रहा है कि कौन दृश्यमान है, कौन

**डेटा-संचालित एल्गोरिदम का उपयोग करके बड़े पैमाने पर सामाजिक कल्याण प्रदान करने का वादा 'लोकतांत्रिक मानदंडों' और 'राजनीतिक जवाबदेही' की कीमत पर हो सकता है।**

शिकायत कर सकते हैं, और जिनकी शिकायत गणना योग्य है। 'समाजवादी राज्य' के दावों के बावजूद, हम भारत के सामाजिक क्षेत्र के खर्च में एक दशक के निचले स्तर पर गिरावट देख रहे हैं, जो 2014-24 के औसत 21% से घटकर 2024-25 में 17% रह गया है। इसके अलावा, साधारण आँकड़ों से परे कुछ दिलचस्प अवलोकन भी हैं। प्रमुख सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं ने इस गिरावट का खामियाजा उठाया है, जहाँ अल्पसंख्यक, श्रम, रोजगार, पोषण और सामाजिक सुरक्षा कल्याण में 11% (कोविड-19 से पहले के चरण में) से 3% (कोविड-19 के बाद के चरण में) तक उल्लेखनीय गिरावट देखी गई।

समानांतर रूप से, सामाजिक टिप्पणीकार अक्सर टिप्पणी करते हैं सूचना का अधिकार (आरटीआई) व्यवस्था 'अस्तित्व के संकट' में है और आरटीआई पर पर्दा डालने वाली यह बात निष्क्रिय सूचना आयोगों की संस्था के भीतर एक गंभीर समस्या को उजागर करती है। 30 जून, 2024 तक, 29 सूचना आयोगों (आईसी) में लंबित मामलों की संख्या चार लाख को पार कर गई, और आठ सीआईसी पद रिक्त थे (सीआईसी की वार्षिक रिपोर्ट, 2023-24)।

भारतीय कल्याणकारी व्यवस्था को अपनी प्रतिक्रियाशीलता और स्थितप्रज्ञता की क्षमता पुनः प्राप्त करनी होगी, ये ऐसे तत्व हैं जो ग्राम सभाओं और अग्रिम पंक्ति के नौकरशाही विवेकाधिकारों के लिए विशिष्ट हैं। लोकतंत्र पर रैंसियर की आलोचना को उद्धृत करते हुए, हम एक प्रमुख आसन्न चिंता को उजागर करते हैं, कि "लोकतंत्र इस बात पर निर्भर करता है कि किसका मुकदमा दृश्यमान और विवादास्पद हो, न कि केवल गणना योग्य"। न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ के आधार असहमति (2018) में इस चिंता को और उजागर किया गया है, जिसमें पहचान के ऐसे संदर्भहीनीकरण के विरुद्ध सटीक चेतावनी दी गई है, जो नागरिकों को असंबद्ध, मशीनी आंकड़ों तक सीमित करने के विरुद्ध चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो देखभाल, संदर्भ या यहाँ तक कि संवैधानिक आश्वासन से भी रहित हैं।

कुछ मामलों में.

एल्गोरिथम अलगाव का एक और उदाहरण: एक और चिंताजनक प्रवृत्ति यह है कि केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CGR) द्वारा संघीय पदानुक्रमों को टिकट-ट्रैकिंग प्रणालियों में शामिल किया जा रहा है। हालाँकि यह टिकटों के समाधान और राज्य एजेंसियों के बीच शिकायतों को रूट करने की एक नई पहल है, लेकिन अनुभवजन्य आँकड़े बताते हैं कि 2022-24 के बीच लाखों शिकायतों का निपटारा किया गया। लेकिन गौर से देखने पर ऐसा लग सकता है कि यह सिर्फ़ दृश्यता को केंद्रीकृत कर रहा है, ज़िम्मेदारी को नहीं—यह एक तरह का एल्गोरिथम अलगाव है जो राजनीतिक जवाबदेही को और भी ज़्यादा मायावी बना देता है।

इन टिप्पणियों का उद्देश्य मूल्य को खारिज करना नहीं है ऐसी पहलों के बजाय, वे इस बात पर गहन चर्चा को आमंत्रित करते हैं कि कल्याणकारी शासन कैसे एक अधिक लचीले और उत्तरदायी राज्य के लिए विकसित हो सकता है। सरकार को अब 'लोकतांत्रिक एंटीफ्रैगिलिटी' की तर्ज पर सोचना चाहिए, ताकि सही डेटा और अपर्याप्त बुनियादी ढांचे पर निर्मित हमारी प्रणालियां तनाव के कारण विनाशकारी रूप से विफल न हो जाएं (तालेब की 'हाइपर-इंटीग्रेटेड प्रणालियों' पर विचार करें)।

हमें राज्यों को संदर्भ-संवेदनशील व्यवस्थाएं तैयार करने के लिए सशक्त बनाने की आवश्यकता है, जहां संघवाद और कल्याण बहुलवाद को एक विशेषता के रूप में बढ़ावा दें। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान और ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को शामिल करके, समुदाय-संचालित प्रभाव लेखापरीक्षाओं (जैसा कि संयुक्त राष्ट्र के विशेष प्रतिवेदक ने अत्यधिक गरीबी पर दोहराया है) को संस्थागत बनाना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सभी राज्यों को ऐसे मंच सहकारी समितियों का निर्माण करने में सक्षम बनाया जाना चाहिए जहाँ स्वयं सहायता समूह मध्यस्थ के रूप में कार्य करें; कार्यात्मक रूप से, केरल के कुदुम्बश्री से सबक सीखा जा सकता है। सामुदायिक जवाबदेही तंत्र को मजबूत करने के लिए नागरिक समाज को जमीनी स्तर पर राजनीतिक शिक्षा और कानूनी सहायता क्लीनिकों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अंत में, अब समय आ गया है कि हम डिजिटल शासन प्रणालियों के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार द्वारा प्रस्तावित "स्पष्टीकरण और अपील के अधिकार" को शामिल करके अपने स्वयं के फॉल-बैक तंत्र, मानव प्रतिक्रिया सुरक्षा उपायों और वैधानिक पूर्वाग्रह लेखापरीक्षाओं को मजबूत और संहिताबद्ध करें।

नागरिकों पर ध्यान केंद्रित करें । भारत के नागरिकों के रूप में, हमें यह समझना होगा कि लोकतांत्रिक विचार-विमर्श से रहित एक कल्याणकारी राज्य एक ऐसी मशीन है जो उन लोगों को छोड़कर, जिनकी मदद करने के लिए इसे बनाया गया है, सभी के लिए कुशलता से काम करती है। एक विकसित भारत के लिए, हमें डिजिटलीकरण को लोकतांत्रिक और कमज़ोर-विरोधी सिद्धांतों के साथ पुनर्निर्देशित करना होगा ताकि नागरिक शासन में भागीदार बनें, न कि केवल बहीखाते में प्रविष्टियाँ।

## संपादक के नाम चिठी

रूसी तेल और व्यापार के मुद्दे पर अमेरिका और भारत के बीच तनाव के बारे में पढ़कर बहुत दुख होता है। अमेरिका को एक बात समझनी चाहिए - अमेरिका का दुश्मन कोई और नहीं है । भारत का दुश्मन। इसके बावजूद, अगर अमेरिका भारत पर रूसी तेल का इस्तेमाल बंद करने का दबाव डालता है, तो भारत उसकी बात मान सकता है। लेकिन बदले में, अमेरिका को भी रियायती राशि चुकानी चाहिए।

रूस भारत को इसके लिए देता है तेल। यह पहली बार नहीं है जब अमेरिका भारत पर दबाव बना रहा है। कुछ साल पहले भी भारत को ईरान के तेल का कुल इस्तेमाल बंद करने के लिए इसी तरह दबाव डाला गया था। भारत जैसे ऊर्जा-खपत करने वाले देश के लिए, 1.4 अरब की आबादी वाले इस देश में, नीतियाँ बनाते समय उसके हितों को केंद्र में रखा जाना चाहिए। भारत को अपने हितों को आर्थिक और राजनीतिक रूप से संतुलित करना होगा।

आर भारती रवि वर्मा, पलानी, तमिलनाडु

संसद में चर्चा, असहमति, बहस और पूरी जानकारी के साथ निर्णय होना चाहिए, लेकिन अब हम जो देख रहे हैं वह इसके उद्देश्य की उपेक्षा है। वर्तमान सरकार के पास प्रधान मंत्री का पद है। यह जिम्मेदारी है कि हम समायोजन करें और चीजों को बिगड़ने न दें।

अय्यासेरी रवीन्द्रनाथ, अरनमुला, केरल

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • बुधवार • 6 अगस्त • 2025
www.rashtriyasahara.com



**अनमोल वचन**

*कर्म, ज्ञान और भक्ति-ये तीनों जहां मिलते हैं, वहीं सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ जन्म लेता है।*
-श्री अरविंद

## गिल-गंभीर युग का आगाज

भारतीय क्रिकेट अब रोहित और विराट के युग से आगे निकल कर गिल और गंभीर के युग में प्रवेश कर गई है। भारतीय युवा टीम ने इस कारनामे को शानदार ढंग से अंजाम दिया है। उन्होंने एंडरसन-तेंदुलकर टेस्ट सीरीज के ओवल में खेले आखिरी टेस्ट को जिस तरह से जीता है, उससे अहसास हो गया है कि टीम की कमान सही हाथों में है। सीरीज की शुरुआत से पहले रोहित शर्मा, विराट कोहली और अश्विन के संन्यास लेने पर कहा जा रहा था कि युवा टीम की यह मुश्किल परीक्षा है। पर इस यंग ब्रिगेड न सिर्फ इस परीक्षा को उम्दा अंदाज में पास किया है, बल्कि यह भी जता दिया है कि आने वाले दिनों में वह क्या करने वाले हैं। असल में

चौथे टेस्ट को जिस तरह हार के कगार से बचा कर टेस्ट ड्रा कराया और फिर ओवल टेस्ट को जीतने से टीम का डीएनए क्या है, यह पता चलता है। इस यंग टीम की सबसे बड़ी खूबी यह दिख रही है कि वह मुश्किल से मुश्किल हालात में भी समर्पण करने में विश्वास नहीं रखती। टीम की यह सोच टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। बहुत संभव है कि कप्तान शुभमन गिल से कुछ मौकों पर फैसलों में चूक हुई हो पर उन्होंने जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों को अपना बेस्ट देने के लिए प्रेरित किया और टीम को महत्त्वपूर्ण मौकों पर एकजुट रखा, उससे लगता है कि वह विराट और रोहित की तरह टेस्ट टीम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकते हैं। गिल इसलिए भी तारीफ के काबिल हैं कि उनकी सेना देशों में इससे पहले प्रदर्शन कोई बहुत अच्छा नहीं था और कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने पर उनका प्रदर्शन बिखर भी सकता था। पर उन्होंने अपने प्रदर्शन से हैरत में ही नहीं डाला बल्कि यह भी दिखाया कि कप्तानी का उनके ऊपर कोई दवाब नहीं है। इस सीरीज ने टेस्ट क्रिकेट को पांच दिनों का ही रखने की सोच को बल दिया है। असल में पिछले कुछ सालों में कई टेस्ट तीन-चार दिन में खत्म हो जाने पर टेस्ट मैचों को चार दिन का करने की चर्चा चलने लगी थी। पर इस सीरीज ने दिखाया कि दोनों टीमों में लड़ने का माद्दा हो और उन्हें अच्छे विकेट मुहैया कराए जाएं तो पांच दिनों तक टेस्ट में रोमांच बना रह सकता है। इस सीरीज के जिन चार टेस्ट मैचों में परिणाम निकला है, वे सभी चार दिन का टेस्ट होने पर ड्रा हो जाते। साथ ही, भारत और इंग्लैंड, दोनों ने ही बेहतरीन क्रिकेट खेल कर दिखाया कि टेस्ट क्रिकेट का कोई सानी नहीं है।

## सीमाओं का संज्ञान

लोक सभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए आपराधिक मानहानि के मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी जिस में गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दरम्यान सीमा पर भारतीय व चीनी सैनिकों के बीच झड़पों पर टिप्पणी की थी। अदालत ने सवाल किया आपको कैसे पता चला दो हजार किमी. भारतीय क्षेत्र पर कब्जा कर लिया गया है। कोर्ट ने पूछा कि क्या उनके पास सबूत है या आप वहां थे। अगर आप सच्चे भारतीय होते तो ये सब बातें नहीं करते। पीठ ने राहुल के सोशल मीडिया पर विचार व्यक्त करने पर भी प्रश्न चिह्न लगाया और संसद में अपनी बात रखने को कहा। गांधी का कहना है कि उनके भाषण संबंधी अपराधों के बीस से ज्यादा मामले चल रहे हैं, कई लोग उन्हें फंसाने की

फिराक में हैं। गांधी के खिलाफ यह मामला अगस्त, 2023 में लखनऊ मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष की गई थी जिसमें इसी मई में उन्हें सम्मन जारी किया गया था। कांग्रेस नेता का कहना कि उनका उद्देश्य सेना की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना नहीं था बल्कि यह सरकारी नीतियों की आलोचना थी। इसे उचित कहा जा सकता है मगर जैसा कि अदालत ने कहा, सांसद होने के नाते गांधी को सरकार के कामकाज या नाकामियों पर जो भी सवाल उठाना है, उसे सदन में उठाने से क्यों हिचकते हैं। राहुल की तरफ से कहा गया कि उन्हें सुनवाई का अवसर दिए बगैर ही सम्मन जारी कर दिया गया जबकि यह सुनी-सुनाई बातों व अखबारी कतरनों पर आधारित था। यह कानूनन साबित होने तक साक्ष्य के तौर पर स्वीकार्य नहीं था। बेशक, गांधी के प्रति की गई यह शिकायत राजनीति प्रतिशोध का उदाहरण कहा जा सकता है। इससे न सिर्फ अदालतों का वक्त जाया होता है बल्कि सनसनी फैलाने का काम भी होता है। गांधी को जिम्मदार नेता का परिचय देते हुए अप्रमाणित आरोपों से बचना सीखना होगा। सवाल सेना या सुरक्षा बलों पर आक्षेप लगाने भर की नहीं है। वरिष्ठ नेता के तौर पर बेवुनियादी बातें करना राहुल को शोभा नहीं देता। यह कहना भी अतिश्योक्ति नहीं होगा कि इसी दरम्यान सात साल बाद सीबीआई अदालत ने आप नेता सत्येन्द्र जैन के खिलाफ एक मामले में कोई सबूत न होने की बात स्वीकारी है। यह न्यायिक व्यवस्था व सत्ताधारी दल की नीयत पर प्रश्न चिह्न लगाता है। राजनीतिक प्रतिशोधों या कीचड़ उछालने वाली राजनीति का यह निम्नतर उदाहरण न बन कर रह जाए, इसका विशेष ख्याल रखा जाना जरूरी है।

**डिजिटल तकनीक/डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा**

## अपराधियों का बढ़ता हौसला

राजस्थान के जोधपुर जिले के मीडिया इंफ्लुएंसर को अपराधियों ने अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हुए 20 लाख रुपये की मांग पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर दो कथित अपराधियों को पकड़ा है। मीडिया इंफ्लुएंसर और उसकी कामेडियन पत्नी को उनके अश्लील वीडिया वायरल करने की धमकी दी गई। खैर, यह तो इन्होंने हिम्मत दिखा कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी अन्यथा देश दुनिया में इस तरह की धमकियां देकर डरा-धमका कर वसूली करने के अपराधों की बाढ़ से आ गई है।

दरअसल, डिजिटल तकनीक का अपराधियों द्वारा अपराध में उपयोग आम होता जा रहा है। डिजिटल तकनीक के कारण अपराधियों के बढ़ते हौसले की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि पिछले दिनों इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अजय भनोट ने एक महिला की निजी तस्वीरों को वाट्सएप पर सार्वजनिक करने के मामलें में जमानत देने से इंकार करते हुए सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति भनोट ने 2023 में भी सोशल मीडिया में अश्लील वीडियो अपालोड के प्रकरण में गंभीर टिप्पणी की थी। दरअसल, डिजिटल क्रांति ने अपराध की दुनिया में भी बड़ी सेंध लगा ली है। अपराधी विभिन्न माध्यमों से डिजिटल तकनीक का उपयोग कर गंभीर अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। कंप्यूटर, कंप्यूटर नेटवर्क, डेटाबेस, डिजिटल डिवाइस, इंटरनेट आदि के माध्यम से नित नये अपराध की तरीके अपना रहे हैं। सोशल मीडिया और स्मार्टफोन का खास तौर से इस्तेमाल करते हुए लोगों की निजी जिंदगी को प्रभावित करने के साथ ही डिजिटल अरेस्ट, साइबर ठगी जैसे गंभीर अपराध बेखौफ कर रहे रहे हैं। मजे की बात यह है कि डिजिटल अरेस्ट या बैंक अकाउंट ठगी के शिकार होने वाले अधिकतर लोग अच्छे पढ़े-लिखे, समाज में अच्छे पदों से सेवानिवृत्त या यों कहें कि समझदार लोग ही अधिक शिकार हो रहे है। कुछ दिनों पहले ही एक माननीय न्यायमूर्ति ने कहा कि वे साइबर ठगी के शिकार होते होते बचे हैं। यह सब तो तब है जब कि सरकार मोबाइल टोन के समय ही ओपनिंग मैसेज के माध्यम से आगाह कर रहे हैं।

# मूल्यांकन अभी शेष

**स्मृतिशेष**
**शिबू सोरेन**

**अरविंद कुमार सिंह**

देश के शीर्ष आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन के समकालीन नेताओं में कई ऐसे हैं, जिन्होंने बहुत लंबी सत्ता का इतिहास बनाया और बहुत सी उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शिबू सोरेन के निधन के बाद दिल्ली और झारखंड में जो नजारा दिखा है, उसने साबित किया कि आदिवासी ही नहीं, गैर-आदिवासियों के दिलों पर भी उन्होंने राज किया। बचपन से लेकर आखिरी सांस तक उनके राजनीतिक जीवन का बड़ा हिस्सा संघर्षों में ही बीता पर उन्होंने जल-जंगल-जमीन की जंग में जितनी लंबी लकीर खींची है, वहां तक पहुंच पाना बहुत कठिन है।

दिशोम गुरु के नाम से विख्यात शिबू सोरेन फिलहाल रामगढ़ के अपने पैतृक नेमरा की मिट्टी में विलीन हो गए पर उन्होंने आदिवासी संघर्ष में ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया है, उनकी अंतिम यात्रा में यह साफ दिखा। झारखंड की धरती महान नायक बिरसा मुंडा, बाबा तिलका मांझी, वीर बुधू भगत और सिदो-कानू जैसे नायकों की श्रेणी में आजादी के बाद के उनके कामों को भी शामिल करेगी। बहुत कंटीले रास्ते पर धारा के खिलाफ शिबू सोरेन का जो सफर आरंभ हुआ था, उसका समापन संतोष भरा था क्योंकि उन्होंने जिन विचारों पर अपनी राजनीति आरंभ की थी वह उनके जीवनकाल में बहुत विस्तारित हुई और उनकी अगली पीढ़ी ने उनकी विरासत को बखूबी संभाल लिया है।

झारखंड को अलग राज्य बनाने में शिबू सोरेन के योगदान को तो सभी मानते ही हैं पर आदिवासी समुदाय में प्राकृतिक संपदा को बचाने और कुरीतियों के खिलाफ उन्होंने जो संघर्ष किया, वह बेमिसाल है। मैदानी इलाकों की तुलना में साधनविहीन इलाकों में राजनीति करना कठिन काम है पर वहीं काम करते हुए वे जंगल के महान नायक और गुरुजी के नाम से विख्यात हुए। महाजनी प्रथा और नशे के खिलाफ आदिवासियों तथा कमजोर तबकों के बीच उन्होंने जो संघर्ष किया वह भावी पीढ़ियों के लिए मिसाल रहेगा। झामुमो नेता हेमंत सोरेन चौथी बार झारखंड के मुख्यमंत्री उनके ही बनाई संघर्षों की जमीन पर बने हुए हैं। शिबू सोरेन के बचपन में ही पिता की हत्या हो गई तो मैट्रिकुलेशन तक ही उनकी शिक्षा हो सकी। लेकिन बचपन से ही वे गरीबों पर अत्याचार, अन्याय, नशाबंदी और महाजनी सिस्टम के खिलाफ मैदान में उतरे और लंबा संघर्ष करते हुए प्रांतीय और राष्ट्रीय राजनीति में अलग जगह बनाई। तीन बार वे झारखंड के मुख्यमंत्री बने लेकिन बहुत सीमित कालखंड के लिए। तीन बार केंद्र में मंत्री भी रहे। संसद के दोनों सदनों में रहे। मुखिया पद पर हार से उनकी राजनीति शुरू हुई और मुख्यमंत्री रहते हुए भी वे चुनाव हार गए तो राजनीतिक विरोधियों ने बहुत तंज कसा था। लेकिन उनकी राजनीति

खत्म नहीं हुई। आखिरी सांस ली तो वे उच्च सदन के सदस्य थे। राष्ट्रीय स्तर की हैसियत बनाने के बाद भी उनके भीतर का गांव कायम रहा। तीन दशक से मैंने उनको करीब से देखा और निजी तौर पर भी उनसे पहचान रही। वे अपने मूल विचारों पर हमेशा कायम रहे। राजनीतिक समझौते भी किए तो उसकी परिधि में आदिवासियों की भलाई शामिल थी।

बेशक, ऐसे नायकों के बारे में मीडिया एक अलग पूर्वाग्रह रखता है। इसीलिए शिबू सोरेन के जीते जी उनका उचित मूल्यांकन नहीं हुआ पर समाज को जगाने वाले नायक के रूप में उनकी अमिट पहचान इतिहास में दर्ज होगी। कम लोगों को पता है कि उन्होंने आदिवासी समाज की शिक्षा-दीक्षा से लेकर कुरीतियों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। रात्रि पाठशाला चलाने के साथ उन्होंने शराब से लेकर कई कुरीतियों के खिलाफ अलख जगाने का काम किया। इस चेतना का जागरण भी किया कि बगैर अलग राज्य बने आदिवासियों का भविष्य सुरक्षित नहीं हो सकेगा। इसीलिए इसके साथ भले ही छत्तीसगढ़ या उत्तराखंड राज्य बन गया हो लेकिन किसी राज्य के लिए लंबे संघर्ष का इतिहास केवल झारखंड का रहा है। 1973 में झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना के बाद आदिवासियों का संघर्ष राष्ट्रीय क्षितिज तक दिखा और अन्य प्रांतों के लिए प्रेरक भी बना। झारखंड खनिज संपदा में देश का सबसे संपन्न राज्य है। भारत के स्वाधीनता आंदोलन में भी यह अग्रणी रहा था और एक दौर तक यहां कांग्रेस का वर्चस्व रहा। खुद शिबू सोरेन के पिताजी भी कांग्रेस से जुड़े थे। 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन मौलाना आजाद की अध्यक्षता में हुआ था जिसमें झारखंड की धरती पर महात्मा गांधी, पं. जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉ. राजेंद्र प्रसाद और ताना भगत समेत तमाम नायक शामिल हुए थे और यहीं से 'भारत छोड़ो' आंदोलन के विचार की भी नींव पड़ी थी।

इसके चार साल बाद शिबू सोरेन का जन्म हुआ जब देश आजाद होने के कगार पर खड़ा था। झामुमो का संघर्ष और जागरूकता भी एक वजह है जिस कारण झारखंड अपने जल-जंगल-जमीन के साथ अपनी संस्कृति और परंपराओं को सहेज कर रखने में सफल रहा।15 नवम्बर, 2000 को नया राज्य बनने के बाद यह शिबू सोरेन के कारण हर सरकार के एजेंडे का हिस्सा रहा। बेशक, भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.4 फीसद हिस्सा झारखंड के पास है, और देश की आबादी का 2.7 फीसद पर, आकार में झारखंड पेरू जितना बड़ा है। पेरू दुनिया का 40वां सबसे बड़ा देश है। प्राकृतिक और भूगर्भ संसाधनों से भरपूर झारखंड में ही देश का सबसे बड़ा कोयला और लौह अयस्क भंडार है पर खनन से विस्थापन नियति बना हुआ है। नक्सलवाद कम होने के बाद भी चुनौती बरकरार है। राज्य की करीब 66.85 फीसद आबादी खेती पर आश्रित है लेकिन खेती चुनौतियों से भरी है।

राष्ट्रीय दलों की अपनी अलग सोच और बाध्यताएं होती हैं, जबकि क्षेत्रीय दलों का एक सीमित दायरे में लक्षित समूह होता है। इसलिए झारखंड में शिबू सोरेन की रचना झामुमो नये विचारों के साथ जल-जंगल-जमीन को एजेंडे में रख कर आगे भी चलेगा। उसका नया नेतृत्व संचार और सूचना क्रांति से भी लैस है पर शिबू सोरेन को आदिवासी नेतृत्व ऐसे नायक के रूप में हमेशा याद रखेगा जिनके पार संघर्षों की बड़ी थाती थी। इसलिए सोहनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां उनके ऊपर फिट बैठती हैं-

*अचल रहा जो अपने पथ पर लाख*
*मुसीबत आने में*
*मिली सफलता जग में*
*उसको, जीने में मर जाने में*

*(लेख में विचार निजी हैं)*

तीन दशक से मैंने उनको करीब से देखा और निजी तौर पर भी उनसे पहचान रही। वे अपने मूल विचारों पर हमेशा कायम रहे। राजनीतिक समझौते भी किए तो उसकी परिधि में आदिवासियों की भलाई शामिल थी। बेशक, ऐसे नायकों के बारे में मीडिया एक अलग पूर्वाग्रह रखता है। इसीलिए शिबू सोरेन के जीते जी उनका उचित मूल्यांकन नहीं हुआ पर समाज को जगाने वाले नायक के रूप में उनकी अमिट पहचान इतिहास में दर्ज होगी

**भारत का चाय निर्यात बढ़ा**

- भारत का चाय निर्यात वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ कर 2,57,880 टन हो गया है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के 2,50,730 टन के मुकाबले 2.85 प्रतिशत अधिक है
- टी बोर्ड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के मुताबिक, निर्यात बढ़ने की वजहें अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूत मांग और देश के प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों से निर्बाध आपूर्ति हैं
- रूस भारतीय पारंपरिक चाय के शीर्ष आयातकों में से एक बना हुआ है। ईरान विशेष रूप से उत्तर भारतीय पारंपरिक किस्मों का महत्त्वपूर्ण खरीदार बना रहा है
- संयुक्त अरब अमीरात प्रत्यक्ष उपभोक्ता और पुनर्निर्यात केंद्र, दोनों रूप में भारतीय चाय का प्रमुख आयातक बना हुआ है, जबकि असम और दार्जिलिंग चाय के लिए यूनाइटेड किंगडम स्थिर बाजार बना रहा है
- अमेरिका ने प्रीमियम और विशेष चाय के लिए बढ़ते गंतव्य के रूप में अपनी बढ़ती प्रवृत्ति जारी रखी। सऊदी अरब, मिस्र, जर्मनी, चीन और कजाकिस्तान ने स्वास्थ्य-केंद्रित और विशिष्ट मिश्रणों वाली भारतीय चाय में रुचि दिखाई है

(मीडिया इनपुट्स)

अपनी भूचाल ला देने वाली टैरिफ नीतियों और अस्थिर तौर-तरीकों से ट्रंप ने चीन की भू-राजनीतिक 'दुकानदारी' में अफरातफरी फैला दी है। किसी भी देश के लिए उनका सामना करना बड़ी चुनौती है-भारत के लिए तो खासी दिक्कत दरपेश है। उनके हालिया फैसले ने रूस के साथ व्यापार में भारत की सक्रियता से पश्चिम का दोहरापन भी उजागर हो गया है।

**ब्रह्म चेलानी, सामरिक चिंतक**
**@Chellaney**

# वर्षों याद रहेंगे गिल के जांबाज

**क्रिकेट | मनोज चतुर्वेदी**

इंग्लैंड का यह समर बेहतरीन टेस्ट क्रिकेट और एक उम्दा टेस्ट कप्तान के तौर पर उभरने के लिए याद किया जाएगा। एंडरसन-तेंदुलकर सीरीज के आखिरी दो टेस्ट बाकी रहने पर भारतीय टीम 1-2 से पीछे थी, और चौथे मैनचेस्टर टेस्ट में इंग्लैंड के पहली पारी में 311 की बढ़त बनाने पर किसने सोचा था कि भारतीय यंग ब्रिगेड सीरीज ड्रा कराकर लौटेगी। पर शुभमन गिल और गौतम गंभीर की इस टीम ने मैनचेस्टर टेस्ट ड्रा ही नहीं कराया, बल्कि ओवल टेस्ट तमाम विपरीत हालात में भी जीत कर सीरीज बराबर करा कर सभी को हतप्रभ कर दिया। इस सीरीज में गिल एक ऐसे कप्तान के तौर पर उभरे हैं, जिनसे आने वाले समय में बहुत उम्मीदें लगाई जानी हैं।

इस यंग ब्रिगेड ने दिग्गजों की अनुपस्थिति में बल्लेबाजी ही नहीं, गेंदबाजी में भी ऐसे कारनामे किए हैं, जिनकी चर्चा आने वाले तमाम सालों तक चलनी हैं। कप्तान गिल ने अपने आलोचकों को धता बताते हुए सीरीज में सबसे ज्यादा 754 रन बनाए जिनमें एक दोहरा और तीन शतक शामिल रहे। भारत ने एक सीरीज में सबसे ज्यादा शतक लगाने के ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के 12-12 शतक के रिकॉर्ड की बराबरी करके दिखाया है कि आने वाले दिन उनके ही रहने वाले हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 1955 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ और पाकिस्तान ने 1982-83 में भारत के ही खिलाफ ये शतक जमाए थे।

इस पूरी सीरीज में 21 शतक लगे और टेस्ट क्रिकेट में नई जान डालने वाली साबित हुई है यह सीरीज। भारतीय कप्तान शुभमन गिल करीब डेढ़ माह पहले इस नई जिम्मेदारी के साथ इंग्लैंड दौरे पर गए थे, तब दिग्गज खिलाड़ियों की अनुपस्थिति की ज्यादा चर्चाएं चल रही थीं। गिल की यह यंग साइड कैसा खेलेगी का किसी को भी अंदाजा नहीं था पर इस यंग ब्रिगेड ने जिस अंदाज में बेहतरीन प्रदर्शन करके सीरीज को बराबर कराया और आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड के जबड़े से जीत को निकाल कर उन्हें हराया, उससे यंग टीम का डीएनए तो पता चलता है। यह सही है कि भारत यदि आखिरी टेस्ट हार कर सीरीज हार जाता तो इस युवा टीम के साथ कोच गौतम गंभीर को भी आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता।

लेकिन मोहम्मद सिराज के दिलेरी भरे प्रदर्शन ने इस टीम को हीरो बना दिया है। भारतीय गेंदबाजों ने चौथे दिन हाथ से निकलते टेस्ट के आखिरी समय में अपनी बेहतरीन

गेंदबाजी से भारत की वापसी करा कर जो माहौल बनाया था, उसकी वजह से ही इंग्लैंड के चार विकेट रहते सिर्फ 35 रन जीत से दूर रहने पर भी भारतीय खेमे में जीत की उम्मीदें बन गई थीं। पर आखिरी दिन का खेल शुरू होने पर प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने बाकी ओवर की चार गेंदों पर दो चौके खाए तो लगा कि मैच हाथ से निकलने वाला है। इस हताशा को सिराज ने अगले ओवर में स्मिथ को विकेट के पीछे कैच करा कर एक बार फिर उम्मीदों में बदल दिया। इसके बाद जिस अंपायर के बारे में माना जा रहा था कि उसके फैसले भारत के खिलाफ जा रहे हैं, उसके फैसले ने ही भारतीय उम्मीदों को नई ऊंचाइयां दीं। ओवर्टन सिर्फ अंपायर कॉल की वजह से ही एलबीडब्ल्यू हुए क्योंकि सिराज की गेंद विकेट को बस छूती हुई ही जा रही थी। हम सभी जानते हैं कि चौथे दिन हैरी ब्रूक के सिराज का कैच पकड़ कर सीमा रेखा के पार चले जाने से ही मैच भारत के हाथ से निकलता दिखा था। पर इस खिलाड़ी ने जब एटकिंसन को बोल्ड करके भारत को छह रनों से जीत दिलाई, उसके साथ ही वह भारतीय जीत का हीरो बन गया। मोहम्मद सिराज चौथे दिन हैरी ब्रूक का कैच छोड़ने की वजह से सो नहीं सके थे। इस कारण ने उन्होंने अगले दिन अल सुबह अपने मोबाइल के बॉल पेपर पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाली बिलीव लिखी फोटो लगाई। साथ ही मन में ठान लिया कि देश के लिए टीम को हर हाल में जिताना है। उन्होंने इसी भावना वाला प्रदर्शन करके असंभव नजर आ रही जीत दिला कर दिखा दिया कि वह जो भी ठानते हैं, उसे कर दिखाने का उनमें माद्दा भी है। सिराज ने इस सीरीज में 23 विकेट निकाल कर इंग्लैंड के खिलाफ भारत के लिए सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने के बुमराह के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। बुमराह ने 2021-22 की सीरीज में यह रिकॉर्ड बनाया था।

शुभमन गिल की यह कप्तान के रूप में पहली सीरीज थी और उन्होंने अपने प्रदर्शन से दिखाया कि आने वाला समय उनका ही है। वह इस सीरीज में तीन शतक और एक दोहरे शतक से सर्वाधिक 724 रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। इस सीरीज के दौरान उनके कुछ फैसलों की आलोचना हुई तो कुछ फैसले सराहे भी गए लेकिन इस दौरान उन्होंने जिस तरह से टीम का नेतृत्व किया और टीम में हार नहीं मानने का जज्बा बनाया उससे तो साफ है कि यह टीम रोहित और विराट के युग से बाहर निकलने में कामयाब हो गई है, और भारत को टेस्ट क्रिकेट में नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का माद्दा रखती है। भारतीय कोच गौतम गंभीर ने भारत के टेस्ट जीतने पर कहा, ...हम कुछ मैच जीतेंगे, कुछ मैच हारेंगे पर आत्मसमर्पण कभी नहीं करेंगे। शाबाश लड़को।... गौतम गंभीर के बयान से यह आसानी से समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में भारतीय टीम का रवैया क्या रहने वाला है।

**इच्छाएं | श्रीराम शर्मा आचार्य**

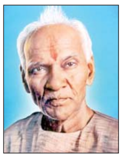

वस्तु एवं विषयों का बाहुल्य हो जाने के कारण मनुष्य की आवश्यकताएं एवं इच्छाएं बहुत बढ़ गई हैं। इस स्थिति में समुपस्थित साधनों की अपेक्षा जनसंख्या की अपरिमित वृद्धि से मनुष्यों का स्वार्थ पराकाष्ठा पार कर गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण संसार की शक्तियों का सन्तुलन बिगड़ गया है, जिससे मनुष्यों के बीच पारस्परिक विश्वास समाप्त हो गया है। आधिक्य तथा अभाव की विषमता के कारण रोग, दोष, शोक, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लाभ आदि की प्रवृत्तियां बहुत बढ़ गई हैं। इन सबके चलते मनुष्य का जीवन पहले से कहीं अधिक जटिल हो गया है। जीविका के लिए जीवन में अत्यधिक व्यस्तता बढ़ जाने के कारण मनुष्य एक निर्जीव यन्त्र बन गया है, उसके जीवन की सारी प्रसन्नता उल्लास, हर्ष एवं आशा आदिक विशेषताएं समाप्त हो गई हैं। मनुष्य निष्ठुर, नीरस, अनास्थावान एवं नास्तिक बन गया है। मन में कोई उत्साह न रहने के कारण धर्म उसके लिए ढोंग और संयमशीलता, रूढ़िवादिता के रूप में बदल गई है। मनुष्य को परेशान करने वाली परिस्थितियों के विकटतम जाल चारों ओर फैल गए हैं। इन परेशानियों में फंसा-फंसा जब वह ऊब उठता है तो नवीनता तथा ताजगी लाने के लिए निकृष्ट मनोरंजनों तथा मद्यादिक व्यसनों की ओर भाग पड़ता है। ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, स्वार्थ एवं संघर्ष आज के समय का वास्तविक जीवन बन गया है। इतनी दुष्ट प्रवृत्तियों एवं परिस्थितियों के रहते हुए मनुष्य परेशान न हो, यह कैसे हो सकता है? क्या अनपढ़ और क्या पढ़ा-लिखा, क्या धनवान और क्या निर्धन, क्या मालिक और क्या मजदूर, बच्चा-बूढ़ा, स्त्री-पुरुष सब समान रूप से अपनी-अपनी तरह परेशान देखे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मनुष्य अपनी इन परेशानियों का इतना अभ्यस्त हो गया हो कि इनकी ओर से उदासीन रह रहा हो, बल्कि वह इन व्यग्रताओं से इतना दुःखी हो उठा है कि उसे जीवन में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं रही, जिसके फलस्वरूप समाज में अपराधों, विकृतियों एवं कुरूपताओं की बाढ़ सी आ गई है। मानव-जीवन के लक्ष्य 'सत्यं शिवम सुन्दरम' का पूर्णरूपेण तिरोधान हो गया है। और यह कारण है कि आज मनुष्य पहले से कहीं अधिक व्यथित है।

## रीडर्स मेल

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

### जेल की जिंदगी का हव्वा बेमानी

अपराध करने वाले को पुलिस पकड़ती है। दंडित कर उसे जेल भेजती है। प्रायः हर अपराधी के साथ ऐसा ही सलूक होता है। जेल में अपराधी को सुधरने का मौका भी दिया जाता है। उसे इस शर्त पर रिहा किया जाता है कि वह फिर कोई अपराधिक गतिविधि नहीं करेगा और लोगों की तरह मेहनत से रोजी-रोटी कमाएगा। विचार तो अच्छा है। जेल में कैदी बंद क्यूं रहे, उसे भी जन सामान्य की तरह जीने दो। इस तरह देखा जाए तो अपने अच्छे बर्ताव से कई बंदी समाज में अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यह भी देखने में आता है कि जेल में रह कर व्यक्ति काम करते हैं, उन्हें इसका पैसा मिलता है। उसे वह अपने घर भी भेजते हैं। सही बात तो यह है कि आदमी काम करेगा तो फितूर उसके दिमाग में घूमेंगे ही नहीं। नरसंहार के आरोपी कोली ने जेल में पढ़ना सीखा। फिर आईटीआर या सूचना के अधिकार से जेल से बाहर आने का रास्ता बनाया। कह सकते हैं कि जेल शब्द वास्तव में हव्वा नहीं है। व्यक्ति वहां रह कर भी अपने अपराधी होने का मुखौटा उतार सकता है।

**सीमा गुप्ता, बरेली**

### शिबू सोरेन ने खींची लंबी लकीर

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन से राष्ट्रीय राजनीति खासकर आदिवासी संवेदना को झटका लगा है। बिहार से पृथक झारखंड राज्य बनवाने से लेकर आदिवासी समाज को राजनीतिक पहचान दिलाने तक की बड़ी भूमिका, झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करने वाले, आदिवासियों के शोषण-महाजनी प्रथा, सूदखोरी, शराब आदि के विरुद्ध लगातार आंदोलन करना; ये कुछ ऐसे काम हैं, जिसकी बदौलत शिबू सोरेन ने लंबी लकीर खींची। तीन बार झारखंड के मुख्यमंत्री, तीन बार राज्य सभा, आठ बार लोक सभा के सदस्य रहे। उनके गुजर जाने से आदिवासियों का सही मायने में खेवनहार चला गया है। देखना है कि उनके बेटे हेमंत सोरेन उनकी दी हुई विरासत को किस ऊंचाई तक ले जाएंगे।

**मीना धानिया, दिल्ली**

### हवाई बातें न करें राहुल गांधी

लोक सभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दावा किया है कि निर्वाचन आयोग बिहार में वोट चोरी में शामिल है, और इस बारे में उनके पास पुख्ता सबूत हैं, जो एटम बम की तरह हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर पुख्ता सबूत हैं, तो देर किस बात की, धमाका कर दें। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार में गहन पुनरीक्षण के दौरान धांधली हुई होगी। लेकिन इसके लिए पुख्ता सबूत देने जरूरी होते हैं। केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाने से प्रमाणित नहीं होता कि वोट चोरी हुई है। राहुल गांधी को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की चुनौती स्वीकारते हुए अपने दावे को सही और उसकी विश्वसनीयता के लिए एटम बम का धमाका करने में देरी नहीं करनी चाहिए। केवल हवा-हवाई बातें करने से न केवल स्वयं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिह्न लगते हैं, बल्कि उनके विरोधी भी मजाक बनाते हैं कि राहुल गांधी तो कुछ भी बेसिर पैर की बातें करते रहते हैं। जनता-जनार्दन में अपनी विश्वसनीयता के लिए राहुल गांधी को गंभीरता के साथ प्रमाणित और मय सबूत अपने दावे को सच साबित करना चाहिए ताकि वे विश्वसनीयता की कसौटी पर खरे उतर सकें।

**हेमा हरि उपाध्याय, 'अक्षत', उज्जैन**

letter.editorsahara@gmail.com

**हमें गर्व है हम भारतीय हैं**

राष्ट्रीय सहारा
• राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण

सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय -011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
वर्ष-34, अंक 349
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्

भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

# ‘जय श्री बांके बिहारी’

**भारत** की जनता धर्म प्राण है इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती मगर इसके साथ यह भी वास्तविकता है कि भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसके कण-कण में यह धर्म प्राण जनता अपने-अपने इष्ट देवों के प्रतिरूपों को खोजती रहती है। इसका कारण यह है कि भारत की धर्म प्राण जनता की अटूट आस्था भरत भूमि पर है। निश्चित रूप से यह आस्था साकार ब्रह्म के हिन्दू उपासकों के मन में अविरल बहती रहती है। यही सनातन है जो हजारों वर्षों से भारत की पहचान बना हुआ है। इसमें अंधविश्वास का पुट तब आता है जब सनातन के वैज्ञानिक स्वरूप को कुछ स्वार्थी तत्व अपने निजी हित में प्रयोग करने लगते हैं। भारत में भगवान कृष्ण के विभिन्न स्वरूपों की पूजा-अर्चना भी हजारों साल से चलती आ रही है जिसमें बांके बिहारी भी एक स्वरूप है। इस स्वरूप की सुन्दरता की व्याख्या किसी महाकवि द्वारा भी शब्दों में वर्णित करना असंभव है क्योंकि भारत के हिन्दू उपासक इसे पारलौकिक मानते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से ब्रज क्षेत्र के वृन्दावन में स्थित भगवान बांके बिहारी मन्दिर को लेकर खासा विवाद उत्पन्न इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अन्य प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों की भांति यहां भी बांके बिहारी कारीडोर बनाना चाहती है जिसका विरोध स्थानीय पंडे या पुजारियों से लेकर क्षेत्र के दुकानदार व निवासी तक कर रहे हैं। यह विरोध उनके निर्वासित होने के डर की वजह से है। मगर इस बारे में राज्य की योगी सरकार लगातार आश्वासन दे रही है कि हर उजड़े हुए व्यक्ति का समुचित पुनर्वास किया जायेगा। श्री बांके बिहारी मन्दिर में पूरे भारत के हिन्दुओं की अटूट आस्था व श्रद्धा है और वे भारी संख्या में हर मौसम में यहां दर्शन करने के लिए आते हैं जिसकी वजह से मन्दिर में भारी भीड़ रहती है। विभिन्न अवसरों पर मन्दिर में भगदड़ के समाचार भी मिलते रहते हैं जिसमें बहुत से लोगों की जान तक चली जाती है। हालांकि राज्य सरकार की ओर से व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आदि बल भी तैनात रहता है मगर मन्दिर के आसपास संकरी गलियों और बाजार को देखते हुए प्रबन्धन भली प्रकार नहीं हो पाता और अक्सर अप्रिय हादसे होते रहते हैं। इसके साथ ही मन्दिर का प्रबन्धन कुछ पुजारियों के परिवारों के हाथ में है। स्पष्ट है कि मन्दिर को हर साल करोड़ों रुपये का दान या भेंट श्रद्धालुओं द्वारा दिया जाता है। इस धन सम्पत्ति का व्यय ब्यौरा सरकार की पहुंच से बाहर रहता है जबकि दूसरी ओर भक्तों की भीड़ में हर वर्ष बढ़ौतरी होती रहती है। इसे देखते हुए ही योगी सरकार ने मन्दिर कारीडोर बनाने की घोषणा की थी।

सबसे पहले यह समझ लिया जाना चाहिए कि मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति नहीं हो सकता। इतिहास बताता है कि किसी भी मन्दिर की स्थापना के समय किसी पुजारी को भी नियुक्त किया जाता था जो मन्दिर के प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार होता था। अत: मन्दिर सार्वजनिक सम्पत्ति ही होता है क्योंकि उसका रखरखाव परोक्ष रूप से श्रद्धालु ही करते हैं। मगर बांके बिहारी मन्दिर को स्वामी हरिदास के वंशज गोस्वामी परिवार के लोग अपनी निजी सम्पत्ति बताते हैं। वास्तव में मुगलकाल के दौरान भक्त शिरोमणि तथा संगीत के महान मर्मज्ञ स्वामी हरिदास ने ही बांके बिहारी मन्दिर की स्थापना की थी।

सबसे पहले यह समझ लिया जाना चाहिए कि मन्दिर किसी की निजी सम्पत्ति नहीं हो सकता। इतिहास बताता है कि किसी भी मन्दिर की स्थापना के समय किसी पुजारी को भी नियुक्त किया जाता था जो मन्दिर के प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार होता था। अत: मन्दिर सार्वजनिक सम्पत्ति ही होता है क्योंकि उसका रखरखाव परोक्ष रूप से श्रद्धालु ही करते हैं। मगर बांके बिहारी मन्दिर को स्वामी हरिदास के वंशज गोस्वामी परिवार के लोग अपनी निजी सम्पत्ति बताते हैं। वास्तव में मुगलकाल के दौरान भक्त शिरोमणि तथा संगीत के महान मर्मज्ञ स्वामी हरिदास ने ही बांके बिहारी मन्दिर की स्थापना की थी। ऐसी किंवदन्ति है कि उन्हें बांके बिहारी जी की प्रतिमा मिली थी जिसकी उन्होंने स्थापना की। स्वामी हरिदास पंजाब के ‘मुल्तान’ इलाके से वृन्दावन आये थे। तब से यह प्रतिमा स्थापित है। मगर वर्तमान में 21वीं सदी चल रही है और आजादी के समय की 34 करोड़ की आबादी बढ़कर 140 करोड़ हो चुकी है अत: मन्दिर परिसर का क्षेत्रफल भारी संख्या में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को सहने में असमर्थ होता जा रहा है जिसे देखते हुए योगी सरकार ने पहले पूरे वृन्दावन नगर का कायाकल्प किया और अब वह मन्दिर का कारीडोर बनाना चाहती है। इसे लेकर पहले इसके खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई जिसे न्यायालय ने खारिज करते हुए नवम्बर 2023 में राज्य सरकार को कारीडर बनाने की अनुमति प्रदान कर दी परन्तु यह पाबन्दी लगा दी कि कारीडोर निर्माण में श्री बांके बिहारी के नाम के बैंक खाते से धन न लिया जाये। इसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गया और देश की सर्वोच्च अदालत विगत 15 मई, 2025 को याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार द्वारा दायर बहुपक्षीय प्रार्थना ( इंटर लोक्यूटरी) को स्वीकार कर लिया। यह याचिका पूरे ब्रज क्षेत्र के मन्दिरों के प्रबन्धन व श्रद्धालुओं को अधिकतम सेवा प्रदान करने सम्बन्धी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तब राज्य सरकार को यह इजाजत दे दी कि वह बांके बिहारी मन्दिर के आसपास की पांच एकड़ जमीन खरीदने के लिए मन्दिर के खाते से धन भी निकाल सकती है। मगर जमीन श्री बांके बिहारी के नाम पर ही होनी चाहिए। इसके तुरन्त बाद 25 मई, 2025 को राज्य सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर श्री बांके बिहारी जी मन्दिर न्यास का गठन कर दिया। यह न्यास मन्दिर का प्रबन्धन आदि का कामकाज देखेगा। सर्वोच्च न्यायालय की दो सदस्यीय पीठ इस मामले को देख रही है जिसमें न्यायमूर्ति सूर्यकान्त व जयमाल्या बागची हैं। विगत दिन को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति सूर्यकान्त ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि उसने अध्यादेश लाने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई ? न्यायालय मन्दिर के प्रबन्धन का कार्य किसी अवकाश प्राप्त न्यायाधीश के नेतृत्व में गठित कमेटी को भी सौंप सकता है। दरअसल राज्य सरकार के अध्यादेश को ही सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। योगी सरकार के वकील ने दलील दी कि जिन लोगों ने अध्यादेश को चुनौती दी है वे मन्दिर के प्रबन्धन का हक नहीं रखते हैं क्योंकि ऐसा करने का दावा बहुत से लोग करते हैं। इस मामले का निष्कर्ष यह निकाला जा सकता है कि सर्वोच्च न्यायालय मन्दिर के प्रबन्धन के लिए किसी उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश को मुखिया बनाकर कारीडोर निर्माण की इजाजत दे सकता है।

## पक्ष-विपक्ष उनके भाषणों का मुरीद...

गीता पाढा

वह शालीन स्वभाव और उच्च कोटि की विचारधारा,
जिन्होंने यूनो में कश्मीर के मुद्दे पर पड़ोसी मुल्क को न जाने कितनी बार धिक्कारा,
पक्ष–विपक्ष उनके भाषणों का मुरीद था ये भारतवर्ष सारा,
स्व. सुषमा स्वराज जी को उनकी पुण्यतिथि पर तहेदिल से वंदन है हमारा !!

# आतंकिस्तान के साथ संधि, भारत के लिए दंड

प्रभु चावला
एडिटोरियल डायरेक्टर
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस
newindianexpress.com

**इतिहास** में कुछ घटनाएं दो बार घटती हैं। पहली बार हास्य के रूप में और दूसरी बार तमाशा के रूप में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों ही हैं। 30 जुलाई को रियलिटी टीवी होस्ट से टैरिफ तानाशाह बने ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर 25 प्रतिशत की आर्थिक गिरावट का बम गिराया, साथ ही कूटनीतिक झूठ का पुलिंदा बांधते हुए दावा किया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित की है। ट्रंप ने नई दिल्ली की पीठ में छुरा घोपने के लिए इस्लामाबाद के साथ हाथापाई की। उनका यह आर्थिक हमला अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि खुद उनके लिए रचा गया है। ट्रंप पाकिस्तान के पैट्रोलियम उत्खननकर्ताओं और क्रिप्टो कार्टेलों को लुभा रहे हैं, अपनी जेबें भरने के लिए ऐसी पाइपलाइन और भुगतान प्लेटफॉर्म की योजना बना रहे हैं जो किसी भी जांच-पड़ताल से बच निकलेंगे। उनकी कुल संपत्ति एक साल में 60 करोड़ डॉलर बढ़ गई और उनकी नैतिकता गर्त में समा गई। यह नापाक हरकत उस व्यक्ति की ओर से हो रही है जिसने कभी डॉलर से भरे प्रवासी भारतीयों से भरे स्टेडियमनुमा तमाशे में नरेंद्र मोदी को गले लगाया था। ‘सच्चा दोस्त’ और ‘महान नेता’ कहा था। बाद में लेन-देन के धुरंधर ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली है जो अपने पिछवाड़े में आतंकी शिविरों को पाल-पोस रहा है। इस नारंगी मुखौटे और अमेरिका ग्रेट अगेन (एमएजीए) की बड़बड़ाहट के पीछे एक ऐसा शख्स छिपा है जो नैतिकता से नहीं, बल्कि अपने संदिग्ध साम्राज्य को मजबूत करने के लिए डॉलर से प्रेरित है।

पाकिस्तान के जनरल सैयद असीम मुनीर अहमद शाह के साथ उनका गठबंधन कायरता की आड़ में एक सोची-समझी साज़िश है जो भारत को पुराने बुरे सपनों में वापस धकेल रही है। याद है 1971, जब रिचर्ड निक्सन ने बंगलादेश युद्ध के दौरान भारत को धमकाने के लिए दुर्जेय विमानवाहक पोत यूएसएस एंटरप्राइज भेजा था? इंदिरा गांधी ने पलक तक नहीं झपकाई। भारत झुका नहीं और इतिहास उसी को याद रखता है जो डटा रहा। इस बार, इतिहास एक तमाशे के रूप में नहीं, बल्कि एक चेतावनी के रूप में दोहराया जा रहा है। ट्रंप लाल टाई पहने निक्सन हैं, जो फिर से इस्लामाबाद का साथ दे रहे हैं। इस बार बस इतना फर्क है कि अमेरिका टैरिफ और ट्वीट्स के जरिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है लेकिन भारत तब और अब झुकने से इन्कार करता है। ट्रंप का विश्वासघात एक दोधारी तलवार है।

पिछले हफ्ते दागी गई उनकी टैरिफ मिसाइल, भारत के अपने सबसे बड़े व्यापारिक साझेदार अमेरिका को 87 अरब डॉलर के निर्यात पर निशाना साध रही है जिससे अनुमानित 7 अरब डॉलर का नुक्सान होने का खतरा है। राष्ट्रपति ने अमेरिकी मोटरसाइकिलों पर भारत द्वारा लगाए गए 70 प्रतिशत शुल्क और 12 प्रतिशत व्यापार-भारित टैरिफ का हवाला देकर इसे उचित ठहराया। उन्होंने फरवरी 2025 से अब तक आठ बार भारत को "बड़ा दुर्व्यवहार करने वाला" करार दिया है और रूस के साथ इसे एक ‘मृत अर्थव्यवस्था’ करार दिया है। ट्रंप ने यह भी कहानी गढ़ी कि भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया है। उन्होंने झूठा दावा किया कि भारत ने ‘बिना टैरिफ वाला सौदा’ पेश किया, जिसका एस. जयशंकर ने खंडन किया। ‘सौदे पारस्परिक रूप से लाभकारी होने चाहिए।’ नई टैरिफ व्यवस्था 2017 के बाद से बने विश्वास को तोड़ती है, जब मोदी और ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मोदी के गर्मजोशी भरे आलिंगन, अहमदाबाद में ट्रंप के 2020 के 'नमस्ते ट्रंप' कार्यक्रम और आपसी प्रशंसा से चिह्नित मोदी की अमेरिकी यात्राओं के जरिए एक मजबूत रिश्ता बनाया था।

2024 तक द्विपक्षीय व्यापार बढ़कर 120 अरब डॉलर हो जाएगा। फरवरी में ट्रंप और मोदी के बीच हुई आखिरी मुलाकात में, भारतीय प्रधानमंत्री ने पारस्परिक शुल्कों से बचने के लिए टैरिफ में कटौती की पेशकश की और 2030 तक 500 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा लेकिन बाद में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ट्रंप के युद्धविराम के झूठ, ‘परमाणु युद्ध’ रोकने और ‘पांच जेट मार गिराए जाने’ के मनगढ़ंत दावे ने पाकिस्तान की रक्षा करते हुए भारत को अपमानित किया।

इसके अलावा, ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मुनीर की मेजबानी की, जहां उन्होंने शेखी बघारी, ‘मैंने परमाणु युद्ध रोका।’ विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तुरंत जवाब दिया : ‘मोदी ने ट्रंप को बताया कि अमेरिका की कोई मध्यस्थता नहीं हुई।’

अमेरिकी राष्ट्रपति भारत और पाकिस्तान के बीच शांति ‘स्थापित’ करने के बारे में बड़े-बड़े झूठ बोल रहे हैं लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसा कि मोदी ने लोकसभा में 20 घंटे की ऐतिहासिक बहस में कहा कि

‘ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई किसी विदेशी नेता ने तय नहीं की थी।’ सच तो यह है कि भारत ने ही हमले तय किए थे। पाकिस्तान से संचालित आतंकी शिविरों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। मोदी आधुनिक महाभारत के योद्धा की तरह दिख रहे थे, उनके साथ जयशंकर जैसे न्यायप्रिय और राजनाथ जैसे हमलावर थे। उन्होंने उजागर किया कि कैसे भारत की मिसाइलों ने नौ आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया और 100 आतंकवादियों को जहनुम पहुंचा दिया, जिसके बाद पाकिस्तान रेंगता हुआ आया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने बड़बड़ाते हुए मोदी पर विनम्रता का आरोप लगाया लेकिन वे नासमझ लग रहे थे। उन्होंने उपहास करते हुए कहा- अगर मोदी में इंदिरा गांधी जैसा जरा भी साहस है तो उन्हें ट्रंप को झूठा कहना चाहिए। मोदी ने उन्हें झूठा नहीं कहा, बल्कि उन्हें दीवाली की तरह रोशन किया, यह बताते हुए कि कैसे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की छिपी चेतावनियों को नकार दिया गया।

जयशंकर ने ट्रंप के व्यापारिक कल्पित दावों की धज्जियां उड़ाते हुए कहा-कोई जुड़ाव, कोई प्रभाव, कोई झूठ टिक नहीं सकता। राजनाथ ने सटीक हमलों की प्रशंसा करते हुए कहा-हमने पहलगाम नरसंहार का बदला 22 मिनट में ले लिया। जब मोदी सैनिकों के साथ मार्च कर रहे थे तो कांग्रेस ट्रंप की परियों की कहानियों को थामे हुए धराशायी हो गई। डीएमके की कनिमोझी ने माना कि विपक्ष ने ‘हमारे सैनिकों की बहादुरी को नजरअंदाज कर दिया।’ मोदी की टीम संसद में अपनी बात पर अड़ी रही तो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में गरजते हुए कहा-भारत के बाज़ार सहयोगियों के लिए हैं, हमलावरों के लिए नहीं।

राष्ट्रपति ट्रंप का जवाबी टैरिफ दोहरा झटका भारत के 1.4 ट्रिलियन डॉलर के बाजार और वैश्विक दक्षिण के नेतृत्व पर लक्षित है। मोदी का '2047 तक विकसित भारत' का विजन स्वायत्तता की मांग करता है, अधीनता की नहीं। यूएनसीटीएडी के अनुसार, ट्रंप के टैरिफ विकासशील देशों को क्षेत्रीय संबंधों की ओर धकेलेंगे। भारत के फार्मास्यूटिकल्स और परिधान जैसे विविध निर्यात एशिया और यूरोप की ओर बढ़ सकते हैं।

ट्रंप का यह प्रयास वैश्विक दक्षिण में प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता है, जिसमें भारत अमेरिकी आधिपत्य के खिलाफ ब्रिक्स का नेतृत्व कर सकता है। भारत अकेला नहीं है, ब्रिक्स उभर रहा है, आसियान देख रहा है और यूरोप पुनर्संतुलन कर रहा है। अगर ट्रंप अड़े रहे तो भारत ब्रिक्स संबंधों को और गहरा कर सकता है जिससे उन्हें एक महत्वपूर्ण सहयोगी को खोने का पछतावा होगा। ट्रंप की टैरिफ चालबाजी कूटनीतिक खींचतान में लिपटी एक दोहरी चाल है। उनका तर्क है कि भारत हार्ले और हैम पर ‘उच्च शुल्क’ लगाता है। ट्रंप के अरबपति होने के दावे ने उनके ब्रांड को तो बढ़ावा दिया है लेकिन भारत, जापान, कनाडा और यहां तक कि नाटो के साथ भी उनके रिश्ते खराब कर दिए हैं। उनके झूठ और टैरिफ उनके साम्राज्य को मजबूत करते हुए एक दोस्त को धोखा देते हैं। 14 देशों पर 25-40 प्रतिशत टैरिफ लगाकर और ब्रिक्स को धमकी देकर उनका आर्थिक विस्तारवाद अमेरिका से ज़्यादा उनके लिए फायदेमंद है।

ट्रंप का दुस्साहस अमेरिका द्वारा सहायता प्राप्त शिक्षाविदों, नौकरशाहों, कॉर्पोरेट दिग्गजों और कुलीन सामाजिक कार्यकर्ताओं के उस अंतर्राष्ट्रीय गिरोह को भी कमज़ोर कर सकता है जो विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक फ़ैसलों को प्रभावित करते हैं। ट्रंप का दिखावा, मुनाफ़ाखोरी और बेतुका झूठ उन्हें लोकतंत्र के संरक्षक के रूप में नहीं, बल्कि एक वैश्विक धौंसिया के रूप में चिह्नित करते हैं। यह अमेरिका फर्स्ट नहीं है, यह ट्रंप फर्स्ट है। पाकिस्तान की ओर उनका झुकाव आतंकी नेटवर्क को नई हवा देता है। यह 1970 के दशक की रणनीति को पुनर्जीवित करता है। भारत को अलग-थलग करो, इस्लामाबाद से दोस्ती बढ़ाओ और शांति स्थापना का दिखावा करो लेकिन समकालीन भारत कोई कमज़ोर देश नहीं है। यह 3.9 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ग्लोबल साउथ की आधारशिला है। वाशिंगटन को संदेश यह होना चाहिए कि भारत को लालच नहीं दिया जाएगा, खरीदा नहीं जाएगा या धमकाया नहीं जाएगा। अगर राष्ट्रपति निक्सन के ‘पोटस’ की भूमिका निभाना चाहते हैं तो भारत एक बार फिर मोदी के ‘डेविड’ की भूमिका निभाएगा, गुलेल से नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत, कूटनीतिक दृढ़ता और अमेरिकी दायरे से परे रणनीतिक गठबंधनों से लैस।

मोदी के नेतृत्व में भारत अडिग और बेपरवाह खड़ा है। अपने 1.4 अरब उपभोक्ताओं और 120 अरब डॉलर के व्यापार के साथ, भारत सम्मान की मांग करता है। मोदी की संसदीय जीत भारत के संकल्प को प्रमाणित करती है। यह उस धौंसिया को परास्त कर देगी जिसका विश्वासघात वैश्विक स्थिरता के लिए खतरा है। तो आगे बढ़िए, श्रीमान ट्रम्प, निक्सन की भूमिका निभाइए। स्कॉटलैंड और इस्लामाबाद में अपने तुच्छ खेल खेलिए लेकिन यह मत भूलिए, भारत की स्मृति लंबी है। भारत प्रतिरोध करता है और भारत उठ खड़ा होगा। जब धूल बैठेगी तो दुनिया देखेगी कि कौन सा सच्चा दोस्त था और कौन सा धोखेबाज।

# ट्रंप के टैरिफ बाउंसर पर मोदी ने छक्का जड़ दिया!

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

फिरोज बख्त अहमद

**यह** जानते हुए कि भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस पार्टनर अमेरिका है, जिस प्रकार का बर्ताव अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को लेकर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ किया है, वह न केवल निंदनीय है, बल्कि वांछनीय है। क्योंकि भारत ने सदा ही अमेरिका और ट्रंप का भरपूर साथ दिया है, चाहे वह गुजरात के मोदी स्टेडियम में उनका हार्दिक अभिनंदन हो या संयुक्त राष्ट्र संघ में हिमायत करना, मगर हाल फिलहाल में ट्रंम ने जिस तरह से भारत को धोखा दिया है, उससे पूरे भारत के लोग क्षुब्ध हैं।

इसके अतिरिक्त, जिस प्रकार से ट्रंप ने 26 भारतवासियों के नरसंहार के विलेन, आसिम मुनीर के साथ दावत खाकर पाकिस्तान को आईएमएफ फंड की बड़ी रक़म दे कर और 42 हज़ार करोड़ की मदद तेल निकालने की सहायता का दावा कर भारतीय जनता के दिलों पर कुठाराघात किया उससे उनकी पलटू दादा की छवि पर ठप्पा लग गया है। स्वयं उनकी अपनी जनता उन्हें ज्यादा विश्वसनीय नहीं मानती। वहीं भारतीय जनता के निकट वह एक धोखेबाज की छवि में अपना स्थान बना चुके हैं।

विपक्ष के नेता इस संदर्भ को लेकर मोदी के विरुद्ध नाना प्रकार के मोर्चे खोलने में लगे हुए हैं कि वे ट्रंप को झूठा नहीं कह रहे, जब उन्होंने कहा कि भारत-पाक युद्ध उन्होंने रुकवाया, जबकि यह पाकिस्तान सेना के डीजीएमओ ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वांस के आगे हाथ जोड़े थे कि भारत से युद्ध विराम की विनती की जाए। लोग सोचते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी को बड़े ज़ोरदार तरीके से ट्रंप को झाड़ लगानी चाहिए थी, मगर मोदी एक सुलझी हुई तबियत के विश्व स्तरीय नेता हैं, न कि ट्रंप की तरह अलट-पलट करने वाले व्यक्ति। यूक्रेन और पूर्व मध्य एशिया में युद्ध को लेकर बहुत से देशों के लिए ट्रंप संवेदनहीन व्यक्ति हैं, जैसे ईरान से बातचीत चलते रहते उन्होंने हमला कर दिया। उनका मामला ऐसा ही है, जैसे उर्दू का मुहावरा है, घड़ी में तोला, घड़ी में माशा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 25% वाले टैरिफ बम के बीच पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी की धरती से साफ किया कि हम उन वस्तुओं को खरीदेंगे जिसे बनाने में किसी न किसी भारतीय का पसीना बहा है। उन्होंने दुकानदारों से भी स्वदेशी चीजें बेचने की अपील की है। पीएम मोदी ने कहा कि अब हर भारतीय को ‘वोकल फॉर लोकल’ होना होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आगाह किया कि विश्व अर्थव्यवस्था अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर में

प्रवेश कर रही है।

विश्व की अस्थिर अर्थव्यवस्था के प्रति चिंता जताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका हित हमारे लिए सबसे ऊपर है। उन्होंने दुकानदारों से भी स्वदेशी माल बेचने की अपील की है। पीएम मोदी का यह बयान अमेरिका की ओर से करीब 70 देशों में टैरिफ लगाने के बाद आया है। व्हाइट हाउस के आदेश के अनुसार, भारत को अब अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात पर 25 फीसदी टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हाल ही में भारत को ‘डेड इकोनॉमी’ कहा था। ट्रंप के बेबुनियाद बयान को लेकर राहुल गांधी ने भी हल्की टिप्पणी की है, जिसका खंडन किया है भाजपा ने।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत भी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। लिहाजा भारत को भी अपने आर्थिक हितों को लेकर सजग रहना ही है। हमारे किसान, हमारे लघु उद्योग, हमारे नौजवानों के रोजगार, इनका ही हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि पहले हमें स्वदेशी और वोकल फॉर लोकल पर ध्यान देना होगा। हमें यह प्रण करना होगा कि हम सिर्फ अपने देश में बना हुआ सामान खरीदें। देश में बने हुए सामानों का प्रयोग करें। अब नया सामान जब भी खरीदें, स्वदेशी सामान ही खरीदें।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वदेशी उद्योग को समर्थन देने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब समय आ गया है कि हर भारतीय, चाहे वह किसी भी राजनीतिक विचारधारा का हो, पक्षपात से ऊपर उठकर स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ मोदी के कहने की बात नहीं है, बल्कि हर भारतीय को यह कहना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, तो हर राजनीतिक दल और हर नेता को अपनी झिझक छोड़कर राष्ट्रहित में काम करना होगा। लोगों में स्वदेशी की भावना जगानी होगी। जय हिंद !

# अनुच्छेद-370 हटने के साक्षी रहे सत्यपाल मलिक

**पूर्व** राज्यपाल सत्यपाल मलिक का मंगलवार को निधन हो गया। 79 वर्षीय सत्यपाल मलिक लंबे समय से बीमार थे। उन्होंने दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में आखिरी सांस ली। सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर के अलावा बिहार, गोवा और मेघालय जैसे राज्यों में राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दीं। 25 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक जाट परिवार में सत्यपाल मलिक का जन्म हुआ। मेरठ से उन्होंने अपनी शिक्षा हासिल की। राजनीतिक सफर की बात करें तो सत्यपाल मलिक ऐसे राजनेता थे, जो मौका देख कांग्रेस, जनता दल और भाजपा की नाव पर सवार हुए।

उन्होंने लोहिया की समाजवादी विचारधारा से प्रेरित होकर 1965-66 में सक्रिय राजनीति में कदम रखा। 1974 में वह बागपत विधानसभा क्षेत्र से भारतीय क्रांति दल के टिकट पर उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य चुने गए और विधानसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक नियुक्त किए गए।

1980 में 'लोकदल' के सहारे उन्होंने संसद में कदम रखा। वह राज्यसभा

● कभी कांग्रेसी, कभी भाजपाई, ऐसे बदलता गया सियासी सफर

सदस्य मनोनीत किए गए थे। हालांकि, 4 साल बाद 'लोकदल' छोड़कर उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। उन्हें 1986 में कांग्रेस ने राज्यसभा भेजा और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव की जिम्मेदारी दी। अगले ही साल, 1987 में 'बोफोर्स घोटाले' से खफा होकर उन्होंने राज्यसभा के साथ-साथ कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और अपनी पार्टी 'जन मोर्चा' का गठन किया। हालांकि, 1988 में उन्होंने अपनी पार्टी का जनता दल में विलय कर लिया।

1989 में जनता दल के टिकट पर वह अलीगढ़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर, 2004 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर बागपत लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा। 2012 में भाजपा ने उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। 2017 तक वह राजनीति से दूर हो गए और भाजपा ने उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया। 23 अगस्त 2018 को सत्यपाल मलिक ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के रूप में शपथ ली। बाद में, वे गोवा चले गए । फिर उन्हें मेघालय का राज्यपाल बनाया गया था। अपने राजनीतिक जीवन में वह जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा में आए। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया और एक पूर्व राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था। संयोग है कि उनके कार्यकाल में ही ठीक 6 साल पहले, 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त किया गया था, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है।

--आईएएनएस

# कर्नाटक में धर्मस्थल मामले में एक और जांच एसआईटी को

**मंगलुरु** ,(पंजाब केसरी: कर्नाटक के मंगलुरु में धर्मस्थल नामक गांव में कथित तौर पर सामूहिक रूप से लोगों को दफनाने से संबंधित मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) को मंगलवार को एक लड़की के शव से जुड़ा एक और मामला सौंपा गया। पुलिस सूत्रों ने यह जानकारी दी।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया और उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना ही लड़की के शव को धर्मस्थल गांव में दफना दिया गया। रिपोर्ट जमा होने के बाद, यह मामला अब एसआईटी के अधिकार क्षेत्र में आ गया है, जो आगे की सभी मामलों की जांच करेगी।

एसआईटी ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जिसमें दोनों शिकायतकर्ताओं द्वारा बताए गए स्थानों की जांच भी शामिल है। दूसरे शिकायतकर्ता, जयंत टी. ने पहले कहा था कि उन्होंने एक लड़की को अवैध रूप से दफनाते हुए देखा था। शुरुआत में, वह जानकारी साझा करने के लिए बेलथांगडी में स्थित एसआईटी कार्यालय पहुंचा।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

# प्रवाह

7 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

अच्छा बनना आसान है, लेकिन न्यायपूर्ण होना बेहद कठिन। -विक्टर ह्यूगो

**उत्तराखंड के धराली गांव में बादल फटने से हुई तबाही ने एक बार फिर इस राज्य में प्राकृतिक दुर्योग से अचानक आने वाली आपदा की ओर ध्यान खींचा है। राहत व बचाव कार्य तो चल ही रहा है, लेकिन बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं नीति नियंताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए।**

## फिर तबाही

उत्तराखंड में उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में बादल फटने के कारण खीरगंगा में भयंकर बाढ़ आने से हुई तबाही भीषण तो है ही, इस त्रासदी ने एक बार फिर इस राज्य में प्राकृतिक दुर्योग से अचानक आने वाली आपदा की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। दरअसल, राज्य का भूगोल चरम मौसमी घटनाओं के प्रति बेहद संवेदनशील है, जो इसे ऐसी आपदाओं का केंद्र बनाता है। धराली में आई बाढ़ के जो दृश्य दिख रहे हैं, वे वाकई भयावह हैं। यह अपने साथ कितने घर, दुकानें और होटल बहा ले गई, उसका आकलन होना बाकी है, लेकिन पीछे छूटे डर व अनिश्चितता के चिह्नों को साफ देखा जा सकता है। उत्तरकाशी के लोग ऐसी विपत्तियों से अपरिचित नहीं हैं, फिर भी इस त्रासदी की गंभीरता आत्ममंथन की मांग तो करती ही है, कि प्रतिक्रिया के बजाय पूर्व तैयारी की जरूरत को समझने से पहले हमें और कितनी जानें गंवानी पड़ेंगी। लगातार बारिश और बाढ़ के साथ काफी मलबा आने से बचाव अभियान में मुश्किलें आ रही हैं। इस बीच धराली के पास सुखी टॉप में भी बादल फटने की खबरें मिली हैं। दरअसल, पूरा हिमालयी क्षेत्र जलवायु परिवर्तन का दंश झेल रहा है, जहां अनियमित मौसमी पैटर्न, ग्लेशियरों का टूटना और बादल फटने की घटनाएं बार-बार हो रही हैं। अनियोजित शहरीकरण और वनों की कटाई ने इस क्षेत्र की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है, जिससे ढलान अस्थिर और बाढ़ की विनाशकारी शक्ति और बढ़ गई है। फिलहाल, पूरा ध्यान त्वरित बचाव और राहत कार्यों पर होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित लोगों को भोजन, आश्रय और चिकित्सा सहायता तो तुरंत मिले ही, बचे हुए लोगों के लिए भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक राहत के उपाय भी होने चाहिए। दरअसल, भविष्य को देखते हुए, उत्तराखंड को अपनी अनूठी भौगोलिक स्थिति के अनुरूप एक व्यापक आपदा प्रबंधन रणनीति की जरूरत है। अन्य आपदा-प्रवण क्षेत्रों में

प्रभावी साबित हुई प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को अपनाने पर भी ध्यान दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, आपदा तैयारियों में स्थानीय समुदाय की भागीदारी उन्हें ज्यादा जागरूक बनाएगी। पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण व भूमि उपयोग के कुछ सख्त नियम बनाने भी जरूरी हैं। धराली में जो नुकसान हुआ, वह फिर यह स्मरण कराता है कि प्रकृति भेदभाव नहीं करती, पर हमारी तैयारियां फर्क ला सकती हैं। बेशक सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ आदि की तत्काल सक्रियता से नुकसान को यथासंभव कम किया जा सका है, इसके बावजूद उत्तराखंड में बार-बार आने वाली प्राकृतिक आपदाएं नीति नियंताओं के लिए चिंता का विषय होना ही चाहिए।

## आखिर कमी कहां रह जाती है

**मुंबई की लोकल ट्रेनों व मालेगांव बम धमाकों में अभियोजन पक्ष अंततः अभियुक्तों के अपराध को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में विफल रहा। कहा जा सकता है कि न्यायपालिका उच्च कानूनी मानकों को बनाए रखना चाहती थी। उसने संदेह या त्रुटिपूर्ण जांच के आधार पर आरोपियों को दोषी ठहराने से इन्कार कर दिया।**

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

हाल ही में दो हाई-प्रोफाइल आतंकी हमलों के मामलों में आए फैसलों ने आतंकवाद से जुड़े मामलों की जांच, साक्ष्य संकलन और कानूनी ढांचे से जुड़ी गंभीर खामियों को उजागर किया है। दोनों ही फैसलों में सभी आरोपियों को बरी कर दिया गया, जिससे न्यायिक प्रक्रिया और उसके निहितार्थों की गहन जांच की मांग उठी है।

वर्ष 2006 में मुंबई में पश्चिमी लाइन पर लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार सात बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोग मारे गए और 800 से अधिक घायल हुए थे। बीती 22 जुलाई को, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया। इसने विशेष मकोका अदालत के उस फैसले को पलट दिया, जिसमें उन्हें पहले दोषी ठहराया गया था। हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस के आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) द्वारा की गई जांच की भी कड़ी आलोचना की तथा गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं और विश्वसनीय साक्ष्यों के अभाव की ओर इशारा किया। अदालत ने टिप्पणी की कि एटीएस ने 'मामले को सुलझाने का झूठा दिखावा' किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाई-प्रोफाइल आतंकी मामलों में जांच-प्रक्रिया की निष्पक्षता और पुलिस की जवाबदेही के प्रति चिंता जताई। अदालत की टिप्पणियों ने उचित प्रक्रिया को बनाए रखने और निष्पक्ष सुनवाई के मानकों को सुनिश्चित करने में व्यवस्थागत विफलता की ओर इशारा किया।

बम बनाने में प्रयुक्त सामग्री, जिहादी साहित्य आदि सहित साक्ष्यों की मौजूदगी के बावजूद, जांच एजेंसी ने मकोका के तहत दर्ज इकबालिया बयानों पर ही काफी हद तक भरोसा किया, जिन्हें उच्च न्यायालय ने अपर्याप्त पाया, क्योंकि उनके समर्थन में कोई साक्ष्य नहीं था। इसके अलावा, प्रक्रियागत त्रुटि का हवाला देते हुए जांच एजेंसी ने कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य नष्ट कर दिए।

देवेंद्र फडणवीस सरकार ने मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले में दोषियों को बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ तुरंत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। नतीजतन, सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक मिसाल के तौर पर हाईकोर्ट के फैसले के

अमल पर रोक लगा दी। हालांकि, उसने कहा कि रिहा किए गए दोषियों को आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं है।

महाराष्ट्र के मालेगांव में एक मस्जिद के पास 29 सितंबर, 2008 को विस्फोट हुआ था, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई और सौ से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 31 जुलाई को मुंबई की एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) अदालत ने घटना के लगभग 17 साल बाद, पूर्व भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित सभी सात आरोपियों को बरी कर दिया। एनआईए कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष 'विश्वसनीय और ठोस' सुबूत पेश करने में विफल रहा।

रमजान के आखिरी दिन और नवरात्र शुरू होने से पहले हुए हमले के इरादे पर अदालत ने साफ कहा कि 'यह स्पष्ट था कि षड्यंत्रकारियों ने लोगों को आतंकित करने, जान-माल की हानि पहुंचाने, समुदाय के लिए आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं को बाधित करने, सांप्रदायिक दरार पैदा करने और राज्य की आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने के इरादे से बम विस्फोट किया।' हालांकि, विशेष न्यायाधीश एके लाहोटी की अध्यक्षता वाली एनआईए अदालत ने अभियोजन पक्ष के मामले में कई गंभीर कमियों को उजागर किया। अदालत ने जोर देकर कहा कि 'मात्र संदेह वास्तविक सुबूत की जगह नहीं ले सकता। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अदालत केवल धारणा के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती।' अदालत ने स्पष्ट किया कि दोषसिद्धि के लिए काल्पनिक आरोपों के बजाय ठोस सुबूतों की आवश्यकता होती है।

मालेगांव मामले की जांच महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) द्वारा शुरू की गई थी। उस समय एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, जो जांच का नेतृत्व कर रहे थे, इस मामले में पहली गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद 26 नवंबर, 2008 को मुंबई आतंकवादी हमले में शहीद हो गए थे।

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 'हिंदू आतंकवाद' का ढिंढोरा पीटा था। साध्वी प्रज्ञा ने अदालत में शिकायत की थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत व अन्य का नाम लेने के लिए उन्हें बुरी तरह प्रताड़ित किया गया था। इसी प्रकार, सैन्य खुफिया विभाग में कार्यरत कर्नल पुरोहित को भी अपराध स्वीकार करने के लिए मानसिक यातना दी गई। वर्ष 2011 में, एनआईए ने इस मामले को अपने हाथ में ले लिया और एटीएस की जांच की आलोचना की, जबकि वह उसी दिशा में आगे बढ़ रही थी। वर्ष 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हालात बदलने लगे। वर्ष 2016 में, उसने यह तर्क देते हुए कि एटीएस ने कड़े आतंकवाद-रोधी कानून को लागू करने में उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया, मकोका के आरोप हटा दिए।

इसके अलावा भी कई खामियां और चूकें थीं, जैसे अदालती रिकॉर्ड से 13 गवाहों के बयान गायब हो गए। तत्कालीन विशेष लोक अभियोजक, रोहिणी सालियान ने सार्वजनिक रूप से आरोप लगाया कि एनआईए ने उन्हें आरोपियों के प्रति 'नरम रुख अपनाने' के लिए कहा था। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लगभग दो दशकों की कानूनी लड़ाई नाकाम हो गई है। पीड़ितों के परिवार अब भी न्याय की तलाश में हैं। दोनों ही मामलों में अभियोजन पक्ष अंततः अभियुक्तों के अपराध को 'उचित संदेह से परे' साबित करने में विफल रहा। फैसलों ने जांच प्रक्रियाओं में गंभीर खामियों की ओर इशारा किया। इसके अलावा, दोनों ही मामलों में अभियुक्तों को बरी होने से पहले वर्षों जेल में बिताने पड़े।

कहा जा सकता है कि न्यायपालिका उच्च कानूनी मानकों को बनाए रखना चाहती थी। उसने संदेह या त्रुटिपूर्ण जांच के आधार पर दोषी ठहराने से इन्कार कर दिया। इन मामलों ने दिखाया कि न्याय के लिए मजबूत जांच पद्धतियों और उच्च-गुणवत्ता वाले साक्ष्यों की जरूरत क्यों है।

चूंकि, एनआईए ने यह नहीं कहा है कि वह बरी किए गए लोगों के खिलाफ अपील करेगी, इसलिए 2006 के मालेगांव विस्फोट से संबंधित मामलों का अभी तक कोई समापन नहीं हुआ है। इसी प्रकार, 2007 के समझौता एक्सप्रेस विस्फोटों, जिनमें 68 लोग मारे गए थे, 2007 के हैदराबाद मक्का मस्जिद विस्फोटों, जिनमें नौ लोग मारे गए थे, तथा 2007 के अजमेर दरगाह शरीफ विस्फोटों, जिनमें तीन लोगों की जान गई थी, के बारे में भी कोई अंतिम न्यायिक निर्णय नहीं हुआ है।

edit@amarujala.com

## जीवन धारा

सुकरात

हमारे पास अपने रास्ते बदलने का और खुद को बेहतर बनाने का हर पल कोई-न-कोई मौका होता है। अपने मन की गहराइयों में उतरें, अपने विचारों को परखें और एक अच्छा जीवन जिएं।

### खुद को जानना ही जीवन का मूल मंत्र

*ज्ञान और सद्गुण की खोज ही अच्छा जीवन जीने की कुंजी है। हमें अपने मन, विचारों और मूल्यों को समझना होगा। अपने आप को जानना ही जीवन का मूल मंत्र है। अगर हम स्वयं को नहीं जानते कि हम कौन हैं, हमारी इच्छाएं क्या हैं, हमारी कमियां क्या हैं, तो हमारी जिंदगी एक बिना नक्शे की यात्रा है। एक अपरीक्षित जीवन जीने लायक नहीं है। इसका मतलब है कि हमें अपने विचारों और कार्यों पर सवाल उठाने चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं, वह क्यों करते हैं? क्या हमारा हर कदम सच और न्याय की ओर ले जाता है? बगैर सवाल किए, लोग अक्सर बिना सोचे-समझे दूसरों का अनुसरण करते हैं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए भीड़ का पीछा करना छोड़ें। अपने मन की आवाज सुनें, और सवाल करें। एकमात्र सच्चा ज्ञान यह जानना है कि हम कुछ नहीं जानते। स्वयं से, दूसरों से सवाल करें। सवाल ही वह चिंगारी है, जो ज्ञान की ज्योति जलाती है। सच्चा ज्ञान तब शुरू होता है, जब हम अपनी अज्ञानता को स्वीकार करते हैं। दुनिया में बहुत से लोग यह मानते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं। लेकिन यह घमंड उनकी प्रगति को रोकता है। ज्ञान एक अनंत यात्रा है। हर सवाल, हर जवाब हमें सत्य के और करीब ले जाता है। हम सभी को, चाहे बुजुर्ग हो या जवान, दुनिया की बाकी सभी चिंताओं को छोड़ देना चाहिए, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा के सर्वोत्तम विकास की चिंता करनी चाहिए। अच्छा इन्सान वही है, जो अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है। धन, शोहरत या सुख-सुविधाएं हमें एक पल की खुशी दे सकती हैं। लेकिन सच्ची खुशी सदाचार में है, साहस, न्याय, संयम, और बुद्धिमत्ता में है। जिंदगी में हार-जीत, सुख-दुख सब आते हैं। दुख ही सुख का कारण है, अंधेरे के बिना उजाला कैसा? मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। चुनौतियां हमें सबक सिखाती हैं। डरने की जरूरत नहीं, हर कदम पर सीखें और आगे बढ़ें। जैसे हमारे वचन होंगे, वैसे ही हमारा सम्मान होगा। और जैसा हमारा कर्म होगा, वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। हम जो करते हैं, वही हमारा भविष्य बनाता है। अगर हम ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं, अगर हम दूसरों के साथ सम्मान और प्रेम से पेश आते हैं, तो हम एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। हमारे जीवन का अच्छा शिक्षक वही है, जो हमें सोचने पर मजबूर कर दे। यानी हमें खुद को समझने के लिए किसी दूसरे पर निर्भर होने की जरूरत नहीं है। एक शिक्षक का काम भविष्य के महान मस्तिष्कों को जागृत और प्रज्वलित करना है। मन में कभी यह विचार न लाएं कि हमारी जिंदगी का फैसला पहले से ही लिखा हुआ है। हमारे पास अपने रास्ते बदलने का, स्वयं को बेहतर बनाने का हर पल कोई-न-कोई मौका होता है। सत्य तक पहुंचने का रास्ता सवालों से होकर जाता है। अपने मन की गहराइयों में उतरें, अपने विचारों को परखें और एक अच्छा जीवन जिएं। ऐसा जीवन, जो न केवल खुद को, बल्कि हमारे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करे। जिंदगी में केवल एक ही चीज अच्छी है, ज्ञान, और केवल एक ही चीज बुरी है, अज्ञानता।*

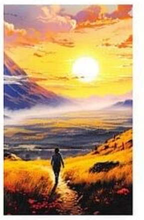

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

### नया गढ़ने के लिए तैयार रहें

सूत्र

*जीवन में बिना रुके हमेशा आगे बढ़ते रहें। मुश्किलें हमारे साथ ही रहेंगी, लेकिन यदि आप इन मुश्किलों को पहले से निर्धारित मानते हैं, तो आप हार जाएंगे। अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण रखें और खुद से कुछ नया गढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहें। जीवन हर दिन पहले से सुंदर और बेहतर हो जाएगा।*

## दूसरा पहलू

एक चिड़ियाघर ने हिंसक पशुओं के आहार के लिए लोगों से उनके मरणासन्न पालतू जानवरों को दान देने की अपील की है।

### क्यों विवादों में घिरे हैं डेनमार्क के चिड़ियाघर

**डेनमार्क** का एक चिड़ियाघर मरणासन्न पालतू जानवरों-गिनी पिग, खरगोश, मुर्गियों और यहां तक कि छोटे घोड़ों-के मालिकों से अनुरोध कर रहा है कि वे इन्हें शिकारी जानवरों के आहार के लिए दान कर दें। बीते दिनों फेसबुक पर आल्बोर्ग चिड़ियाघर ने ऐसी अपील की। इन जानवरों को प्रशिक्षित कर्मचारियों द्वारा 'धीरे-धीरे मार दिया जाएगा' और फिर चिड़ियाघर के शिकारी जानवरों, जैसे यूरोपीय वनबिलाव, शेर व बाघ आदि के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। घोड़ों के लिए शर्त रखी गई है कि उनका हाल में किसी बीमारी के लिए इलाज न हुआ हो। मुर्गियों, खरगोशों और गिनी पिग्स को कार्यदिवसों में सुबह दस बजे से दोपहर एक बजे के बीच स्वीकार किया जाएगा, लेकिन एक बार में चार से ज्यादा जानवर नहीं होने चाहिए।

अलेक्सा रॉबलेस गिल

आलोचक इसे अस्वीकार्य और गलत चलन बता रहे हैं। हालांकि, ऑलबोर्ग चिड़ियाघर प्रबंधन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है।

आलोचक इसे अस्वीकार्य व गलत चलन बता रहे हैं। आल्बोर्ग चिड़ियाघर ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। एक प्रवक्ता ने *पॉपुलर साइंस* को बताया कि 'कई वर्षों से' कर्मचारी 'मांसाहारी जानवरों को छोटे जानवर खिलाते आ रहे हैं।' हालांकि, कुछ लोग इस पहल की सराहना भी कर रहे हैं। एक यूजर ने टिप्पणी की कि उसका खरगोश को दान करने का अनुभव शानदार रहा। बीते चालीस वर्षों से आल्बोर्ग चिड़ियाघर में नियमित आने वाली सिग्ने फ्लाइवहोम ने कहा कि वह अपने प्रिय घोड़े को दान करना चाहती हैं, क्योंकि वह बहुत कमजोर हो गया है। यह पहली बार नहीं है कि डेनमार्क के चिड़ियाघरों को उनके बेपरवाह दृष्टिकोण के कारण आलोचना का सामना करना पड़ा है। 2014 में कोपेनहेगन चिड़ियाघर ने शेर व अन्य हिंसक जानवरों को खिलाने के लिए मारियस नाम के एक स्वस्थ युवा जिराफ को मार दिया था और शव का परीक्षण देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था। कुछ हफ्तों बाद चिड़ियाघर में चार शेरों-दो शावक और उनके माता-पिता को मार डाला। इसके पीछे चिड़ियाघर प्रबंधन ने तर्क दिया कि ऐसा इसलिए किया गया, ताकि नर शेर अपनी बेटियों के साथ प्रजनन न कर सकें और युवा नर शेर शावकों पर हमले न कर सकें। इन मौतों ने पशु अधिकार कार्यकर्ताओं की नाराजगी बढ़ाई, लेकिन चिड़ियाघर प्रबंधन के प्रति एक ट्रांस-अटलांटिक दार्शनिक विभाजन को भी दर्शाया। अमेरिकी चिड़ियाघर अक्सर जानवरों की आबादी में तेजी से वृद्धि को रोकने के लिए गर्भनिरोधक उपायों पर निर्भर रहते हैं, जबकि यूरोपीय चिड़ियाघर जानवरों को प्रजनन करने की अनुमति देते हैं, और बाद में 'अतिरिक्त' जानवरों को मार देते हैं।

2014 में कोपेनहेगन चिड़ियाघर ने हिंसक जानवरों को खिलाने के लिए मारियस नाम के एक स्वस्थ युवा जिराफ को मार दिया था और शव का परीक्षण देखने के लिए लोगों को आमंत्रित भी किया था।

*-साथ में एमिली एथेंस,* ©The New York Times 2025

## आंकड़े

### जीएसटी की चोरी

बीते पांच वित्त वर्षों में देश में सात लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की जीएसटी चोरी पकड़ी गई है। यह एजेंसियों की सक्रियता की वजह से संभव हुआ है।

| | |
|---|---|
| 2021 | 49,384 |
| 2022 | 73,238 |
| 2023 | 1,31,613 |
| 2024 | 2,30,332 |
| 2025 | 2,23,375 |

आंकड़े संबंधित वित्त वर्षों में पकड़ी गई जीएसटी चोरी के, करोड़ रुपये में | स्रोत : FoM

एक धनवान ने महाराज गोसाईं जी से कहा कि वह उनकी कुटिया को मजबूत और टिकाऊ बनवा देगा। उन्होंने कहा, अपने मन की कुटिया को मजबूत करो।

### ईंटों की कोठी कितने दिन टिकेगी

अंतर्यात्रा
संकलित

**बाबा** चैनराम जी के शिष्य महाराज गोसाईं पूर्वी बलिया के मिल्की गांव के निवासी थे। वह गृहस्थ जीवनयापन करते थे। किसी से अधिक मतलब नहीं रखते थे और कहीं किसी के यहां शीघ्र नहीं जाते थे। उनके घर में किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं था। फिर भी महाराज गोसाईं जी अपने गांव के बाहर पेड़ों के नीचे कुटिया बनाकर रहते थे और भगवान के भजन में लीन रहते थे। वह पूर्णतः विरक्त जीवन जीते थे।

उनके शिष्यों ने भगवान का नाम जपते हुए अपने हाथों से मिट्टी खोदकर सुंदर और विशाल कुटिया तैयार की थी। एक धनवान व्यक्ति ने महाराज गोसाईं जी से कहा कि वह कुटिया को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए इसे पक्की करने की आज्ञा दे दें। गोसाईं जी ने कहा, 'बेटा! तुम्हारी ईंटों की कोठी कितने दिन टकेगी? हमारी मिट्टी की कुटिया ही अच्छी है।' उन्होंने कहा, 'करना ही है, तो अपने मन की कोठी को मजबूत करो।' यह बात सुनते हुए धनवान को समझ आ गया कि असली संपत्ति तो राम नाम की कमाई है। कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता, तो गोसाईं जी महाराज कहते, 'मन लगाकर इस कुटिया को साफ कर दो।' ईश्वर कृपा से उसकी समस्या ठीक हो जाती। बताते हैं कि गोसाईं जी कुटिया की सफाई के लिए इसलिए कहते थे कि ताकि व्यक्ति को अपने अंदर की सफाई की प्रेरणा भी मिले।

## अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 06 अगस्त 1951

### भारतीय सेनाओं को सीमाओं से नहीं हटाया जाएगा

भारतीय सेनायें सीमा से नहीं हटेंगी

गांववालों द्वारा नशेबाज, सिपाही की पिटाई करने पर पुलिस दल द्वारा गांव पर चढ़ाई

**पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खां ने कश्मीर को भारत का अंग न मानकर अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। इस पर भारत ने कहा, कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग है। भारतीय सेनाएं सीमाओं से नहीं हटाई जाएंगी।**

## पुलिस भी तो स्मार्ट बने

**साइबर धोखाधड़ी और हाईटेक अपराधों के मामले जिस गति से बढ़ रहे हैं, पुलिस व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित होने की जरूरत है।**

सुनील कुमार गुप्ता, पूर्व आईपीएस, विधिक एवं प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञ

तकनीक

साइबर धोखाधड़ी, तस्करी, शहरी अपराध और सीमा पार आतंक जैसी जटिल समस्याएं बढ़ रही हैं, पुलिस व्यवस्था को भी उतनी ही तेजी से विकसित होने की जरूरत है। इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनिवार्य तत्व बन गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां जांच प्रक्रिया को तेज करने के लिए एआई को सक्रिय रूप से अपना रही हैं।

हवाई अड्डों पर 'डिजीयात्रा' परियोजना के तहत चेहरा पहचानने के सिस्टम से न सिर्फ बोर्डिंग की प्रक्रिया तीव्र हो रही है, बल्कि वांछित व्यक्ति भी पहचाने जा रहे हैं। हाईवे पर एआई आधारित नंबर प्लेट पहचान प्रणाली का पायलट परीक्षण हो रहा है, ताकि संदिग्ध या चोरी हुए वाहनों की पहचान कर उन्हें समय रहते रोका जा सके। ये प्रणाली केंद्रीय अपराध डाटाबेस से जुड़ी होती हैं और निकटतम गश्ती दल को त्वरित सूचना भेजती हैं। यह प्रणाली विशेष रूप से अंतरराज्यीय तस्करी, अपहरण या वाहन चोरी जैसे मामलों में प्रभावी सिद्ध हो रही है। टोल प्लाजा, सीसीटीवी नेटवर्क और सीमा चौकियां अब एक जुड़े हुए निगरानी तंत्र का हिस्सा बनती जा रही हैं।

पारंपरिक तरीकों की सीमाएं हैं-जैसे धुंधले सीसीटीवी फुटेज या अधूरी गवाही-एआई आधारित समाधान सहायक सिद्ध हो रहे हैं। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में एआई-सक्षम स्केचिंग सॉफ्टवेयर का परीक्षण किया गया है, जो गवाहों द्वारा दिए गए विवरणों के आधार पर डीप लर्निंग तकनीक से चेहरे की डिजिटल छवियां तैयार करता है। तैयार की गई छवियों की तुलना राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) द्वारा बनाए गए चेहरे पहचान डाटाबेस से की जाती है। यह प्रणाली विशेष रूप से गुमशुदा व्यक्तियों, झपटमारी और नए अपराधियों की पहचान में प्रभावी रही है। एनसीआरबी के अनुसार, भारत में साइबर अपराधों में 20 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि हुई है। तेलंगाना व कर्नाटक जैसे राज्यों में एआई-सक्षम साइबर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं।

एनसीआरबी द्वारा विकसित 'ई-साक्ष्य' एप पुलिस अधिकारियों को वीडियो या ऑडियो जैसे डिजिटल साक्ष्यों को मेटाडाटा और एन्क्रिप्शन सहित प्रस्तुत करने की सुविधा देता है, जिससे वे अदालत में स्वीकार्य और छेड़छाड़ से मुक्त रहते हैं। इसी तरह, 'ई-प्रोसीक्यूशन' पोर्टल जो अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (सीसीटीएनएस) से जुड़ा हुआ है, पुलिस थानों से अभियोजन कार्यालयों तक प्रकरण विवरण को स्वचालित रूप से भेजता है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, उत्तर प्रदेश ने इस प्लेटफॉर्म का सबसे प्रभावी उपयोग किया है और मामलों का त्वरित निपटारा किया है।

एआई आधारित पुलिसिंग केवल दिल्ली, मुंबई या बंगलूरू जैसे महानगरों तक सीमित नहीं है। छोटे शहरों में भी इसे 'डिजिटल इंडिया' के तहत परीक्षण के लिए अपनाई जा रही है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक रीयल-टाइम एआई डैशबोर्ड लागू किया गया है, जो एफआईआर की प्रगति पर नजर रखता है, समय पर चार्जशीट दाखिल करने को सुनिश्चित करता है और प्रक्रियात्मक त्रुटियों की पहचान करता है। आगरा और भोपाल जैसे जिलों में पुलिस अधिकारियों को एआई आधारित चैट असिस्टेंट के माध्यम से एफआईआर का मसौदा तैयार करने, केस लॉ का सारांश बनाने और शिकायतों का भाषाई अनुवाद करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

2024 में प्रकाशित एक अध्ययन ने एआई को लेकर प्रमुख चिंता उजागर की है-'ब्लैक बॉक्स समस्या', यानी पारदर्शिता की कमी। उदाहरण के लिए, चेहरे की पहचान प्रणालियों में विश्व स्तर पर महिलाओं, वृद्धों और गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्तियों में त्रुटि दर अधिक पाई गई है। भारत में जिम्मेदार और प्रभावी एआई पुलिसिंग को साकार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक हैं। पहले, राज्यों को एक समान राष्ट्रीय ढांचा अपनाना चाहिए, जो एआई उपकरणों की खरीद, प्रशिक्षण, जवाबदेही और सार्वजनिक शिकायत निवारण की प्रक्रियाओं को निर्धारित करे। दूसरे, प्रत्येक जिले में समर्पित 'टेक सेल्स' की स्थापना की जानी चाहिए, जो स्थानीय पुलिस को एआई के नैतिक व प्रभावी उपयोग में मार्गदर्शन दे सकें। तीसरे, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरडी) को चाहिए कि वह पुलिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में एआई संबंधित मॉड्यूल अनिवार्य करे-जिसमें संचालनात्मक उपयोग के साथ-साथ नैतिक साक्षरता भी शामिल हो। सबसे महत्वपूर्ण, नागरिकों को यह जानकारी दी जानी चाहिए कि उनका डाटा कैसे एकत्र और उपयोग कैसे होता है, और उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है। पुलिस की जनसंपर्क गतिविधियों को सीसीटीवी कवरेज तक सीमित नहीं रहना चाहिए। यह भी समझें कि एआई का उपयोग कैसे निष्पक्ष और वैध तरीके से किया जा रहा है।

विशाल और युवा जनसंख्या, स्मार्टफोन की बढ़ती पहुंच और क्षेत्रीय विविधता के चलते भारत में एक ऐसा मॉडल विकसित हो सकता है, जो नवाचार व अधिकारों के बीच संतुलन बनाए। सही कानूनी सुधारों, संस्थागत दूरदर्शिता व जनविश्वास के साथ पुलिस बल तकनीकी रूप से उन्नत होकर और प्रभावी बन सकता है।

*-साथ में अक्षिता गुप्ता, शोध छात्रा (विधि)।*

हिन्दुस्तान
1936
सत्य • सार्थक • सदैव

# बादल और आपदा

उत्तराखंड के उत्तरकाशी में धराली गांव के ऊपर बादल फटने से मची तबाही का मंजर बेहद डरावना था। इस कुदरती हादसे में वास्तविक नुकसान तो खैर बचाव व राहत कार्यों के खत्म होने के बाद ही पता चल सकेगा, मगर जिस तरह चंद सेकंडों में दर्जनों पक्के मकान और होटल जमींदोज हो गए, उससे एक बार फिर यही पुष्ट हुआ है कि पुराने हादसों से हमने कुछ नहीं सीखा। इस विध्वंस के जो वीडियो फुटेज सामने आए हैं, वे साफ-साफ दिखा रहे हैं कि खीर गंगा नदी के बहाव क्षेत्र में बड़ी संख्या में कई-कई मंजिल की इमारतें खड़ी हो चुकी हैं। बल्कि एक पूरा बाजार विकसित हो चुका है। अगर तंत्र ने वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मानव बसाहट के विस्तार की योजना बनाई होती, तो इस तबाही से बचा जा सकता था। बहरहाल, संतोष की बात यह है कि जल्द ही सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गईं और मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का काम शुरू हो गया। एम्स, ऋषिकेश को भी आपात स्थिति के लिए सचेत कर दिया गया, ताकि घायलों को तत्काल जरूरी उपचार मिल सके।

मानसून के समय पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं होती रहती हैं, मगर इस सच्चाई से नहीं मुकरा जा सकता कि पिछले एक दशक में इनकी बारंबारता बढ़ी है। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के स्थानीय जलचक्र में बदलाव इसकी बड़ी वजह है। पहले पहाड़ी इलाकों में इंसानी गतिविधियां कम होती थीं, मगर हाल के दशकों में विकास कार्यों के कारण बड़ी संख्या में पेड़ों की कटाई, वनों में आग लगने की अधिक घटनाओं और पर्यटन के अधिकाधिक दोहन के लिए अविवेकपूर्ण निर्माण कार्यों ने स्थानीय पारिस्थितिकी को बुरी तरह प्रभावित किया है। निस्संदेह, पहाड़ी इलाकों के बाशिंदों को आधुनिक सुख-सुविधाएं मिलनी चाहिए। सड़क, बिजली और अस्पताल जैसी बुनियादी सहूलियतों पर भी उनका अधिकार है। मगर उनके लिए सुविधाएं जुटाते समय इन इलाकों की नाजुक पर्यावरणीय स्थितियों को ध्यान में रखने की भी जरूरत है। विडंबना यह है कि हमारी विकास परियोजनाओं में स्थानीय लोगों की आवश्यकता से अधिक सैलानियों की सहूलियत रहने लगी है। इस पर नए सिरे से गौर करने की जरूरत है।

**धराली की घटना कह रही है कि विकास-कार्यों में हमें आत्मघाती उदासीनता से अब उबर जाना चाहिए, अन्यथा ऐसी आपदाओं में अधिक नुकसान हम उठाते रहेंगे।**

उत्तरकाशी की इस घटना ने जून 2013 के केदारनाथ हादसे की यादें ताजा कर दी हैं, जिसमें पांच हजार से अधिक श्रद्धालु और स्थानीय लोग असमय काल के गाल में समा गए थे। उस हादसे में भी गांव के गांव बह गए थे और तब काफी जोर-शोर से यह मांग उठी थी कि संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में मानव बसाहट व निर्माण-कार्य को लेकर नए सिरे से नीति-निर्धारण किया जाए। धराली बाजार की तबाही बता रही है कि इस दिशा में कितनी संजीदगी से काम हुआ है! यह स्थिति सिर्फ पहाड़ी इलाकों की नहीं है, प्रयागराज और बनारस में घरों में पानी घुसने की तस्वीरें भी अखबारों में रोज साया हो रही हैं। जल विशेषज्ञों की मानें, तो पहले ढाई दिनों में बाढ़ का पानी इसलिए उतर जाता था, क्योंकि उनकी निकासी के मार्ग अवरुद्ध नहीं होते थे। अब उन रास्तों पर कंक्रीट के जंगल उग आए हैं। ऐसा नहीं है कि विकसित देशों को कुदरत बख्श देती है या वहां बाढ़ से लोग नहीं मरते, पर उनकी नीतियां मानव क्षति को न्यूनतम करने के दर्शन से प्रेरित होती हैं। धराली की घटना कह रही है कि हमें आत्मघाती उदासीनता से अब उबर जाना चाहिए, वरना हम नुकसान उठाते रहेंगे।

## हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
06 अगस्त, 1950

### राजनीतिक चलचित्र

गुरुवार को प्रधानमंत्री पं. जवाहरलाल नेहरू ने संसद में 70 मिनट तक जो भाषण किया, वह अन्तरराष्ट्रीय भाषणों के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगा। संसार की वर्तमान संकटपूर्ण स्थिति का उन्होंने वास्तविक चित्रण करते हुए कहा : 'युद्ध तथा शांति के संबंध में संसार का भाग्य एक पतले धागे से लटका जान पड़ता है, जो तलवार से कट सकता है अथवा तोप से उड़ सकता है।' जब ऐसी स्थिति हों, तब कोई विश्वासपूर्वक यह नहीं कह सकता कि कोरियाई युद्ध कोरिया तक ही सीमित रहेगा और संसार के अन्य क्षेत्रों में भयंकर विस्फोट नहीं होंगे। जबकि संसार के कतिपय बड़े राष्ट्र अणु बम को शांति का एकमात्र रक्षक समझने लगे हैं, भारत की धारणा इससे भिन्न है। वह नैतिकता को सब प्रश्नों की कसौटी मानकर शांतिपूर्ण तथा समझौते के तरीकों को ही अपनाना चाहता है। इसका यह अर्थ नहीं कि भारत आक्रमण तथा अन्याय की स्थिति में भी शुतुरमुर्ग की भांति बालू में गर्दन गड़ाकर प्रतिरोध से बचना चाहता है।

भारत के उच्चतम प्रवक्ता कितनी ही बार इस बात को स्पष्ट कर चुके हैं कि अन्तरराष्ट्रीय गुटबन्दी के बारे में उसकी तटस्थता का अर्थ सब स्थितियों में निष्क्रिय तटस्थता नहीं है। नेहरूजी ने संसद में अपने भाषण में तथा फिर बहस के उत्तर में स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की अपनी स्वतंत्र नीति है और वह किसी राष्ट्र के चरण-चिह्नों का अनुगामी नहीं बन सकता। उन्होंने कहा : 'हम स्वयं अपने लिए यह निर्णय करते हैं कि हमारे तथा विश्व-शांति के हित में क्या ठीक है।' नेहरूजी के शांति-प्रस्तावों का कुछ क्षेत्रों में जो गलत अर्थ लगाया गया था, उसका भी प्रधानमंत्री के इस भाषण तथा संसद की बहस से निराकरण हो जाता है। भारत यह नहीं कहता कि चीन की जन-सरकार के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में नहीं लिया जाता, तब तक कोरियाई प्रश्न को हल ही नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन इसमें संदेह नहीं कि यदि चीन की साम्यवादी सरकार के प्रतिनिधि को संयुक्त राष्ट्र संघ में ले लिया जाये, तो वातावरण बदल जायेगा और उस स्थिति में कोरिया की समस्या को सुलझाने में अधिक आसानी रहेगी। इस सत्य से कौन आंखें मूंद सकता है कि विश्व-शांति की एकमात्र आशा संयुक्त राष्ट्र संघ है। इस संघ का अर्थ केवल एक ही विचारधारा के देशों का संघ नहीं, अपितु संसार के सभी राष्ट्रों का संघ है।

# रूस से हमारे रिश्ते पर कुढ़ता अमेरिका

यहां स्कैन करें

**विवेक काटजू** | पूर्व राजनयिक

**भारत ने उचित ही कहा कि रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों का भारत को निशाने पर लेना अनुचित और अन्यायपूर्ण है।**

सोमवार की देर शाम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में यह इल्जाम लगाया कि भारत न केवल बड़ी मात्रा में रूस से तेल आयात कर रहा है, बल्कि उसको अंतरराष्ट्रीय बाजार में बड़े मुनाफे पर बेच भी रहा है। उन्होंने यूक्रेन-युद्ध में मारे जा रहे लोगों की अनदेखी करने का आरोप भी भारत के सिर पर मढ़ा और धमकी दी कि इसी कारणवश वह भारतीय निर्यात पर अधिक सीमा शुल्क लगाएंगे। याद रहे, भारतीय निर्यात पर 25 फीसदी सीमा शुल्क लगाने की घोषणा वह पहले ही कर चुके हैं।

ट्रंप की इस पोस्ट के कुछ ही घंटों के भीतर भारत की तीखी प्रतिक्रिया आई। विदेश मंत्रालय के बयान में भारत ने कहा कि रूस से तेल आयात करने के मामले में अमेरिका और यूरोपीय संघ के देशों का भारत को निशाने पर लेना 'अनुचित' और 'अन्यायपूर्ण' है। इस बयान में याद दिलाया गया कि यूरोपीय संघ के देश भी रूस से ऊर्जा आयात करते रहे हैं और उसके साथ बड़े पैमाने पर व्यापार भी किया है। यही नहीं, खुद अमेरिका न सिर्फ अपने परमाणु और इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग के लिए रूस से आयात कर रहा है, बल्कि उर्वरक व रसायन भी वहां से मंगवाता रहता है। अंततः, भारत ने यह साफ कर दिया कि वह अपने राष्ट्रहित व आर्थिक सुरक्षा के लिए हर उचित कदम उठाएगा।

हालांकि, भारतीय बयान में अमेरिका और यूरोपीय संघ, दोनों को समान रूप से निशाने पर लिया गया है, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ट्रंप प्रशासन के दौरान दोनों का रवैया अलग-अलग रहा है। बेशक, दोनों चाहते हैं कि भारत रूस से तेल आयात न करे। यूरोपीय संघ ने हमारी कुछ तेल कंपनियों पर प्रतिबंध भी लगाए हैं, जो रूस से तेल खरीदती रही हैं। मगर यूरोपीय संघ ने वैसा कोई कदम नहीं उठाया है, जिस तरह की धमकी राष्ट्रपति ट्रंप देते रहे हैं। इसलिए, इस समय भारत की आर्थिक चुनौतियां मुख्य रूप से ट्रंप प्रशासन की देन हैं, न कि यूरोपीय संघ की।

इसका मतलब है कि भारत की प्रतिक्रिया और नीति यूरोपीय संघ और अमेरिका के प्रति अलग-अलग होनी चाहिए। जो बयान जारी किया गया, यदि वह ट्रंप की धमकी तक सीमित रहता, तो उसका शायद ज्यादा असर पड़ता। बहरहाल, सवाल यह है कि ट्रंप इतना आक्रामक रुख क्यों अपना रहे हैं और हमारा अगला कदम क्या होना चाहिए? इसका जवाब तलाशने के लिए हमें ट्रंप के उन बयानों को याद करना चाहिए, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि पद संभालते ही वह रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करा देंगे। वह वास्तव में बताना चाहते थे कि रूस के प्रति जो बाइडन की नीति गलत थी। मगर ऐसा नहीं हो सका है।

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की पर तो उनका दबाव काफी हद तक काम कर गया है, पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अड़े हुए हैं कि यूक्रेन न तो यूरोपीय संघ व नाटो का सदस्य बनेगा और रूस के प्रभाव-क्षेत्र में रहेगा, बल्कि जो इलाके मॉस्को ने इस युद्ध में कब्जा कर लिए हैं, उन पर भी यूक्रेन और विश्व को मुहर लगानी होगी। चूंकि ट्रंप की नजर में ये पुतिन की गैर-वाजिब शर्तें हैं, लिहाजा रूस के प्रति उनकी नाराजगी बढ़ रही है। इसीलिए, वह उसके विभिन्न स्रोतों पर शिकंजा कसने का प्रयास कर रहे हैं। यह और बात है कि तेल-निर्यात से रूस को खूब आर्थिक मदद मिलती है। वह फिलहाल अपना 80 प्रतिशत तेल चीन और भारत को बेच रहा है और अनुमान है कि बीते दो-ढाई वर्षों में वह भारत को तेल-आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया है। भारत सरकार का यह फैसला बिल्कुल सही है, क्योंकि राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना हर सरकार का पहला कर्तव्य होता है।

मगर सिद्धांतों के आधार पर अंतरराष्ट्रीय संबंध नहीं चलते। यदि कोई देश इन पर अटल रहता है, तो उसे कुछ-न-कुछ कीमत भी चुकानी पड़ती है। यही कारण है कि भारत के सामने नई चुनौतियां पेश आई हैं। ऐसे में, सवाल यह है कि क्या भारत अपने सिद्धांतों पर अटल रहेगा या फिर कुछ नरमी दिखाकर रूस से अपना तेल आयात कम कर लेगा? हालांकि, खबर यह भी है कि हमारी निजी तेल कंपनियों ने खुद ही रूस से तेल मंगाना कम कर दिया है।

जाहिर है, भारत और अमेरिका के रिश्ते इस वक्त ट्रंप की नीतियों के कारण एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। भारत को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के निजी रिश्ते इतने सुखद हैं कि दोनों देश अपने मतभेदों का समाधान निकाल लेंगे। मगर जब दांव पर राष्ट्रीय हित हो, तो शासनाध्यक्षों की मित्रता शायद ही मायने रखती है। इस समय हमें आर्थिक ही नहीं, अमेरिका से राजनीतिक व सामरिक चुनौती भी मिलती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपने रिश्ते पाकिस्तान से ज्यादा मधुर करने की कोशिश कर रहा है। इतना ही नहीं, तमाम खंडन के बावजूद ट्रंप बार-बार कह रहे हैं कि भारत-पाकिस्तान संघर्ष में उन्होंने ही मध्यस्थता करवाई है। इन सबसे लगता है, ट्रंप अमेरिका की पुरानी नीति पर शायद लौट रहे हैं कि भारत अपने पश्चिमी पड़ोसी की ओर ज्यादा नहीं देखे और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में वाशिंगटन से अधिक सहयोग करे। भारत के लिए मुश्किल यह भी है कि चीन के प्रति भी ट्रंप का रुख लचीला दिख रहा है। ऐसे में, मोदी सरकार को अब देश को साथ लेकर चलना होगा, क्योंकि विदेशी मोर्चे पर एक के बाद दूसरी कई चुनौतियां बढ़ गई हैं।

यहां रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया जखारोवा के बयान पर भी गौर करना चाहिए। उनका कहना है कि अमेरिका 'उपनिवेश-व्यवस्था' फिर से कायम करना चाहता है और रूस 'ग्लोबल साउथ' (वैश्विक दक्षिण) के देशों से अपना रिश्ता आगे बढ़ाएगा। मगर ऐसा कहते हुए वह शायद भूल गईं कि आज दुनिया जिन चुनौतियों से जूझ रही है, उसका बहुत हद तक कारण 2022 में रूस का यूक्रेन पर किया गया आक्रमण ही है, जो आज भी बदस्तूर जारी है। बेशक, उस समय रूस को उकसाने का प्रयास किया गया था, लेकिन इस आक्रमण को किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं ठहराया जा सकता। यह भी एक तरह का 'उपनिवेशवाद' ही है, जिसके लिए मारिया अब अमेरिका की तरफ उंगली उठा रही हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

# उत्तरकाशी में तबाही के लिए बरसात को दोष मत दीजिए

यहां स्कैन करें

**पंकज चतुर्वेदी** | वरिष्ठ पत्रकार

मंगलवार, 5 अगस्त का दिन उत्तरकाशी में तबाही लेकर आया। गंगोत्री धाम के प्रमुख पड़ाव धराली में खीर गंगा में बादल फटने से विनाशकारी बाढ़ आई। बाढ़ के चलते न जाने कितने होटल और घर तबाह हो गए हैं, जिसके वीडियो काफी भयावह हैं। खीर गंगा के जल ग्रहण क्षेत्र में ऊपर कहीं बादल फटा, जिसके कारण यह बाढ़ आई।

क्या इसका दोष बादल, बरसात या बाढ़ को दिया जाए? या यह भी देखा जाए कि पहाड़ी नदी से सटाकर निर्माण क्यों किए गए या फिर जब सरकारी रिपोर्ट चेता रही थी कि उत्तराखंड के पहाड़ों पर भूस्खलन का दायरा बढ़ता जा रहा है, तब संवेदनशील इलाकों में निर्माण के लिए पहाड़ों को गिराना क्या जरूरी है? मानसून है, तो दुनिया के सबसे जिंदा पहाड़ पर यह सब तो होना ही था।

इसी तरह, प्यास और पानी के लिए पलायन के कारण कुख्यात बुंदेलखंड में महाराज छत्रसाल द्वारा स्थापित छतरपुर शहर के सबसे बड़े तालाब किशोर सागर पर अवैध कब्जा कर कालोनी बसा लेने का विवाद आया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने 7 अगस्त, 2014 को किशोर सागर तालाब के मूल रकवा, भराव क्षेत्र और 10 मीटर के ग्रीन जोन को कब्जा मुक्त करने का आदेश दिया। सवाल अटक गया कि भराव क्षेत्र का निर्धारण कैसे हो? इस साल सावन में इतना पानी बरसा कि किशोर सागर के भीतर बसे मकानों में दस फुट तक पानी भर गया। एक झटके में तालाब ने बता दिया कि उसका अपना दायरा कहां तक है। अब भले ही समाज और मीडिया इसे बाढ़ कहे, किशोर सागर ने नैसर्गिक तरीके से अपना घर-पता दर्ज करवा दिया। सारे देश के हर गांव-कस्बे में छोटी नदियां हों, या पारंपरिक तालाब या फिर जोहड़, उन पर कब्जे हुए और अदालती लड़ाई में यह साबित करना टेढ़ी खीर हो गया कि अमुक जल-निधि का फैलाव कहां तक है? मानसून में इसका स्वाभाविक तरीका खुद-ब-खुद सामने दिख जाता है, बशर्ते उसे मापने-आंकने और दर्ज करने की इच्छाशक्ति हो।

**जब पहाड़ों पर भूस्खलन का दायरा बढ़ता जा रहा है, तब संवेदनशील इलाकों में कंक्रीट निर्माण की इजाजत देना क्या जरूरी है?**

नैसर्गिक बाढ़ विनाशकारी नहीं होती और उसके कुछ सकारात्मक पहलू भी होते हैं। बाढ़ के विकराल होने के पीछे नदियों का उथला होना, जलवायु परिवर्तन, बढ़ती गरमी, रेत की खुदाई, शहरी प्लास्टिक, खुदाई मलबे का नदी में भरना, जमीन का कटाव जैसे कई कारण दिनोंदिन गंभीर होते जा रहे हैं। जब नदी का पानी फैलता है, तो उससे आसपास के भूजल स्रोतों का पुनर्भरण होता जाता है। भूजल स्तर में सुधार से न केवल पानी का भंडार होता है, बल्कि यह धरती की सेहत के लिए भी अनिवार्य है। असम का बड़ा हिस्सा हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का उपजाऊ दोआब, ये सभी बाढ़ से बहकर आई मिट्टी से ही बने हैं। बाढ़ यह भी याद दिलाती है कि नदी इंसान की तरह एक जीवंत संरचना है और उसकी याददाश्त है और उसके जिम्मे पृथ्वी को समयानुसार संरचित करना भी है। सबसे बड़ी बात, इंसान जो भी कचरा, मलबा चुपके से नदी में डाल देता है, बाढ़ उसे साफ करती है और नदी के लिए गैरजरूरी तत्वों को छांटकर किनारे पटक देती है। बाढ़ के पानी से नदियों के प्रदूषक बहकर समुद्र या अन्य जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे नदी की शुद्धता और स्वच्छता में सुधार होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, यानी एनडीएमए के पूर्व सचिव नूर मोहम्मद का मानना है कि देश में समन्वित बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था पर कभी ध्यान नहीं दिया गया।

पानी को स्थानीय स्तर पर रोकना, नदियों को उथला होने से बचाना, बड़े बांध पर पाबंदी, नदियों के करीबी पहाड़ों पर खुदाई पर रोक और नदियों के प्राकृतिक मार्ग से छेड़छाड़ को रोकना कुछ ऐसे सामान्य प्रयोग हैं, जो बाढ़ को प्रकोप बनने से बचा सकते हैं। बाढ़ को एक आपदा के रूप में देखने के बनिस्बत इसके दीर्घकालिक लाभों पर विचार करना होगा। बाढ़ न केवल नदियों और उनके आसपास के पारिस्थितिकी तंत्र को पुनर्जीवित करती है, बल्कि यह प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में संतुलन बनाए रखने में भी मदद करती है। मानव सभ्यता को बाढ़ के साथ सह-अस्तित्व की रणनीतियों को अपनाने और इसके फायदों को समझने की जरूरत है, ताकि प्राकृतिक आपदाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम किया जा सके और इसके सकारात्मक पहलुओं का अधिकतम लाभ उठाया जा सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

## मनसा वाचा कर्मणा

# उपासना की नींव

बहुत सारे लोगों ने 'भक्ति, ज्ञान और ध्यान' के रहस्य को जानने की इच्छा जाहिर की है। आज इसी विषय पर आपसे बात करूंगा। इस संसार में, हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें अनेक प्रकार के स्वामियों, अधिकारियों और नियंत्रकों का अनुभव होता है। कोई किसी संस्था का प्रमुख होता है, कोई किसी विभाग का, कोई किसी संपत्ति का और कोई किसी शासन व्यवस्था का। परंतु इन सभी के ऊपर एक ऐसी सत्ता है, जो इन सबके संचालन की मूल शक्ति है, यानी परम पुरुष, परमब्रह्म या महेश्वर।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

संस्कृत में 'ईश' का अर्थ होता है नियंत्रित करना और 'ईश्वर' का अर्थ होता है नियंत्रक। विभिन्न व्यवस्थाओं के अनेक ईश्वर हो सकते हैं, परंतु उन सबके जो नियंता हैं, वह महेश्वर हैं, अर्थात सर्वोच्च! परमसत्ता नियंत्रक ही नहीं, उस शक्ति का स्रोत भी है, जो समस्त ब्रह्मांड को कंपित करती है। यह कंपन ही सभी सृजन का मूल है। जहां कहीं भी गति है, वहां तरंगें हैं- प्रकाश की, ध्वनि की और सूचनाओं की।

इन तरंगों द्वारा जो अभिव्यक्तियां होती हैं, वे देवता नाम से जानी जाती हैं। यही देवता सृष्टि के विभिन्न रूपों और गुणों के प्रतिनिधि हैं। परंतु इन सभी देवताओं के भी नियंता परम पुरुष ही हैं। इसीलिए उन्हें देवाधिदेव महादेव कहा जाता है।

ज्ञान के क्षेत्र में भी यही बात दिखाई देती है। जहां जानने की प्रक्रिया होती है, वहां दो भाग होते हैं- एक जो जान रहा है, और दूसरा, जिसे जाना जा रहा है। जानने वाले को 'परा' कहा जाता है और जाने गए को 'अपरा।' यह द्वैत लगातार बदलता रहता है। और अंततः, जब आत्मा भी जानी जाती है, तब जानने वाला केवल परम पुरुष रह जाते हैं, सर्वोच्च परा, वही परम विषयता। इसलिए यदि किसी को वास्तव में कुछ जानना है, तो सबसे पहले उसे परम पुरुष को जानना चाहिए, क्योंकि वही सब कुछ जानते हैं और उन्हें जानना ही सच्चे ज्ञान की शुरुआत है।

ध्यान करते समय एक गूढ़ प्रश्न उठता है कि जब परम पुरुष ही सर्वोच्च विषयता हैं, तो हम कैसे उन्हें ध्यान का 'विषय' बना सकते हैं? इसका उत्तर ध्यान की उस मनोवृत्ति में छिपा है, जहां साधक यह स्वीकार करता है कि वह स्वयं परम पुरुष के ध्यान का विषय है। अर्थात ध्यान में यह समझ होनी चाहिए कि मैं जिस पर ध्यान कर रहा हूं, वह वास्तव में मुझे देख रहा है, मैं उसका विषय हूं। मेरी गतिविधियां, मेरा चिंतन, मेरी चेतना, सब कुछ उसके ज्ञान में समाहित हैं।

**ध्यान में यह समझ होनी चाहिए कि मैं जिस पर ध्यान कर रहा हूं, वह वास्तव में मुझे देख रहा है, मैं उसका विषय हूं। मेरी गतिविधियां, मेरा चिंतन, मेरी चेतना, सब कुछ उसी में समाहित हैं।**

यह भाव ही भक्ति का मूल है। जब साधक यह समझ जाता है कि वह उस अनंत सत्ता का विषय है, तब अहंकार समाप्त होता है और एक विनम्रता जन्म लेती है, जो सच्चे ध्यान और उपासना की नींव बनती है।

**श्री श्री आनंदमूर्ति**

**आशुतोष राणा** | अभिनेता

**पानी का अनियंत्रित प्रवाह गांवों को और वाणी का अनियंत्रित प्रवाह संबंधों को मिटा देता है। पानी पर नियंत्रण के लिए विज्ञान और वाणी के लिए सामान्य ज्ञान जरूरी है। पानी और वाणी पर नियंत्रण कर हम बस्ती और हस्ती बचा सकते हैं।**

## अनुलोम-विलोम
### राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार

# सही व्यक्ति को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार

शाहरुख खान महज अभिनेता नहीं, एक ब्रांड बन चुके हैं। फिल्मी दुनिया के वह ऐसे इंसान हैं, जिनका करीब तीन दशकों का इतिहास है, जिसमें संघर्ष भी है और सराहना भी। *दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बाजीगर, दिल से, स्वदेश, चक दे इंडिया, माय नेम इज खान* जैसी न जाने कितनी सफल फिल्में उन्होंने दी हैं। ऐसे अभिनेता को अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार न मिलना ही अपने आप में शोचनीय मसला था, अगर अब उस गलती को सुधारने का प्रयास किया गया है, तो इसमें विवाद क्यों खड़ा किया जा रहा है? क्या शाहरुख खान राष्ट्रीय पुरस्कार के लायक नहीं हैं? उन्हें तो *स्वदेश* के समय ही यह सम्मान मिल गया होता, यदि उस समय सैफ अली खान की मां सेंसर बोर्ड की अध्यक्ष न होतीं, जिनके बारे में कहा जाता है कि अपने प्रभाव का कथित इस्तेमाल करके उन्होंने *हम तुम* फिल्म के लिए सैफ अली को पुरस्कृत करवाया।

*जवान* शाहरुख खान की सफल फिल्मों में एक है। इसने शाहरुख के अलग रूप से हम सबका परिचय कराया। जिस तरह की भूमिका उन्होंने इस फिल्म में निभाई है, वह विरल ही दिखती है। यही कारण है कि इस फिल्म को काफी पसंद किया गया और कमाई के मामले में भी इसने सफलता के झंडे गाड़े। ऐसी फिल्म को यदि राष्ट्रीय पुरस्कार के लायक समझा गया है, तो इसमें गलत क्या है? इसकी आलोचना का तर्क समझ में नहीं आ रहा है। कहा जा रहा है कि इस बार आशुतोष गोवारिकर पुरस्कार निर्णायक मंडल के अध्यक्ष थे और उन्होंने ही *स्वदेश* फिल्म बनाई, तो उस समय जो गलत हुआ था, उसे ठीक करने के लिए उन्होंने शाहरुख खान को पुरस्कृत किया है? मगर क्या ऐसा करते हुए उन्होंने कोई बेईमानी की है? क्या शाहरुख के ऐसे फिल्म का चयन नहीं किया गया है, जो बॉक्स ऑफिस पर सफल रही है? लिहाजा, आशुतोष और शाहरुख के कनेक्शन की जो बात सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही है, उसका सच से कोई वास्ता नहीं दिख रहा।

शाहरुख खान रोमांस, एक्शन, कॉमेडी, स्पोर्ट्स ड्रामा जैसी कई विधाओं में काम कर चुके हैं। उन्होंने 90 से अधिक फिल्में की हैं और 'रोमांस किंग' के रूप में जाने जाते हैं। पुरस्कारों की ही बात करें, तो उनके खाते में 14 फिल्मफेयर अवार्ड हैं, जिनमें से आठ बार उन्होंने 'बेस्ट एक्टर' का खिताब जीता है। यह बताता है कि शाहरुख खान का फलक कितना व्यापक है। इसके बावजूद उन्हें अब तक राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला, तो यह पूरी प्रणाली पर सवाल है। वास्तव में, ऐसे व्यक्ति के पुरस्कृत होने से राष्ट्रीय पुस्कारों का ही सम्मान बढ़ता है।

**दीपक कुमार**, टिप्पणीकार

# चयन में कहीं-न-कहीं चूक हो गई

*चक दे इंडिया* भारतीय सिनेमा इतिहास की गिनी-चुनी उन फिल्मों में शामिल है, जो खेल जगत पर है और बेहद स्तरीय है। फिल्म से जुड़ी हर चीज उम्दा है- अभिनय, निर्देशन, गीत-संगीत, कहानी, संवाद सब कुछ। उस फिल्म के लिए शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार आज भी मिले, तो भरपूर तालियां बजेंगी। इसी तरह, उनकी एक और फिल्म है, *स्वदेश,* जो प्रतिभा पलायन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर आधारित है। इसमें भी शाहरुख का अभिनय उत्कृष्ट है, फिल्म भी अच्छी है। इस फिल्म के लिए भी शाहरुख खान को राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। *दिल से* उनकी एक और क्लासिक फिल्म है, जो मणिरत्नम ने बनाई है। शाहरुख को उसके लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार नहीं मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार मिला किसके लिए? एक ऐसी फिल्म *जवान* के लिए, जिसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संदिग्ध है। यह तुलनात्मक रूप से लोकप्रिय भी कम हुई और इसमें क्लासिक भी नहीं है। अभिनय, गीत-संगीत, कहानी सब औसत है। शाहरुख खान जैसे सशक्त अभिनेता को उनकी कमजोर फिल्मों में से एक *जवान* के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिलते देखना हैरान कर रहा है।

**आफताब आलम**, टिप्पणीकार

शाहरुख खान को *जवान* फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है। इसको लेकर चर्चाएं खूब हो रही हैं। दरअसल, असहिष्णुता जैसे मसलों पर अपने बयानों के कारण शाहरुख मौजूदा सरकार के समर्थकों के निशाने पर रहे हैं और उनके बायकॉट तक की मुहिम चलाई जा चुकी है। उनके बेटे आर्यन को नशे की तस्करी के मामले में जेल भेजा गया, मगर कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। शाहरुख अक्षय कुमार की तरह प्रधानमंत्री मोदी के मुखर समर्थक भी नहीं रहे हैं। *पठान* और *जवान* की जबर्दस्त कामयाबी और *डंकी* को मिली सराहना से शाहरुख ने धमाकेदार वापसी की है। फिर भी सवाल है कि क्या फिल्म पुरस्कार तय करने वालों की नजर में *जवान* फिल्म में शाहरुख खान का अभिनय उनके अब तक के करियर का सर्वश्रेष्ठ काम है? आखिर तीन दशक से ज्यादा की अभिनय-यात्रा के बाद शाहरुख खान को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार देने के पीछे क्या संदेश हो सकता है? जिस समय ओटीटी की वजह से हिंदी पट्टी के दर्शकों के बीच भी अन्य भारतीय भाषाओं की अच्छी फिल्में बहुत लोकप्रिय हो रही हैं, सरकार मुंबईया मसाला सिनेमा पर खुलकर इतनी मेहरबान कर रही है। क्या मलयालम, मराठी या बांग्ला सिनेमा में इस साल पुरस्कृत होने लायक कोई अच्छी फिल्म नहीं बनी? हैरत है।

**अमिताभ श्रीवास्तव**, टिप्पणीकार

संकल्प की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है

# ट्रंप की नई धमकी

अपने बेतुके बयानों और फैसलों से अपनी फजीहत करा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है कि वे 24 घंटे के भीतर भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर अमेरिकी आयात शुल्क 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। उनके जो मन में आए, वह करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि वे यह समझ रहे हैं कि भारत उनकी दादागीरी के आगे झुक जाएगा तो अब इसकी संभावना न्यून है, क्योंकि उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया गया है। भारत कूटनीतिक शिष्टाचार के चलते उन्हें उनकी जैसी भाषा में तो जवाब नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे उनकी धमकियों के आगे झुकना भी नहीं है। वे अब हद पार कर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की मर्यादा से खेल रहे हैं। उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। यह भी दिख रहा है कि वे कुंठा से ग्रस्त होकर विवेक खो रहे हैं। भारत को एक कुंठित-अहंकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के अहं को तुष्ट करने के बजाय उसका सामना साहस और संयम से करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। भारत को ट्रंप की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए फौरी एवं दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब हमारे कारोबारी भी राष्ट्रधर्म समझेंगे। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता ठीक करनी होगी। आयातकों को खास तौर पर उन अमेरिकी अथवा चीनी वस्तुएं खरीदने का लोभ छोड़ना होगा, जो भारत में बन सकती हैं। इससे ही स्वदेशी का मंत्र कारगर साबित हो सकता है। ट्रंप यह तय करने वाले कोई नहीं कि भारत रूस अथवा अन्य किसी देश से क्या खरीदे? अमेरिका की तरह भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है। यदि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से भी ले रहा है। यदि भारत रूस से तेल न ले तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके दाम चढ़ जाएंगे और इसके दुष्परिणाम विश्व के अनेक देशों के साथ अमेरिका को भी भोगने पड़ेंगे। क्या ट्रंप यह बताएंगे कि अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक क्यों खरीद रहा है? इसी तरह यूरोपीय देश उससे गैस, खनिज आदि क्यों खरीद रहे हैं? ट्रंप यह समझने को तैयार नहीं कि भारत के टैरिफ किंग होने के उनके दावे की पोल खुद अनेक अमेरिकी अर्थशास्त्री खोल रहे हैं। विश्व बैंक का भी यह आकलन है कि अमेरिका के मुकाबले भारत की टैरिफ दरें मामूली ही अधिक हैं। आखिर भारत अमेरिका से वह सब क्यों खरीदे, जो उसे चाहिए ही नहीं? ट्रंप यह समझें तो बेहतर कि भारत तब अमेरिका से नहीं दबा था, जब वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था और उसे परमाणु परीक्षण के चलते प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। भारत को ट्रंप का सामना करते हुए यह भी देखना होगा कि उसे रूस या चीन पर निर्भर नहीं होना है।

# हकमारी पर रोक

शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति लागू कर राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि नौकरियां स्थानीय लोगों को ही मिले, कोई बाहरी उनकी हकमारी न करे। वाजिब भी है। देश के ज्यादातर राज्यों ने इसी तरह की नीतियों को लागू कर बिहार के युवाओं की राह रोक रखी है, तब बिहार में क्यों न डोमिसाइल नीति लागू हो। वैसे भी उद्योग-धंधों की कमी के कारण दूसरे संपन्न प्रदेशों के मुकाबले यहां युवाओं के पास नौकरियों के सीमित विकल्प हैं, ऐसे में शिक्षक की नौकरी उन्हें सबल कर रही। खासकर, पिछली नियुक्तियों ने महिलाओं की सशक्तीकरण की राह खोली है। पिछले दो वर्षों में जिन 2.23 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। चूल्हा-चौका का काम निपटाते हुए महिलाएं अब घर की देहरी से बाहर निकलकर न सिर्फ खुद अपने पांव पर खड़ी हो रहीं, बल्कि बच्चों को शिक्षित, संस्कारित करने में अहम भूमिका अदा कर रहीं। इन्हें घरों से निकलकर स्कूलों में पढ़ाते हुए देखकर बेटियों को उच्च शिक्षा देने का चलन भी बढ़ रहा। अब लोगों को विश्वास हो रहा कि बेटियों को अच्छे से पढ़ा लिया तो उसके लिए शिक्षक की नौकरी का एक बेहतर विकल्प उपलब्ध है। राज्य सरकार ने तो पूर्व से शिक्षक नियुक्ति में स्थानीय महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा कर ही रखी है। उम्मीद है कि आने वाले समय में और अधिक महिलाएं इस दायित्व का निर्वहन करती नजर आएंगी।

> शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में डोमिसाइल लागू करना बेहतर कदम है

**कह के रहेंगे** — माधव जोशी

**जागरण जनमत** — कल का परिणाम

क्या सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी संभलकर बोलेंगे?

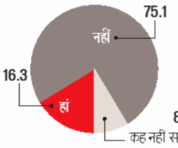


**आज का सवाल**
क्या पर्वतीय क्षेत्रों में अनियंत्रित निर्माण आपदाओं को विकराल बना रहा है?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

# सुनिश्चित हो संवैधानिक दायित्व की पूर्ति

हृदयनारायण दीक्षित

**दलबदल से जुड़ी याचिकाओं पर निर्णय में इतना विलंब न हो कि सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाए। पीठासीन अधिकारी इस मुद्दे पर तत्परता दिखाएं**

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल की याचिकाओं के निस्तारण पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायी सदनों के अध्यक्षों/सभापतियों के निर्णय में विलंब से चिंताजनक स्थिति निर्मित हुई है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, 'हम ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते जहां आपरेशन सफल हो, लेकिन मरीज ही मर जाए।' याचिकाओं पर निर्णय में ऐसा विलंब न हो कि सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाए। न्यायपीठ ने तेलंगाना विधानसभा में भारत राष्ट्र समिति के 10 विधायकों के दलबदल मामले में सुनवाई के बाद कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दी गई याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष तीन महीने के भीतर निर्णय दें। न्यायालय ने पहले भी कहा था कि याचिकाओं के निर्णय में विलंब से 10वीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। सदन के अध्यक्षों/सभापतियों को ही ऐसी याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे सुनवाई की समयसीमा सुनिश्चित करने का अधिकार है। ये बातें मणिपुर विधानसभा सहित कई मामलों में समयसीमा निर्धारित करने की मांग पर कही गई हैं। एक मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायापीठ ने कहा था कि आवश्यक कार्यवाही में देरी पर न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। रवि एस. नायक बनाम भारत संघ मामले (1994) में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी टिप्पणी की गई थी।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही सरकार में मंत्री और सदन में पीठासीन अधिकारी बनते हैं। राजनीतिक दल उनके निर्वाचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे चुनाव जीतकर अपने दल के प्रति निष्ठावान रहते हैं, पर तमाम प्रतिनिधि लोभवश दलबदल करते हैं। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही दलबदल का सिलसिला चल निकला था। 1967 में हरियाणा के एक नेता ने एक दिन में ही तीन बार दलबदल किया था। कई राज्यों में दलबदलू नेता दल छोड़ते ही मंत्री बने। नैतिक और विधिक दृष्टि से यह अपराध है। मतदाता के प्रति धोखाधड़ी भी है। हमारे यहां राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है, लेकिन हम संवैधानिक नैतिकता वाले राजनीतिक दल नहीं बना पाए। राजनीतिक दल भी अपने सदस्यों में निष्ठा नहीं ला पाते, कुछ दलबदल कराते हैं और कुछ दलबदल करते हैं। ऐसे दल राष्ट्र हितैषी नहीं हो सकते।

कहा जाता है कि राजीव गांधी ने भयवश 52वां संविधान संशोधन पारित करवाया था। तब स्वेच्छा से दल त्याग दंडनीय माना गया, पर एक तिहाई सदस्यों के दल त्याग को विलय कहा गया था। एक तिहाई सदस्य जुटाना मुश्किल नहीं था। कुछ राज्यों में इक्का-दुक्का सदस्य आते रहे और एक तिहाई होते गए। दलबदल के तमाम तरीके ईजाद होते रहे। 1991 में संविधान संशोधन द्वारा एक तिहाई की जगह दो तिहाई सदस्यों का प्रविधान किया गया। इसका भी बहुत लाभ नहीं हुआ। सदस्यता छीन लेने जैसे सख्त कानून के बावजूद दलबदल जारी है। एक कारण पीठसीनों की ढिलाई भी है। इसलिए हाल के तेलंगाना मामले सहित कई अवसरों पर पीठासीन अधिकारियों पर टिप्पणियां हुई हैं। आरोप लगते रहे हैं कि वे जानबूझकर पक्षपात करते हैं। यचिकाएं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि इस गंभीर विषय पर विमर्श के लिए एक आयोग बने। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। सदनों के सभापति/अध्यक्ष सम्माननीय संवैधानिक संस्था हैं। 10वीं अनुसूची में संविधान ने इन्हें उत्तरदायी माना है। इन संस्थाओं को अपने संवैधानिक कर्तव्य का सही पालन करना चाहिए, मगर दल त्यागने का रोग इतने भर से दूर नहीं होगा। माननीय विशेष अवसरों के लिए दल त्याग करेंगे। कुछ दंडित होंगे, होते भी हैं और शेष तकनीकी कारणों से बच निकलेंगे। इसलिए इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श हो।

अवधेश राजपूत

जहां स्वेच्छा से दल त्याग दंडनीय है, वहीं किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दल त्याग की घोषणा सुविचारित भी हो सकती है। पार्टी का नेतृत्व विचारधारा बदल सकता है। विचारनिष्ठ सदस्यों के लिए यह अस्वीकार्य हो जाता है। वे सदन में अपने नेताओं के विरुद्ध भी बोलते हैं। संविधान में विचार अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है। दलीय अनुशासन का डंडा सदस्यों को अखरता है। दलबदल रोकने से राजनीतिक स्थिरता तो रहती है, किंतु निर्वाचित सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित भी नहीं किया जा सकता। बजट और अविश्वास प्रस्ताव जैसे अवसरों पर सदस्यों को दलीय अनुशासन चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। दलबदल के कानूनी प्रविधानों ने सदस्यों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया है, जबकि संविधान सदनों में विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता देता है। संसदीय जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। इसके बावजूद दलबदल के विरुद्ध अभियान चलाते रहना चाहिए। समाज इसकी निंदा करे। राज्य दंड दे।

आखिर ब्रिटिश संसद ने भारत जैसा दलबदल कानून क्यों नहीं बनाया? ब्रिटेन का दल तंत्र ऐसी समस्याएं स्वयं सुलझा लेता है। ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली अपना कर भी, दलबदल कानून के बावजूद भारत क्यों इस समस्या से ग्रस्त बना हुआ है। ब्रिटेन में पार्टी बदलने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अमेरिका में भी दलबदल कानून नहीं है। अमेरिका में दो दल हैं। दलबदल भी होते हैं। एक समय डेमोक्रेटिक पार्टी के 16 प्रतिनिधि रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी का अनुशासन अमेरिका में ऐसी समस्याएं सुलझा लेता है। यूरोप के अधिकांश देशों में सख्त कानून है। दल त्याग पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। पड़ोसी बांग्लादेश में भी पार्टी के विरुद्ध सदन में मतदान करने और पार्टी बदलने पर त्यागपत्र लिया जाता है। केन्या, दक्षिण अफ्रीका आदि में दलबदल की छूट नहीं है। भारत का मन बदल रहा है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। संपूर्ण राजनीतिक दल तंत्र और विधायिका के सभी सदस्यों को संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए संवेदनशील होना चाहिए। न्यायपीठ का निर्णय स्वागतयोग्य है। इससे विधायिका और न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

# श्रीमान झूठ बोलिए, लेकिन संभलकर

राजीव सचान

**राजनीति में सच और झूठ का अंतर मिटता जा रहा है और अब तो यह लगता है कि झूठ के भी पैर होने लगे हैं**

राहुल गांधी संसद के भीतर-बाहर खूब बोल रहे हैं। उनके कथित धारदार बयान चर्चा में हैं। जो उनसे सहमत हैं, वे उनकी वाहवाही कर रहे हैं और जो असहमत हैं, वे जाहिर है कि उनकी आलोचना-निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी यानी नेता विपक्ष ने हाल में लोकसभा में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह मर चुका है और लोकसभा चुनाव में भी धांधली हुई थी। राहुल पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं और जिस कारण वे लोकसभा में नेता विपक्ष बन सके। उन्होंने ऐसे आरोप तब नहीं लगाए, जब 2014 में कांग्रेस को 44 और 2019 में 52 सीटें मिली थीं। जब 99 सीटें मिलीं, तब वे कह रहे हैं कि धांधली हुई। उन्होंने लोकसभा में चुनाव आयोग को एक तरह से देख लेने की धमकी दी। पता नहीं वे उसे कैसे देखेंगे, पर उन्होंने सांसद के सदन में बोलने के अधिकार का पूरा 'लाभ' उठाया। सांसद और विधायक सदनों में बिना किसी भय, दबाव के बोलने और उसके खिलाफ किसी अदालत में कार्रवाई न हो सकने के विशेषाधिकार का खूब लाभ उठाते हैं। चूंकि किसी विधायक, सांसद के खिलाफ सदन में उसके आचरण के लिए न्यायालय में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वे निडर होकर कुछ भी करते और कहते हैं।

यदि कोई सांसद, विधायक सदन में बहुत ही गलत आचरण कर दे तो उसके खिलाफ सदन ही विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई कर सकता है और उसकी सदस्यता भी रद कर सकता है, लेकिन इस पर वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उसे वहां से राहत भी मिल सकती है। विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई पक्ष-विपक्ष के किसी भी सदस्य के खिलाफ हो सकती है, लेकिन यदि कभी सत्तापक्ष किसी विपक्षी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई करता है तो कहा जाता है कि यह तानाशाही है।

विधायी सदनों में पक्ष-विपक्ष के सदस्य अपने विशेषाधिकार का किस हद तक मनमाना इस्तेमाल करते हैं, इसका एक उदाहरण 'नई तरह की राजनीति' करने वाली आम आदमी पार्टी का है। वह जब दिल्ली में सत्ता में थी तो विधानसभा के एक-दो दिन के सत्र इस उद्देश्य से भी बुलाती थी कि किसी की मनमानी तरीके से निंदा-भर्त्सना कर सके। एक बार उसके विधायक ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेने के लिए सदन में एक नकली ईवीएम 'खोलकर' यह बताने की कोशिश की थी कि उसे हैक किया जा सकता है। ईवीएम के खिलाफ एक लंबे समय से मोर्चा खुला हुआ है। इस मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल है। यह सनद रहे कि ईवीएम का इस्तेमाल कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन आज की कांग्रेस को इससे मतलब नहीं?

एक रैली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव ● फाइल

राहुल की मानें तो चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर भाजपा को छल-छद्म से जिताने का काम कर रहा है और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के जरिये भी लोकतंत्र ही नष्ट कर रहा है। बहती गंगा में तेजस्वी यादव ने भी हाथ धोया। चुनाव आयोग की ओर से बिहार की मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी होते ही उन्होंने दावा किया कि इसमें तो उनका नाम ही नहीं है। इस पर चुनाव आयोग ने उनके दावे को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में है और अमुक मतदान केंद्र में अंकित है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का गहन विरोध करने वाले राहुल के अनुसार महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई थी। उनका कोई समर्थक और शुभचिंतक यह पूछने को तैयार नहीं कि यदि ऐसा है तो झारखंड और जम्मू-कश्मीर के नतीजे कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों के पक्ष में क्यों रहे? जो कुतर्क करने में माहिर हैं, उनका 'तर्क' है कि भाजपा इन दोनों राज्यों में इसलिए जानबूझकर हारी, ताकि चुनाव आयोग पर संदेह न हो। शायद ऐसे ही लोगों का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं रहा होगा।

राहुल गांधी ने हाल में दिवंगत अरुण जेटली पर आरोप लगाया कि उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध करने पर उन्हें धमकाया था। इस पर अरुण जेटली के बेटे को कहना पड़ा कि ये कानून तो उनके पिता के निधन के बाद आए। शायद राहुल भूमि अधिग्रहण बिल का संदर्भ देना चाहते थे। सच वही जानें, लेकिन उनकी ओर से यह भी तो कहा जा चुका कि राफेल विमान सौदे में दलाली खाई गई.. चौकीदार चोर है। सावरकर अंग्रेजों से डरते थे...माफीवीर थे और चीन ने भारत की दो हजार वर्ग किमी भूमि कब्जा ली...चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इन तीनों मामलों में राहुल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें फटकारने वाले न्यायाधीशों को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। जिसे झूठ कहा जाता है, उसे संसदीय भाषा में मिथ्या या सत्य से परे कहते हैं। अब नेताओं की ओर से खूब झूठ बोला जाता है। वे झूठ के पैर लगाकर उसे दौड़ा देते हैं। पहले भी ऐसा होता था, पर कम। आज तो पक्ष-विपक्ष के तमाम छोटे-बड़े नेता बिना किसी संकोच मिथ्या यानी झूठ बोलते हैं। वे अपने विरोधी की किसी बात या उसके दावे की ऐसी व्याख्या करते हैं कि वह मिथ्या, सत्य से परे अर्थात झूठ ही होती है, लेकिन यदि आज की राजनीति में ऐसी बातें न की जाएं तो शायद वह अमेरिका से लेकर भारत तक में चल नहीं सकती। झूठ का सहारा लेने वाले नेताओं की बातें कभी-कभार उनकी बोलती भी बंद करती हैं, लेकिन उन पर मुश्किल से ही फर्क पड़ता है। वे संभलकर बोलने को तैयार नहीं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

## ऊर्जा

### मानव से सिद्धात्मा

संसार में रहते हुये सांसारिक पदार्थों का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे असंपृक्त रह पाना कठिन है। वैरागी मन पर राग की अनगिनत परतें होती हैं। वासना, आसक्ति, मोह, लोभ, कामना, लालसा, स्पृहा मानव मन के स्वाभविक रंग हैं। कभी मन में सात्विक भाव का उदय होता है तो हम करुणा, प्रेम, कर्तव्यपालन, परिश्रम और परमार्थ की भावना से भर उठते हैं। वहीं, तम गुण के हावी होने पर क्रोध, भय, विनाशक प्रवृत्ति से भर जाते हैं। हालांकि यह मानवीय प्रकृति है, इस पर ग्लानि नहीं, अपितु नियंत्रण का प्रयास हो।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

साधक वही है जो उस साधना में लगा है कि मन को कैसे जीता जाए। जब आंशिक रूप से राग-द्वेष, लोभ-लालसा, उद्वेग-संवेग शेष रहते हैं, तब भी वह साधक ही है। साधक किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह है जो विद्यार्जन कर रहा है, अनुशासन में ढलने का प्रयास कर रहा है, घंटों बैठकर अध्ययन करने का शरीर को प्रशिक्षण देता है। साधक वही जो काया और माया को साधने का जी-तोड़ प्रयास करे। अतः कुछ समय के लिए भी वीतरागी होने का मन करे तो समझना चाहिए कि साधना का पावन मार्ग खुल चुका है। मन की मूल प्रवृत्ति है वीतराग, वह अपने स्वरूप में लौटना चाहता है।

इच्छाओं के वशीभूत माया के कारागार में फंसा मनुष्य जब पूरी तरह से क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से विरत हो जाए तब वह 'सिद्ध' पुरुष कहलाता है। सिद्ध होने के लिए कुछ वर्ष ही पर्याप्त नहीं। यह भी अनिवार्य है कि सिद्ध पुरुष होने के लिए मानव बनकर ही जन्म लेना पड़ता है। मानव से साधक, साधक से सिद्ध होने की यात्रा इसी काया में संभव है। देवताओं को भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथमतः अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि मानव रूप में जन्म मिला, दूसरा यदि प्रेरणा, सत्संग, स्वाध्याय किसी भी माध्यम से आत्मउन्नति की राह दिखे तो उस पर निःसंकोच चल देना चाहिए।

ट्विंकल तोमर सिंह

## पाठकनामा

pathaknama@pat.jagran.com

### भगवा आतंक का उलटा पड़ा दांव

'षड्यंत्र था भगवा आतंक का जुमला' में संध्या जैन ने यथार्थ लिखा कि इस्लामिक आतंक की धारणा को संतुलित करने के लिए ही भगवा या हिंदू आतंक का फर्जीवाड़ा किया गया। इसे स्थापित करने के लिए ही कई कड़ियां भी जोड़ी गईं। समाज सेवा में संलग्न ऐसे लोगों को उसमें आरोपित बनाया गया, जिनसे हिंदू समाज प्रेरणा लेता है। यह इसलिए भी किया गया, ताकि हिंदुत्व की ओर आकर्षित लोग हिंदुत्व और इस्लाम को एक जैसा मानकर उससे बिदक जाएं। दरअसल कांग्रेस सहित कथित सेक्युलर दलों का यही सोचना था कि भगवा आतंकवाद का जुमला स्थापित कर वे मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी राजनीति चमका सकें। हालांकि परिणाम इन दलों की आशा के अनुरूप नहीं रहे। इस कवायद में जिन्हें आतंकवादी के रूप में बदनाम किया गया, वे ससम्मान इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। जबकि यह जुमला आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे यह दांव उलटा पड़ा।

युवराज पल्लव, सहारनपुर (उप्र)

### युवा प्रतिनिधित्व आवश्यक

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की संकल्पना की है। कोई भी राष्ट्र उसके 'विकसित नागरिक' के आधार पर ही 'विकसित राष्ट्र' की श्रेणी में खड़ा हो सकता है। वर्ष 2047 तक भारत की कुल आबादी एक अरब 60 करोड़ अनुमानित है, जिसमें युवाओं की आबादी करीब एक अरब 25 करोड़ होगी, जो भारत की आबादी का 75 प्रतिशत होगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्र की दशा और दिशा को निर्धारित करने वाली सबसे बड़ी संस्था संसद भवन में भी युवाओं का उचित प्रतिनिधित्व आवश्यक है, ताकि युवा प्रतिनिधि दूसरे युवाओं की समस्या के समाधान के लिए व्यावहारिक कदम उठा सकें। जिस तरह सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था कर सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े हुए समूह के लोगों के आगे बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है, ठीक उसी प्रकार युवाओं को भी भारतीय राजनीति में उचित यथोचित प्रतिनिधित्व का मौका देना चाहिए। तभी युवा देश को युवाओं के अनुरूप वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाया जा सकता है। इस विषय पर एक सर्वदलीय बैठक का आह्वाव कर इसे मूर्त रूप दिया जा सकता है अथवा संसद के माध्यम से राजनीति में अधिकतम आयु सीमा एवं युवाओं का अनुपात भी तय किया जा सकता है। जब न्यूनतम आयु 25 वर्ष निर्धारित है तो अधिकतम आयु की सीमा को भी निर्धारित किए जाने की आवश्यकता समय के अनुकूल प्रतीत होती है। पूर्व राष्ट्रपति डा. एपीजे अब्दुल कलाम भी युवाओं का देश कहकर राष्ट्र को संबोधित करते थे। इस संबंध में गत 30 जुलाई को दैनिक जागरण में प्रकाशित राहुल वर्मा का आलेख 'युवाओं की प्रतीक्षा करती राजनीति' ध्यान आकृष्ट कराता है। अतः इस विषय पर संसद को गंभीरतापूर्वक विचार करते हुए युवाओं का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना चाहिए।

ललित कुमार सिंह, समस्तीपुर

### हिरोशिमा दिवस प्रासंगिक

विश्व में जगह-जगह युद्ध की विभीषिका को देखते हुए हिरोशिमा दिवस (छह अगस्त) की प्रासंगिकता बढ़ गई है। इस दिवस का उद्देश्य परमाणु बम विस्फोटों के दुखद परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शांति की राजनीति को बढ़ावा देना है। अस्सी वर्ष पूर्व छह अगस्त 1945 को अमेरिका ने पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर पर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका के इस हमले में हिरोशिमा में एक लाख चालीस हजार लोग मारे गए थे। उनमें से अधिकांश साधारण नागरिक, बच्चे, बूढ़े तथा स्त्रियां थीं। उसके बाद भी अनेक वर्षों तक अनगिनत लोग विकिरण के प्रभाव से मरते रहे। हिरोशिमा पर बम गिराने के तीन दिन बाद ही नौ अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर परमाणु बम गिराया था, जिसमें अनुमानित 74 हज़ार लोग विस्फोट व प्रचंड ताप के कारण मारे गए। नागासाकी में भी कई वर्षों तक विकिरण के प्रभाव से जनजीवन अस्तव्यस्त रहा। परमाणु हमले के दर्द को जापान कभी नहीं भूल सकता है। आज फिर से दुनिया पर परमाणु हमले का खतरा मंडरा रहा है, अमेरिका एवं उसके मित्र पश्चिमी राष्ट्र इस संकट को बढ़ावा दे रहे हैं, जो मानवता विरोधी कार्य है। संयुक्त राष्ट्र संघ अप्रासंगिक हो चुका है। ऐसे भारत जैसे सभी शांतिप्रिय देशों को मिलकर स्थिति बिगड़ने के पहले रूस व यूक्रेन युद्ध के समाधान का मार्ग तलाशना चाहिए।

ई हिमांशु शेखर, केसपा, गयाजी

## X पोस्ट

उत्तरकाशी में बदल फटने और सैलाब में एक झटके में सब बह जाने की तस्वीर आंखों के आगे से जा नहीं रही। यह सिर्फ एक आपदा की बात नहीं है। हिमालयी क्षेत्र में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं, उनसे सबक न सीखने की हमारी नीयत को कुदरत नहीं बख्शने वाली। परिणाम हमारे सामने हैं। छोटी-छोटी कई घटनाओं की तो गिनती रखना भी कठिन है।

मीनाक्षी कंडवाल@MinakshiKandwal

कुछ दशक पहले ऐसे लेख पढ़ने को मिलते थे कि टेस्ट क्रिकेट के दिन गिने-चुने ही बचे हैं। ओवल टेस्ट ने दर्शाया कि ऐसी धारणा कितनी गलत थी।

जान सिंपसन@JohnSimpsonNews

यदि ट्रंप भारत-अमेरिकी रिश्तों को बर्बाद करना चाहते हैं तो करने दें। भारत इस स्थिति से निपट लेगा। मैं तो बस यही चाहता हूं कि मोदी सरकार इस मौके पर व्यापक घरेलू सुधारों को आगे बढ़ाए। हम एक विशालकाय अर्थव्यवस्था हैं और अमेरिका एक सीमा से परे हमें परेशान नहीं कर सकता।

कुशल मेहरा@kushal_mehra

## जनपथ

'सच्चे' होते तो कहां करते ऐसी बात,
'भारतीय' कोई कहां खड़ा पाक के साथ!
खड़ा पाक के साथ कर रहा जेट की गिनती,
इनको करिए ठीक यही है जज से विनती।
या फिर करिए माफ समझकर ये हैं बच्चे,
क्योंकि ये इस जन्म न बन पाएंगे सच्चे!!

– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 116

********

कल्पमेधा

*अगर आप उन चीजों को खरीदते हैं, जिनकी आपको जरूरत नहीं है तो शीघ्र ही आपको उन चीजों को बेचना पड़ेगा जिनकी आपको जरूरत है।*

*– वारेन बफे*

## दोहरे मापदंड

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले हफ्ते भारत पर पच्चीस फीसद शुल्क लगाने और रूस से तेल एवं गैस खरीदने पर जुर्माना लगाने का एलान किया था। निश्चित तौर पर यह भारत पर अनावश्यक दबाव बनाने की रणनीति है। मगर अमेरिका की उम्मीदों के उलट भारत ने अपने रुख को और सख्त कर स्पष्ट कर दिया है कि जब राष्ट्रहित का मसला हो तो कोई बाहरी दबाव मजबूत इरादों को लक्ष्य से डिगा नहीं सकता है। भारत ने साफ कहा है कि रूस से तेल खरीदने के लिए शुल्क बढ़ाने की चेतावनी अनुचित और अव्यावहारिक है। यही नहीं, भारत ने दुनिया के सामने इस बात को भी उजागर किया है कि अमेरिका किस तरह दोहरे मापदंड अपनाकर अपने हितों को साधने की चेष्टा कर रहा है। असल में इस तरह का प्रयास किसी भी देश की राष्ट्रीय संप्रभुता पर अतिक्रमण और उसके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना है। दूसरी ओर रूस ने भी अमेरिका के इस कदम को वैश्विक दक्षिण देशों के खिलाफ नव-उपनिवेशवादी नीति करार देकर और इन देशों के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा व्यक्त कर साफ कर दिया है कि अब दुनिया बहुध्रुवीय व्यवस्था की पक्षधर है।

भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद को लेकर अमेरिका और यूरोपीय संघ पर पलटवार करते हुए रूस के साथ उनके व्यापारिक संबंधों की ओर ध्यान दिलाया है। विदेश मंत्रालय ने रूस के साथ ऊर्जा संबंधों की आलोचना को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अमेरिका खुद अपने परमाणु उद्योग के लिए रूस से यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, विद्युत वाहन उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायनों का आयात करता है। वहीं, यूरोपीय संघ इस मामले में दो कदम आगे है। वर्ष 2024 में यूरोपीय संघ का रूस के साथ 67.5 अरब यूरो का द्विपक्षीय व्यापार हुआ। वर्ष 2023 में इसमें सेवाओं से जुड़ा व्यापार लगभग 17.2 अरब यूरो आंका गया। यह उस वर्ष या उसके बाद रूस के साथ भारत के कुल व्यापार से काफी अधिक है। वास्तव में वर्ष 2024 में एलएनजी का यूरोपीय आयात रेकार्ड 16.5 मिलियन टन तक पहुंच गया, जो 2022 में 15.21 मिलियन टन से कहीं अधिक है। ऐसे में सवाल है कि जो देश खुद रूस से तेल-गैस और अन्य सामग्री खरीद रहे हैं, वे किसी अन्य देश को रूस से व्यापार करने से कैसे रोक सकते हैं? क्या यह दोहरे मापदंडों का प्रदर्शन नहीं है?

अमेरिका की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि रूस भारत को कच्चे तेल की बिक्री से अर्जित धन का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में कर रहा है। मगर इस बात की क्या गारंटी है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों की ओर से रूस से जो सामग्री खरीदी जा रही है, उससे मिले धन का इस्तेमाल यूक्रेन युद्ध में नहीं हो रहा है? जाहिर है, अमेरिका दोहरे मापदंड अपनाकर अपने भू-राजनीतिक हित साधना चाहता है। दरअसल, वह उभरती विश्व व्यवस्था में अपने आधिपत्य को नुकसान से चिंतित है। भारतीय विदेश मंत्रालय का साफ कहना है कि रूस से कच्चे तेल का जो आयात किया जाता है, उसका उद्देश्य देश में उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की लागत को किफायती बनाए रखना है। किसी भी देश के लिए उसकी घरेलू जरूरतों को पूरा करना उसका प्राथमिक कर्त्तव्य होता है। ऐसे में भारत का अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा के लिए हरसंभव आवश्यक उपाय करना स्वाभाविक है।

## हिंसा की राजनीति

पश्चिम बंगाल में जिस तरह राजनीतिक हिंसा की घटनाएं आम हो चुकी हैं, उससे ऐसा लगता है कि वहां लोकतांत्रिक तरीके से अपने विचारों की राजनीति करने से ज्यादा प्राथमिक सीधे टकराव को मान लिया गया है। वरना क्या वजह है कि अगर दो दलों या उनके नेताओं के बीच किसी मुद्दे पर मतभेद है, तो उस पर संवाद के बजाय उनके कार्यकर्ता आक्रामक रुख अख्तियार कर लेना अपना पहला काम मान लेते हैं। गुरुवार को राज्य की विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पथराव की घटना इसका ताजा उदाहरण है कि वहां राजनीतिक गतिविधियों का अर्थ स्वस्थ बहस या संवाद नहीं रह गया है, बल्कि हिंसक रास्ते के जरिए अपने प्रतिद्वंद्वी को रोकने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है कि शुभेंदु अधिकारी पार्टी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाए जाने के मसले पर पुलिस अधीक्षक से मिलने जा रहे थे कि इसी बीच रास्ते में उनके काफिले में शामिल वाहनों पर पत्थरों और डंडों से हमला हुआ। यह समझना मुश्किल है कि राज्य में इस तरह की घटना के वक्त पुलिस मूकदर्शक क्यों बनी रहती है।

स्वाभाविक रूप से इस घटना के बाद एक रिवायत की तरह भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप के क्रम ने फिर जोर पकड़ लिया, लेकिन सच यह है कि राज्य की राजनीति में हिंसा या आक्रामकता एक आम चलन के रूप में घुल गई है। लगभग सभी दल इसी को अपना प्राथमिक औजार मानने लगे हैं। शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हमला इस तरह की कोई अकेली घटना नहीं है। पिछले कुछ दिनों के दौरान तृणमूल कांग्रेस से जुड़े दो नेताओं की हत्या की खबरें आईं। इससे पहले भाजपा के एक नेता के आवास के बाहर बम विस्फोट की घटना हुई थी। विडंबना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में हिंसा को एक अघोषित मूल्य के रूप में देखा जाने लगा है। खासतौर पर वहां चुनावों के दौरान हिंसा-प्रतिहिंसा की घटनाओं में तेजी आ जाती है। मगर अब ऐसी घटनाएं निरंतरता में होने लगी हैं। सवाल है कि क्या यह राज्य के पुलिस तंत्र के बेअसर हो जाने का उदाहरण है। अगर यह स्थिति बनी रहती है तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य में लोकतंत्र के सामने किस तरह का संकट खड़ा होगा।

# खेल के मैदान में कृत्रिम मेधा का दखल

**आज खिलाड़ी की तंदरुस्ती का स्तर, हृदयगति, थकान, नींद का चक्र और यहां तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी तकनीकी उपकरणों और साफ्टवेयर से मापी जाती है। अब भारत में कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे पारंपरिक खेलों में भी यह तकनीकी हस्तक्षेप दिखाई देने लगा है।**

**मनीष जैसल**

भारत में खेलों की परंपरा सदियों पुरानी है। किसी गांव के धूल भरे अखाड़े से लेकर शहर के चमचमाते सिंथेटिक ट्रैक तक, हमारी साझी स्मृति में पसीने की गंध और माटी की सोंधी खुशबू बराबर रची-बसी है। मगर पिछले कुछ वर्षों में इस पारंपरिक दृश्य के सामने एक नई रोशनी चमकी है, जैसे स्क्रीन, स्मार्ट रीडर और कलाइयों में लिपटी स्मार्ट-बैंड। बीते कुछ वर्षों में खेल का मैदान केवल खिलाड़ियों की मेहनत और अभ्यास का अखाड़ा नहीं रहा, बल्कि अब यह तकनीक की प्रयोगशाला बनता जा रहा है। जहां पहले एक कोच की आंख और खिलाड़ी की संवेदनाएं प्रदर्शन को मापती थीं, वहीं आज कृत्रिम मेधा (एआइ) की आंखें, डेटा विश्लेषण और आधुनिक तकनीकी उपकरण खेल के हर पल को बारीकी से पकड़ते हैं। ऐसे में उभरती खेल शक्ति के रूप में भारत के लिए यह बदलाव का अवसर भी है और चुनौती भी। खिलाड़ी के शरीर का हर सूक्ष्म कंपन अब डेटा है, जिसे 'एल्गोरिदम' पलक झपकते पढ़ लेते हैं।

हाल ही में जारी हुई 'इंडिया एआइ मिशन और राष्ट्रीय खेल नीति-2025' ने इस बदलाव को संस्थागत जामा पहना दिया है। खेल नीति दरअसल तीन बड़े वादों पर टिकी है। पहला, जनभागीदारी- मतलब हर बच्चे को कम से कम एक खेल से जोड़ना। दूसरा, उच्च प्रदर्शन- यानी वर्ष 2036 के ओलंपिक तक भारत पदकों की दहलीज पर खड़े रहने के बजाय ऊपर की सीढ़ियां चढ़े। तीसरा, खेल उद्योग का विकास- यानी खेल को करिअर, बाजार और नवाचार का पूर्णकालिक तंत्र बनाना। इन तीनों वादों को गति देने के लिए खेल नीति में कृत्रिम मेधा को ईंधन मान लिया गया है, जैसे किसी रथ को तीन घोड़े खींच रहे हों और कृत्रिम मेधा उनकी लगाम थामे सारथी हो। विद्यालयों में तंदरुस्ती संबंधी आंकड़े एकत्र करना, राज्यों में खेल विज्ञान केंद्र खोलना और निजी क्षेत्र को कर-रियायत देकर नवाचार की राह चौड़ी करना, ये सब उसी विचार-शृंखला का हिस्सा हैं।

आज खिलाड़ी की तंदुरुस्ती का स्तर, हृदयगति, थकान, नींद और यहां तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी तकनीकी उपकरणों और साफ्टवेयर से मापी जाती है। फुटबाल, क्रिकेट और हाकी जैसे खेलों में तो यह सामान्य बात हो गई है, लेकिन अब भारत जैसे देशों में कुश्ती, कबड्डी और एथलेटिक्स जैसे पारंपरिक खेलों में भी यह तकनीकी हस्तक्षेप दिखाई देने लगा है। 'मशीन की आंख' यानी कृत्रिम मेधा सिर्फ आंकड़े इकट्ठा नहीं करती, बल्कि कोच और खेल संस्थानों को यह समझने में मदद करती है कि कौन-सा खिलाड़ी किस समय किस तरह का प्रदर्शन करेगा।

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में अब कबड्डी खिलाड़ियों को 'स्मार्ट रीडर जैकेट' पहनाई जाती है। इससे खिलाड़ी के कूदने, मुड़ने, सांस की गति, यहां तक कि पैंतरे बदलते वक्त उसकी आंखों की सूक्ष्म झपक भी दर्ज हो जाती है। लखनऊ की महिला हाकी अकादमी में 'सेंसर स्टिक' से पता चला कि 'ड्रैग-फ्लिक' के समय ज्योति सिंह की दाहिनी कलाई जरूरत से अधिक घूमती है। एक हफ्ते में सुधार आया और उसने एशियन चैंपियंस ट्राफी में निर्णायक गोल दागा। पेरिस ओलंपिक 2024 की तैयारियों के दौरान फ्रांस और अमेरिका ने कृत्रिम मेधा का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। अमेरिका की जिम्नास्टिक टीम ने खिलाड़ियों की 'बाडी मूवमेंट' का थ्री डी विश्लेषण करने के लिए एक कृत्रिम

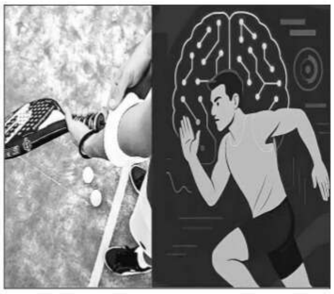

मेधा उपकरण का इस्तेमाल कर व्यक्तिगत कमजोरियों की पहचान की और प्रशिक्षण को उसी मुताबिक बदला। फ्रांस की साइक्लिंग टीम ने स्मार्ट हेलमेट का उपयोग कर खिलाड़ियों के दिल की धड़कन, आक्सीजन स्तर और थकान को मापा, जिससे उन्हें प्रतियोगिता के दौरान रणनीति बदलने में मदद मिली।

> राष्ट्रीय खेल नीति-2025 ने तकनकी बदलाव को संस्थागत जामा पहना दिया है। खेल नीति तीन बड़े वादों पर टिकी है। पहला, जनभागीदारी- मतलब हर बच्चे को कम से कम एक खेल से जोड़ना। दूसरा, उच्च प्रदर्शन- यानी वर्ष 2036 के ओलंपिक तक भारत पदकों की दहलीज पर खड़े रहने के बजाय ऊपर की सीढ़ियां चढ़ें। तीसरा, खेल उद्योग का विकास- यानी खेल को करिअर, बाजार और नवाचार का पूर्णकालिक तंत्र बनाना। इन तीनों वादों को गति देने के लिए खेल नीति में कृत्रिम मेधा को ईंधन मान लिया गया है, जैसे किसी रथ को तीन घोड़े खींच रहे हों और कृत्रिम मेधा उनकी लगाम थामे सारथी हो।

भारत की नई राष्ट्रीय खेल नीति में भी इस तकनीकी क्रांति को जगह दी गई है। सरकार ने कृत्रिम मेधा, डेटा विश्लेषण और खेल विज्ञान के उपयोग को नीति के मूल में रखा है। इसका उद्देश्य सिर्फ ओलंपिक में पदक लाना नहीं है, बल्कि खेल को जन आंदोलन बनाना, युवाओं को सशक्त करना और देश को एक 'फिट इंडिया' में भी बदलना है। चयन प्रक्रिया में भी कृत्रिम मेधा ने बड़ा उलट-फेर किया है। पूरे सत्र के प्रदर्शन का आंकड़ा खिलाड़ी की निरंतरता और तंदरुस्ती का सच सामने रख देता है। पारदर्शिता बढ़ी है और यह अच्छी बात है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि सुदूर क्षेत्रों से आने वाले खिलाड़ियों के पास अगर सेंसर-युक्त जूते नहीं हैं, तो उनकी दौड़ का 'डेटा' बनेगा कैसे? संभावना यह भी है कि गांव की कोई धाविका तकनीकी अभाव के कारण चयन सूची से बाहर रह सकती है।

उधर, कृत्रिम मेधा ने एक नया बाजार खोल दिया है- 'स्पोर्ट्स टेक'। केपीएमजी की एक रपट बताती है कि भारत का स्पोर्ट्स टेक बाजार 18 फीसद वार्षिक दर से बढ़ रहा है और वर्ष 2030 तक यह ढाई अरब डालर का हो जाएगा। नई नीति में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 50 फीसद पूंजीगत मदद की बात कही गई है। मगर बाजार के साथ जोखिम भी आते हैं। सबसे बड़ा खतरा निजी जानकारी की गोपनीयता का है। खिलाड़ी के हार्मोन, हृदय गति, नींद और सोशल मीडिया रुझान आदि के आंकड़े अगर सट्टेबाजों के हाथ लग जाएं, तो उनका करिअर तबाह हो सकता है। दूसरा, खतरा एल्गोरिदम के पूर्वाग्रह का है। अगर प्रशिक्षण आंकड़ा शहरों से आता है, तो मशीनी सीख इसी ढांचे को आदर्श मान लेगी। उदाहरण के लिए छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के आदिवासी युवाओं द्वारा भाला फेंकने की 'टुक्का थ्रो' शैली को कृत्रिम मेधा आधारित कोचिंग प्रणाली 'डिफार्म टेक्नीक' मान सकती है, जबकि यह तकनीक उनकी कलाई की ताकत, वर्षों की स्थानीय अभ्यास विधि और क्षेत्रीय शारीरिक क्षमता का अनूठा उदाहरण है।

तीसरी चुनौती कोचिंग के 'मानवीय कौशल' से जुड़ी है। दशकों के अनुभव से प्रशिक्षक कभी-कभी ऐसा निर्णय लेते हैं, जिसे 'डेटा' नहीं पकड़ पाता। फुटबाल के मैच में कोच ने देखा कि उसका स्ट्राइकर भले ही थका लग रहा हो, मगर प्रतिद्वंद्वी उससे भी ज्यादा हांफ रहा है; कोच ने स्ट्राइकर को रुके रहने दिया और मैच पलट गया। अगर उस क्षण एल्गोरिदम का सुझाव सुनते, तो शायद बदलाव हो जाता और नतीजा अलग होता। इसीलिए जरूरी है कि अंतिम फैसला इंसानी विवेक का ही रहे। कृत्रिम मेधा सलाह दे, संचालक न बने। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या खेल मानवीय त्रुटियों, भावनात्मक क्षणों और बेजोड़ हुनर का रंग खो देगा? जवाब है नहीं, अगर हम चेतन रहें। शतरंज के उदाहरण से अगर समझें तो कंप्यूटर के आने के बाद डर था कि खेल उबाऊ हो जाएगा, लेकिन मैग्नस कार्लसन और विदित गुजराती जैसे खिलाड़ी उन्हीं इंजनों को चुनौती दे रहे हैं और नई रचनात्मक चालें ढूंढ़ रहे हैं।

हमें तीन सूत्र पकड़ने होंगे। पहला, 'डेटा' तक बराबर पहुंच- अगर संसाधन शहर के ही हिस्से हुए, तो सपने भी शहर तक सीमित रह जाएंगे। दूसरा, अंतिम निर्णय में इंसानी विवेक- एल्गोरिदम सलाह दे सकता है, मगर खेल की 'कहानी' इंसान ही लिखेगा। तीसरा, खिलाड़ी कल्याण- बीमा, मानसिक स्वास्थ्य, डेटा सुरक्षा सब एक ही ताने-बाने में बुने जाएं। खेल का उद्देश्य पदक ही नहीं, एक स्वस्थ और नैतिक समाज बनाना भी है। हालांकि, तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि कृत्रिम मेधा और डेटा एनालिटिक्स से खिलाड़ियों के प्रदर्शन की रोज निगरानी होगी और सुधार के मौके समझ में आएंगे। महिला खिलाड़ी, दिव्यांगजन, आदिवासी और पारंपरिक खेलों को विशेष समर्थन मिलेगा, ताकि वे भी कामयाबी की यात्रा का हिस्सा बन सकें।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

# एकांगी सोच का दंश

**राजेंद्र बज**

जिंदगी में ऐसे अनेक मोड़ आते हैं, जब हम सामान्य अवस्था में नहीं रह पाते, असहज हो जाते हैं। यह स्थिति प्रतिकूल या फिर अनुकूल, दोनों ही अवस्थाओं में हमारी मानसिकता पर गहरा प्रभाव डालती है। इसके अतिरिक्त इसका शारीरिक प्रभाव भी पड़े बिना नहीं रहता। यही नहीं, प्रसन्नता या अवसाद का अतिरेक हमारे सामान्य विवेक को भी हर लेता है। आमतौर पर ऐसी स्थिति अपेक्षा के विपरीत कुछ हो जाने या घट जाने पर निर्मित हुआ करती है। यों भी अपेक्षा को दुख के कारण के रूप में निरूपित किया गया है। यह कोई जरूरी नहीं है कि सब कुछ हमारी अपनी धारणा के अनुरूप ही हो।

हर किसी का वैचारिक स्तर एक समान नहीं होता। और तो और, सोचने और समझने की दृष्टि भी सबकी अपनी अलग-अलग हो सकती है। इसके चलते न तो कोई व्यक्ति सर्वमान्य हो पाता है और न ही कोई विचार। वास्तव में व्यक्तिगत और वैचारिक स्तर पर जनसाधारण की समान मानसिकता का विस्तार कहीं से कहीं तक संभव नहीं होता। ऐसी स्थिति में अगर अपने आपको सामने वाले के स्थान पर रखकर देखा जाए, तो बहुत स्वाभाविक है कि हम किसी न किसी एक सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। अनावश्यक रूप से अहं की लड़ाई के चलते हम अपनी मानसिक और शारीरिक क्षमता का लाभ नहीं ले पाते।

दुनिया भर के तमाम विवादों का मूल कारण किसी एक पक्ष की एकतरफा सोच ही होती है, जिसके चलते समाधान के अभाव में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। लगातार तमाम तरह के बढ़ते विवादों के चलते न्याय की अपेक्षा करने वालों की कतार इतनी लंबी हो गई है कि अंतिम न्याय पाने की कोशिश में जिंदगी का एक बड़ा भाग जाया हो जाता है। कभी-कभी तो व्यवस्थित रूप से जोड़-घटाव करने के बाद भी हासिल कुछ नहीं बचता। या कभी बचता भी है, तो लगभग न के बराबर। बात सिर्फ आर्थिक ही नहीं है, बल्कि लंबी प्रतीक्षा और मानसिक संताप का भी अगर आर्थिक दृष्टि से मूल्यांकन करें, तो चौंकाने वाले परिणाम हमारे सामने होंगे।

**दुनिया मेरे आगे**

> दुनिया भर के तमाम विवादों का मूल कारण किसी पक्ष की एकतरफा सोच ही होती है, जिसके कारण समाधान के अभाव में न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाया जाता है। लगातार तमाम तरह के बढ़ते विवादों के चलते न्याय की अपेक्षा करने वालों की कतार इतनी लंबी हो गई है कि अंतिम न्याय पाने की कोशिश में जिंदगी का एक बड़ा भाग जाया हो जाता है।

हालांकि जमाने में सब कुछ निर्विवाद नहीं हो सकता। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उभय पक्ष अपनी-अपनी जगह लगभग सही हो। ऐसी स्थिति में जब समाधान की कोई सूरत ही नजर नहीं आती हो, तब न्यायपालिका का सहारा लिया जाए, लेकिन व्यवहार में देखा गया है कि कभी-कभी किसी मामले को लंबे समय तक टालने की दृष्टि से भी न्यायपालिका का सहारा लिया जाने लगा है। यही कारण है कि देश भर की तमाम अदालतों में मुकदमों की भरमार नजर आती है। ऐसी स्थिति में जिनके लिए वास्तव में न्याय अपेक्षित होता है, उन्हें भी लंबी कतार में लगने को बाध्य होना पड़ता है और यही वजह है कि न्याय पाने की प्रक्रिया समय और धन साध्य हो जाती है।

ऐसे में सबके लिए यह अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि हम सुलह का रास्ता अख्तियार करने की दिशा में गंभीरता का परिचय दें। यों भी, न्यायपालिका की मध्यस्थता मे अनेक तरह के मामलों का लोक अदालत द्वारा पटाक्षेप करने का प्रयास किया जाता रहा है, जिसमें दोनों पक्ष के अभिभाषक वर्ग की अत्यंत सराहनीय भूमिका निकल कर आती रही है। समय की मांग के अनुरूप यह सिलसिला अनवरत रूप से चलते रहना चाहिए। इससे कुल मिलाकर देश में उपलब्ध शारीरिक और मानसिक श्रम शक्ति का और भी समुचित दोहन होने का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, क्योंकि देश की ऊर्जा और चेतना का एक बड़ा भाग न्याय की अपेक्षा में खोया-खोया नजर आता है।

दरअसल, त्वरित न्याय के लिए देश में ऐसा वातावरण बनाया जाना जरूरी है कि अव्वल तो विवाद हो ही नहीं, और हो तो भी सीमित मात्रा में। इसके लिए हर एक आदमी को एकतरफा सोच की स्थिति से उबरना होगा। इस दिशा में सामाजिक प्रभाव और दबाव भी कारगर हो सकता है। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका और अभिभाषक वर्ग की भूमिका भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण होगी। हालांकि न्यायपालिका और अभिभाषक वर्ग का हर संभव प्रयास त्वरित न्याय की दिशा में ही होता है, लेकिन मुकदमों की बहुतायत के चलते इसका प्रत्यक्ष परिणाम कहीं दिखाई नहीं देता। इसका नतीजा होता है कि तारीख पर तारीख और तारीख पर तारीख ही मिलती चली जाती है। इसके चलते विलंबित न्याय, अन्याय के प्रतिरूप में ही दिखाई देने लगता है।

बहरहाल, मुद्दे की बात यह कि इन तमाम स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अगर एकतरफा विचार के बजाय निष्पक्ष और तटस्थ दृष्टि से किसी मामले का आकलन किया जाए, तो सहज रूप से अदालत से परे मामले का समाधान संभव हो सकता है। इस दिशा में सामाजिक नेतृत्व अपने समाज में ऐसा वातावरण निर्मित कर सकता है कि विभिन्न समाजों के बीच एक संतुलन का वातावरण निर्मित हो सके।

जाहिर है कि जब इस प्रक्रिया का विस्तार होने लगेगा, सारा का सारा सामाजिक परिवेश ही शांति का पुजारी बन जाएगा। अन्यथा हालात ऐसे ही रहे, तो दिनोंदिन बढ़ती मुकदमों की संख्या न्याय को और भी अधिक समय और धन साध्य बनाकर रख देगी। इस वजह से सामाजिक सद्भाव पर तो विपरीत असर पड़ेगा ही, कानून और व्यवस्था के समक्ष भी गंभीर चुनौती उपस्थित हो सकती है। यों भी अधिकतर धन संपत्ति और अपराध के मामले विचाराधीन रहा करते हैं। ऐसे में धन संपत्ति के मामले में आपराधिक वर्ग के हस्तक्षेप को पूरी तरह से नहीं रोका जा सकेगा। यह स्थिति आम नागरिकों के सामान्य जनजीवन पर भारी भी पड़ सकती है। इसलिए यह जरूरी है कि हर कोई अपनी एकतरफा सोच-विचार का परित्याग करके चले।

**चौपाल**

## मित्रता का दायरा

आमतौर पर सभी संबंध जन्म और परिवार से जुड़े होते हैं। सिर्फ एक दोस्ती का संबंध दिल से बनता है। निस्संदेह जीवन में दोस्त का अहम स्थान होता है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर मौके पर लोगों को किसी न किसी दोस्त की जरूरत महसूस होती है। किसी भी इंसान की पहली दोस्त उसकी मां होती है। युवा अवस्था में भाई-भाई भी एक दूसरे का दोस्त बनते हैं। वहीं यह भी कहा जाता है कि भाई से बड़ा कोई दोस्त नहीं और भाई से बड़ा कोई शत्रु भी नहीं होता है। दोस्तों के बीच कोई ऊंच-नीच, अमीरी-गरीबी और जाति-धर्म की दीवार नहीं होती है। भगवान कृष्ण और सुदामा की दोस्ती सदैव लोगों को सच्ची दोस्ती की प्रेरणा देती रहेगी। आज सोशल मीडिया पर लोगों की मित्र सूची में हजारों नाम जुड़े होते हैं, लेकिन जब वास्तविक जीवन में संकट की घड़ी आती है, तो कोई भी साथ खड़ा नहीं होता है। सोशल मीडिया के दौर में मित्र भी आभासी बनते जा रहे हैं। आजकल लोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए भी दोस्ती कर रहे हैं। फिल्मों में भी दोस्ती की कई कहानियां दिखाई गई हैं। दोस्ती को पवित्र बनाए रखना आज के युवाओं के हाथों में है।

*– हिमांशु शेखर, गयाजी, बिहार*

## कठघरे में जांच

'जांच पर आंच' (संपादकीय, 2 अगस्त) में दिए तथ्य कई ज्वलंत प्रश्न खड़े करते हैं। न्यायालय द्वारा संदेह का लाभ देना और ठोस सबूत देने में सफल न होने को इंगित करना न्यायिक परिधि में जरूर है, लेकिन यह सवाल मुंह बाए खड़ा है कि निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार अंततः कौन है? साक्ष्यों, ठोस प्रमाणों और प्रत्यक्षदर्शियों के अलावा अन्य कोण से गहराई से जांच करने में क्यों कोताही की गई? मालेगांव विस्फोट मामले में एनआइए की विशेष अदालत उस नतीजे पर पहुंची, जिस पर मुंबई उच्च न्यायालय भी ट्रेन विस्फोट मामले की सुनवाई करते हुए पहुंचा था। यह निर्णय जांच एजंसी को कठघरे में अवश्य खड़ा करता है। ऐसे निर्णय से पीड़ितों के परिजन अपने को ठगा महसूस करते हैं। अगर जांच के दायरे में लाए गए सभी आरोपी निर्दोष हैं, तो वास्तविक अपराधी कौन है? अब मालेगांव और मुंबई ट्रेन घटना के दोषियों को कैसे शिकंजे में लाया जाएगा।

*– अशोक कुमार, पटना*

## स्वदेशी का संकल्प

प्रधानमंत्री ने स्वदेशी को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। संकल्प लेना होगा कि घर में जो भी नया सामान आए, वह स्वदेशी ही आएगा। भारत को अपने आर्थिक हितों के प्रति सजग रहना होगा। प्रधानमंत्री का आह्वान निश्चित रूप से देशहित में है। यह हर भारतवासी के लिए लाभप्रद साबित होगा। कोई दो मत नहीं कि पड़ोसी देशों की बार-बार बदलती फितरत को जवाब देने के लिए देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने 29 मई को गांधीनगर में कहा था कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए विदेशी सामान का बहिष्कार जरूरी है। इसके लिए जरूरी है गांव-गांव शपथ दिलाने की। इससे चीन को भी करारा जवाब मिलेगा। उम्मीद है कि हम स्वदेशी का संकल्प लेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था के लिए योगदान देंगे। स्वदेशी सामान अपनाने से दूसरे देशों की निर्भरता तो कम होंगी ही, भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भी मजबूती मिलेगी।

*– योगेश जोशी, बड़वाह*

## नाहक दबाव

हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने फिर आरोप लगाया कि भारत का शुल्क सबसे अधिक है। साथ ही ट्रंप ने यह भी घोषणा कर दी कि रूस से तेल और हथियार खरीदने के कारण भारत पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। भारत से आयातित वस्तुओं पर 25 फीसद अतिरिक्त शुल्क लागू किया जाना तय है। शुल्क थोप कर डोनाल्ड ट्रंप भारत पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वह अमेरिका से लड़ाकू विमान खरीदे, जबकि रूस के पास तकनीकी दृष्टि से कहीं अधिक उन्नत विकल्प मौजूद हैं। अमेरिका भारत पर डेयरी उत्पाद, मांस और अन्य कृषि वस्तुएं आयात करने के लिए भी दबाव बना रहा है। यह विडंबना ही है कि एक ओर अमेरिका हमें स्वतंत्र कूटनीति का सम्मान करने की सीख देता है और दूसरी ओर स्वयं भारत के नीतिगत निर्णयों पर दबाव बना रहा है। सरकार को चाहिए कि वह राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखे।

*– विभूति बुपक्या, खाचरौद, मप्र*

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

{ संपादकीय }

नई दिल्ली, बुधवार 6 अगस्त 2025
संस्थापक-सम्पादक : स्व. मायाराम सुरजन

## दो जुझारू नेताओं का निधन

भारतीय राजनीति से दो दिनों में दो कद्दावर नेताओं का निधन बड़ी शून्यता कायम कर गया है। 4 अगस्त को शिबू सोरेन का निधन हुआ और 5 अगस्त को सत्यपाल मलिक का। श्री सोरेन और श्री मलिक दोनों की राजनीति के तौर-तरीके अलग थे, दल अलग थे, विचारधारा अलग थी। लेकिन मिज़ाज दोनों का एक ही तरह का था, जुझारू, अक्खड़पना, जमीन से जुड़ाव और गांधी की भाषा में कहें तो अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति की फिक्र दोनों नेताओं की राजनीति के केंद्र में रही। शिबू सोरेन आदिवासियों के बड़े नेता थे, उन्हें झारखंड के लोग केवल दिशोम गुरु (समाज का गुरु) ही नहीं कहते हैं, बल्कि भगवान की तरह मानते हैं। सत्यपाल मलिक का जनाधार बेशक शिबू सोरेन की तरह नहीं रहा, लेकिन उन्होंने भी गरीब, वंचित पीड़ित लोगों के हितों को तरजीह दी। शिबू सोरेन और सत्यपाल मलिक में सबसे बड़ी समानता यह रही कि सत्ता के साथ रहते हुए जी हुजूरी नहीं की और सत्ता के खिलाफ रहे तो खौफ नहीं खाया।

साल 1944 में अविभाजित बिहार के हजारीबाग में जन्मे शिबू सोरेन के संघर्ष की शुरुआत अल्पायु में ही हो गई थी। उनके पिता सोबरन सोरेन की हत्या कर दी गई, क्योंकि उन्होंने आदिवासी इलाकों में फैले महाजनों के आतंक के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। पिता के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए शिबू सोरेन ने भी महाजनी प्रथा के खिलाफ़ आवाज़ उठाई और धान कटनी आंदोलन चलाया। उन्होंने आदिवासियों को जागरूक किया कि धान लगाने वाला ही धान काटेगा और इस पर महाजनों का कोई अधिकार नहीं है। 70 से 80 के दशक में ये आंदोलन बहुत बड़ा हो गया, इसने झारखंड के किसानों, कामगारों और काश्तकारों को एकजुट किया, आदिवासियों को शोषण के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिलाई। इसी वजह से शिबू सोरेन को झारखंड के लोगों ने दिशोम गुरु की उपाधि दी। कई सालों तक शिबू सोरेन ने आदिवासियों के लिए रात्रि पाठशाला चलाई ताकि दिन भर अपना-अपना काम निपटाने के बाद आदिवासी पढ़ पाएं। शिक्षा के अलावा शराब और नशे से आदिवासियों को दूर करने की कोशिश भी शिबू सोरेन ने की। 1980 में पहली बार सांसद बनने के बाद जब उन्होंने संसद में भाषण दिया तो शराब के विरोध में बोले।

शिबू सोरेन ने सामाजिक सुधार के साथ 1973 में राजनीति में कदम रखा, विनोद महतो और कामरेड एके राय के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना की। अविभाजित बिहार में प्राकृतिक संसाधनों का खजाना लिए दक्षिण के 26 जिलों को मिलाकर एक झारखंड राज्य बने, ऐसी कल्पना उन्होंने की। लंबे संघर्ष और राजनैतिक उठापटक के बाद आखिरकार 2000 में झारखंड राज्य बना, साथ में छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड भी बने। हालांकि झारखंड निर्माण के बाद कई बार राजनैतिक अस्थिरता बनी। इस दौरान शिबू सोरेन कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा, कभी विधानसभा के सदस्य बनते रहे। विभिन्न दलों के साथ उनके वैचारिक, सैद्धांतिक टकराव हुए। दिल्ली की सत्ता पर बैठे लोगों के साथ उन्होंने समझौते भी किए, लेकिन इन सबके बीच आदिवासियों के हितों के उद्देश्य से गुरुजी एक बार भी नहीं भटके। आठ बार लोकसभा सांसद, दो बार राज्यसभा सांसद, दो बार विधायक बनने वाले शिबू सोरेन ने केन्द्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री जैसे पद संभाले, हालांकि कई तरह के मामले-मुकदमों और राजनैतिक उठापटक में वे अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाए। आज जब सत्ता पर किसी भी तरह बैठना ही कई नेताओं का अंतिम लक्ष्य बन गया है, तब शिबू सोरेन जैसे नेताओं के जीवन को याद करना चाहिए, जिन्होंने सत्ता से पहले नागरिकों का ख्याल रखा।

सत्यपाल मलिक का भी राजनीतिक जीवन पांच दशक लंबा रहा। 1968-1969 में छात्र राजनीति से शुरुआत करते हुए श्री मलिक किसान नेता चौधरी चरण सिंह के करीब आए और 1974 में चुनावी राजनीति में उतरे। बागपत से विधानसभा का चुनाव जीतकर पहली बार विधायक बने। इसके बाद वे चौधरी चरण सिंह के साथ ही लोक दल में शामिल हो गए, उन्हें पार्टी का महासचिव बनाया गया। सत्यपाल मलिक 1980 में लोक दल की ओर से ही राज्यसभा पहुंचे। 1984 में वे कांग्रेस में शामिल हो गए थे। कांग्रेस ने उन्हें 1986 में एक बार फिर राज्यसभा पहुंचाया। बोफोर्स मामला उठने के बाद श्री मलिक वी पी सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल में शामिल हुए, 1989 में सांसद बने और केन्द्रीय राज्य मंत्री भी। इसके बाद 2004 में सत्यपाल मलिक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। राजनीतिक उथल-पुथल, सत्ता के खेल इन सबको श्री मलिक ने करीब से देखा, कई बार उनमें प्रत्यक्ष या परोक्ष तौर पर शामिल हुए। जिस पार्टी के साथ रहे, उससे मतभेद भी हुआ। लेकिन भाजपा में नरेन्द्र मोदी का शासनकाल शुरु होने पर जिस तरह उनके मतभेद सामने आए, वे सर्वाधिक चर्चित हुए। पुलवामा हमले पर मोदी सरकार ने उन्होंने जो हमला बोला, उसकी काफी चर्चा हुई। यहां बताना जरूरी है कि देशबन्धु के यूट्यूब चैनल डीबीलाइव पर ही सबसे पहले श्री मलिक ने पुलवामा को लेकर नए खुलासे किए थे। इसके ठीक बाद द वायर के लिए करण थापर ने उनसे इसी आधार पर इंटरव्यू लिया, हालांकि श्री थापर ने इसके लिए डीबीलाइव को श्रेय नहीं दिया। बहरहाल, सत्यपाल मलिक ने खुलासा किया था कि उन्होंने सरकार से कहा था कि जवानों को हवाई मार्ग से भेजा जाना चाहिए, लेकिन उनकी सलाह नहीं मानी गई। इसके अलावा उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। इससे पहले किसान आंदोलन, महिला पहलवानों का जंतर-मंतर पर धरना, अग्निवीर पर फैसला, भूमि अधिग्रहण विधेयक इन सब पर उन्होंने मोदी सरकार की मुखालफत की। मेघालय, गोवा, बिहार, जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए भी श्री मलिक ने कभी सत्ता की जी हुजूरी नहीं की, बल्कि जो गलत लगा, खुलकर उसके खिलाफ आवाज उठाई।

अपने अंतिम दिनों में भी सत्यपाल मलिक का संघर्ष जारी रहा। उन पर सीबीआई की जांच सरकार ने बिठाई थी। जिस पर अस्पताल से लिखी एक पोस्ट में सत्यपाल मलिक ने लिखा- मैं सरकार को और सरकारी एजेंसियों को बताना चाहता हूं कि मैं किसान कौम से हूं, मैं ना तो डरने वाला हूं ओर ना ही झूकने वाला हूं।

सरकार ने मुझे बदनाम करने में पूरी ताकत लगा दी, हालांकि सच्चाई तो यह है कि 50 साल से अधिक लंबे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़े-बड़े पदों पर देशसेवा करने का मौका मिलने के बाद आज़ भी मैं एक कमरे के मकान में रह रहा हूं ओर कर्ज में भी हूं। अगर आज मेरे पास धन दौलत होती तो मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाता।

# दंभोक्ति है कि 'हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता'

'कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता।' यह बात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी के नेता अक्सर कहते रहते हैं, लेकिन यही बात अब केंद्र सरकार की ओर से संसद में भी कह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले दिनों राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए कहा- 'मैं गर्व से कह सकता हूं कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता।' इसे संयोग कहें या कुछ और कि गृह मंत्री के इस भाषण के अगले ही दिन राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके मामले का फैसला सुनाते हुए भाजपा की पूर्व सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत सातों अभियुक्तों को बरी कर दिया।

अमित शाह से पहले यही बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान मशहूर अभिनेता कमल हासन के बयान के जवाब में कही थी। अभिनेता से नेता बने कमल हासन ने अपनी एक चुनावी सभा में कहा था कि- 'देश का पहला आतंकवादी नाथूराम गोडसे हिंदू था, जिसने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या की थी।' कमल हासन के इस बयान पर मोदी ने एक टीवी चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि 'आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन इसी के साथ अगली सांस में उन्होंने यह भी कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता और जो आतंकवादी होता है, वह कभी हिंदू नहीं हो सकता।'

वह पहला मौका था जब देश के किसी प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरह की बात निकली हो। मोदी ने पीएम के रूप में यह बात पहली बार कही थी और चुनाव अभियान के दौरान कही थी जिसका राजनीतिक मकसद साफ था। वे अपनी चुनावी रैलियों में लगातार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने वाले भाषण दे रहे थे। गोडसे के बारे में भी उनके कथन से साफ था कि उन्होंने परोक्ष रूप से राष्ट्रपिता के हत्यारे का बचाव किया था।

बहरहाल भाजपा की ओर से अभी तक जो बात संसद के बाहर कही जाती रही थी, उसे अब सरकार की ओर से शाह ने संसद में भी दोहरा दिया है। उनका यह बयान न सिर्फ देश के तमाम गैर हिंदू समुदायों को लांछित और अपमानित करने वाला है बल्कि उस संविधान को भी सीधे-सीधे चुनौती है, जिसकी शपथ लेकर वे धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक भारत के गृह मंत्री बने हुए हैं।

इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होता है। मगर ऐसा कहने के साथ ही जब कोई यह कहता है कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता तो उसका यह कथन न सिर्फ उसके पूर्व कथन का खोखलापन जाहिर करता है बल्कि उसके अपराधबोध और वास्तविक इरादों का भी परिचय कराता है। उसके इस कथन का निहितार्थ होता है कि कोई हिंदू तो आतंकवादी नहीं हो सकता, लेकिन कोई गैर हिंदू जरूर आतंकवादी हो सकता है। सवाल है कि जब कोई गैर हिंदू ही आतंकवादी हो सकता है तो फिर यह कहने का क्या मतलब है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता?

जब कोई यह कहता है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, तो यह सवाल पूछना लाजिमी हो जाता है कि जब कोई हिंदू किसी स्त्री के साथ बलात्कार कर सकता है, किसी की हत्या कर सकता है, चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, लूटपाट कर सकता है, इसके अलावा और भी तमाम तरह के आपराधिक कृत्यों में लिप्त हो सकता है तो फिर वह आतंकवादी क्यों नहीं हो सकता? फिर सवाल यह भी है कि आखिर आतंकवाद किसे कहेंगे? सामान्य समझ तो यही कहती है कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा अपने नाजायज मकसद को पाने के लिए किसी भी तरह के जान-माल का नुकसान करना और समाज में भय का माहौल बनाना ही आतंकवाद है।

अनिल जैन

> इस बात से तो कोई इनकार नहीं करेगा कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकवादी सिर्फ आतंकवादी ही होता है। मगर ऐसा कहने के साथ ही जब कोई यह कहता है कि कोई भी हिंदू कभी आतंकवादी हो ही नहीं सकता तो उसका यह कथन न सिर्फ उसके पूर्व कथन का खोखलापन जाहिर करता है बल्कि उसके अपराधबोध और वास्तविक इरादों का भी परिचय कराता है।

इस ऐतिहासिक तथ्य से कौन इनकार कर सकता है कि महात्मा गांधी की निर्मम हत्या आजाद भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी आतंकवादी वारदात थी, जो सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित थी। उसे अंजाम देने वाला वाला व्यक्ति कोई पाकिस्तान या अफगानिस्तान से नहीं आया था। जो था, वह हिंदू नाथूराम गोडसे ही था।

यही नहीं, महात्मा गांधी की हत्या की साजिश में शामिल रहे विनायक दामोदर सावरकर, गोपाल गोडसे, नारायण आप्टे, मदनलाल पाहवा, रामकृष्ण करकरे, दिगंबर बडगे आदि नाथूराम के सभी सहयोगी भी हिंदू ही थे। नाथूराम गोडसे तो ऐसा हिंदू था कि गांधी जी पर गोलियां दागने के पहले हुई धक्का-मुक्की में उनकी पोती मनु के हाथ से जमीन पर गिरी पूजा वाली माला और आश्रम की भजनावली को भी वह अपने पैरों तले रौंदता हुआ आगे बढ़ गया था। 20वीं सदी का जघन्यतम अपराध करने- एक निहत्थे बूढ़े, परम सनातनी हिंदू, राम के अनन्य- आजीवन आराधक का सीना गोलियों से छलनी करने।

हिंदू राष्ट्रवादियों का नुमाइंदा नाथूराम गोडसे गांधी की हत्या के जरिए आतंक पैदा कर देश के बाकी नेताओं को यही तो संदेश देना चाहता था कि हिंदू-मुस्लिम मेलमिलाप की बात करने वालों का वही हश्र होगा जो गांधी का हुआ है। क्या नरेन्द्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत और उनकी राष्ट्रवादी जमात के अन्य नेता इस हकीकत को नकार सकते हैं कि 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में हुआ सिखों का कत्लेआम देश के बंटवारे के बाद की सबसे बड़ी त्रासदी थी। उस त्रासदी के दौरान भी असंख्य सिखों को जिंदा जलाने वालों और उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार करने ज्यादातर हिंदू ही तो थे।

सवाल यह भी है कि कोई ढाई दशक पूर्व ओडिशा में ग्राहम स्टेंस नामक निर्दोष बूढ़े पादरी और उसके मासूम बच्चों को जिंदा जलाने का कृत्य क्या आतंकवाद नहीं कहा जाएगा? उस कृत्य को अंजाम देने वाला बजरंग दल का पदाधिकारी दारासिंह क्या किसी दूसरे देश का गैर हिंदू नागरिक था? ओडिशा में ही करीब डेढ़ दशक पहले विश्व हिंदू परिषद के एक नेता लक्ष्मणानंद के नक्सलियों के हाथों मारे जाने की घटना का ठीकरा ईसाई मिशनरियों के माथे फोड़ कर लगभग एक माह तक विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कंधमाल में हिंसा का जो तांडव मचाया था, क्या वह आतंकवाद नहीं था? वहां रहने वाले सभी ईसाइयों के घरों और चर्चों को आग के हवाले कर डेढ़ सौ से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिए जाने का समूचा घटनाक्रम किस तरह के राष्ट्रवाद से प्रेरित था?

इसी सिलसिले में सवाल गुजरात को लेकर भी बनता है कि इसी सदी के शुरुआती दौर में वहां 'क्रिया की प्रतिक्रिया' के नाम पर मुसलमानों का संगठित कत्लेआम क्या आतंकवादी कार्रवाई नहीं थी? उसी कत्लेआम के दौरान मुस्लिम समुदाय की कई गर्भवती स्त्रियों के गर्भ पर लातें मार-मार कर उनकी और उनके गर्भस्थ शिशुओं की हत्या कर देना किस तरह के मानव धर्म या राष्ट्रभक्ति से प्रेरित कृत्य था? उसी हिंसा में सौ से अधिक लोगों की हत्या के लिए जिम्मेदार बाबू बजरंगी को क्या आतंकवादी नहीं माना जाएगा, जिसे अदालत ने आजीवन कारावास की सजा दे रखी है।

शायद मोदी, अमित शाह और उनकी संस्कार शाला (आरएसएस) के नेताओं की नजरों में किसी स्त्री के साथ बलात्कार या किसी को जिंदा जला देना आतंकवाद तो क्या सामान्य अपराध की श्रेणी में भी नहीं आता होगा! अगर आता तो वे यह बचकानी दलील कतई नहीं देते कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। पृथक गोरखालैंड तथा बोडोलैंड के लिए दशकों से हिंसक गतिविधियों में संलग्न लड़ाकों को भी क्या मोदी और शाह हिंदू नहीं मानेंगे?

सीमा पार के आतंकवाद के साथ ही हमारा देश आज जिस एक और बड़ी चुनौती से जूझ रहा है, वह है माओवादी आतंकवाद। देश के विभिन्न इलाकों में सक्रिय विभिन्न माओवादी संगठनों में अपवाद स्वरूप ही कोई एकाध मुस्लिम युवक होगा, अन्यथा सारे के सारे लड़ाके संघ की परिभाषा के तहत हिंदू ही हैं।

उपरोक्त सारे उदाहरणों का आशय समूचे हिंदू समाज को लांछित या अपमानित करना कतई नहीं है। मकसद सिर्फ यह बताना है कि चाहे वह गोडसे हो या दारासिंह, चाहे सिख विरोधी हिंसा के अपराधी हो या गुजरात के कातिल, चाहे वह चर्चों और ईसाइयों के घरों में आग लगाने वाले हों या माओवादी लड़ाके, सबके सब चाहे वे जिस जाति या प्रदेश के हो या चाहे जो भाषा बोलते हो, वे सब संघ की परिभाषा के तहत हिंदू ही हैं। इसलिए यह दंभोक्ति निहायत ही अतार्किक और बेमतलब है कि कोई हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता।

**(लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं)**

# हिरोशिमा का शांति संदेश

■ बाबा मायाराम

इस समय दुनिया में कई छोटे-बड़े युद्ध हो रहे हैं। पूरा विश्व, युद्ध से घायल हो रहा है। इसे टीवी के पर्दे पर भी दिखाया जा रहा हैं। लोग मारे जा रहे हैं, जिन में बहुत से बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसे माहौल में शांति की, करूणा की और अहिंसा की खबरें गायब हो जाती हैं। युद्धों के कई दूरगामी, दीर्घकालीन और पीढ़ियों तक असर होते हैं। यहां युद्ध से जुड़ी तीन मार्मिक कहानियों के माध्यम से उसकी विभीषिका व तबाही को समझा जा सकता है।

एक कहानी सडाको की है, जो 'सडाको और कागज के पक्षी' नामक किताब में दर्ज़ है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब अमरीका ने जापान के हिरोशिमा पर बम बरसाए, तब जापानी लड़की सडाको दो साल की थी। लेकिन बाद में वह बीमार हो गई। उसे एटम-बम के असर से बीमारी हो गई। बम गिरने के 9 साल बाद सडाको को खून का कैंसर यानि लुकीमिआ हो गया।

फिर हिरोशिमा दिवस आया। उस दिन को याद करने के लोगों ने दीवारों पर एटम बम में मारे गए लोगों के फोटो चिपकाए। कागज की बनी लालटेन के अंदर मोमबत्तियां जलाईं। सडाको ने अपनी लालटेन पर मृत दादी का नाम लिखा, और उसे नदी में बहाया। ये सब लालटेनें जुगुनियों की तरह टिमटिमा रही थीं।

सडाको का, स्कूल की रिले रेस में दौड़ने के लिए चयन हुआ था। वह बहुत उत्साहित थी। वह उस दिन दौड़ी भी और जीत गई थी। पर इसी दौरान उसका सिर चकराने लगा। कुछ दिन बाद भी स्कूल में वह दौड़ते समय गिर गई। जब अस्पताल में उसका एक्स रे लिया गया तो खून का कैंसर निकला।

इलाज के लिए उसे कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। इस दौरान उसके परिजन व स्कूल के दोस्त मिलने आए। एक दिन उसकी प्रिय मित्र चुजूकी आई। उसने उसे अच्छा होने का अनोखा तरीका बताया। उसने एक कागज की चिड़िया बना दी। और कहा कि अगर कोई बीमार व्यक्ति एक हज़ार कागज की चिड़िए मोड़े तो स्वस्थ हो जाता है।

इस तरह कागज की चिड़िया बनाने का सिलसिला शुरू हो गया। सडाको ने कागज की चिड़िया बनाना सीखा। और सभी को कतार में सजाया। जगह कम पड़ी तो उसके एक दोस्त मासाहीरो ने उन्हें छत से लटका दिया। सडाको कई दिनों तक चिड़िया बनाती रही। पर बीमारी शरीर में फैलती रही। वह उसको नजरअंदाज कर कागज़ की चिड़िया बनाने में लगी रही। अब तक वह चार सौ चौसठ चिड़िया बना चुकी थी। अब वह जल्दी थक जाती थी। कुछ और हिम्मत की। उसने 644 चिड़िया बनाई, पर उसमें शक्ति नहीं बची। अब कागज मोड़ने की अवस्था नहीं रही। और वह चिड़ियों को निहारते-निहारते गहरी नींद में सो गई। फिर कभी नहीं उठी और चल बसी।

बाद में उसकी कक्षा के दोस्तो ने शेष 356 चिड़ियाएं बनाई और हजार चिड़ियों के साथ सडाको को दफना दिया गया। उसके बाद सडाको के मित्रो ने उसकी याद में एक स्मारक बनाया। अब शांति दिवस के दिन सडाको के स्मारक पर कागज के पक्षियों की मालाएं पहनाते हैं। उस स्मारक पर लिखा है - यही हमारे आंसू हैं, यही हमारी प्रार्थना है, दुनिया मे शांति हो।

इसी प्रकार, एक और कहानी है 'शिन की तिपहिया साइकिल'। इस कहानी को तातसुहारू कोडामा ने लिखा है। शिन जब तीन साल का था, तो तिपहिया साइकिल चला रहा था, तब हिरोशिमा पर अमेरिका ने बम बरसाए।

शिन को साइकिल बहुत प्रिय थी। उसकी दो बहनें भी थीं- मिचिका और योको। लेकिन कई दिनों बाद उसके फौजी चाचा ने उसे जन्मदिन पर तोहफा दिया, और वह भी तिपहिया साइकिल। उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। वह खुशी के मारे उछलने लगा।

लेकिन उसे क्या पता था कि यह खुशी ज्यादा देर न रह सकी। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और शिन न रहा। उसकी दोनों बहनें भी मर गईं। वह घर ढहने से उसकी लकड़ियों के नीचे दब गया था। लेकिन वह उस समय भी अपनी तिपहिया साइकिल को पकड़े हुए था। वह आग में झुलस गया था, उसकी मां उसे नदी की ओर लेकर दौड़ी। वहां सैकड़ों लोग रोते हुए बिलख रहे थे। शिन ने धीमी आवाज़ में पानी मांगा। पर उसे बचाया न जा सका। उसी रात वह चल बसा। उस समय उसकी उम्र सिर्फ चार साल की ही थी। उसे उसकी प्रिय साइकिल के साथ दफना दिया गया। शिन की कहानी भी दुनिया को शांति का संदेश देती है।

ऐसी ही एक कहानी है 'वफादार हाथी' की। इसे युकियो थुचिया ने लिखा है। यह एक चिड़ियाघर के हाथियों की कहानी है, जिन्हें इसलिए मारा गया कि अगर बम गिरे तो ये जानवर उत्पाद न फैला दें। यह टोकयो का चिड़ियाघर था।

इस चिड़ियाघर में कई जानवर थे, इनमें तीन हाथी भी शामिल थे। यह हाथी दर्शकों को करतब दिखाते थे। इन हाथियों का नाम जॉन, टौंकी, वैनली था। युद्ध में रोज ही बम बरसाए जा रहे थे।

चिड़ियाघर के लोगों ने सोचा कि अगर बम यहां गिरेगा तो जानवर भागेंगे, शहर में उत्पाद मचाएंगे, इसलिए उन्हें मार डाला जाए। पर मारे कैसे, सभी प्रयास करने के बाद उन्हें भूखा रखा गया। एक हाथी तो कुछ दिन बाद मर गया। पर दो बच गए। उनका खाना-पीना बंद कर दिया गया। भूख के मारे उनकी हड्डियां निकल आईं। यह सब देखकर हाथियों की परवरिश करने वाले महावत से रहा नहीं गया। उसने उन्हें खाना खिलाया, चिड़ियाघर के किसी भी कर्मचारी अधिकारी ने इसका विरोध नहीं किया। क्योंकि सभी इससे दुखी थे।

लेकिन कुछ दिन बाद दोनों हाथी मर गए। महावत रोने लगा और प्रार्थना करने लगा कि युद्ध बंद करो, युद्ध बंद करो। अब उन हाथियों की याद में स्मारक बना है।

शांति पर एक और पुस्तक है- द स्टोरी ऑफ फरडीनैंड। इसे मनरो लीफ ने लिखा है। यह फरडीनैंड नामक एक बैल की कहानी है, जिसे लड़ाई पसंद नहीं है, वह उसका विरोध करता है। उसे फूल बहुत पसंद हैं। घास के मैदान में बैठा-बैठा वह फूलों की खुशबू सूंघता था। दूसरे बैल लड़ते रहते थे, मत्थे से मत्था लड़ाते थे, पर वह फूलों की खुशबू में मगन रहता था। एक बार उसे बैलों की लड़ाई के लिए ले जाया गया, पर वहां भी नहीं लड़ा। बल्कि मैदान में बैठ गया।

शांति का संदेश फैलाने वाली इस किताब को दुनिया भर में पढ़ा जा रहा है। इन सभी पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद व प्रकाशन का श्रेय लेखक व टॉयमेकर अरविंद गुप्ता को जाता है, जो लगातार शांति की पहल में बरसों से लगे हैं। उन्होंने विज्ञान को जन-जन तक पहुंचाने के लिए भी काम किया है। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है।

कुल मिलाकर, युद्ध में घायल विश्व को हिरोशिमा दिवस पर ऐसी मार्मिक कहानियों को याद करना जरूरी है, जिससे हमें शांति की प्रेरणा मिलती है। युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, इससे विनाश और तबाही ही होती है। इसलिए जरूरत है शांति समर्थक ताकतों को हर संभव प्रयास शांति के लिए करने चाहिए और इस समय इसकी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है।

> युद्ध में घायल विश्व को हिरोशिमा दिवस पर ऐसी मार्मिक कहानियों को याद करना जरूरी है, जिससे हमें शांति की प्रेरणा मिलती है। युद्ध में जीत किसी की नहीं होती, इससे विनाश और तबाही ही होती है। इसलिए जरूरत है शांति समर्थक ताकतों को हर संभव प्रयास शांति के लिए करने चाहिए और इस समय इसकी शिद्दत से जरूरत महसूस की जा रही है।

## आपके पत्र

### भस्मासुर की मौत हुई,वैसे कश्मीर से आतंकवाद खत्म होगा

आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तथ्य को नकारना रेत में सुई ढूंढना ही होगा। जिस तरह सरकार ने 2026 तक माओवादियों को अल्टीमेटम दे दिया है,उसके भय से आत्म समर्पण की गति तेज हो गई है। सीमापार सरकार की ताकत जानते हैं। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण घाटी में आतंकवादियों का आना कम हो गया है। कश्मीर में अमन है। जिस व्यक्ति के दिमाग पर कोई कोई शक्ति हावी हो जाती है। सामान्य तर्क उसके सामने बेनामी होते है। पहले कश्मीर घाटी के युवाओं को पत्थरबाजी का जुनून सवार था। अब युवा कम्प्यूटर और इंटरनेट से जुड़ाव होने से मुख्यधारा में जुड़ चुके है। जुनून एक जीवन की पथरीली राहो पर ले जाता है और योग्यता वाला जुनून आदमी बनाने में अहम भूमिका बनाता है। पाकिस्तान की भूमिका डरावनी ही रही है। कश्मीर में लोकतांत्रिक सरकार बहाल होने के बाद अमन है। लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई है। कश्मीर में सैलानियों की तादात बढ़ीं है। सरकार भी अपना फर्ज अदा करने के लिए हर समय लोगों की खुशहाली की तरफ आगे बढ़ रही है। हम इस बात से बेखबर रहे की कश्मीर में अनुदान की राजनीति की राशि से ऐसा वर्ग पैदा होगा,जिसके लिए हिन्दुस्तान से पैसा खींचना ही राजनीति है। डुप्लीकेट करेंसी के जोर पर पाकिस्तान पलता रहा और आतंकवादियों को पालते रहे,लेकिन सरकारों ने लंबी सोच नहीं रखी। कांग्रेस ने विभाजन के बाद ही कश्मीर की स्थिति गम्भीर कर दी। 370 हटने के बाद कश्मीर में अमन है तो लोगों को जीने की उम्मीदें बंधी है। यह बात हम अच्छी तरह जानते है कि पूर्व का दौर ऐसा था कि दिल्ली में संदूक बन्द रहेगा तो बन्दूक उठेगी। ऐसी स्थिति थी कश्मीर में अनुच्छेद 370 के पूर्व कश्मीरी अवाम को ही जकड़ लिया था। स्कूल कॉलेज और सड़कों की चहल-पहल यथावत है। आतंकवाद के खिलाफ ही भावना भड़कने लगी थी। आतंकवाद अभी भी दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है। पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवाद गले की फांस बना तो ऑपरेशन सिन्दूर की सफलता पाकिस्तान के हाथ बांधने में हम सफल ही नही हुए है। आगे भी कश्मीर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। भारत की चेतावनी है कि अब पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकी कश्मीर में हमला करेगा तो भारत उसे युद्ध की तरह ही समझेगा। पथराव का इस्तेमाल बच्चों को लालच देकर अभी हाल ही के वर्षों में किया गया है ऐसा नहीं है। पथराव राजनैतिक इस्तेमाल कश्मीर में पहले भी हो चुका था। शेख अब्दुल्ला और उनके घोर विरोधी मीरवाइज यूसुफ शाह के समर्थकों के बीच शेर बकरी की लड़ाइयों में मुख्य हथियार पत्थर ही हुआ करता था। पत्थरबाजी फंडिंग पर चलती थी। दुनिया में आतंकवाद फंडिंग से चलता है। करोड़ों रुपए का फंडिंग आतंकवाद को पाल पोस रहा है। कश्मीर घाटी में आतंकवाद का नामोनिशान मिट जाएगा। सरकार इसी तरफ लक्ष्य रखे हुए है। हर तरह का आतंकवाद कालांतर में व्यवसायिक ही हो जाता है। आतंकवाद के आर्थिक स्त्रोत बन्द कराने से ही आतंकवाद नेस्तनाबूद होगा। आतंकवादी संगठनों की कमर टूटेगी। एक संगठन बन्द होता है और कुछ ही दिनों में दूसरे नामो से संगठन बनाकर बंदूके पकड़ा दी जाती है। आईआईटी ,मेक इन इंडिया मेड इन इंडिया जैसे आय के स्त्रोत खड़े हुए है,उसके बाद बच्चों के हाथों में बन्दूक की जगह कम्प्यूटर है। शिक्षा का स्तर बेहतर होने की वजह से बच्चे सरकारी नौकरी और निजी सेक्टर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। यही नतीजा है कि आतंकवाद की जगह एम्प्लाई बनकर अपना भविष्य संवार रहे हैं। कुछ वर्ष पूर्व कश्मीर से ही बच्चे आतंकी बनकर पाकिस्तान से लौटते थे। वो कश्मीर में अपनों पर गोलियां चलाते थे। ये बातें भूतकाल बन गई हैं।

**- कांतिलाल मांडोत, सूरत**

## ललित सुरजन की कलम से

### युद्ध की तारीफ में

*'नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, यह उनका एक व्यक्तित्व है। वे एक बड़े देश के प्रधानमंत्री हैं, यह उनका दूसरा व्यक्तित्व है। वे संघ के कार्यकर्ता होने के नाते पाकिस्तान से लड़ने की बात करते हैं, उसे नेस्तनाबूद करने की धमकी देते हैं, तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री होने के नाते संयम बरतते हैं। उन्हें अब शायद पता है कि दो देशों के बीच युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। अटलबिहारी वाजपेयी ने भी जान लिया था कि एटम बम बना लेने से देश सुरक्षित नहीं हो जाता। किन्तु इन भक्तों का क्या करें? उन्हें तो जो पाठ पढ़ाया गया है वे उसी को दोहराते रहते हैं। दोहराते क्या, बल्कि जब मौका मिले जुगाली करते रहते हैं। कितना अच्छा हो कि सुभाष चन्द्रा और अर्णब गोस्वामी के नेतृत्व में इन तमाम वीर बालकों को सीमा पर भेज दिया जाए ताकि वे अपनी शाब्दिक देशभक्ति को व्यवहार में बदल सकें।'*

**(देशबन्धु में 29 सितंबर 2016 को प्रकाशित)**

https://lalitsurjan.blogspot.com/2016/09/blog-post_28.html

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

## पावन प्रसंग

### योग्य माता राष्ट्र की निर्मात्री

किसी भी राष्ट्र के निर्माण में महिलाओं का महत्व इसलिए भी सर्वोपरि है कि महिलाएं बच्चों को जन्म देकर उनका पालन पोषण करते हुए उनमें संस्कार एवं सद्गुणों का उच्चतम विकास करती हैं,और राष्ट्र के प्रति उनकी जिम्मेदारी को सुनिश्चित करती है। जिससे राष्ट्र निर्माण और विकास निर्बाध गति से होता रहे। वीर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, विवेकानंद जैसी विभूतियों का देश हित में अवतार मां के लालन-पालन की ही देन है। जीजाबाई,जयंताबाई, पन्ना धाय जैसी अनेक माताओं को त्याग समर्पण और त्याग को भी इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया गया है। माताएं ही हैं जो बहुआयामी व्यक्तित्व का निर्माण और विकास करती है। मूलत: माताएं, स्त्रियां की राष्ट्र निर्माण की सशक्त सूत्रधार होती है। राष्ट्र निर्माण के संदर्भ में नारी विधाता की सर्वोत्तम और उत्कृष्ट कृति है। जो जीवन की बगिया को महकाती है और न केवल व्यक्तिगत बल्कि राष्ट्र निर्माण एवं विकास में अपनी महती भूमिका निभाती है। नारी के लिए यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उनमें विविधता में एकता होती है। महिलाओं के बाह्य रूप और सौंदर्य तथा पहनावे में विस्तृत विविधता तो होती ही है, लेकिन उनके मानस में एक आकार और केंद्रीय शक्ति ईश्वर की तरह एक ही होती है। नारी का स्वरूप न केवल बाहर अपितु अंतर्मन के ममत्व भाव का वृहद स्वरूप का भी रहस्योद्घाटन करती हैं, नारी प्रकृति एवं ईश्वरीय जगत का अद्भुत पवित्र साध्य है, जिसे अनुभव करने के लिए पवित्र साधन एवं दृष्टि का होना आवश्यक है, नारी का स्वरूप विराट होता है जिसके समक्ष स्वयं विधाता भी नतमस्तक हो जाते हैं, नारी अमृत वरदान होने के साथ-साथ दिव्य औषधि भी है। समाज के सांस्कृतिक धार्मिक भौगोलिक ऐतिहासिक और साहित्यिक जगत में नारी यानी स्त्री का दिव्य स्वरूप प्रस्फुटित हुआ है और जिसके फलस्वरूप राष्ट्र ने नई ऊंचाइयों को भी शिरोधार्य किया है। सभ्यता, संस्कृति ,संस्कार और परंपराएं महिलाओं के कारण ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती हैं। अत: महिलाओं की सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक कार्य शक्ति ही परिवार तथा समाज और राष्ट्र को सशक्त बनाते हैं। नारियों के संदर्भ में यह भी कहा गया है कि सशक्त महिला सशक्त समाज की आधारशिला होती है। माताएं शिशु की प्रथम शिक्षिका होती है। माता के बाद बहन,पत्नी का अवतार राष्ट्र निर्माण और विकास के साथ-साथ पथ प्रदर्शक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पत्नी चाहे तो पति को गुणवान और सद्गुणी बना सकती है। इतिहास गवाह है कि जब भी कभी देश में संकट आया है तो पत्नियों ने अपने पतियों के माथे पर तिलक लगाकर जोश, जुनून और विश्वास के साथ रणभूमि भेजा है और विजयश्री प्राप्त की है।

भारतीय ऋषियों ने अथर्व वेद में माताओं को 'माता भूमिह पुत्र अहं पृथ्व्या'।

अर्थात भूमि मेरी माता है और हम इस धरा के पुत्र हैं, कहकर प्रतिष्ठित किया है,तभी से विश्व में नारी महिमा का उद्घोष हो गया था। महान शासक नेपोलियन बोनापार्ट ने नारी की महत्ता को महिमा-मंडित करते हुए कहा था कि 'मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुम्हें एक योग्य राष्ट्र दूंगा'। मानव कल्याण की भावना, कर्तव्य, सृजनशीलता और ममता को सर्वोपरि मानते हुए महिलाओं ने इस जगत में मां के रूप में अपनी सर्वोपरि भूमिका को निभाते हुए राष्ट्र निर्माण और विकास में अपने विशेष दायित्वों का निर्वहन किया है।

**-संजीव ठाकुर**

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

## चिंतन

# यूएस खुद रूस से कर रहा ट्रेड, अपने हित देखे भारत

भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ धमकियों व चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इसका कारण है कि एक तो खुद अमेरिका दोहरा मानदंड अपना रहा है, दूसरा भारत को अपने राष्ट्रीय हित की रक्षा करने का हक है। भारतीय निर्यात पर ट्रंप जितना भी शुल्क लगाए, उसका अमेरिकी जनता को ही खामियाजा भुगतना होगा। फौरी तौर पर हो सकता है कि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात में कमी आए, लेकिन इससे भारत को विचलित होने की जरूरत नहीं है। इसे भारत को एक अवसर के रूप में लेना चाहिए और भारतीय निर्यातकों को वैकल्पिक बाजार की ओर रुख करना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने मंगलवार को चेतावनी दी है कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है, इसलिए इस दक्षिण एशियाई देश पर अगले 24 घंटों में भारी नया टैरिफ आयद किया जाएगा। ट्रंप ने पिछले हफ्ते ही भारत से आयातित उत्पादों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की थी व रूस से तेल एवं गैस खरीदने की वजह से भारत पर अलग से जुर्माना लगाने की बात भी कही थी। भारत ने आंकड़ों के जरिये अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाया है कि अमेरिका खुद रूस के साथ व्यापार कर रहा है व भारत-रूस व्यापार पर उंगली उठा रहा है। पिछले साल कड़े प्रतिबंधों और टैरिफ के बावजूद, अमेरिका ने रूस के साथ लगभग 3.5 अरब डॉलर का व्यापार किया था। अमेरिका अब भी रूस से अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इंडस्ट्री के लिए पैलेडियम, उर्वरक और कच्चे रसायन आयात करता है। यूक्रेन ये युद्ध शुरू होने के बाद भारत ने रूस से इसलिए तेल का आयात शुरू किया था, ताकि वैश्विक आपूर्ति तंत्र बना रहे व कीमतों को नियंत्रित रखा जा सके। तब खुद अमेरिका ने भारत के इस कदम का स्वागत किया था। खुद अमेरिका व यूरोप यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, वे वास्तव में युद्ध का अंत चाहते हैं तो यूक्रेन को हथियारों की मदद बंद कर दें। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2024 में रूस के साथ 67.5 अरब यूरो मूल्य का वस्तु व्यापार किया। यह भारत के रूस के साथ उस वर्ष अथवा उसके बाद के कुल व्यापार से कहीं अधिक है। 2024 में यूरोप द्वारा रूस से एलएनजी का आयात 1.65 करोड़ टन तक पहुंच गया, जो 2022 में बने 1.521 करोड़ टन के पिछले रिकॉर्ड को भी पार कर गया। अमेरिका व यूरोप के दोहरे रवैये को देखते हुए अमेरिका का भारत को निशाना बनाना अनुचित और तर्कहीन है। किसी भी प्रमुख अर्थव्यवस्था की तरह, भारत भी अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाता है। ट्रंप की इस नई चेतावनी के बाद रूस ने भारत का समर्थन करते हुए जवाब दिया है कि 'किसी भी देश को रूस के साथ व्यापार बंद करने के लिए मजबूर करना अवैध है। संप्रभु देशों को अपने व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए साझेदारों को चुनने का अधिकार है। भारतीय सेना ने भी अमेरिका को वर्ष 1971 की याद दिलाते हुए उसका असली चेहरा दिखाया है कि कैसे अमेरिका व चीन ने भारत से युद्ध में पाकिस्तान की मदद की थी। अभी टैरिफ दर में, आईएमएफ से लोन दिलाने में व ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अमेरिका ने अपनी पाकपरस्ती दिखाई है। इसलिए भारत को अमेरिका के असली चेहरे को पहचानते हुए अपने राष्ट्रीय हित में कदम उठाना चाहिए और ट्रंप को जैसे को तैसा की तर्ज पर जवाब देना चाहिए। भारत व अमेरिका का संबंध ट्रेड के इर्द-गिर्द ही रहा है, इसमें दोस्ती जैसी कोई बात नहीं है।

# दिशोम गुरु से गुरुजी का कठिन सफर

श्रद्धांजलि
ओंकारेश्वर पांडे

**अलग झारखंड का सपना उठाने वाले कई थे, पर उसे सच करने वाला सिर्फ एक नाम था दिशोम गुरु। लोग कहते हैं, "गुरुजी सिर्फ नेता नहीं थे, आंदोलन की आत्मा थे।" उनके समर्थकों के लिए वे एक विचार थे, एक प्रतिरोध की पहचान। भारतीय राजनीति में झारखंड आंदोलन दरअसल आदिवासी पहचान की वह कहानी है, जिसे दिशोम गुरु ने खून-पसीने से लिखा। "गुरुजी का भरोसा सिर्फ लिखित वादों पर था, शब्दों से नहीं।" उन्होंने कसम खाई "जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी जाएगी।" सवाल है कि क्या यह नारा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा या पिता की राह पर चलते हुए हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी मुक्ति मोर्चा के रूप में स्थापित कर पाएंगे।**

दिशोम गुरु शिबू सोरेन चले गए। 10 बार सांसद, 3 बार मुख्यमंत्री, और उससे भी बढ़कर, वो शख्स जिसने तीर-कमान से नहीं, बल्कि संघर्ष और अपनी सियासी चालों से बिहार के आदिवासियों को उनका हक दिलाया। अलग झारखंड का सपना उठाने वाले कई थे, पर उसे सच करने वाला सिर्फ एक नाम था दिशोम गुरु। लोग कहते हैं, "गुरुजी सिर्फ नेता नहीं थे, आंदोलन की आत्मा थे।" उनके समर्थकों के लिए वे एक विचार थे, एक प्रतिरोध की पहचान। भारतीय राजनीति में झारखंड आंदोलन दरअसल आदिवासी पहचान की वह कहानी है, जिसे दिशोम गुरु ने खून-पसीने से लिखा। 11 जनवरी 1944 को रामगढ़ के नेमरा गांव में जन्मे शिबू सोरेन ने बचपन में साहूकारों की लूट देखी, खनन कंपनियों का लालच देखा। 1969 का अकाल, जब सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा था और आदिवासी भूख से मर रहे थे, ने उनके भीतर ज्वाला भर दी। उन्होंने कसम खाई "जल, जंगल, जमीन की लड़ाई लड़ी जाएगी।"

नेमरा (रामगढ़) की गलियों से उठी उनकी आवाज़ ने 1960–70 के दशक में आवाम को झकझोरा। जब धनकटनी आंदोलन शुरू हुआ, तब आदिवासी महिलाएं खेतों से धान काटकर ले जाती थीं, पुरुष तीर-कमान लिए पहरे पर खड़े रहते थे। पर सिस्टम भी था, सरेंडर, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी वारंट तक जारी। उनकी शुरुआत छोटी थी, पर असर बड़ा। धान जब्ती आंदोलन से शिबू सुर्खियों में आए। साहूकारों के गोदामों से अनाज निकालना, तीर-कमान लिए आदिवासी पहरेदारों का पहरा, यह केवल विरोध नहीं था, यह सिस्टम को सीधी चुनौती थी। एक दिन शिबू सोरेन पारसनाथ के जंगलों में छिप गए, वहीं से आंदोलन चला "बाहरी" लोगों को निकालो, "झारखंड को शोषण से मुक्त करो" सपनों के इस आंदोलन ने उन्हें 'दिशोम गुरु' की पहचान दी। 1973 में उन्होंने ए.के. रॉय और बिनोद बिहारी महतो के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा बनाई। उस समय उनके नारे गूंजते थे "हमारी जमीन हमारी है, कोई दीकु (बाहरी) नहीं छीन सकता।" इसके साथ ही झारखंड आंदोलन तेज होने लगा। उस समय जेएमएम का बनना कोई आसान बात नहीं थी, राजनीतिक विरोध, विभाजन और मानसिक खींचतान के बीच उन्होंने पार्टी को जीवंत रखा। तब लालू यादव ने 1998 में कहा था, "झारखंड मेरी लाश पर ही बनेगा,"। लेकिन शिबू सोरेन ने सभी विरोधों को पार करते हुए, कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी से गठबंधन बनाया और बातचीत से राज्य का मामला संसद तक पहुंचाया। शिबू सोरेन ने समझ लिया था कि झारखंड का सपना सिर्फ जंगलों में धरना देकर पूरा नहीं होगा, इसके लिए दिल्ली की सत्ता के दरवाजे खोलने होंगे। और यही उन्होंने किया। 1989 में वी.पी. सिंह की सरकार को समर्थन, 1993 में नरसिम्हा राव को अविश्वास मत से बचाना, फिर 1999 में वाजपेयी की एनडीए सरकार से डील, शिबू हर बार सही मोड़ पर सही दांव खेलते रहे। कहते हैं, "गुरुजी का भरोसा सिर्फ लिखित वादों पर था, शब्दों पर नहीं।" और हुआ भी वही। 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड बना। जयपाल सिंह मुंडा ने आंदोलन की शुरुआत की थी, लेकिन उसे मंज़िल तक पहुंचाने वाला नाम था शिबू सोरेन। शिबू सोरेन की राजनीति का मूल था आदिवासी पहचान और जल-

जंगल-जमीन की रक्षा। उन्होंने सरहुल जैसे त्योहारों को विरोध का मंच बनाया। खदान मजदूरों को संगठित किया और खनन कंपनियों की नाक में दम किया। उनकी पहल पर पेसा कानून आया, जिसने ग्राम सभाओं को जमीन पर फैसला लेने का अधिकार दिया। 2006 का वन अधिकार कानून भी उनकी जिद का नतीजा था। झारखंड से अरबों का कोयला और लौह अयस्क दिल्ली तक गया, पर गांवों तक सिर्फ गरीबी पहुंची। यही विडंबना है राज्य तो बना, पहचान मिली, पर आर्थिक न्याय अब भी अधूरा है। झारखंड देश के सबसे समृद्ध खनिज राज्यों में है। कोयले, लौह अयस्क और अन्य खनिजों से केंद्र को सालाना 40-45 हजार करोड़ से ज्यादा का हिस्सा मिलता है, जबकि राज्य को खुद के टैक्स से करीब 34 हजार करोड़ की आमदनी होती है।

आसान शब्दों में खनिज निकलता है झारखंड से, फायदा जाता है दिल्ली को। यही सबसे बड़ी लड़ाई रही है। और यह लड़ाई आज भी जारी है। दिशोम गुरु का सफर सियासत और मुकदमों की सफेद-स्याह परछाइयों और विवादों से भरा रहा। 1975 में 'बाहरी-विरोधी अभियान', जिसमें 11 मौतें हुईं, उन पर हत्या का आरोप लगा। 1993 के अविश्वास मत में रिश्वत का आरोप, 1994 में उनके निजी सचिव शशिनाथ झा की हत्या का मामला 2006 में सजा हुई, फिर 2007 में बरी हुए। फिर भी जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। जेल से निकलकर भी चुनाव जीते। तीन बार मुख्यमंत्री बने। दस बार सांसद रहे। पार्टी के एक नेता कहते हैं "एक आदिवासी जब खड़ा होता है, तो उसे राजनीति में फंसाया भी जाता है। हेमंत सोरेन को भी जेल में डाला गया। पर क्या साबित हुआ? जनता अब इन चालों को अच्छी तरह समझने लगी है।" शिबू सोरेन के उपर मुकदमे, सज़ा और विवादों का बोझ था, पर जनता ने उनका साथ नहीं छोड़ा। उनके योगदान को लोग याद करते हैं, उन्होंने झारखंड का सपना रखा, आदिवासी पहचान को राष्ट्रीय विमर्श में रखा, और सबसे बड़ी बात कारपोरेट पावर को चुनौती दी। आज के दौर में विकास की जो रफ़्तार है, वह आर्थिक अधिकारों के सवाल को और गहरा कर देती है, क्या राज्य की खनिज संपदा उसी जनता को लाभान्वित कर पाएगी जिसने इसे जन्म दिया? गुरुजी चले गए, पर सवाल वहीं हैं। शिबू सोरेन ने कभी बीजेपी का समर्थन किया, फिर आरजेडी से हाथ मेला, कभी कांग्रेस से तालमेल किया—हर कदम पर साबित किया कि राजनीतिक दृढ़ता और पहचान की चुनौतियाँ गठबंधन नीति से होकर गुजरती हैं।

"गुरुजी का भरोसा सिर्फ लिखित वादों पर था, शब्दों से नहीं।" भाषणों की नहीं, जमीन की राजनीति की गई। यह उन्हें अलग बनाता है। शिबू सोरेन ने झारखंड का सपना देखा, उसे संसद में गूँजाया, और आखिरकार राज्य के रूप में राजनीतिक हक की लड़ाई जीत ली। "इतिहास उन्हें सिर्फ नेता नहीं, बगावत और पहचान का प्रतीक लिखेगा..." लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, और आर्थिक आत्मनिर्भरता का संघर्ष जारी है। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री हैं। यह भरोसा सिर्फ बेटे पर नहीं, बल्कि उस इतिहास पर है जो शिबू सोरेन ने लिखा। हेमंत कहते हैं "विकास जरूरी है, पर वह हमारी पहचान को मिटाए नहीं।" आदिवासियों को राजनीतिक हक मिला, पर आर्थिक हक का सवाल अब भी अधूरा है। यही वह लड़ाई है जो आज हेमंत को लड़नी है। क्या हेमंत वह कर पाएंगे जो गुरुजी के दौर में अधूरा रह गया? जमीनी राजनीति की बिसात पर सतर्कता और सफलता से चल रहे हेमंत सोरेन के सामने उनका नारा "जल, जंगल, जमीन" अब भी गूँजता है। सवाल है कि क्या यह नारा सिर्फ झारखंड तक सीमित रहेगा या पिता की राह पर चलते हुए हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा को आदिवासी मुक्ति मोर्चा के रूप में स्थापित कर पाएंगे।

*(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।*

*लेख पर अपनी प्रतिक्रिया* **edit@haribhoomi.com** *पर दे सकते हैं।*

## प्लास्टिक संधि

राज कुमार सिन्हा

# प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्ति के लिए विश्व की उम्मीदें

स्विट्जरलैंड के जेनेवा में 5 से 14 अगस्त तक प्लास्टिक संधि के लिए अन्तरराष्ट्रीय वार्ता समिति के प्रतिनिधिमंडल अंतिम बैठक के लिए एकत्रित हुए हैं। जहां प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बंधनकारी (आईएलबीआई) समझौता पर अंतिम दौर की बातचीत होगी। इसके पहले मई 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने समुद्री पर्यावरण सहित प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतरराष्ट्रीय, कानूनी रूप से बाध्यकारी उपाय विकसित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया था। तब से अब तक पांच दौर की बातचीत पूर्ण हो चुकी है। अंतिम दौर की बातचीत अगस्त में होने जा रही है, जिसमें मुख्यतः प्लास्टिक उत्पादों के पूरे जीवन काल में प्राथमिक पॉलिमर उत्पादन से लेकर निपटान तक को ध्यान में रखें जाने की बात होगी। अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार, प्लास्टिक की मांग सन् 2000 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई है। एक हालिया अध्ययन के अनुसार, 2022 में फीडस्टॉक सहित 436.66 मिलियन टन पॉलिमर और प्लास्टिक का व्यापार हुआ, जिसमें अंतिम प्लास्टिक उत्पादों की मात्रा 111 मिलियन टन थी। आज, 99 फीसदी प्लास्टिक जीवाश्म ईंधन से बनता है। जीवाश्म ईंधनों को परिष्कृत करके मोनोमर्स (निर्माण खंड) और फिर पॉलिमर में संसाधित किया जाता है और उत्पादन के विभिन्न चरणों में मध्यवर्ती पदार्थ और रसायन (अध्ययनों से पता चलता है कि 16,000 से अधिक रसायनों का उपयोग किया जाता है) मिलाए जाते हैं। प्लास्टिक को विनियमित करने का अर्थ अनिवार्य रूप से इन पेट्रोरसायनों को विनियमित करना होगा। प्लास्टिक उत्पादन और उपभोग को विनियमित करने के लिए, इन निर्माण खंडों, जिनमें इनका व्यापार भी शामिल है, पर ध्यान केंद्रित करना अनिवार्य है। विश्व भर के 600 से अधिक नागरिक समाज समूहों ने प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करने के लिए एक मजबूत संधि की मांग करते हुए एक घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें प्लास्टिक उत्पादन में महत्वपूर्ण कटौती पर जोर दिया गया है। घोषणापत्र में कहा गया है कि जलवायु, जैव विविधता, मानव स्वास्थ्य, मानवाधिकारों और ग्रह की जीवन को सहारा देने और बनाए रखने की क्षमता पर हानिकारक प्रभाव डालता है। नागरिक समूहों ने वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन में उल्लेखनीय कमी सुनिश्चित करने के लिए संधि की माँग की है। प्लास्टिक के जीवनचक्र में हानिकारक रसायनों के उन्मूलन, प्लास्टिक संबंधी जानकारी में पारदर्शिता, कार्यान्वयन के लिए स्पष्ट और पर्याप्त वित्तीय प्रतिबद्धताएं और तंत्र, प्रभावित समुदायों के लिए न्यायोचित परिवर्तन, झूठे समाधानों द्वारा जारी अपशिष्ट उपनिवेशवाद और पर्यावरणीय नस्लवाद का अंत, पुनः उपयोग और पुनः भरने की प्रणालियों को प्राथमिकता देने और मानव अधिकारों के संरक्षण का भी आह्वान किया है। कहा गया है कि प्लास्टिक और खतरनाक अपशिष्ट के उत्पादन में प्रयुक्त खतरनाक रसायनों पर बासेल, रॉटरडैम और स्टॉकहोम द्वारा नियंत्रण किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा शासित होता है, और प्रस्तावित आईएलबीआई के प्रावधान डब्ल्यूटीओ समझौतों के विपरीत होंगे। इससे विकासशील देश और वे देश जो पॉलिमर व्यापार पर निर्भर हैं, व्यापार पर अंकुश लगाने से प्रभावित होंगे।इधर पर्यावरण पर 20वें अफ्रीकी मंत्रिस्तरीय सम्मेलन (एएमसीईएन-20) ने वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करने की प्रतिबद्धता जताई है, तथा प्लास्टिक प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी रूप से बाध्यकारी साधन विकसित करने के लिए अंतर-सरकारी वार्ता समिति के साथ महाद्वीप की सहभागिता की आवश्यकता की पुष्टि की है। 18 जुलाई को नैरोबी में संपन्न हुई इस बैठक में स्वीकार किया गया कि अफ्रीका अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसमें विविध पारिस्थितिकी तंत्र, परिदृश्य, वायु, समृद्ध जैव विविधता से लेकर विशाल खनिज संपदा, मीठे पानी और समुद्री संसाधन शामिल हैं। इस कार्यक्रम में सदस्य देशों से पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' के दृष्टिकोण को अपनाने तथा समुदायों, महिलाओं और युवाओं को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने का आह्वान किया गया, ताकि पर्यावरणीय संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सके। भारत के नागरिक अपने प्रतिनिधिमंडल से आग्रह करते हैं कि इस होने वाले वार्ता में मानव स्वास्थ्य और अपस्ट्रीम समाधानों पर केंद्रित एक मजबूत वैश्विक प्लास्टिक संधि का समर्थन करें। जबकि प्लास्टिक पैकेजिंग, डिज़ाइन और सामग्री के उपयोग पर जीवनचक्र आकलन के आधार पर स्पष्ट लागू करने योग्य दिशानिर्देशों की तत्काल आवश्यकता है।

*(लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)*

# मुंह के मौन से ज़्यादा ज़रूरी 'मन का मौन'

संकलित
**दर्शन**

हम सभी मनुष्य जन्मते ही अपना मुख चलाना शुरू कर देते हैं, जिसका प्रमाण है जन्म लेते ही शिशु का रोना। बोलना हमारी स्वाभाविक क्रिया है, जो हमें करनी ही पड़ती है। यह बात और है कि कभी-कभी बाहर के शोर में हम इतने खो जाते हैं कि ईश्वर का स्वर हमें सुनाई ही नहीं पड़ता। इसीलिए ही महापुरुषों से हमें एक उत्तम राय मिलती है कि सप्ताह में या माह में एक दिन अवश्य मौन रहें, परंतु हम मुख को तो बंद कर लेते हैं, परंतु हमारे मन का बोलना बंद नहीं हो पाता। इसलिए ही तो अधिकतर डाक्टर सभी मरीजों को कहते हैं कि 'अपने मन को ज्यादा नहीं चलाओ।' अर्थात 'मन का मौन' करो। कहते हैं कि बिना हड्डी की जीभ जब बोलने लगती है, तो कइयों की हड्डियां तोड़ देती है। इसीलिए तो हमें यह बचपन से सिखाया जाता है कि पहले सोचो फिर बोलो, क्योंकि जैसे कमान से निकला हुआ तीर वापस नहीं आता, ठीक उसी तरह मुख से निकला हुआ वचन भी वापस नहीं लिया जा सकता। इसका सबसे श्रेष्ठ उदहारण है महाभारत की कथा, जिससे हमें यह सीख मिलती है कि कैसे एक जुबान के फिसलने से संकटकाल का निर्माण हो गया। इसीलिए 'कम बोलें-धीरे बोलें-मीठा बोलें।' हम जब भी कुछ बोलें तो हमारे वचन दूसरों के लिए सुखदायी हों, न कि कांटा चुभाने वाले दुखदायी। संसार में ऐसे अनेक लोग हैं जिन्होंने कटु वचन बोलने के संस्कार के कारण अपने संबंधों में खटास पैदा कर ली है। इसलिए हमें सदैव सही समय और सही जगह पर सही शब्द का प्रयोग करना चाहिए।

# बिन बुलाए किसी के घर न जाए

संकलित
**प्रेरणा**

माता सती के पिता प्रजापति दक्ष शिव जी को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि शिव जी ने ब्रह्मा जी का पांच में से एक सिर काट दिया था। अपने पिता ब्रह्मा जी के साथ हुई इस घटना की वजह से दक्ष शिव जी को अपमानित करने के अलग-अलग अवसर खोजते रहते थे। दक्ष की पुत्री सती ने भगवान शिव से विवाह कर लिया था और दक्ष इस विवाह को रोक नहीं सके। विवाह के कुछ समय बाद दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी-देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को नारद से मालूम हुआ कि उनके पिता दक्ष यज्ञ करवा रहे हैं। सती इस यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। शिव जी ने देवी सती को समझाया कि बिना बुलाए हमें यज्ञ जैसे आयोजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिव जी के समझाने पर भी देवी नहीं मानीं और यज्ञ में चली गईं। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि यज्ञ में शिव जी के अतिरिक्त सभी देवी-देवता आए हुए हैं। सती ने पिता दक्ष से शिव जी को न बुलाने का कारण पूछा तो दक्ष ने शिव जी के लिए अपमानजनक बातें कहना शुरू कर दीं। शिव जी का अपमान सती सहन नहीं कर सकीं और उन्होंने हवन कुंड में कूदकर अपनी देह त्याग दी। जब ये बात शिव जी को मालूम हुई तो वे बहुत क्रोधित हो गए। शिव जी के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। इसके बाद शिव जी के कहने पर वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को उजाड़ दिया और दक्ष का सिर काट दिया।

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

## अंतर्मन

### आज की पाती

**कश्मीर से खत्म होगा आतंकवाद**

आतंकवाद एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। तथ्य को नकारना रेत में सिर छिपाना ही होगा। जिस तरह सरकार ने 2026 तक माओवादियों को अल्टीमेटम दे दिया है, उसके भय से आत्म समर्पण की गति तेज हो गई है। सीमापार सरकार की ताकत जानते है। सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के कारण घाटी में आतंकवादियों का आना कम हो गया है। कश्मीर में अमन है। जिस व्यक्ति के दिमाग पर कोई शक्ति हावी हो जाती है। सामान्य तर्क उसके सामने बेनामी होते है। पहले कश्मीर घाटी के युवाओं को पत्थरबाजी का जुनून सवार था। अब युवा कम्प्यूटर और इंटरनेट से जुड़ाव होने से मुख्यधारा में जुड़ चुके है। जुनून एक जीवन की पथरीली राहो पर ले जाता है और योग्यता वाला जुनून आदमी बनाने में अहम भूमिका बनाता है। पाकिस्तान की भूमिका डरावनी ही रही है। *- कांतिलाल मांडोत, सूरत*

## करंट अफेयर

# जापान में परमाणु बम पीड़ित फैला रहे लोगों में जागरूकता

हिरोशिमा और नागासाकी पर 80 साल पहले हुए परमाणु बम हमले में जीवित बचे लोगों ने बढ़ते परमाणु खतरों और वैश्विक नेताओं द्वारा परमाणु हथियारों को स्वीकार किए जाने पर चिंता जताई है। अमेरिका ने छह अगस्त, 1945 को हिरोशिमा पर और उसके तीन दिन बाद नागासाकी पर परमाणु बम से हमला किया था, जिससे उस वर्ष के अंत तक 2,00,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। इस घातक हमले में कुछ लोग जीविच बच गए, लेकिन वे विकिरण संबंधी बीमारियों से ग्रस्त हो गए। परमाणु बम हमले के लगभग एक लाख लोग अभी जीवित हैं। उनमें से कई लोगों ने खुद को और अपने परिवारों को आज तक जारी भेदभाव से बचाने के लिए अपने अनुभवों को छिपा रखा है जबकि कुछ लोग खुद के साथ हुई भयावह विभीषिका के चलते अपनी आपबीती नहीं बता पाए। कुछ जीवित बचे लोगों ने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में परमाणु बम हमले के खिलाफ इस उम्मीद के साथ बोलना शुरू किया है, कि उनकी आपबीती सुन कर शायद दूसरे लोग परमाणु हथियारों के खात्मे के लिए दबाव बना सकें। परमाणु बम हमले के पीड़ित 83 वर्षीय कुनिहिको आईडा अनेक स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद अपनी सेवानिवृत्ति के वर्षों में लोगों को अपनी पीड़ा बता रहे हैं।

## ऑफ बीट

# कुछ कपड़े धोने पर सिकुड़ जाते हैं ? कैसे रोका जाए

कपड़े आखिर क्यों सिकुड़ते हैं, यह जानने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि कपड़े बनते कैसे हैं। सूती और लिनन जैसे सामान्य रेशे पौधों से हासिल होते हैं। ये रेशे अपने प्राकृतिक स्वरूप में अनियमित आकार के और झुर्रीदार होते हैं। अगर आप इन रेशों के अंदर गहराई से देखेंगे, तो आपको लाखों छोटे, लंबी-शृंखला वाले सेल्यूलोज अणु नजर आएंगे, जो प्राकृतिक रूप से सर्पिल आकार में मौजूद होते हैं। कपड़ा बनाते समय इन रेशों को यांत्रिक रूप से खींचा और मोड़ा जाता है, ताकि ये सेल्यूलोज शृंखलाएं सीधी हो जाएं और कतार में आ जाएं। इस प्रक्रिया में चिकने, लंबे धागे बनते हैं। रासायनिक स्तर पर, ये शृंखलाएं 'हाइड्रोजन बॉन्ड' से जुड़ी होती हैं, जो रेशों और धागों को मजबूत एवं लचीला बनाते हैं। 'फाइबर मेमोरी' के कारण ही कुछ कपड़ों पर आसानी से सिलवटें पड़ जाती हैं, जबकि कुछ कपड़े धोने के बाद सिकुड़ भी जाते हैं। कपड़े धोने के दौरान, गर्म पानी रेशों के ऊर्जा स्तर को बढ़ाने में मदद करता है– यानी वे तेजी से हिलते हैं, जिससे उन्हें एक-दूसरे से जोड़े रखने वाले 'हाइड्रोजन बॉन्ड' टूट जाते हैं। रेशों को जिस तरह से बुना या पिरोया जाता है, इसकी भी अहम भूमिका होती है। ढीले बुने हुए कपड़ों में धागों के बीच ज्यादा खुली जगह और लूप होते हैं, जो उन्हें न सिर्फ अधिक लचीला और सांस लेने योग्य बनाते हैं।

## ट्रेंड

### बचाव कार्य

उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड की घटना को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात कर घटना की जानकारी ली। आईटीबीएस की 3 और एनडीआरएफ की 4 टीमों को घटनास्थल के लिए भेज दिया गया है, जो शीघ्र पहुँच कर बचाव कार्य में लगेंगी।
-अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री

### गठबंधन में नहीं बसपा

बहुजन समाज पार्टी ना तो एनडीए गठबंधन के साथ है और ना ही कांग्रेस के इण्डिया समूह (गठबंधन) के साथ है, ना ही अन्य किसी के साथ है, बल्कि अपनी 'सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय' के अम्बेडकरवादी सिद्धान्त व नीति पर चलने वाली पार्टी है।
-मायावती,पूर्व सीएम, उप्र

### धर्म विशेष के लोग

जो भी गैर-क़ानूनी हो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो क्योंकि अवैध तो अवैध होता फिर क्यों किसी जाति या धर्म विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट जाएंगे।
- अखिलेश यादव, सांसद, सपा

### मलिक का निधन दुखद

पूर्व राज्यपाल व किसान हितैषी नेता सत्यपाल मलिक के निधन का समाचार बेहद दुखद है। वे बेबाकी और निडरता से सत्ता को सच्चाई का आईना दिखाते रहे। शोकाकुल परिवारजनों और समर्थकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं।
- मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस अध्यक्ष

### अपने विचार

**हरिभूमि कार्यालय**

टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-4242222, 23 पर या सीधे मेल से **hbcgpati@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

दैनिक जागरण
संकल्प की शक्ति से असंभव भी संभव हो सकता है

# ट्रंप की नई धमकी

अपने बेतुके बयानों और फैसलों से अपनी फजीहत करा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने नई धमकी दी है कि वे 24 घंटे के भीतर भारत पर टैरिफ और बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कि भारत से अमेरिका जाने वाली वस्तुओं पर अमेरिकी आयात शुल्क 25 प्रतिशत से अधिक हो जाएगा। उनके जो मन में आए, वह करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन यदि वे यह समझ रहे हैं कि भारत उनकी दादागीरी के आगे झुक जाएगा तो अब इसकी संभावना न्यून है, क्योंकि उन्हें जवाब देना शुरू कर दिया गया है। भारत कूटनीतिक शिष्टाचार के चलते उन्हें उनकी जैसी भाषा में तो जवाब नहीं दे सकता और देना भी नहीं चाहिए, लेकिन उसे उनकी धमकियों के आगे झुकना भी नहीं है। वे अब हद पार कर अमेरिकी राष्ट्रपति पद की मर्यादा से खेल रहे हैं। उनका अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। यह भी दिख रहा है कि वे कुंठा से ग्रस्त होकर विवेक खो रहे हैं। भारत को एक कुंठित-अहंकारी अमेरिकी राष्ट्रपति के अहं को तुष्ट करने के बजाय उसका सामना साहस और संयम से करने के लिए कमर कस लेनी चाहिए। भारत को ट्रंप की ओर से पेश की जा रही चुनौतियों का सामना करने के लिए फौरी एवं दीर्घकालिक रणनीति बनानी होगी। इसमें सफलता तब मिलेगी, जब हमारे कारोबारी भी राष्ट्रधर्म समझेंगे। उन्हें अपने उत्पादों की गुणवत्ता और उत्पादकता ठीक करनी होगी। आयातकों को खास तौर पर उन अमेरिकी अथवा चीनी वस्तुएं खरीदने का लोभ छोड़ना होगा, जो भारत में बन सकती हैं। इससे ही स्वदेशी का मंत्र कारगर साबित हो सकता है।

ट्रंप यह तय करने वाले कोई नहीं कि भारत रूस अथवा अन्य किसी देश से क्या खरीदे? अमेरिका की तरह भारत भी एक संप्रभु राष्ट्र है। यदि भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो अमेरिका से भी ले रहा है। यदि भारत रूस से तेल न ले तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में उसके दाम चढ़ जाएंगे और इसके दुष्परिणाम विश्व के अनेक देशों के साथ अमेरिका को भी भोगने पड़ेंगे। क्या ट्रंप यह बताएंगे कि अमेरिका रूस से यूरेनियम और उर्वरक क्यों खरीद रहा है? इसी तरह यूरोपीय देश उससे गैस, खनिज आदि क्यों खरीद रहे हैं? ट्रंप यह समझने को तैयार नहीं कि भारत के टैरिफ किंग होने के उनके दावे की पोल खुद अनेक अमेरिकी अर्थशास्त्री खोल रहे हैं। विश्व बैंक का भी यह आकलन है कि अमेरिका के मुकाबले भारत की टैरिफ दरें मामूली ही अधिक हैं। आखिर भारत अमेरिका से वह सब क्यों खरीदे, जो उसे चाहिए ही नहीं? ट्रंप यह समझें तो बेहतर कि भारत तब अमेरिका से नहीं दबा था, जब वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम नहीं था और उसे परमाणु परीक्षण के चलते प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा था। भारत को ट्रंप का सामना करते हुए यह भी देखना होगा कि उसे रूस या चीन पर निर्भर नहीं होना है।

# ड्रेनेज पर सुस्ती

उत्तराखंड के शहरों में जल-जमाव के हालात चिंता में डाल रहे हैं। स्वाभाविक भी है, वर्तमान में प्रदेश का शायद ही कोई ऐसा शहर होगा, जहां यह समस्या विकराल रूप न ले चुकी हो। इसकी तह में जाएं तो इसके दो प्रमुख कारण नजर आते हैं। पहला स्थानीय निकायों की उदासीनता और दूसरा नीति नियंताओं की अदूरदर्शिता। ड्रेनेज प्लान को लेकर जिम्मेदारों को जिस सक्रियता के साथ काम करना चाहिए था, वह होता नहीं दिखा। बंद कमरों में योजनाएं बनीं, लेकिन फाइलों से बाहर नहीं निकल पाईं। कहने में हिचक नहीं कि जनप्रतिनिधियों से लेकर नौकरशाह तक इस समस्या के समाधान के प्रति गंभीर नहीं दिखते हैं। रही सही कसर निकाय पूरी कर देते हैं। न तो उनका नाला सफाई गैंग सक्रिय दिखता है और न ही शहरी विकास विभाग से जुड़े अन्य विभाग की नींद टूटती है। सूरतेहाल प्रतीत होता है कि जिम्मेदारों को शहरवासियों की पीड़ा से शायद कोई लेना-देना नहीं है। अगर होता तो एसी कमरों में बैठकर फरमान सुनाने के बजाय धरातल पर जाकर परिस्थितियों को देखते और उसके अनुरूप समाधान तलाशते। चूंकि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं। इनमें बड़ा सवाल यह है कि आखिर जिम्मेदार महकमे किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्यों शहरवासियों के धैर्य की परीक्षा ली जा रही है? यह बात समझ से परे है। विभागों को चाहिए कि वह नई परिस्थितियों के अनुरूप शहरों का ड्रेनेज प्लान तैयार कर इस दिशा में आगे बढ़ें। उम्मीद की जानी चाहिए कि इसको लेकर विभागीय अधिकारियों की तंद्रा टूटेगी और जल्द ही प्रदेश के शहरों का ठोस ड्रेनेज प्लान मूर्तरूप लेता दिखेगा।

> उत्तराखंड में शहरों का एक अदद ड्रेनेज प्लान न बन पाना जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा रहा है

# सुनिश्चित हो संवैधानिक दायित्व की पूर्ति

हृदयनारायण दीक्षित

**दलबदल से जुड़ी याचिकाओं पर निर्णय में इतना विलंब न हो कि सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाए। पीठासीन अधिकारी इस मुद्दे पर तत्परता दिखाएं**

अवधेश राजपूत

हाल में सर्वोच्च न्यायालय ने दलबदल की याचिकाओं के निस्तारण पर गंभीर टिप्पणी करते हुए कहा कि विधायी सदनों के अध्यक्षों/सभापतियों के निर्णय में विलंब से चिंताजनक स्थिति निर्मित हुई है। प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा, 'हम ऐसी स्थिति की अनुमति नहीं दे सकते जहां आपरेशन सफल हो, लेकिन मरीज ही मर जाए।' याचिकाओं पर निर्णय में ऐसा विलंब न हो कि सदन का कार्यकाल ही समाप्त हो जाए। न्यायपीठ ने तेलंगाना विधानसभा में भारत राष्ट्र समिति के 10 विधायकों के दलबदल मामले में सुनवाई के बाद कहा कि संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दी गई याचिकाओं पर विधानसभा अध्यक्ष तीन महीने के भीतर निर्णय दें। न्यायालय ने पहले भी कहा था कि याचिकाओं के निर्णय में विलंब से 10वीं अनुसूची के उद्देश्य विफल हो सकते हैं। सदन के अध्यक्षों/सभापतियों को ही ऐसी याचिकाओं की सुनवाई का अधिकार है। कोर्ट ने यह भी कहा कि उसे सुनवाई की समयसीमा सुनिश्चित करने का अधिकार है। ये बातें मणिपुर विधानसभा सहित कई मामलों में समयसीमा निर्धारित करने की मांग पर कही गई हैं। एक मामले (1992) में सर्वोच्च न्यायापीठ ने कहा था कि आवश्यक कार्यवाही में देरी पर न्यायालय को हस्तक्षेप का अधिकार है। रवि एस. नायक बनाम भारत संघ मामले (1994) में अध्यक्ष की निष्पक्षता पर भी टिप्पणी की गई थी।

निर्वाचित जनप्रतिनिधि ही सरकार में मंत्री और सदन में पीठासीन अधिकारी बनते हैं। राजनीतिक दल उनके निर्वाचन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। वे चुनाव जीतकर अपने दल के प्रति निष्ठावान रहते हैं, पर तमाम प्रतिनिधि लोभवश दलबदल करते हैं। स्वतंत्रता के कुछ समय बाद ही दलबदल का सिलसिला चल निकला था। 1967 में हरियाणा के एक नेता ने एक दिन में ही तीन बार दलबदल किया था। कई राज्यों में दलबदलू नेता दल छोड़ते ही मंत्री बने। नैतिक और विधिक दृष्टि से यह अपराध है। मतदाता के प्रति धोखाधड़ी भी है। हमारे यहां राष्ट्र जीवन के सभी क्षेत्रों में उन्नति हुई है, लेकिन हम संवैधानिक नैतिकता वाले दल नहीं बना पाए। राजनीतिक दल भी अपने सदस्यों में निष्ठा नहीं ला पाते, कुछ दलबदल कराते हैं और कुछ दलबदल करते हैं।

कहा जाता है कि राजीव गांधी ने भयवश 52वां संविधान संशोधन पारित करवाया था। तब स्वेच्छा से दल त्याग दंडनीय माना गया, पर एक तिहाई सदस्यों के दल त्याग को विलय कहा गया था। एक तिहाई सदस्य जुटाना मुश्किल नहीं था। कुछ राज्यों में इक्का-दुक्का सदस्य आते रहे और एक तिहाई होते गए। दलबदल के तमाम तरीके ईजाद होते रहे। 1991 में संविधान संशोधन द्वारा एक तिहाई की जगह दो तिहाई सदस्यों का प्रविधान किया गया। इसका भी बहुत लाभ नहीं हुआ। सदस्यता छीन लेने जैसे सख्त कानून के बावजूद दलबदल जारी है। एक कारण पीठसीनों की ढिलाई भी है। इसलिए हाल के तेलंगाना मामले सहित कई अवसरों पर पीठासीन अधिकारियों पर टिप्पणियां हुई हैं। आरोप लगते रहे हैं कि वे जानबूझकर पक्षपात करते हैं। यचिकाएं ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। चुनाव आयोग ने सुझाव दिया था कि इस गंभीर विषय पर विमर्श के लिए एक आयोग बने। सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा है कि निष्पक्षता के लिए न्यायपालिका के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में न्यायाधिकरण का गठन किया जाना चाहिए। सदनों के सभापति/अध्यक्ष सम्माननीय संवैधानिक संस्था हैं। 10वीं अनुसूची में संविधान ने इन्हें उत्तरदायी माना है। इन संस्थाओं को अपने संवैधानिक कर्तव्य का सही पालन करना चाहिए, मगर दल त्यागने का रोग इतने भर से दूर नहीं होगा। माननीय विशेष अवसरों के लिए दल त्याग करेंगे। कुछ दंडित होंगे, होते भी हैं और शेष तकनीकी कारणों से बच निकलेंगे। इसलिए इस मुद्दे पर व्यापक विमर्श हो।

जहां स्वेच्छा से दल त्याग दंडनीय है, वहीं किसी व्यक्ति या समूह द्वारा दल त्याग की घोषणा सुविचारित भी हो सकती है। पार्टी का नेतृत्व विचारधारा बदल सकता है। विचारनिष्ठ सदस्यों के लिए यह अस्वीकार्य हो जाता है। वे सदन में अपने नेताओं के विरुद्ध भी बोलते हैं। संविधान में विचार अभिव्यक्ति मौलिक अधिकार है। दलीय अनुशासन का डंडा सदस्यों को अखरता है। दलबदल रोकने से राजनीतिक स्थिरता तो रहती है, किंतु निर्वाचित सदस्यों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से वंचित भी नहीं किया जा सकता। बजट और अविश्वास प्रस्ताव जैसे अवसरों पर सदस्यों को दलीय अनुशासन चाहिए। इसके अतिरिक्त उन्हें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता चाहिए। दलबदल के कानूनी प्रविधानों ने सदस्यों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को सीमित किया है, जबकि संविधान सदनों में विचार अभिव्यक्ति की असीम स्वतंत्रता देता है। संसदीय जनतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनिवार्य है। इसके बावजूद दलबदल के विरुद्ध अभियान चलाते रहना चाहिए। समाज इसकी निंदा करे। राज्य दंड दे।

आखिर ब्रिटिश संसद ने भारत जैसा दलबदल कानून क्यों नहीं बनाया? ब्रिटेन का दल तंत्र ऐसी समस्याएं स्वयं सुलझा लेता है। ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली अपना कर भी, दलबदल कानून के बावजूद भारत क्यों इस समस्या से ग्रस्त बना हुआ है। ब्रिटेन में पार्टी बदलने पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अमेरिका में भी दलबदल कानून नहीं है। अमेरिका में दो दल हैं। दलबदल भी होते हैं। एक समय डेमोक्रेटिक पार्टी के 16 प्रतिनिधि रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हो गए थे। पार्टी का अनुशासन अमेरिका में ऐसी समस्याएं सुलझा लेता है। यूरोप के देशों में सख्त कानून है। दल त्याग पर संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। बांग्लादेश में भी पार्टी के विरुद्ध सदन में मतदान करने और पार्टी बदलने पर त्यागपत्र लिया जाता है। केन्या, दक्षिण अफ्रीका आदि में दलबदल की छूट नहीं है। भारत का मन बदल रहा है। सारी दुनिया आश्चर्यचकित है। संपूर्ण राजनीतिक दल तंत्र और विधायिका के सभी सदस्यों को संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन के लिए संवेदनशील होना चाहिए। न्यायपीठ का निर्णय स्वागतयोग्य है। इससे विधायिका और न्यायपालिका की गरिमा बढ़ेगी।

(लेखक उत्तर प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हैं)
response@jagran.com

# श्रीमान झूठ बोलिए, लेकिन संभलकर

राजीव सचान

**राजनीति में सच और झूठ का अंतर मिटता जा रहा है और अब तो यह लगता है कि झूठ के भी पैर होने लगे हैं**

राहुल गांधी संसद के भीतर-बाहर खूब बोल रहे हैं। उनके कथित धारदार बयान चर्चा में हैं। जो उनसे सहमत हैं, वे उनकी वाहवाही कर रहे हैं और जो असहमत हैं, वे जाहिर है कि उनकी आलोचना-निंदा कर रहे हैं। राहुल गांधी यानी नेता विपक्ष ने हाल में लोकसभा में संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए कहा कि वह मर चुका है और लोकसभा चुनाव में भी धांधली हुई थी। राहुल पिछले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे थे, जिसमें कांग्रेस को 99 सीटें मिलीं और जिस कारण वे लोकसभा में नेता विपक्ष बन सके। उन्होंने ऐसे आरोप तब नहीं लगाए, जब 2014 में कांग्रेस को 44 और 2019 में 52 सीटें मिली थीं। जब 99 सीटें मिलीं, तब वे कह रहे हैं कि धांधली हुई। उन्होंने लोकसभा में चुनाव आयोग को एक तरह से देख लेने की धमकी दी। पता नहीं वे उसे कैसे देखेंगे, पर उन्होंने सांसद के सदन में बोलने के अधिकार का पूरा 'लाभ' उठाया। सांसद और विधायक सदनों में बिना किसी भय, दबाव के बोलने और उसके खिलाफ किसी अदालत में कार्रवाई न हो सकने के विशेषाधिकार का खूब लाभ उठाते हैं। चूंकि किसी विधायक, सांसद के खिलाफ सदन में उसके आचरण के लिए न्यायालय में कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए वे निडर होकर कुछ भी करते और कहते हैं।

यदि कोई सांसद, विधायक सदन में बहुत ही गलत आचरण कर दे तो उसके खिलाफ सदन ही विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई कर सकता है और उसकी सदस्यता भी रद कर सकता है, लेकिन इस पर वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है और उसे वहां से राहत भी मिल सकती है। विशेषाधिकार हनन की कार्रवाई पक्ष-विपक्ष के किसी भी सदस्य के खिलाफ हो सकती है, लेकिन यदि कभी सत्तापक्ष किसी विपक्षी सदस्य के खिलाफ विशेषाधिकार हनन के तहत कार्रवाई करता है तो कहा जाता है कि यह तानाशाही है।

विधायी सदनों में पक्ष-विपक्ष के सदस्य अपने विशेषाधिकार का किस हद तक मनमाना इस्तेमाल करते हैं, इसका एक उदाहरण 'नई तरह की राजनीति' करने वाली आम आदमी पार्टी का है। वह जब दिल्ली में सत्ता में थी तो विधानसभा के

एक रैली में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव। फाइल

एक-दो दिन के सत्र इस उद्देश्य से भी बुलाती थी कि किसी की मनमानी तरीके से निंदा कर सके। एक बार उसके विधायक ने चुनाव आयोग को निशाने पर लेने के लिए सदन में एक नकली ईवीएम 'खोलकर' यह बताने की कोशिश की थी कि उसे हैक किया जा सकता है। ईवीएम के खिलाफ एक लंबे समय से मोर्चा खुला हुआ है। इस मोर्चे में कांग्रेस भी शामिल है। यह सनद रहे कि ईवीएम का इस्तेमाल कांग्रेस के शासनकाल में शुरू हुआ, लेकिन आज की कांग्रेस को इससे मतलब नहीं?

राहुल की मानें तो चुनाव आयोग मोदी सरकार के इशारे पर भाजपा को छल-छद्म से जिताने का काम कर रहा है और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण के जरिये भी लोकतंत्र ही नष्ट कर रहा है। बहती गंगा में तेजस्वी यादव ने भी हाथ धोया। चुनाव आयोग की ओर से बिहार की मतदाता सूची का पहला ड्राफ्ट जारी होते ही उन्होंने दावा किया कि इसमें तो उनका नाम ही नहीं है। इस पर चुनाव आयोग ने उनके दावे को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनका नाम लिस्ट में है और अमुक मतदान केंद्र में अंकित है। मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध करने वाले राहुल के अनुसार महाराष्ट्र में वोट की चोरी हुई थी। उनका कोई समर्थक और शुभचिंतक यह पूछने को तैयार नहीं कि यदि ऐसा है तो झारखंड और जम्मू-कश्मीर के नतीजे कांग्रेस एवं उसके सहयोगी दलों के पक्ष में क्यों रहे? जो कुतर्क करने में माहिर हैं, उनका 'तर्क' है कि भाजपा इन दोनों राज्यों में इसलिए जानबूझकर हारी, ताकि चुनाव आयोग पर संदेह न हो। शायद ऐसे ही लोगों का इलाज हकीम लुकमान के पास नहीं रहा होगा।

राहुल गांधी ने हाल में दिवंगत अरुण जेटली पर आरोप लगाया कि उन्होंने कृषि कानूनों का विरोध करने पर उन्हें धमकाया था। इस पर अरुण जेटली के बेटे को कहना पड़ा कि ये कानून तो उनके पिता के निधन के बाद आए। शायद राहुल भूमि अधिग्रहण बिल का संदर्भ देना चाहते थे। सच वही जानें, लेकिन उनकी ओर से यह भी तो कहा जा चुका कि राफेल विमान सौदे में दलाली खाई गई.. चौकीदार चोर है। सावरकर अंग्रेजों से डरते थे...माफीवीर थे और चीन ने भारत की दो हजार वर्ग किमी भूमि कब्जा ली...चीनी सैनिक भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं। इन तीनों मामलों में राहुल को सुप्रीम कोर्ट की फटकार लगी, लेकिन उनके समर्थकों ने उन्हें फटकारने वाले न्यायाधीशों को ही कठघरे में खड़ा कर दिया। जिसे झूठ कहा जाता है, उसे संसदीय भाषा में मिथ्या या सत्य से परे कहते हैं। अब नेताओं की ओर से खूब झूठ बोला जाता है। वे झूठ के पैर लगाकर उसे दौड़ा देते हैं। पहले भी ऐसा होता था, पर कम। आज तो पक्ष-विपक्ष के तमाम छोटे-बड़े नेता बिना किसी संकोच मिथ्या यानी झूठ बोलते हैं। वे अपने विरोधी की किसी बात या उसके दावे की ऐसी व्याख्या करते हैं कि वह मिथ्या, सत्य से परे अर्थात झूठ ही होती है, लेकिन यदि आज की राजनीति में ऐसी बातें न की जाएं तो शायद वह अमेरिका से लेकर भारत तक में चल नहीं सकती। झूठ का सहारा लेने वाले नेताओं की बातें कभी-कभार उनकी बोलती भी बंद करती हैं, लेकिन उन पर मुश्किल से ही फर्क पड़ता है। वे संभलकर बोलने को तैयार नहीं।

(लेखक दैनिक जागरण में एसोसिएट एडिटर हैं)
response@jagran.com

## ऊर्जा

### मानव से सिद्धात्मा

संसार में रहते हुये सांसारिक पदार्थों का मन पर जो प्रभाव पड़ता है, उससे असंपृक्त रह पाना कठिन है। वैरागी मन पर राग की अनगिनत परतें होती हैं। वासना, आसक्ति, मोह, लोभ, कामना, लालसा, स्पृहा मानव मन के स्वाभाविक रंग हैं। कभी मन में सात्विक भाव का उदय होता है तो हम करुणा, प्रेम, कर्तव्यपालन, परिश्रम और परमार्थ की भावना से भर उठते हैं। वहीं, तम गुण के हावी होने पर क्रोध, भय, विनाशक प्रवृत्ति से भर जाते हैं। यह मानवीय प्रकृति है, इस पर ग्लानि नहीं, नियंत्रण का प्रयास हो। साधक वही है जो उस साधना में लगा है कि मन को कैसे जीता जाए। जब आंशिक रूप से राग-द्वेष, लोभ-लालसा, उद्वेग-संवेग शेष रहते हैं, तब भी वह साधक ही है। साधक किसी विद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी की तरह है जो विद्यार्जन कर रहा है, अनुशासन में ढलने का प्रयास कर रहा है, घंटों बैठकर अध्ययन करने का शरीर को प्रशिक्षण देता है। साधक वही जो काया और माया को साधने का प्रयास करे। अतः कुछ समय के लिए भी वीतरागी होने का मन करे तो समझना चाहिए कि साधना का पावन मार्ग खुल चुका है। मन की मूल प्रवृत्ति है वीतराग, वह अपने स्वरूप में लौटना चाहता है।

इच्छाओं के वशीभूत माया के कारागार में फंसा मनुष्य जब पूरी तरह से क्रोध, लोभ, मोह, मद आदि से विरत हो जाए तब वह 'सिद्ध' पुरुष कहलाता है। सिद्ध होने के लिए कुछ वर्ष ही पर्याप्त नहीं। यह भी अनिवार्य है कि सिद्ध पुरुष होने के लिए मानव बनकर ही जन्म लेना पड़ता है। मानव से साधक, साधक से सिद्ध होने की यात्रा इसी काया में संभव है। देवताओं को भी यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। अतः प्रथमतः अपने भाग्य को सराहना चाहिए कि मानव रूप में जन्म मिला, दूसरा यदि प्रेरणा, सत्संग, स्वाध्याय किसी भी माध्यम से आत्मउन्नति की राह दिखे तो उस पर निःसंकोच चल देना चाहिए।

ट्विंकल तोमर सिंह

https://t.me/AllNewsPapersPaid1

# बाढ़ का बढ़ता प्रकोप

सुधीर कुमार

> भारी बारिश और हिमनदों के टूटने से बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हर साल हजारों लोगों की जान जा रही है

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने हाल में जलजनित आपदाओं से मानवता की रक्षा के प्रति आगाह करते हुए कहा कि भारी बारिश और हिमनदों के टूटने से जुड़ी बाढ़ की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे हर साल हजारों लोगों की जान जाती है और अरबों डालर का नुकसान होता है। इन दिनों दक्षिण-पश्चिमी मानसून में आई तेजी के कारण देश के कई हिस्से बाढ़ग्रस्त हो गए हैं। ऐसी स्थिति में प्रभावित आबादी के लिए चेतावनी तंत्र को मजबूत बनाना, बाढ़ प्रबंधन को प्रभावी बनाना और ठोस पुनर्वास व्यवस्था अपनाना जरूरी हो गया है। गौरतलब है कि भारत बांग्लादेश के बाद भारत दुनिया का सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित देश है।

भारत में वर्षा का प्रमुख स्रोत दक्षिण-पश्चिमी मानसून है। जून से सितंबर के दौरान देश की लगभग 75 प्रतिशत वर्षा की आवश्यकता इसी से पूरी होती है। हालांकि नदियों में गाद जमा होने, वनों की कटाई और अनियोजित शहरीकरण के कारण जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाती, जिससे वर्षा का जल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करने में सहायक बनता है। बाढ़ से से न सिर्फ जान-माल की हानि होती है, बल्कि लाखों किसानों की मेहनत पर भी पानी फिर जाता है। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग के अनुसार देश में लगभग चार करोड़ हेक्टेयर भूमि बाढ़ की चपेट में है और औसतन 1.86 मिलियन हेक्टेयर भूमि सालाना प्रभावित होती है। इसमें प्रभावित होने वाला वार्षिक औसत फसली क्षेत्र लगभग 37 लाख हेक्टेयर है। वहीं 2011 से 2020 के बीच हर साल लगभग 1500 लोगों को बाढ़ के कारण जान गंवानी पड़ी है। इससे इतर बाढ़ के आने से सड़क, पुल, रेलवे लाइन जैसी आधारभूत संरचनाएं भी प्रभावित होती है, जिससे न सिर्फ जनजीवन प्रभावित होता है, अपितु देश की अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का भी लगता है। बाढ़ के कारण मानवता विस्थापन का दंश भी झेलती है। इससे प्रभावित आबादी का जनजीवन और आजीविका दोनों प्रभावित होता है। इस दौरान उन्हें भोजन, स्वच्छ पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी सुविधाओं से दो-चार होना पड़ता है। बाढ़ के समाप्त हो जाने के बाद भी प्रभावित आबादी को पुनः मुख्यधारा से जोड़ना एक दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। जानमाल की क्षति की भरपाई एवं स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा सुनिश्चित करना चुनौती बन जाती है।

बहरहाल बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है, जिसे आने से पूरी तरह रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इससे होने वाली हानि को कम जरूर किया जा सकता है। जल स्रोतों की नियमित सफाई, मानसून के आगमन से पूर्व तालाब आदि का निर्माण, वनीकरण को बढ़ावा और छत वर्षा जल संग्रहण आदि प्रयास इस दिशा में कारगर हो सकते हैं। इससे न सिर्फ भूमिगत जल का स्तर बढ़ाया जा सकता है, बल्कि बाढ़ की विकरालता को भी कम किया जा सकता है।

(लेखक बीएचयू में शोधार्थी हैं)

## मेलबाक्स

### भगवा आतंक का उलटा पड़ा दांव

'षड्यंत्र था भगवा आतंक का जुमला' में संध्या जैन ने यथार्थ लिखा कि इस्लामिक आतंक की धारणा को संतुलित करने के लिए ही भगवा या हिंदू आतंक का फर्जीवाड़ा किया गया। इसे स्थापित करने के लिए ही कई कड़ियां भी जोड़ी गईं। समाज सेवा में संलग्न ऐसे लोगों को उसमें आरोपित बनाया गया, जिनसे हिंदू समाज प्रेरणा लेता है। यह इसलिए भी किया गया, ताकि हिंदुत्व की ओर आकर्षित लोग हिंदुत्व और इस्लाम को एक जैसा मानकर उससे बिदक जाएं। दरअसल कांग्रेस सहित कथित सेक्युलर दलों का यही सोचना था कि भगवा आतंकवाद का जुमला स्थापित कर वे मुस्लिम तुष्टीकरण की अपनी राजनीति चमका सकें। हालांकि परिणाम इन दलों की आशा के अनुरूप नहीं रहे। इस कवायद में जिन्हें आतंकवादी के रूप में बदनाम किया गया, वे ससम्मान इस चक्रव्यूह से बाहर निकले। जबकि यह जुमला आगे बढ़ाने वाली कांग्रेस अपना राजनीतिक वजूद बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उसे यह दांव उलटा पड़ा।

युवराज पल्लव, सहारनपुर (उप्र)

### कब सुधरेंगे राहुल

यह पहली बार नहीं है जब शीर्ष कोर्ट ने राहुल गांधी के अतिशयोक्तिपूर्ण वक्तव्यों पर नाराजगी जाहिर की है। राहुल गांधी बार-बार उन चीजों पर आपत्तिजनक बयान देने के आदी हो गए हैं जो उनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता। अपने इसी मंतव्य को साबित करने के लिए उन्होंने राफेल विमान की खरीद में कमीशनखोरी का आरोप लगाते हुए 'चौकीदार चोर है' जैसा आपत्तिजनक नारा लगाना शुरू कर दिया। बाद में जिसके लिए उन्हें कोर्ट से फटकार सुननी पड़ी। यही नहीं दो जन्मों तक काला पानी की कठोर सजा पाए जन-मन में 'वीर' की उपाधि से विभूषित महान क्रांतिकारी सावरकर को उन्होंने 'माफी वीर' जैसे शब्दों से अपमान करना शुरू कर दिया। जिसके लिए भी उन्हें फटकार सुननी पड़ी। 'भारतीय सैनिकों को चीनी सैनिकों द्वारा पीटा गया' जैसे आपत्तिजनक शब्द का उपयोग करने से भी उन्होंने गुरेज नहीं किया। आजकल उनके सारे वक्तव्य पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियां बन जाते हैं और पाकिस्तानी सरकार उसे भारत के खिलाफ अपने अस्त्र के रूप में इस्तेमाल करती है, आखिर इसका क्या कारण है? राहुल गांधी को समझना चाहिए कि सत्ता के लिए राष्ट्र का अपमान देश की जनता भी पसंद नहीं करती।

वेदप्रकाश पांडेय, अंबेडकर नगर, उप्र

### डिजिटल क्रांति की मिसाल यूपीआइ

भारत का यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआइ) 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा रियल-टाइम पेमेंट सिस्टम बन गया है, जिसने वैश्विक वित्तीय इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जोड़ दिया है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यूपीआइ हर दिन 650 मिलियन ट्रांजेक्शन दर्ज कर रहा है, जो अमेरिका के वीजा नेटवर्क (639 मिलियन) से भी अधिक है। केवल जून 2025 में ही यूपीआइ के माध्यम से 18.39 बिलियन ट्रांजेक्शन हुए, जिनकी कुल कीमत 24 लाख करोड़ रुपये थी, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 32 प्रतिशत अधिक है। भारत में आज कुल डिजिटल भुगतानों का 85 प्रतिशत और वैश्विक स्तर पर 60 प्रतिशत रियल-टाइम ट्रांजेक्शन यूपीआइ के जरिए हो रहे हैं। यह केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि एक सामाजिक-आर्थिक क्रांति का प्रमाण है। 2016 में नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा शुरू की गई इस प्रणाली ने मुफ्त लेनदेन की सुविधा, अत्यधिक सरलता, और विभिन्न एप्स एवं बैंकों के बीच पूर्ण इंटरआपरेबिलिटी के जरिए आम नागरिक को भी डिजिटल भुगतान की दुनिया से जोड़ दिया। गूगल पे, फोने पे और पेटीएम जैसे एप्स के जरिए 675 से अधिक बैंक यूपीआइ से जुड़े हुए हैं। इससे व्यक्ति-से-व्यक्ति (पी2पी) और व्यक्ति-से-व्यापारी (पी2एम) ट्रांजेक्शन सहज, सुरक्षित और तेज हो गए हैं। यूपीआइ अब भारत के बाहर भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, नेपाल सहित सात देशों में यह सेवा उपलब्ध हो चुकी है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम, मप्र

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: response@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष: नई दिल्ली कार्यालय: 011-43166300, नोएडा कार्यालय: 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।
********